खण्ड–492, अंक–3
सोमवार, 04 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(23 फरवरी, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 492 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रदेश में नकल माफियाओं द्वारा ठेके पर नकल कराये जाने का प्रकरण उठाने का प्रयास	7
प्रदेश में स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग एवं इलाज की व्यवस्था कराये जाने की मांग ...	7–8
प्रश्नोत्तर	8–89
भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देने हेतु प्रस्ताव लाने का प्रयास ...	90
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	90–92
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	92–93
प्रदेश के सीमावर्ती चेक–पोस्टों पर फल–फूल आदि कच्चा माल ढोने वाले वाहनों हेतु अलग से लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	93–94
प्रदेश की मण्डी समिति में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पंचम एवं छठा वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला ककरा में शवों को जलाने के लिये एक व्यवस्थित शवदाहगृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	94–95
वाराणसी महानगर में पौराणिक लक्ष्मीकुण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद आगरा की कतिपय मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	95–96
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में मंडी समिति द्वारा बनाई गई सड़कों की विशेष मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	96
गोरखपुर समेत प्रदेश के समस्त सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की दवा पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
नौतनवां से सौनोली एवं सौनोली से नेपाल के मध्य बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद रायबरेली में मुख्य डलमऊ नहर (ए) में ग्राम धैताली का पुरवा में	97

विषय	पृष्ठ–संख्या
लिफ्ट पम्प लगाकर सिंचाई की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	97–98
जनपद कासगंज में सहावर से सोरों के मध्य प्रस्तावित मार्ग के मरम्मत कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	98
जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र जनपद कानपुर के अन्तर्गत गभाना–बरौली सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	98–99
जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर के राजस्व ग्राम अहिरवा में जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने एवं मुख्य मार्गों को बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	99
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के कतिपय चौराहों पर जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	99
महानगर बरेली में श्यामतगंज रोड पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	99
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	99–100
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गोला अन्तर्गत ग्राम बेवरी के निकट सरयू नदी पर गोला–गोरखपुर से रौनापार–आजमगढ़ को जोड़ने हेतु पीपा पुल/पक्का पुल का निर्माण जनहित में कराये जाने विषयक श्री विद्याधर पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	100
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गोला के अन्तर्गत ग्राम हरपुर (चीनी मिल रोड) से प्रेम नगवा होते हुए पठखौली (राम जानकी राज्य मार्ग, गोला–उरुवा रोड) तक के कच्चे मार्ग को जनहित में पिच सड़क बनवाये जाने विषयक श्री राजकुमार तिवारी आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	100–101
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर एवं विकास खण्ड खोराबार के अन्तर्गत बोहाबार से रामपुर चौराहे तक क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री कालीचरन आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित	101

की गई) ... ...

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा हरैइया में मझने नाला पर स्थित झिरझरवा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राज बहादुर निषाद व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 101

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत गोहडौर चौराहे से टमठा तक की जर्जर सड़क का जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री कालीचरन आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	101
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के अन्तर्गत कुसम्ही बाजार से मोती राम अड्डा तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री गोपाल राजभर आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	101
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत गोहटा बन्धा पर रैंप के नीचे दबे रेगुलेटर को जनहित में यथाशीघ्र चालू कराये जाने विषयक श्री शब्बीर व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की)	102
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	102–168
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	168–170

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–292

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
20. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
21. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
22. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
23. अरूण कुमार, डा0 बरेली
24. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
25. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
26. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
27. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
28. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
29. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
31. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
32. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
33. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
34. आलमबदी, श्री आजमगढ़
35. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
36. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
37. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
38. आशीष यादव, श्री बदायूं
39. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
40. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
41. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
42. इकबाल, श्री बिजनौर
43. इकबाल महमूद, श्री संभल
44. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
45. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
46. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
47. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
48. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
49. उदयराज, श्री उन्नाव
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
51. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
52. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ

53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
55. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
56. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
57. काली चरन सुमन, श्री आगरा
58. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
59. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
60. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
61. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
62. कैलाश, श्री गाजीपुर
63. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
64. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
65. गजराज सिंह, श्री हापुड़
66. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
67. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
68. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
69. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
70. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
71. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
72. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
73. गोमती यादव, श्री लखनऊ
74. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
75. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
76. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
77. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
78. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
79. जगपाल, श्री सहारनपुर
80. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
81. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
82. जफर आलम, श्री अलीगढ़
83. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
84. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
85. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
86. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
87. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
88. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
89. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
90. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
91. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
92. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
93. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
94. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
95. दलजीत सिंह, श्री बांदा
96. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
97. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
98. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
99. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
100. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
101. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
102. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
103. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
104. धर्मराज, श्री बाराबंकी
105. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
106. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
107. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
108. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
109. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
110. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
111. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
112. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
113. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
114. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
115. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
116. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल

117. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
118. पीतमराम, श्री पीलीभीत
119. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
120. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
121. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
122. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
123. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
124. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
125. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
126. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
127. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
128. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
129. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
130. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
131. बदलू खां, श्री उन्नाव
132. बाबू खां, श्री हरदोई
133. बाबूलाल, श्री गोण्डा
134. बावन सिंह, श्री गोण्डा
135. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
136. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
137. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
138. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
139. बैजनाथ, श्री मऊ
140. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
141. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
142. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
143. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
144. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
145. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
146. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
147. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
148. मनीष रावत, श्री सीतापुर
149. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
150. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
151. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
152. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
153. महबूब अली, श्री अमरोहा
154. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
155. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
156. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
157. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
158. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
159. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
160. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
161. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
162. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
163. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
164. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
165. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
166. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
167. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
168. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
169. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
170. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
171. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
172. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
173. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
174. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
175. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
176. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
177. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
178. रणजीत सुमन, श्री एटा
179. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
180. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
181. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ

182. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
183. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
184. रवि शर्मा, श्री झांसी
185. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
186. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
187. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
188. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
189. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
190. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
191. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
192. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
193. राजिव, श्री सहारनपुर
194. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
195. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
196. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
197. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
198. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
199. राधे श्याम, श्री अमेठी
200. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
201. राम करन आर्य, श्री बस्ती
202. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
203. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
204. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
205. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
206. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
207. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
208. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
209. राम मगन, श्री बाराबंकी
210. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
211. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
212. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
213. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
214. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
215. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
216. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
217. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
218. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
219. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
220. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
221. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
222. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
223. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
224. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
225. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
226. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
227. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
228. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
229. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
230. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
231. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
232. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
233. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
234. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
235. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
236. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
237. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
238. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
239. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
240. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
241. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
242. वीरपाल राठी, श्री बागपत
243. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
244. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
245. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
246. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
247. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी

248. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
249. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
250. शाकिर अली, श्री देवरिया
251. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
252. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
253. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
254. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
255. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
256. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
257. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
258. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
259. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
260. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
261. संजय कपूर, श्री रामपुर
262. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
263. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
264. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
265. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
266. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
267. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
268. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
269. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
270. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
271. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
272. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
273. सीमा, श्रीमती जौनपुर
274. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
275. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
276. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
277. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
278. सुधाकर, श्री मऊ
279. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
280. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
281. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
282. सुरेश राणा, श्री शामली
283. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
284. सुल्तान बेग, श्री बरेली
285. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
286. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
287. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
288. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
289. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
290. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
291. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
292. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00 बजे, प्रदेश में नकल माफियाओं द्वारा ठेके पर नकल कराये जाने का प्रकरण उठाने का प्रयास

(विपक्ष के अनेकानेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में नकल माफिया सिर उठाये हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है यह बहुत ही गम्भीर बात है। नकल माफिया ठेके पर नकल करा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए। प्रश्नकाल होने दीजिए। आप सभी लोग बैठें।

श्री प्रदीप माथुर–

ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

एक बात को कितनी बार कहेंगे। बैठिए अब। इसे लिखा नहीं जायेगा।

प्रदेश के स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग एवं इलाज की व्यवस्था कराये जाने की मांग

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में सैकड़ों लोग स्वाइन फ्लू से मर रहे हैं। अकेले लखनऊ में ढाई–तीन सौ लोग इससे प्रभावित हैं। कल अकेले 30 लोगों को इस बात के लिये आंकलित किया गया। हम यह चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में टेस्टिंग की व्यवस्था हो और इलाज की व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न हो जाने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह ऐसी महामारी है जिसमें तत्काल इलाज की आवश्यकता है। मान्यवर, आपको अधिकार है कि आप नियमों को निलम्बित करके जब उचित समझे तो मा0 मंत्री जी से इस सदन में वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

आप की बात आ गई है अब आप बैठें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं मा0 सदस्य से कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई सूचना नहीं है और अगर आपकी यह सूचना है कि सैकड़ों लोग स्वाइन फ्लू से मर गए हैं तो यह सूचना गलत है। ऐसी सूचना देकर लोगों में पैनिक क्रियेट करना, डर, खौफ पैदा करना अच्छी

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बात नहीं है। सदन में किसी मा0 सदस्य का और ऐसे व्यक्ति का जो किसी पार्टी का जिम्मेदार भी हो उनका इतना गैर जिम्मेदाराना बयान मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। कोई पैनिक नहीं है। सारी दवा का इंतजाम है और न इस तरह के हालात हैं जैसे आप बता रहे हैं। खुदा न करे अगर इस तरह के हालात होते भी हैं तो उसके लिये सरकार के पास पूरे इंतजाम हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह ली, अब मंत्री जी को सुनिये। मा0 माथुर साहब, प्रश्न पहर में प्रश्न हो जाने दीजिये, अब आप बैठिये। आप बार–बार उसी बात को कह रहे हैं।

प्रश्नोत्तर

ख 11.04 बजे, नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में भू–गर्भ जल का स्तर लगातार गिरने के कारण सरकार की प्रभावी नीति के अनुसार कार्यवाही किया जाना

''1–श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू–गर्भ जल का स्तर लगातार गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी नीति बनाकर समयबद्ध समीक्षा करके तद्नुसार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

जी हां। प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में भू–जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गिरते भू–जल स्तर की समस्या के प्रभावी निदान के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा प्रदेश में भू–जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रिचार्ज हेतु 'समग्र नीति' निर्गत की गयी है, जिसके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप प्रश्न भी देख लें और उत्तर भी देख लें। यह प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है। भू–गर्भ जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है और सरकार ने अपने उत्तर के पहले पैराग्राफ में इस बात को स्वीकार भी किया है। इस उत्तर के पहले पार्ट में यह आना चाहिये था कि कितना क्षेत्र इससे प्रभावित है। मान्यवर, दूसरा पैराग्राफ देख लें, इसमें उत्तर में यह दिया गया है कि दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा प्रदेश में भू–जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रीचार्ज हेतु समग्र नीति निर्गत की गई है। अब नीति को लेने के लिये हम ऊपर जाएं और फिर से शासनादेश ढूंढे। हमारा यह अधिकार है कि हमको सुसंगत उत्तर मिलना चाहिये। यहॉ पर या तो संक्षेप में नीति दी गई होती या नीति की कॉपी लगाई गई होती, परन्तु यहां पर न तो नीति संक्षेप में दी गई और न

ही नीति की कॉपी लगाई गई। यह अपने आप में ऐसा उत्तर है जो अपूर्ण है। मान्यवर, फिर भी मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से 02 सवाल पूछना चाहता हूं, पहला–कि कितना क्षेत्र प्रभावित है, कितने ब्लाक क्रिटिकल हैं और कितने ब्लाक इससे आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जहां भू–जल स्तर गिर रहा है और दूसरा प्रश्न जब 18 फरवरी, 2013 को यह नीति लागू कर दी है तो उसमें समीक्षा की क्या व्यवस्था है और उसको लागू करने के बाद अब तक कितने ब्लाकों में या कितने आंशिक ब्लाकों में इसकी प्रगति क्या आंकलित की है ? इस नीति को लागू हुए एक वर्ष हो गया है तो एक वर्ष में हम प्रगति जानना चाहते हैं कि एक वर्ष में कितने प्रतिशत जल ब्लाकों में नीचे से ऊपर आया, यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज से नहीं जब से सरकार का गठन हुआ है, इसके पूर्व किसी सरकार ने गिरते हुए भू–जल स्तर पर कभी कोई कार्यवाही नहीं की। सबसे पहले तो मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि वर्ष 2013 में इसकी समग्र नीति मुख्य मंत्री जी ने बनाई। सरकार बनने के बाद उन्होंने समग्र नीति बनाई और समग्र नीति बना करके केवल कागज पर कार्यवाही नहीं किया, अभी आपने कहा है कि जो नीति बनी है, उसकी कापी हमें नहीं दी गयी, लेकिन मैं जवाब देने के लिए सदन में खड़ा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समग्र नीति पर अमल किया है। खन्ना साहब, आप इस सदन में हमसे बहुत पहले से हैं और आज तक हर सरकारों ने केवल इस पर आश्वासन दिया होगा कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे, लेकिन किसी सरकार ने कभी इस पर कार्यवाही नहीं किया। पहले मुख्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के और पहली सरकार है, समाजवादी पार्टी की कि इसकी समग्र नीति बनाने के बाद उस पर कार्यवाही करने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, इसमें सबसे पहले भू–गर्भजल शोधन की गुणवत्ता के लिए 01 करोड़ 66 लाख रुपये का बजट प्राविधान किया गया, जिस पर काम चल रहा है। दूसरा इसमें वाटर हार्वेस्टिंग सेण्टर के लिए 03 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने विश्व बैंक से बात करके 85 करोड़ 92 लाख की योजना स्वीकृत कराई। इस पर भी कार्यवाही चल रही है, शायद आपको पता हो या न हो, अभी आपने कहा कि प्रदेश के कितने ब्लाकों में जल स्तर गिर रहा है। मान्यवर, जब पिछली सरकार थी, मा0 मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार से बात की, 'एक्यूफर मैपिंग' की एक योजना भारत सरकार की है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस एक्यूफर मैपिंग की योजना में उत्तर प्रदेश को लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में जिस दिन एक्यूफर मैपिंग की योजना लागू हो गई, इसके माध्यम से हम सही स्टेटा माप सकेंगे कि किस एरिया में कितना जल स्तर गिर रहा है, किस क्षेत्र में किस एरिया में कितना जल स्तर आज की डेट में है और यह कब तक चलेगा, कब तक वहां पर पानी का स्टेटा बरकरार रहेगा, उसका शोध इस योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, तब आपको सही रिपोर्टिंग मिलेगी। आज की डेट में जो हम पानी का स्टेटा बताते हैं कि हमारे पास इतना पानी का स्टेटा है, कितना जल स्तर गिरा है,

उसके लिए हाई टेक्निक है, वह हाई टेक्निक हमारे पास नहीं थी। इस योजना के माध्यम से हाई टेक्निक हमारे पास आयेगी क्योंकि यह बहुत लम्बी प्रक्रिया है, इसे सुधारने के लिए 1–2 महीने, 4 महीने का समय नहीं चाहिए, इसे सुधारने के लिए लम्बा समय चाहिए। अध्यक्ष जी, न तो हम किसी को पानी पीने से रोक सकते हैं, अगर कोई किसान अपने खेत में बोरिंग कराना चाहता है, न तो हम उसे रोक सकते हैं क्योंकि यह किसानों की सरकार है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि पानी के बगैर कोई व्यक्ति मरने न पाए। इसलिए हम इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते अगर हम कोई अच्छा उपाय नहीं करेंगे तो जाहिर है कि पानी का स्टेटा लगातार गिरता जायेगा। आपने पूछा कि आपने क्या कार्यवाही किया, कितने ब्लाक हैं जो सुरक्षित श्रेणी में आए ? मान्यवर, 13 ब्लाक हमारे सुरक्षित श्रेणी में आए हैं, समग्र नीति बनने के बाद। अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने पूछा कि पहले कितने ब्लाक थे ? पहले 108 ब्लाक क्रिटिकल श्रेणी के थे और आज की डेट में 179 ब्लाक अतिदोहित क्रिटिकल श्रेणी में हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष जी, मैंने यह पूछा था कि इसका परिणाम क्या हुआ ? किसी भी नीति को लागू करने का एक साल में कोई न कोई परिणाम सामने आना चाहिए। एक साल आपने नीति लागू कर दी 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत उसकी प्रगति क्या हुई यह हमें अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जानना है।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर 13 ब्लॉक जो क्रिटिकल थे उन ब्लाकों में वे रिचार्ज पर कार्य किया गया उन ब्लॉकों में पानी का स्टेटस ठीक हो गया और जो ब्लॉक आपने कहा 108 पहले थे 179 हो गए आप जानते हैं जहां क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक रहते हैं क्योंकि हमारे पास वो संसाधन नहीं थे। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी अब हम जब समग्र नीति बनाए हैं तो हम उस संसाधन की व्यवस्था कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी की व्यवस्था कर रहा हूं जिस दिन यह सारी चीजें हो जाएगी उस दिन पूरे प्रदेश का आंकड़ा अध्यक्ष जी हर जगह का आंकड़ा क्योंकि अध्यक्ष जी जो हमारी बोरिंग होती है उसके माध्यम से हम आंकड़ा निकालते हैं एक्यूफर मैपिंग योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 90897 वर्ग किमी0 का क्षेत्र लिया गया है और आप यह जानते हैं जब पूरा क्षेत्र हमारा यह ले लेगा उसके बाद सही स्टेटस और सही चीज की जानकारी जिन ब्लाक 108 के बाद क्रिटिकल हुए वहां पर हमें जानकारी नहीं थी लेकिन हमने रिसर्च करायी शोध कराया उसके बाद जो जानकारी आई वहां पर और क्रिटिकल ब्लॉक हो गए हमने जो क्रिटिकल ब्लॉक थे उनमें से 13 को सुरक्षित श्रेणी में लाया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय लक्ष्मीकांत बाजपेई जी।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 18 फरवरी 2013 का शासनादेश है उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो माननीय मंत्री जी ने माननीय खन्ना जी के

अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बता दी। लेकिन मैं इतनी ही जानकारी करना चाहता हूं मेरा पहला प्रश्न यह है कि समीक्षा का स्तर क्या है और अब तक कितनी बार समीक्षा हुई है और समीक्षा के जो निष्कर्ष निकले हैं उन पर क्या कार्यवाही हुई है। नीति तो सरकार बनने के एक वर्ष बाद आई और नीति के लागू करने के बाद भी 108 से 189 ब्लॉक हो गए प्रयास सरकार के करने के बाद, तो यह समीक्षा का स्तर क्या है और लोग कहते हैं कि यह ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर समीक्षा है कमीश्नरी स्तर पर समीक्षा है या प्रदेश स्तर पर जो समीक्षा में निष्कर्ष निकलता है उन पर कार्यवाही की स्थिति क्या है। नम्बर एक दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जितनी भी आवासीय योजनाएं है बड़े–बड़े टावर बनते हैं या कालोनियां बनती हैं उनमें डेवलेपर के लिए जिम्मेदारी है कि वो वहां पर रेन वॉटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था भवनों से और ओपन लैण्ड में से करेगा लेकिन जो नियम हैं कि किसी भी कालोनी को या टॉवर को डेवलेप करने के बाद उसकी पूर्णता का प्रमाण–पत्र डेवलेपमेण्ट अथोरिटी से लेना होता है वह बाध्यता लागू नहीं हो पा रही है अगर वह लागू हो तो यह रेन वाटर हारवेस्टिंग भवनों से या कालोनी के पार्कों में हो सकती है वो लागू न होने के कारण एक बहुत बड़ा भाग जो जमीन के जल स्तर को रिचार्ज करने का काम कर सकता है मान्यवर वह नहीं हो पा रहा है उस पर मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस पर मा0 मंत्री जी का क्या उत्तर है और अंतिम बात जानना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हम बोरिंग को रोक नहीं सकते न किसान को पीने के पानी के लिए लेकिन फिर भी जल निगम ने एक नीति बनाई थी कि कोई भी हैण्डपम्प इंण्डिया मार्क टू का लगेगा दूसरा हैण्डपम्प 200 मी0 के घेरे में दूसरा हैण्डपम्प नहीं लगेगा। सामान्यतः इसका उल्लंघन अब हो रहा है क्या सरकार इस नीति का पालन करेगी जिससे कि 200 मी0 के घेरे के भीतर यह हैण्डपम्प न लगाएं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी।

श्री राज किशोर सिंह–

अध्यक्ष जी बाजपेई जी या तो दूसरी तरफ सुन रहे थे या इन्होंने सवाल को गम्भीरता से लिया नहीं। हमने आपको बताया है कि समग्र नीति जो बनी उसके बाद हमारी यह योजनाएं हैं अगर किसी स्तर पर इसका उल्लंघन न होता अगर इसकी समीक्षा न होती तो मुख्य मंत्री जी कैसे ये सारी चीजे कर देते यह रिपोर्ट मुख्य मंत्री जी को भी मिली होगी और मुख्य मंत्री जी ने इसे गम्भीरता से लिया और यहां से लेकर भारत सरकार तक करोड़ों रुपये इसके लिए व्यवस्था करवाई क्योंकि आपकी जो तकलीफ है उससे पूरा प्रदेश पीड़ित है और इस सरकार में जो लोग बैठे है उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी ताकत के साथ उनकी मदद करे और जो व्यवस्था हो वह हम उन पर न्यौछावर करें और दूसरी चीज जो बाजपेई जी ने कहा है कि जो बड़े–बड़े मकान बन रहे हैं एक योजना भी आवास की आप बता दीजिए लगभग 30 हजार वर्ग मीटर का क्षेत्रफल इस प्रणाली के अंतर्गत लिया गया है। वाटर रिचार्ज के क्षेत्र में उसमें भी पैसे की व्यवस्था की गई है और इन्होंने जल निगम के बारे में कहा कि

इण्डिया मार्का हैण्डपम्प का जो मानक है वह 200 मी0 पर लगता है। अब 75 मी0 आ गया है और अब 75 मी0 है। अगर 75 मीटर के अंदर न लगा हो तो आप सरकार के संज्ञान में ला दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह नहीं कहा कि सरकार ने समीक्षा नहीं की और सरकार ने समीक्षा पर कार्रवाई नहीं की। मेरा यह कहना है कि शासनादेश के अनुरूप समीक्षा का स्तर क्या है। मैंने यह पूछा, और प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं आया। दूसरा मैंने यह पूछा था कि जो प्राइवेट डेवलपर हैं जो प्राइवेट कालोनियां और टॉवर बनाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसका उन्होंने बता तो दिया ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। उसका पालन कराने के लिए सरकार क्या करेगी और क्या सरकारी भवनों पर भी वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था पर सरकार विचार करेगी ?

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, 10 जनपदों में सरकारी भवनों पर वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था शुरू हो गयी है। और आने वाले समय में हम इसे पूरे प्रदेश में सरकारी भवनों में लेंगे और आपने एक सवाल और किया कि हमने समीक्षा किस स्तर पर की। जिले स्तर पर हमारा एक्सिएन होता है वह जिले स्तर पर समीक्षा करता है उसके बाद निदेशालय में आता है निदेशालय स्तर पर समीक्षा होती है। निदेशालय से शासन में आता है और उसके बाद शासन से मुख्य मंत्री जी तक जाता है। इसमें समीक्षा बराबर चल रही है। बाजपेयी जी इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दीजिए आप मा0 मुख्य मंत्री जी को। 30 सालों में कितनी सरकारें आयीं और किसी सरकार ने इसमें पांच पैसे का काम नहीं किया है। यह पहली सरकार है जिसने वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में काम किया है। इनको धन्यवाद देना चाहिए और अपना सवाल वापस ले लेना चाहिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से बहुत छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा। लेकिन इसके पहले मा0 मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सदन में स्वीकार तो किया कि भारत सरकार ने 90 लाख हे0 भूमि के एक्यूफर मैपिंग की व्यवस्था की है।

श्री राज किशोर सिंह–

पिछली सरकार ने।

श्री प्रदीप माथुर–

इनकी सरकार ने कुछ नहीं दिया है। मान्यवर, यू0पी0ए0 की सरकार कांग्रेस की सरकार ने दिया है। यह कांग्रेस की यू0पी0ए0 की सरकार का पैसा है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, जितनी मजबूती के साथ मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि पिछले 30 साल में किसी सरकार ने कुछ किया ही नहीं, मूलतः यह अपनी पुरानी सरकारों पर टिप्पणी कर रहे हैं। किसी और ने काम किया या नहीं किया लेकिन इस बात की गारंटी हो गयी कि पिछले 30 सालों में इनकी जो सरकारें बनती थीं उन्होंने कुछ नहीं किया। अब अध्यक्ष जी, मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। एक सवाल सदन में बार–बार आ रहा है भू–रिचार्ज का। सरकार ने इसी सदन में कहा था कि विभिन्न महानगरों में जितने पोखरे और तालाब होंगे उनके अतिक्रमण पर नियंत्रण किया जाएगा उस पर रोक लगायी जाएगी। सरकार ने सदन में स्वयं इस बात को कहा था। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर में 113 पोखरे थे और धीरे–धीरे सब इनक्रोच होते जा रहे हैं। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि गोरखपुर के जो 113 पोखरे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न का इससे कहां सम्बन्ध है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इसी से संबंध है। अगर हम पोखरों के कब्जे को नहीं रोकेंगे। तो क्या सरकार ने इन पोखरों के अतिक्रमण को रोकने की योजना बनायी है ?

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से सारे पोखरों पर अतिक्रमण हटाने का आदेश है और हटाया भी जा रहा है। अभी हमने एक व्यवस्था की है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी पोखरे हैं हर जनपद के पोखरों को हमने बजट में लिया है और आने वाले समय में जब उनमें काम होगा तो उनमें जहॉं कहीं अतिक्रमण होगा वह हटेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब बीस मिनट इस सवाल पर हो गये। अब नहीं। अब अगला सवाल लेने दीजिए।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये। अरे भई इनको आप जरा समझाते रहिये। अब नहीं। अब आगे बढ़ गये। आप बैठिये। आपका यह सवाल नहीं था। आप बैठिये।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 में कितने जनपदों पर कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी गई विस्तृत विवरण की जानकारी

'01–श्री सतीश महाना, डा0 अरुण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत प्रदेश में क्या कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2014 में कितने जनपदों हेतु कार्य योजना बनाकर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है तथा इसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास तथा जल सम्पूर्ति मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी हां।

वर्ष 2014 में 03 जनपदों की कुल 07 कार्य योजनायें स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजी गयी है, जिनमें कानपुर जनपद की 04 योजनायें, इलाहाबाद जनपद की 01 योजना तथा वाराणसी जनपद की 02 योजनायें सम्मिलित हैं जिनकी स्वीकृति भारत सरकार से अपेक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–02, नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या–01

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी मुझे विश्वास है कि आज सारी जानकारी माननीय मंत्री जी के पास होगी क्योंकि इस प्रश्न को लेकर पहले भी एक बार मैंने प्रश्न लगाया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो योजनायें हैं, इन योजनाओं में किस मेकर के कार्य हैं। जो योजनाएं भेजी जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें क्या कार्य हैं, यह स्पष्ट रूप से उसमें आया होगा। मान्यवर कौन–कौन से तथा किस प्रकार के कार्य हैं जैसे, सीवरेज लाइन, पानी की लाइन है, घाटों की सफाई, इत्यादि–इत्यादि जो माननीय मंत्री जी बतायेंगे। मान्यवर, आपके माध्यम से दो छोटे–छोटे प्रश्न हैं कि कौन–कौन से कार्य भारत सरकार को प्रस्तावित किये ? कानपुर में जो चार योजनाएं हैं वह कौन–कौन सी हैं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

पिछली सरकारों में भी और इसमें भी इस प्रश्न पर इतनी बहस हुई है कि सब याद हो गये हैं आपके सवाल भी और क्या आप पूछेंगे यह भी। मान्यवर, सीवरेज योजना कानपुर की है सीवर लाइन 245.77 किमी दूसरी है पुरानी सीवर का जीणोंद्वार 179.72

किमी भारत सरकार को चली गयी है। दूसरी है सीवर लाइन 158.39 किमी सीवरेज पम्पिंग स्टेशन एक नग, तीसरी है सीवर लाइन 122.88 किमी सीवरेज पम्पिंग स्टेशन 02 नग और एक में डिटेल इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। 370.40, 183.21, 148.81, 245.91 करोड़ की यह योजनायें हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह गंगा रिवर बेसिन अथारिटी का भी काम है और उसके पहले जी0एन0एन0आर0एन0 के अन्तर्गत गंगा सफाई और उससे सम्बन्धित बहुत बड़े काम इस विधान सभा में चर्चा में आते रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न भी याद हैं और बहुत सारे उत्तर भी याद हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह चौथी कानपुर नगर में अप ग्रेडेशन ऑफ एस0टी0पी0 है। जो 245.91 करोड़ का है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, जी0एन0एन0आर0एन0 भी उससे मिलती योजना है क्योंकि यह गंगा से सम्बन्धित है और गंगा सफाई और गंगा रिवर बेसिन अथारिटी से सम्बन्धित है। इसकी चिन्ता स्वाभाविक रूप से सब लोग करते हैं मैं आरोप–प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसमें सिर्फ पाजिटिव बात निकलती है। मान्यवर जे0एन0एन0आर0एन0 की जो योजना थी माननीय मंत्री जी ने इस विधान सभा क्षेत्र में भी स्वीकार किया है और इसकी जो गठित प्रदेश की समिति है उसमें भी बहुत गम्भीरता के साथ इसको लिया है और बहुत ही कड़ाई के साथ सम्बन्धित अधिकारियों से कहा। उस योजना के लिए भी मैं बड़े दुःख के साथ यह कहना चाहता हूं कि उसमें सैकड़ों करोड़ रुपये लगे, सैकड़ो करोड़ हजार तक पहुंचे या नहीं इसका आकड़ा माननीय मंत्री जी के पास होगा। उसके पश्चात भी मान्यवर न तो सिवर लाइनें चालू हुईं और नई योजना, पुरानी योजनाओं को इस प्रकार से समाप्त करके सुचारू रूप से जनहित में उपयोग लाने के बाद उसकी भी समीक्षा होगी क्योंकि मान्यवर हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक करती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्रता के साथ पूछना भी चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि उन योजनाओं के साथ इसे लिंक करके योजनाओं के बारे में विचार किया जायेगा और कार्य प्रारम्भ किया जायेगा क्योंकि उसमें कानपुर के 36 एयर वाटर रिजरवायर वह भी चालू नहीं हैं इतने ओवर हेड टैंक बनाकर खड़े कर दिये गये हैं। 05–05 साल हो गये ओवर हेड टैंक बनाकर खड़े करने के बाद आज तक किसी एक में भी पानी नहीं भरा गया।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछिये।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर सवाल पूछ रहा हूं मैं बताऊंगा नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उन्हें पता चले कि इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए। इसकी भी समीक्षा करने के बाद आगे भारत सरकार से प्रयास करके जल्दी उनको लिखे ताकि वहां से पैसा आये। उस योजना के कार्य करने तथा उसे ठीक तरीके से चालू करते हुए यह योजना चालू की जायेगी। इसके ऊपर माननीय मंत्री जी विचार करें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कुछ ओवरहेड टैंक का जिक्र आप यहां पहले भी कर चुके हैं और हम जवाब भी दे चुके हैं कि गत सरकार में स्वजल योजना के तहत जो ओवरटैंक बने थे, वह इस पोजीशन में नहीं हैं कि उन्हें भरा जा सके। जब भी उनमें पानी भरा जाता है तो या तो लाइनें बर्स्ट हैं या वह ओवरहेड टैंक इतने खतरनाक हैं कि आधा भी पानी नहीं भरता है और वह हिलने लगते हैं और इस तरह का सुझाव चल रहा है कि सारे ओवरहेड टैंक कैबिनेट में लाकर सब गिरा दिये जाएं वरना उनसे जान का बहुत खतरा है। दूसरे, जहां सीवर का काम होता है तो कई चरणों में होता है और कहीं एस0टी0पी0 में देर होती है, कहीं पाइप डालने में देर होती है, कहीं अतिक्रमण होता है, कहीं कोर्ट का स्टे आ जाता है, तो इन सारी चीजों की वजह से देर लग जाती है, क्योंकि पैसे का एलाटमेण्ट हो जाता है पहले ही, इसलिए काम न कराने की कोई मंशा नहीं रहती है, लेकिन काम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। जो कानपुर की योजनाएं गई हुई हैं, भारत सरकार को, उसे भी पूरा होमवर्क करके ही भेजा गया है और उम्मीद करते हैं कि यह पैसा जल्दी ही आ जायेगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि बहुत सारे ओवरहेड टैंक्स थे जो झूल रहे थे, जिसमें पूरा पानी नहीं भरा जा सकता, स्वाभाविक रूप से यह मेरी भी चिन्ता थी और इसको मा0 मंत्री जी ने निर्भयता से अच्छे मन से स्वीकार भी किया है। क्योंकि मा0 कोई भी अधिकारी इस प्रकार के ओवरहेड टैंक बनाकर चला जायेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी, तो मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं और जिसको कैबिनेट में लाने के पश्चात् आप ध्वस्तीकरण की बात कहते हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर के उन्हें सख्त से सख्त सजा भी मिले, केवल कार्रवाई ही न हो। इसके ऊपर मा0 मंत्री जी का जवाब चाहता हूं। यह जरूरी है मान्यवर, अगर सजा नहीं मिलेगी तो मा0 बनायेंगे वह, गाली खायेंगे हम और आप। हम यहां पर विधान सभा में बैठे हैं, पाप करेंगे वह और झेलेंगे हम। मा0 मंत्री जी आप उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे, यह विधान सभा में बोल दें, तभी इनके ऊपर दबाव बनेगा और इस तरह का पाप करने का काम वह नहीं करेंगे। यह बात सच है कि वह पाप करें और आप उसके ऊपर चिन्ता भी करते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि यह संदेश भी जाना चाहिए जो आपने कहा है, लेकिन मा0 जब तक आप इन्हें जेल नहीं भेजेंगे, तब तक इन पर अंकुश नहीं लगेगा। मा0 इसका जवाब दिलवा दीजिए, क्या मा0 मंत्री जी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, डा0 अरुण कुमार जी खड़े हैं।

डा0 अरूण कुमार–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बताया कि 03 जनपदों की 07 कार्य योजनाओं हेतु स्वीकृति भारत सरकार के पास भेजी गई है और इससे पहले पिछली बार आपने बताया था कि 08 नगरों में 12 सीवरेज योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। मैं जानना चाहूंगा, जब 12 सीवरेज योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है तो फिर से 07 परियोजनाओं को क्यों केन्द्र सरकार के पास भेजा गया, बाकी 05 को क्यों नहीं भेजा गया ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या बरेली भी इस योजना में सम्मिलित है ? यदि नहीं तो क्या सरकार बरेली महानगर को भी जहां की सीवर व्यवस्था बहुत ही ध्वस्त है, को भी इस योजना में शामिल करेगी ? यदि हां तो क्या डी0पी0आर0 बनाकर के केन्द्र सरकार के पास जल्द ही इसको भेजेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लेंगे और भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मा0 अध्यक्ष महोदय, गंगा रीवर बेसिन अथॉर्टी के द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं, उसमें वाराणसी भी एक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा भी दुःख यही है और जनता की परेशनी भी यही है कि जल निगम द्वारा जितने भी ओवरहेड टैंक बनाये गये हैं, वह बार–बार टेस्टिंग में फेल हो रहे हैं। न तो उसमें पानी भरा जा रहा है, न तो उससे पानी की आपूर्ति करना सम्भव हो पा रहा है, जिससे कि जो पेयजल का संकट भोग रहे हैं, उनको राहत मिल सके। दूसरी बात यह है कि 566 किमी0 या समथिंग ऐसा ही है, 86 करोड़ रुपये की एक योजना लोगू हुई जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत, जिसमें घर बैठ कर के डी0पी0आर0 बना लिया गया और भारत सरकार से रुपया भी ले लिया गया और आज भी सैकड़ों जगह ऐसी हैं मा0 अध्यक्ष महोदय कि जहां पाईप लाईनें नहीं हैं और जो पी0वी0सी0 का पाईप लाईन यह लोग बिछा रहे हैं मनमाने तरीके से कहीं भी बिछा दे रहे हैं, क्योंकि इनके यहां कोई प्रॉपर डी0पी0आर0 बना ही नहीं कि कहां है पाईप लाईन, कहां नहीं है। तो यह काम भी नहीं हो रहा है और सीवर लाईन का जहां तक सवाल है, मा0 मंत्री जी स्वयं संवेदनशील हैं और मैं उनको लिखता रहता हूं, कई बार उठाता भी रहा हूं लेकिन मुझे बहुत दुःख है कि आपके लाख प्रयास के बाद भी, बहुत दबाव के बाद भी वाराणसी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है और वहां आये दिन सीवर जाम है, सीवर ओवर फ्लो है, पानी नहीं मिल रहा है। इसी में सारा वक्त गुजर जाता है, जल संस्थान को फोन करने में और ये सब करने में। मा0 मंत्री जी, आप बता पायेंगे कि आपके सारे दबाव का परिणाम कब असर दिखायेगा और जो ओवर हेड टैंक

बनकर खड़े हैं, जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं, वे कब चालू होंगे ? इसी के साथ में जो सीवर लाइन है उसका भी काम होगा। जो पेयजल पाइप लाइन है, वे जहां जरूरत है वहां भी बिछा दी जायेंगी और जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, दादा ने बहुत अच्छा अफसाना सुनाया लेकिन इसमें कोई प्रश्न नहीं है। अगर कहीं के बारे में आप बतायें कि कहॉ का सीवर बन्द हो गया है, कहॉ ओवर फ्लो है, कौन सा ओवर हेड टैंक ऐसा है जो बन गया और फंक्शनल नहीं है, कहॉ की लाइन कट गई है ? मान्यवर, अफसाना तो अच्छा था लेकिन उसका कोई एण्ड नहीं आया। अगर आप कोई जगह बतायेंगे तो मैं उसको जरूर दिखवाऊंगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे अनुभव की कमी हो सकती है। मा0 मंत्री जी तो बहुत भिज्ञ हैं और आप हमको टेक्निकली उत्तर न दे करके, आप काबिल हैं, आप उत्तर दे सकते हैं, आपके संज्ञान में है लेकिन आप पूछ रहे हैं कि आप बताइये कि अमुक प्वाइण्ट पर ओवर हेड टैंक बना है तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि मछोदरी पार्क में दक्षिणी विधान सभा के अन्तर्गत जो ओवर हेड टैंक बना हुआ है, वह चालू नहीं हो रहा है। कोनिया क्षेत्र में जो ओवर हेड टैंक बना हुआ है, वह चालू नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, मा0 मंत्री जी ने बता दिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

आपने कहा न कि नाम बताना है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने बता दिया कि वह सब इस काबिल नहीं है, उस योग्य नहीं हैं कि उसमें पानी भरा जाये तो आप उसको क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मा0 मंत्री जी, यह दर हकीकत है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, अब दादा की बात को गलत तो कहा ही नहीं जा सकता और सही भी नहीं है। (सदन में हंसी) मान्यवर, देखिये जब कोई ओवर हेड टैंक बनता है तो पाइप लाइन है उसकी टेस्टिंग है ये सब चलती है। मैं उसको दिखवा लूंगा। मैं इन सबको दिखवा लूंगा कि कहां कमी है ? कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह के जितने भी काम हों, पाइप लाइन का बिछना हो या ओवर हेड टैंक का बनना हो। वह बिल्कुल क्वालिटी का हो, उसमें कोई खराबी या कमी न हो। इसके अलावा, दादा आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली सरकार में ही हमने पूरे बनारस की जितनी भी पाइप लाइन हैं, उसे चेंज कराया है और ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि पूरे बनारस की पुरानी लाइन को, जो खराब हो गई थी, गल गई थी। इतने घने शहर के अन्दर पूरी

लाइन को बदलवाना कितना बड़ा चैलेंज था, आप उसके लिये तो कम से कम धन्यवाद कर दीजिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मैं आपका शुक्रिया इस अफसाने के साथ करना चाहता हूं कि जो ट्रंक सीवर लाइन थे उसको आपने जरूर मेहनत करके चेंज कराया था लेकिन जो ग्राण्ट सीवर लाइन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस पर भी आप थोड़ा गौर करें और थोड़ा संजीदा हों।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बिल्कुल संजीदा हो गया, आज के बाद और संजीदा हो जाऊंगा और उसे भी देख लूंगा।

श्रीमती ज्योत्स्ना श्रीवास्तव–

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे वहां जो ओवर हेड टैंक हैं उनमें जब पानी भरता है तो उनसे झरने की तरह पानी गिरता है मल्लापुरा खुर्द में। इसके अलावा, कोनिया का अभी दादा ने जिक्र किया। इन सब में झरने की तरह पानी गिरने लगता है, बन्द हो जाते हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 से रिलीविंग सीवर लाइन आई। 2012 में रुपया आ गया लेकिन 2014 तक काम शुरू नहीं हुआ। 2014 में हम लोगों के द्वारा बहुत चिल्लाने के बाद एक काम पूरा हुआ है अस्सी से नरिया तक। दूसरा शुरू हुआ है और फिर आधे में रुका हुआ है। बहुत कुछ कहने के बाद वह शुरू हुआ है, मतलब एक पूरा हुआ है कैण्ट विधान सभा में। 04 आये थे, एक पूरा हुआ है, दो शुरू नहीं हुआ और एक आधा हुआ है। ये है काम की प्रगति और जो पाइप लाइन की बात हो रही है तो उसमें कहीं तो पाइप लाइन डबल–डबल हो जा रही है और कहीं पाइप लाइन बिछी ही नहीं है। अभी भी शिवपुरवा के शिवपुरम् में पाइन लाइन नहीं बिछी है, निरालानगर में पानी नहीं है।

सवाल मेरा यह है कि जो जे0एन0एन0आर0यू0एम0 में पैसा दे दिया गया, जो पेमेण्ट आ गई है सारी, वह काम कब शुरू होगा, कब हम लोग इस ओवर फ्लो की समस्या से निजात पाएंगे। मान्यवर, मैंने नियम–301 के माध्यम से कई बार यह सवाल उठाया है लेकिन हमें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जवाब नहीं अब आपको संतोषजनक काम मिलेगा, जो पैसा आ जाता है भारत सरकार से उसे जल्द से जल्द लगाया जाता है, चूंकि फेजेज में आता है, लिहाजा हमारी परेशानी है कि उसको फेजेज में ही खर्च कर सकते हैं। दूसरा जहां तक यह झरनों का सवाल है, जब पानी ओवर फ्लो हो जाता है, उसको मैं दिखवा लूंगा, जिन–जिन जगहों का आपने नाम बताया है। ओवर फ्लो के बाद ही वह पानी ऊपर से गिरता है, बाकी टैंक में कोई खराबी नहीं होती है। मैं इसे दिखवा लूंगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली यू0पी0ए0 की सरकार में शहरों के नवीनीकरण के लिए जवाहर लाल नेहरू अर्बन रेन्यूवल मिशन बाद में जो नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथॉरिटी के नाम से योजनायें चलाई गई हैं, उसमें सीवर पानी आदि की व्यवस्था करनी है। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इलाहाबाद की भी एक योजना भारत सरकार में भेजी गई है। हमारे क्षेत्र के डिस्ट्रिक–सी के सीवर की योजना है, जो सेकेण्ड फेज में है, क्या वह इसमें सम्मिलित है और अगर सम्मिलित है तो इसको कब से शुरू करा देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह आपके नगर की सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–ई की अवशेष कार्य की योजना है। यह 62.2 करोड़ की योजना है, ये चला गया है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जो फेजेज में पैसा आता है वह स्वाभाविक रूप से फेजेज में खर्चा होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाकर उस पर एक प्रश्न करना चाहता हूं कि कानुपर में जो क्लियर वॉटर रिजर्वाइस बनने थे, उसके लिए आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व, जो उसका इलेक्ट्रिकल मैन्टेनेन्स और मोटर का काम था, उसकी सारी परचेजिंग कर ली गई थी। जिस समय सारी बिल्डिंग बन जायेगी उस समय स्विच और बल्ब बाद में खरीदा जायेगा और वह सारी की सारी परचेज करने के बाद जाजमऊ जो सीवरेज प्लांट है वहां पर रख दिया गया था। मेरी पक्की जानकारी के अनुसार विधान सभा में मैं कह रहा हूं कि वह पूरा का पूरा पैसा तब लगना था जिस समय यह बन जाता। न वह पॉच साल में बना और इलेक्ट्रिक मैन्टेनेन्स का जो पूरा का पूरा सैकड़ों करोड़ का, वह सारा का सारा चोरी हो गया या वह खराब हो गया। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जो इलेक्ट्रिक का मैन्टेनेन्स का सामान उन वॉटर रिजर्वस के लिए आज से 5 वर्ष पहले खरीदा गया, आज तक नहीं लगा, उसके चोरी हो जाने पर, उसके नष्ट हो जाने पर, उसकी जॉच कराकर उसकी जिम्मेदारी तय करेंगे और इस पर जिम्मेदारी तय करके कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह मेरे लिए सूचना है। यदि ऐसा है तो मैं सदन में ऐसा निर्देशित कर रहा हूं कि तीन दिन के अंदर विभाग मुझे इसकी सूचना देगा।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए। इसमें मथुरा का तो कुछ है नहीं आप क्यों परेशान हैं ?

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में खाली गंगा नदी ही नहीं आती है, यमुना नदी भी उसमें शामिल है। अच्छा होता कि आप यमुना नदी के बारे में भी इसमें बोलते, क्योंकि यमुना प्रमुख नदियों में से है।

श्री अध्यक्ष–

आपने सवाल तो लगाया नहीं है, दूसरे के सवाल में पूछ रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्मय से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी बताएंगे कि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के अन्तर्गत वर्ष 2014 में यमुना नदी हेतु कितने जनपदों के लिए कार्य योजना बनाकर भारत सरकार में स्वीकृति के लिए भेजी गई तथा इसका विस्तृत विवरण है, यदि नहीं तो क्यों ? बताइये।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कैसे कहते हैं बताइये, पहले आप बैठिए तो। माननीय मंत्री जी आप बतायें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है अभी।

श्री प्रदीप माथुर–

रस्सी जलने में भी आप ही का हाथ है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

क्यों नहीं, ठीक, ठीक रहे होते। मान्यवर, कुछ ऐसा चल रहा है और ऐसा सुझाव भी है, भारत सरकार में भी इस पर काफी बात चल रहीं है और हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि सभी नदियों को इसमें शामिल कर लिया जाए।

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अगस्त, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक धर्मान्तरण के दर्ज मामलों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

'01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री दीपक पटेल, श्री धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अगस्त, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक धर्मान्तरण के खिलाफ क्या मामले दर्ज किये गये हैं ? यदि हां, तो कब, कहां और कितने मामले दर्ज किये गये हैं और उस पर क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी हां।

प्रदेश में अगस्त, 2014 से 31–12–2014 तक जनपद आगरा में एक अभियोग मु0अ0सं0–68/14 धारा–153क (बी)/415/417 भा0द0वि0 थाना सदर, आगरा में दिनांक 09–12–2014 को वादी श्री इस्माइल की सूचना पर नन्द किशोर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त नन्द किशोर उर्फ किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद–25 से 29 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन इधर जब से भा0ज0पा0 की सरकार केन्द्र में आयी है तब से लगातार धर्म की स्वतंत्रता के इस अधिकार पर बाधा डाली जा रही है। मान्यवर, 8 दिसम्बर, 2014 को धर्म परिवर्तन की एक घटना घटित हुई है जवाब में आया है कि इसमें एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें विवेचना जारी है। मान्यवर, जो इसमें बाकी लोग संलग्न थे उनके बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। मान्यवर, इस तरह से इन घटनाओं को घटित करके समाज में उन्माद का वातावरण पैदा किया जा रहा है। मान्यवर, इसमें जो आगरा में इस संगठन के समन्वयक श्री राजेश्वर सिंह जी हैं उनका बयान आया है कि वह इस तिथि को आगरा में थे और वहां पर हमने धर्म परिवर्तन कराया है। और उनका जो सबसे खतरनाक बयान आया है वह यह है कि वर्ष 2021 तक सभी ईसाई और मुस्लिमों को धर्म परिवर्तित करके हिन्दू बनना होगा अन्यथा उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। मान्यवर, जिनका धर्म परिवर्तित कराया गया है वह गरीब लोग हैं, कूड़ा बीनते हैं और श्रम करके अपना जीवन पालन करते हैं। मान्यवर, इस तरीके से लगातार कोशिश करके धर्म परिवर्तन की व्यवस्था की है। मान्यवर, वैसे वहां पर धर्म परिवर्तन की व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि हर जगह भी धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जा रहा है और वहां पर लोगों की कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, वहां पर इस्माईल नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखायी है कि वहां लोगों को लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराने का काम किया गया है। मान्यवर, इस तरह से जो लोग धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं और जो वहां पर उपस्थित थे उनको इस विवेचना में सम्मिलित न किये जाने का क्या कारण है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो रिपोर्ट है वह यही है कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है यह जबरन कराया गया है। मान्यवर, धर्म और मजहब इतना सस्ता नहीं है जिसे परिवर्तित कराया जा सके। मान्यवर, जिस तरह के वे लोग थे गरीब थे उनके पास पुराने बोशीदा कपड़े थे उनके सिर पर टोपियां नहीं थीं नई टोपियां थीं। मान्यवर, यह बहुत दुःखद है। मान्यवर, यह वाकई संविधान का किसी हद तक खिलवाड़ भी है। मान्यवर, अफसोस की बात है कि गैर जिम्मेदारना बयानात जो जिम्मेदार संगठन हैं उनकी तरफ से आ रहा है। लेकिन इस पर कार्यवाही हुई है। मान्यवर, इसमें दरअसल समाज में जागरूकता लाने की जरुरत है और यह एहसास दिलाने की जरुरत है कि धर्म और मजहब को इतना सस्ता

न बनाया जाये। मान्यवर, कोई व्यक्ति एक वक्त के खाने और कुछ अन्य प्रलोभन में आकर धर्म परिवर्तन कर दे तो यह बात समझ में नहीं आती। हो सकता है अगर हम इस पर विचार करते कि उस गरीब व्यक्ति को यह कहा जाता कि उसे मकान दिया जायेगा उसे किसी फैक्ट्री का मालिक बनाया जायेगा तो कोई बात समझ में आती। लेकिन एक वक्त का खाना खिलाकर कोई अपने मजहब को बदल सकता है तो फिर वह मजहब नहीं है। यह कहा गया है कि उन लोगों ने ऐसा ही किया है। मान्यवर, जो किसी को आस्था को बदलने के लिए ऐसी पहल करने के लिए और उसकी पब्लिसिटी करने के लिए जो यह किया गया है उसकी निन्दा करनी चाहिए थी।

श्री प्रदीप माथुर–

ख ग ग ग ,

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य एक साथ होकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब, आप बैठें। जो प्रश्न था उसका पूरा उत्तर आ गया है अब इसमें कुछ नहीं बचा है।

माथुर साहब, आप बैठिये अब लिखा नहीं जायेगा।

माथुर साहब अब मेरा आग्रह है आपका तो यह सवाल भी नहीं था आप बैठिये क्या आप बार–बार कह रहे हैं। आप बैठिये अब लिखा नहीं जायेगा। जो यह बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, माथुर साहब की बात को कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, आगे का प्रश्न लेने दीजिये। यह क्या हो गया है। आपका इसमें जो सवाल था उसका उत्तर आ गया एक ही सवाल था।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य अपने–अपने आसन पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री मोहम्मद आजम खां–

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, समझ में यह नहीं आ रहा है कि इसमें बी0जे0पी0 को इतना बुरा क्यों लग रहा है। (व्यवधान)

कुछ कह दिया इन्होंने, किसको कह दिया भा0ज0पा0 को कुछ कह दिया ? अगर कुछ कह दिया है तो वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा अध्यक्ष जी ने कह दिया है।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब बैठें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा कार्यवाही से निकलवायें बहुत अच्छा है मानसिकता से भी निकलवायें इसे। मानसिकता से भी निकलवाये भारतीय जनता पार्टी की। इस तरह से बहुत बर्बादी हो रही है, मानसिकता से निकलवायें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (सदन के वेल से)–

मान्यवर, इनके पास कोई सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा आचरण किया है। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने आसन पर खड़े होकर बतायें कि क्या कहना है यह तो बताते नहीं हो।

(श्री अध्यक्ष के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने–अपने आसन पर चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो माथुर साहब ने कहा उसकी कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमने तो सुना नहीं आप बताइये क्या कहा ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, जो भी कहा उसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपकी पीठ से निर्देश हो गया कि अगला प्रश्न लिया जाय उसके बाद माथुर साहब ने जो कुछ कहा वह कार्यवाही का अंग नहीं बनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अब आप बैठें।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है, आप बैठें।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह प्रदेश को अराजकता मे झोंक देंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय माथुर जी ने कोई ऐसी बात यहां पर नहीं कही जिस पर इतनी उत्तेजना यहां पर फैलाई जाय। मेरा कहने का मतलब है कि विवेचना हो रही है उस विवेचना में केवल नन्द किशोर को ही आपने आरोपी ठहराया है या जांच में कोई और नाम उसमें आये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत गम्भीर है अच्छा हुआ कि इस पर उस तरह की बहस सदन में नहीं हुई और होना भी नहीं चाहिए लेकिन जिस तरह का यह वाक्या था या जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना या देश भर में जिम्मेदार संगठनों ने जिस तरह की बात कही वह पूरे देश के माहौल को जला देने के लिये काफी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सूझबूझ के साथ काम लिया है, उत्तेजना को बढ़ने नहीं दिया गया है। जहां वाकया हुआ है, उसे उसी जगह पर रोक दिया गया है। इस मुकदमें में भी जांच चल रही है और मैं आश्वस्त करता हूं कि इसमें जो भी लोग जिम्मेदार होंगे, उसके खिलाफ पूरी तरीके से कठोर कार्यवाही होगी। हमारी अपनी जिम्मेदारी यह भी है कि इस तरह का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ कानून के साथ–साथ हम समाज को इस बात के लिए तैयार करें कि जो लोग सिर्फ वोटों के लिए देश को जलाना चाहते हैं, उनको सबक सिखाये और वह ऐसे नतीजे दिल्ली में पा भी चुके हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं और इसके विरोध में सदन से बर्हिगमन करता हूं।

(मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री प्रदीप माथुर ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन किया)

प्रदेश में कानून व व्यवस्था नियंत्रित करने की दृष्टि से जनसंख्या के अनुपात में पुलिस वाहनों को उपलब्ध कराया जाना

'02–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कानून व व्यवस्था नियंत्रित करने की दृष्टि से जनसंख्या के अनुपात में पुलिस वाहनों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के पुलिस थानों को नये व आधुनिक दो पहिया व चार पहिया पर्याप्त वाहन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानून व शान्ति व्यवस्था नियंत्रित करने हेतु जनसंख्या के अनुपात में वाहन स्वीकृत करने का कोई मानक निर्धारित नहीं है। जनसंख्या, अपराध की संख्या एवं जनपद की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत थानों की स्थापना की जाती है। प्रदेश के पुलिस थानों को हल्के चार पहिया वाहन तथा दो पहिया वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का बड़ा जनरल सा जवाब दे दिया है। मान्यवर, मेरी मन्शा यह थी कि जनसंख्या के अनुपात में वाहनों की व्यवस्था हो जाये। कई थानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है जैसे कि मेरे जनपद अलीगढ़ में एक कोतवाली इगलास है, जिसमें 400 गांव हैं और मेरे ही क्षेत्र में एक थाना ऐसा है जिसमें 60 ग्राम हैं, वहां भी एक खटारा गाड़ी है और यहॉ भी एक खटारा गाड़ी है। जनसंख्या के हिसाब से वाहन रखने की एक नीति बनाने का अनुरोध मैंने इसलिये किया है क्योंकि जो बड़े थाने हैं वहां पर ज्यादा वाहन मिल जाये और छोटे थानों में एक वाहन से ही काम चल जायेगा। मान्यवर, सरकार ने यह बयान दिया है कि सरकार के समक्ष इस तरह की कोई नीति विचाराधीन है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास अगर सूचना हो कि वर्ष 2010 से पहले थानों में कितने घटिया वाहन चल रहे हैं, तो कृपया उसे बता दें। दूसरी मेरी बात यह है कि यू0पी0 में बहुत अधिक गति से अपराध बढ़ रहे हैं। दिल्ली से लगे हुए जितने भी नेशनल हाई–वे है, चाहे वह अलीगढ़ एन0एच0 हो, चाहे यमुना एक्सप्रेस–वे हो यहां बहुत अपराध हो रहे हैं, ए0के0–47 एवं ए0के0–56 से अपराध हो रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस के पास अच्छे वाहन नहीं है, यहां से वहां तक चलने के वाहन नहीं है, जो एन0सी0आर0 से लगे हुये थाना क्षेत्र हैं, चाहे यह बुलन्दशहर के हो, चाहे गाजियाबाद के हों, चाहें अलीगढ़ के हो, चाहे मथुरा के हों, फास्ट गति से चलने वाले वाहनों का पीछा करने वाले वाहन हमारी पुलिस के पास नहीं हैं। मैं जानकारी चाहता हूं कि इस तरीके से फास्ट गति से चलने वाले अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था करने पर क्या सरकार विचार कर रही है? इसके अतिरिक्त जो ज्यादा आबादी के कोतवाली हैं, क्या वहां पर सरकार अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ? मैं उदाहरण स्वरूप फिर कहना चाहता हूं कि जैसे इगलास कोतवाली 400 ग्रामों की कोतवाली है। यहां पर एक खटारा जीप लेकर वहां का इन्सेपक्टर घूमता है,

वह कैसे अपराध नियंत्रित कर पायेगा ? तो मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्या सरकार के पास ऐसी नीति निर्धारण करने की कोई योजना है कि जो ज्यादा आबादी के बड़े थाने हैं, उन पर वाहनों की अतिरिक्त व्यवस्था करायेगी?

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी नीति है, उसके अन्तर्गत चार पहिया वाहन एक थाने में और दो पहिया वाहन एक थाने में दिये जाते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि वह वाहन कितने किलोमीटर चल गया है अथवा यह कितने साल पुरानी गाड़ी है, उसके एतबार से यह बदली जाती है। जो नई हालत है, वह यह है कि प्रदेश में कुल 1525 थाने हैं और 553 थानों में चरणबद्ध तरीके से दोपहिया वाहन उपलब्ध करा दिये गये हैं, चार पहिया वाहन उपलब्ध करा दिये गये हैं और 164 थानों में दोपहिया वाहन उपलब्ध करा दिये गये हैं। प्रदेश बहुत बड़ा है और ज्यादा वाहनों की डिमाण्ड भी की गई है और गाड़ियों का इंतजाम हो रहा है। मान्यवर, यह अंदाजा हुआ होगा कि पिछली सरकार में जो हालत पुरानी गाड़ियों की थी, अब उतनी पुरानी गाड़ियां नहीं है और गाड़ियों की तादाद भी बढ़ी है। जहां–जहां कमी है वहां कमी को पूरा किया जा रहा है और आप जहां की बात कर रहे हैं इसे विशेष रूप से देखकर अगर वहां पुरानी गाड़ी है और वहॉ नई नहीं आई है, तो इसे जल्दी ही बदलवाने की व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल किसी एक जनपद की समस्या की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं प्रदेश व्यापी समस्या बता रहा हूं। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और आपके संज्ञान में भी है कि जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मथुरा यह बिल्कुल ऐसे मुहाने पर स्थापित हैं जो एन0सी0आर0 से बिल्कुल लगे हुये हैं और यहां पर बहुत फास्ट गति से अपराध, हत्या, लूट और डकैती की घटनायें हो रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह अपराध करने वाले केवल हमारे ही प्रदेश के लोग हैं वह दिल्ली के भी हैं, वह हरियाणा के भी हैं। वहां से इस तरह से अपराध हो रहे हैं, उनके लिये मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से इन जनपदों के लिये वाहन की व्यवस्था आप करायें, आपसे पहले किसी सरकार ने शायद कराई होगी कि इस तरह के वाहन सड़कों पर दिये गये थे। मैं चाहता हूं कि इसमें आप नीति निर्धारित करने के लिये कोई आश्वासन दे दें, तो प्रदेश हित में बहुत अच्छा रहेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जिज्ञासा बिल्कुल सही है लेकिन अपराध रोकने के लिये सिर्फ वाहन की जरूरत ही नहीं होती, बहुत सी चीजों की होती है। वाहन भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन स्थिति पहले से बहुत बेहतर है इसको और बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी और जहां–जहां के लिये आपने इंगित किया है, उसके लिये खास व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज जो अपराधी हैं, उनके पास इतने हाईटेक वाहन होते हैं, कि उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा नहीं कर पाती हैं। आपकी पुलिस की गाड़ियां 80 किमी0 की रफ्तार से चलती हैं जबकि अपराधियों की गाड़ियां 120–140 किमी0 की रफ्तार से चलती हैं। तो क्या हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस उन हाईटेक गाड़ियों को खरीदेगी जो अपराधियों की हाईटेक गाड़ियों का पीछा कर सके।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वहां पर पुलिस के पास हाईटेक गाड़ियां ही हैं। गाजियाबाद है, बल्कि मुरादाबाद तक की पट्टी तक इनोवा गाड़ियां हैं, जिप्सीज हैं। आपको जानकारी नहीं है क्योंकि आप या तो बाई रोड चलते नहीं हैं। हम तो बहुत चलते हैं इसलिये हमें मालूम हैं। यह सही है कि पहले वाहन बहुत खराब थे हमारी गाड़ियां आगे निकल जाती थीं और थानेदार साहब पीछे लौट जाया करते थे, लेकिन अब उनकी गाड़ियां साथ चलती हैं। देखिये दिल्ली की सरकार अब चली गयी है, अब सड़क पर भी चला कीजिये।

प्रदेश में नगर निगमों, नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डों में दूषित पेयजल के स्थान पर शुद्ध पेयजल का नियमित ओ0टी0 टेस्ट कराकर उपलब्ध कराये जाने की मांग

'03–श्री मनीष असीजा, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री नदीम जावेद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डों में दूषित पेयजल सप्लाई के कारण अनेक बार डायरिया एवं अन्य संक्रामक रोग फैलने के मामले संज्ञान में आते रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनीकृत जलापूर्ति कराने एवं नियमित ओ0टी0 टेस्ट कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में कुल 635 नगर स्थानीय निकाय हैं जिनकी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 4.45 करोड़ है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.96 करोड़ का लगभग 22 प्रतिशत है। 635 नगरीय निकायों में से 14 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषद् में पाइप पेयजल आपूर्ति की जा रही है जबकि 427 नगरीय पंचायत के सापेक्ष 420 नगरीय पंचायतों में पाइप पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्त नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डों में पेयजल से सम्बन्धित समस्त कार्यों का रख–रखाव सम्बन्धित नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डों द्वारा ही किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि आपका नगर विकास विभाग में अनुभव और आपकी संवेदनशीलता हम सबको मालूम है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इतना अधिक कंट्राडिक्टरी है, इसकी अपेक्षा मुझे नहीं थी। मेरे प्रश्न में यह साफ पूछा गया है कि छावनी बोर्डो में दूषित पेयजल सप्लाई के कारण अनेक बार डायरिया एवं अन्य संक्रामक रोग फैलने के मामले संज्ञान में आते रहे हैं, यहीं से मेरे प्रश्न की मूल भावना यह थी कि मैं आपके माध्यम से यह जानकारी भी ले सकूं और आपको तथा सदन को यह अवगत भी करा सकूं कि साफ पीने का पानी स्वस्थ जीवन के लिये कितना आवश्यक है। जहॉ हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री मनीष असीजा–

महोदय इस प्रश्न के लिये मुझे आपको थोड़ा सा समय देना होगा। जहां अनेक प्रकार की योजनायें चल रही हैं मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिये अरबों–खरबों रुपया खर्च हो रहा है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लू0 एच0 ओ0 की रिपोर्ट है कि दुनिया की लगभग 37 ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा साबित होती हैं और उसमें से 21 बीमारियां दूषित पानी से पैदा होती हैं। इसका सबसे पहला शिकार छोटे बच्चे और कमजोर मातायें होती हैं तो यह इस प्रश्न की मूल भावना थी, जिसको उत्तर में बिल्कुल स्थान नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि अब के दौर में साफ पीने का पानी यह मूलभूत नागरिक अधिकार होना चाहिए और सरकार से यह मैं अपेक्षा भी करता हूं कि एक समग्र स्वच्छ पेयजल नीति का आप निर्माण करें, इसमें आवश्यक बजटीय प्रावधान करें, इसको इम्प्लाइड करें तब तो मान्यवर काम चलेगा नहीं तो दो साल पहले जब सदन में यह क्वैश्चन आया था।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल करेंगे या सुझाव देंगे, आप सवाल तो कीजिए।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, दो साल पहले जब यह क्वेश्चन आया था तब भी इसका यही उत्तर था। अगर हम अपने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल नहीं दे सकते तो आप समझिये कि हम कौन सी चीज का न्याय करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछिये।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, संविधान का जो अनुच्छेद–21 है जीवन जीने का अधिकार। सीधे–सीधे अगर हम उसको साफ पानी नहीं देते हैं तो संविधान के अनुच्छेद का भी उल्लंघन है। मैं आपके माध्यम से दो सीधे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आप प्रदेश में स्वच्छ जलनीति बनाकर उसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान करके जमीनी स्तर पर नागरिकों को

साफ पीने का पानी देने का अधिकार बनाने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब तक यह काम नहीं होगा, मान लीजिए पीछे से काम नहीं होगा तब तक विशेष निकाय में चाहे वह ओवर हेड टैंक हो, चाहे सी0डब्लू0आर0 हो, चाहे टी0टी0एस0पी0 हो और चाहे ट्यूबवेल से सीधे सप्लाई हो, उनको क्लोरीकरण करने के लिए जो इलेक्ट्रानिक डोजर है उनको अनिवार्य रूप से स्थापित करने का जी0ओ0 जारी करके मासिक समीक्षा में सघन समीक्षा करने का कार्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप दो प्रश्नों का उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री मनीष असीजा–

धन्यवाद मा0 अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न की गम्भीरता को आपने समझ लिया आपको बहुत–बहुत धन्यवाद्।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने कोशिश बताई कि कितना काम इसमें हो रहा है और हमारे जो अपने रोजमर्रा के तजुर्बे हैं उनसे यह जानते हैं कि पानी की खराबी की वजह से कितनी बीमारियॉ फैलती थीं अब शायद ऐसा सुनने को नहीं मिलता है, प्लेग है, हैजा है इस तरह की महामारी नहीं आतीं और वैसे भी आम तौर पर पानी की खराबी की शिकायत सिर्फ एक मिलती है और उसको भी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जहॉ से पाइपलाइन किसी ऐसे इलाके से गुजर रही है जहां कोई नाला है, कोई गन्दगी की जगह है और वह गल गई है और उसने गन्दा पानी ले लिया है, उसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाता है। इसके अलावा जमीन से निकलने वाले पानी में या देने वाले पानी में पहले सारी टेस्टिंग करा ली जाती है उसी के बाद वहॉ से पानी निकालकर सप्लाई दी जाती है। जहां तक क्लोरीन देने का सवाल है, यह बड़ा काम है इस ओर से विचार हो रहा है कि सब पर ऑटोमैटिक यन्त्र लगाये जाएं लेकिन बहुत सी जगहों पर लगाये गये हैं और वह काम कर रहे हैं। हर 15 दिन में क्लोरीन दी जाती है, इसके अलावा टेस्टिंग बराबर जारी रहती है अगर टेस्टिंग का सिलसिला जारी नहीं रहेगा तो ओवरहैड टैंक से बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी अभी तक कोई भी सूचना सदन को नहीं मिली होगी, सदन में बैठे हुए सदस्यों को नहीं मिली होगी कि ओवर हेड टैंक से मिलने वाले पानी से कहीं कोई बीमारी हुई है या किसी तरह की कोई मौत हुई है तो मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों का संज्ञान लिया जायेगा और इस तरह की कोई परेशानी नहीं है न ही इस तरह की कोई बीमारी इस पानी से फैली है और न ही किसी बीमारी के फैलने का अंदेशा है। पानी बहुत स्वच्छ मिल रहा है, बहुत अच्छा पानी मिल रहा है, आगे भी अच्छा मिलेगा और इससे अच्छा मिलेगा।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पानी कितना स्वच्छ मिल रहा है इसके बारे में अगर आप रिपोर्ट करें तो हर घर में तो आर0ओ0 लग गया है जो सक्षम

व्यक्ति है। बाजार में अगर आप देखें तो पानी की 20 लीटर की कंटेनर ली जा रही है, बोतल बंद पानी की बिक्री कितनी बढ़ गई है। मान्यवर, ऐसा नहीं है, सबसे धरातल की स्थिति यह है कि गरीब आदमी तो मजबूर है खराब पानी पीने के लिए। हर सक्षम व्यक्ति ने या तो आर0ओ0 लगा लिया है या फिर वह बाजार से पानी खरीदकर पीता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी लेकिन मान्यवर इलेक्ट्रॉनिक डोजर का जो मामला है यह ज्यादा मंहगा नहीं है, अगर साफ–सुथरे तरीके से खरीददारी की जाए तो अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रॉनिक डोजर 10–12 हजार रुपए का आ जायेगा। गड़बड़ में वह 20–25 हजार रुपये का आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

सुझाव न दीजिए, सवाल पूछिये।

श्री मनीष असीजा–

सवाल मेरा फिर वहीं आकर टिकता है, जब माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि पानी साफ आ रहा है तो मैं यह कहता हूं कि कई जगह साफ आ रहा होगा लेकिन पूरे प्रदेश में आप यह सर्वेक्षण करा लें, नगर पालिका, नगर निगमों से कोई पानी पीने को तैयार नहीं है, आये दिन डायरिया की समस्यायें आती हैं। मैं आपसे फिर यह अनुरोध करता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक डोजर मात्र 10–12 हजार रुपये का आता है जब तक स्वच्छ जल नीति नहीं बनती, आप इसको अनिवार्य करने का जी0ओ0 जारी कर दें, मात्र 10–12 हजार रुपये का एक इलेक्ट्रॉनिक डोजर है जो टंकी, सी0डब्लू0आर0 और ट्यूबवेल की लागत में बहुत सस्ता है, यह अगर अनिवार्य कर देंगे तो काफी कण्ट्रोल होगा। यह मैं आपसे दोबारा अपेक्षा करता हूं कि क्या आप यह करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, क्या आप इनके सुझाव को मानेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अब लोगों ने वाटर फ्यूरीफायर्स लगा रखे हैं, बाजार से खरीदकर भी पीते हैं उस पर तो कोई प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता। लेकिन जितने मार्क–टू नल लगे हुए हैं उनके बारे में मेरा अपना मानना यह है कि कहीं–कहीं वह ओवर–हेड टैंक से भी बढ़िया पानी देते हैं मिसाल के तौर पर अगर मैं जौहर यूनिवर्सिटी की बात करूं, आप कभी तशरीफ लायें हमारे यहां मार्क–टू नल का इतना अच्छा पानी है कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में जो फ्यूरीफायर्स लगे हुए थे, वह हटा दिये गये हैं। हमने पानी की टेस्टिंग करायी, इतना अच्छा पानी था कि जो मशीन से पानी आता है उसमें सारे मिनरल्स और साल्ट खत्म हो जाते हैं और पानी की जगह पत्थर शरीर में जाता है और शरीर के अन्दर बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वह खत्म होती है। पूरी दुनिया में इस बात पर विचार हो रहा है कि इन मशीनों से फायदे के बजाए नुकसान पहुंच रहा है। जो कुदरती पानी है वह इंसानी जिस्म के लिए फायदेमंद है और जरूरी है जैसे आपने एक यंत्र लगाने की बात कही है, बहुत से यंत्र लगे हैं देश में, पानी के मीटर्स लगे, बिजली

के मीटर्स लगे फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स आये रिलायन्स वालों ने भी मीटर्स लगाये मगर रिलायन्स के मीटरों पर भी चूना लगने लगा तो मीटर हटाकर अब दूसरे तरीके इख्तियार किये हैं। तो मीटरिंग सिस्टम से तो मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं होता हूं यह करप्शन का एक नया दरवाजा खुल जाता है।

श्री मनीष असीजा–

इलेक्ट्रॉनिक डोजर ऐसा होता है जिसमें क्लोरीन मिलती है पानी में।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जितने नये ओवर–हैड टैंक बनाये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डोजर उनमें ऑलरेडी लग रहा है, लेकिन सदन को बिल्कुल सही जानकारी देंगे कि जब वह खराब हो जाता है तो उसकी इत्तिला तब मिलती है जब लोग इसकी शिकायत करते हैं। वह भी कोई कामयाब सिस्टम नहीं है। कामयाब वही है कि पाबंदी से पानी की जांच होती रहे, जो टेस्ट–ट्यूब से जॉच होती है, वह होती रहे, वह सबसे बेहतर तरीका है और ये मशीनी तरीके बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहे हैं लेकिन हम लगा रहे हैं। जितना ज्यादा सम्भव हो सकता है उसे लगा रहे हैं लेकिन बहुत कामयाब नहीं है। कैसी कम्पनी है, कैसा सप्लाई हो गया, आप तो खुद ही कह रहे थे कि 10–12 हजार रूपये का आता है और बहुत बढ़कर मिले तो 20–25 हजार का आता है, जहां यह हालात हों उसमें कैसे होंगे, उस पर अभी कोई बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। तर्जुबा कर रहे हैं, देखते हैं जो बेहतर से बेहतर होगा वह करेंगे।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की अनुरक्षण नीति सुनिश्चित कराने विषयक

'04–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों के अनुरक्षण की क्या नीति है ? क्या सरकार प्रदेश में उक्त विभाग (आर0ई0डी0) द्वारा निर्मित सड़कों का अनुरक्षण सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित ''उ0 प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति–2013'' के अनुसार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विभागों/संस्थाओं के बजट से निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गों पर पंचायती राज विभाग का स्वामित्व मानते हुए उक्त मार्ग का अनुरक्षण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्राप्त धनराशि से डिपाजिट कार्य के रूप में किये जाने की नीति है।

उ0 प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013 के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30–12–2014 को सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ''पंचायती राज विभाग प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से

कराये जाने के निमित्त, प्रदेश के स्थानीय निकाय संस्थाओं/जिला पंचायतों को अपने स्तर से 'एडवाइजरी' निर्गत करते हुए मान0 मंत्रि–परिषद् के अनुमोदन से प्रख्यापित उ0 प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013 के माध्यम से स्थापित व्यवस्था का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करायें'' इस प्रकार धनराशि होने के उपरान्त अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि सरकार भी इसकी आवश्यकता को समझती है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा जो मार्ग बनाए जाते हैं उनके अनुरक्षण की आवश्यकता है। आप उत्तर का पहला पार्ट देख लें कि 2013 में जो अनुरक्षण नीति बनी थी दिसम्बर 2014 तक उसके अनुपालन की स्थिति नहीं आ पाई। दिसम्बर 2014 में यह निश्चित किया गया कि जिला पंचायतों के द्वारा उसमें डिपाजिट वर्क के माध्यम से उसमें पैसा लेकर उसका अनुरक्षण कराया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसमें स्थायी नीति बने ताकि जिस प्रकार पी0डब्लू0डी0 की सड़कों का अनुरक्षण होता है उसी प्रकार से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं उसका भी अनुरक्षण रेगुलर स्थायी रूप से होता रहे। यह इस प्रश्न का उद्देश्य है लेकिन उत्तर में एक साल के बाद तो वह नीति बनी अभी भी उसमें यह नहीं हो पाया है कि उसमें पैसा कहां से आएगा। क्या उसमें अलग से बजट प्राविधान किया जाएगा क्योंकि जिला पंचायतों की इतनी आमदनी नहीं है कि वह अपनी आय से इसका अनुरक्षण ठीक प्रकार से कर लें। मैं आपके माध्यम से दो सवाल पूछना चाहता हूं नम्बर एक कि जिस प्रकार से पी0एम0जी0एस0वाई में सड़क निर्माण एजेंसी से ही पांच साल तक उसके मेंटीनेंस करने का प्राविधान है अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनती है तो पांच साल तक वहीं एजेंसी उसका अनुरक्षण करेगी। क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था को लाने पर विचार करेंगे दूसरे मान्यवर, धन की व्यवस्था कहां, कब और कैसे होगी यह दो सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर नीतिगत तौर पर तो यह तय किया गया था कि आर0ई0एस0 इसका मेंटीनेंस करेगा लेकिन दोनों विभागों के बीच अभी तक कोई समन्वय नहीं बन पाया है और नीति पर जितनी प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पायी 8,832 कि0मी0 सड़कों का स्वामित्व पंचायती राज को सौंप दिया गया है। इसके अलावा 132 करोड़ रुपए की आर0ई0एस0 विभाग ने डिमाण्ड की है बहराल यह अण्डर कंसीडरेशन है इस पर विचार हो रहा है लेकिन सच बात यह है कि यह अभी पूरी तरह से तय नहीं हो सका है कि इसका कैसे रख–रखाव किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के पास इंजीनियर्स की कमी है वह यहां काफी है किन्हीं कारणों से वह नहीं चाहते कि उनकी सड़कों का मेंटीनेंस उनके अलावा कोई और करे इस पर थोड़ी सी बात चल रही है विचार–विमर्श के बाद इस पर कोई जल्द निर्णय निकलेगा।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

माननीय अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि आपके विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क आर0ई0एस0 बना रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की दो सड़कें डुमरियागंज में बन रही हैं अभी वह शुरू ही नहीं हुईं कि उनके प्लास्टर वगैरह उखड़ने लगे। क्या माननीय मंत्री जी उन तीनों सड़कों को सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज तहसील में इटवा क्षेत्र में जो माननीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र में बन रही हैं क्या उनको दिखवाकर उनको ठीक कराने का निर्देश देंगे ताकि सही नार्म के अनुसार वह बनें।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई सवाल नहीं है।

श्री दलबीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आर0ई0एस0 विभाग का अपना कोई व्यक्तिगत बजट नहीं है यह कार्यदायी संस्था है कार्यदायी संस्था होने के नाते जो भी इनको पैसा दे देता है वहां यह सड़क बनाते हैं मेंटीनेंस की अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है तो बजट का भी प्राविधान होना चाहिए। जितनी भी सड़कें पी0एम0जी0एस0वाई0 की हैं आर0ई0एस0 के द्वारा बनी हुई पूरे प्रदेश में उनका बहुत खस्ताहाल है पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़कों का यह हाल है कि ठेकेदारों ने पहला पेमेंट लेने के बाद कह दिया कि हमारी तो इसी में पूर्ति हो गई इसी में हमें लाभ हो गया हमें आगे मरम्मत करनी ही नहीं है। अब आगे तो हमें मरम्मत करनी नहीं है जो अनुबंध में लिखित है। पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़कों की जो हालत है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पूरी सड़कों को लोक निर्माण विभाग को दे दिया जाना चाहिए। पी0एम0जी0एस0वाई0 कोई काम नहीं कर रही है, आर0ई0एस0 विभाग के पास मरम्मत का कोई फंड नहीं है। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं हमारी विमला जी। पंचायत विभाग में खूब पैसा है। अगर उनको बाध्य कर दिया जाय कि जिला पंचायत में आया हुआ बजट का प्रयोग केवल आर0ई0एस0 द्वारा बनाई सड़कों पर किया जायेगा तो बहुत कुछ काम किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार अपना रुख तय करे, नीति बनाये। जब तक नीति नहीं बनेगी तब तक सड़कों का रख–रखाव नहीं हो सकता।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, इधर तो जब से नई राजनैतिक व्यवस्था बदली है तब से कोई धन नहीं आया और यह सही है कि क्वालिटी चेक भारत सरकार की तरफ से भी कराया जाता रहा है और उस पर कार्यवाहियां होती रही हैं। जहां–जहां कमियां हैं उस पर और गौर किया जायेगा। यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरह हमारे यहां सी0 एण्ड डी0एस0 है उसी तरह आर0ई0एस0 भी एक कार्यदायी संस्था के रूप में है। इनका अपना कोई बजट नहीं है। मैंने इसीलिये आपसे अर्ज किया कि 132 करोड़ रुपये की

मांग की गई है। यह पैसा अगर मिल जाता है तो आपकी बात को साकार किया जा सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर जिस ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी उसको पांच साल मेन्टीनेंस करना होगा तो जिस समय वह सड़क बनायेगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से सीधा सीधा यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने पर विचार करेंगे कि सड़क निर्माण जो एजेन्सी करे वही पांच वर्ष तक उसको मेन्टीनेंस करे ? क्या इस प्रकार की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ? उससे सड़क की क्वालिटी भी ठीक होगी और पांच वर्ष तक उसके मेन्टीनेंस की जिम्मेदारी भी मान्यवर किसी और की नहीं होगी। इसीलिये मान्यवर हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर यह हो जायेगा तो मान्यवर बहुत बड़ा सिर दर्द दूर हो जायेगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर चूंकि पैसा भारत सरकार से आता है लिहाजा शर्तें भी वहीं से आनी चाहिए। जो शर्ते आयेंगी हम उन्हें लागू करा देंगे।

'5–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त,

प्रदेश में बिगड़ती कानून–व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार की नीति

'06–श्री सतीश महाना, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बिगड़ती कानून–व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्तमान में उ0 प्र0 की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है फिर भी प्रदेश सरकार द्वारा कानून–व्यवस्था की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :–

1–आपसी विवाद एवं रंजिश के मामले को समय से निपटाया जा रहा है, जिससे उन्हें बड़ी घटना में बदलने से रोका जाय।

2–साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की जा रही हैं :–

(1) पुलिस का आम जनता के प्रति मित्र छवि उपस्थित करना।

(2) कम्यूनिटी पुलिसिंग के जरिये जनता की कठिनाइयों को दूर किया जाना।

(3) महिला उत्पीड़न/छात्राओं के साथ छेड़–छाड़ की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश हेतु महिला हेल्पलाइन 1090 चालू किया जाना।

(4) समाधान दिवस पर जनता की शिकायतों को गुण–दोष के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाना।

(5) समय–समय पर विभिन्न कार्यशालायें आयोजित कर पुलिसजनों को सद्व्यवहार प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाना।

(6) भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिये जनपदों में बनी हुई दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास करते रहना।

3–साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

4–जातिगत एवं धार्मिक तनाव उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पक्षता से कार्यवाही की जा रही है।

5–माफिया, गुण्डों, अपराधियों के विरुद्ध कड़ी और प्रभावी कार्यवाही तत्परता से की जा रही है।

6–महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

7–सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्रों के खुले प्रदर्शन व हर्ष फायरिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

8–थानों पर सभी अभियोगों का पंजीकरण कराकर विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा सी0सी0टी0एन0एस0 के माध्यम से इस कार्य को और अधिक प्रभावी कर दिया गया है।

9–जनता की शिकायतों पर तत्काल सुनवायी कर उसके निस्तारण के लिये व्यवस्था की जा रही है।

10–आधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित कर घटना पर त्वरित कार्यवाही के प्रथम चरण में क्रमशः जनपद लखनऊ/गाजियाबाद/कानपुर/इलाहाबाद में प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपदों में भी स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

11–कानून–व्यवस्था को और सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में एक साथ विशेष अभियान चलाकर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।

12–सम्बन्धित अधिकारियों के निर्देशित किया गया है कि बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता से कानून का शासन स्थापित किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 16–05–2012 का सभी जनपदीय पुलिस अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–6 पर सतीश महाना जी का नाम पुकारने पर माननीय मंत्री श्री मोहम्मद आज़म खां द्वारा उत्तर पढ़ने पर)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा भी नाम था आपने लिया नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आपका नाम है उसमें। अब यह खड़े हो गये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर मेरा नाम भी था।

श्री अध्यक्ष–

तीन लोगों का नाम है उसमें हमने सबका नाम नहीं पढ़ा। आपका नाम है, पहाड़िया जी का भी नाम है। अब उत्तर आ जाने दीजिये ना।

प्रदेश में पूर्ण रूप से गन्दे पानी को रोककर गंगा के पानी के शोधन की कार्य योजना की जानकारी

'07–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री नीरज कुशवाहा (मौर्य)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गंगा के अपने 1000 कि0मी0 की यात्रा में कितनी शहरों तथा सहायक नदियों से कितने मिलियन लीटर गन्दगी प्रतिदिन गंगा में गिरती है एवं इसमें से कितना मिलियन लीटर जल के शोधन की व्यवस्था है ? क्या गन्दे पानी को गंगा में गिरने से पूर्णतः रोकने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में गंगा नदी व इसकी सहायक नदियों–काली, रामगंगा व यमुना नदी के किनारे बसे 48 प्रमुख नगरों से वर्तमान में 3451.32 मिलियन लीटर प्रतिदिन घरेलू सीवरेज का उत्पादन होता है। जिसके सापेक्ष 1603.55 मिनियन लीटर प्रतिदिन के सीवरेज शोधन की व्यवस्था उपलब्ध है।

जी हां।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत घरेलू सीवरेज को गंगा नदी में गिरने से रोकने हेतु वर्ष 2020 तक परियोजनायें विरचित कर निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 14 परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं। जिनकी कुल लागत रु0 2256.01 करोड़ है। इसके अतिरिक्त 06 परियोजनायें, जिनकी अनुमानित लागत रु0 1228.30 करोड़ है, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

(मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश में प्रतिदिन भारी मात्रा में निकलने वाले प्लास्टिक कचरे से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरे को रोकने के उपाय

'08–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिदिन भारी मात्रा में निकलने वाले प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण तथा मानव जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्यावरण तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों को देखते हुए प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्लास्टिक के विनिर्माण, उपयोग व निस्तारण हेतु भारत सरकार द्वारा ''प्लास्टिक वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स 2011'' अधिसूचित किया गया है, तद्नुसार नियंत्रण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इस सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जारी किये जा चुके हैं। प्लास्टिक के विनिर्माण एवं उपयोग तथा निस्तारण हेतु शतत् प्रयास किये जा रहे हैं। घर–घर से कूड़ा, जिसमें प्लास्टिक अंश भी सम्मिलित है, को एकत्र किये जाने तथा उनके ''नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000'' के अनुसार वैज्ञानिक विधि से निस्तारण के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न नगरों में चरणबद्ध रूप से योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 26 नगरों की सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनमें सें 11 नगरों की परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में 177 नागर निकायों में चरणबद्ध रूप से 5 वर्षों में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं का क्रियान्वयन लक्षित है। इन 170 नगरों में से 03 कलस्टरों की रु0 58.30 करोड़ की लागत की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अन्तर्गत नागर निकायों में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताएं शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

'09–डा0 अरुण कुमार–

ख्ले शुक्रवार के तारा0प्र0सं0–11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना

'10–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त पुलिस बल नहीं है तथा थानों की भी कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्याप्त सुरक्षा देने हेतु पुलिस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासनादेश संख्या–4147/6–पु7–1–08–120/2008, दिनांक 11–12–2008 द्वारा थानों के नये मानकीकरण के अनुरूप जनशक्ति की आवश्यकता के दृष्टिगत निरीक्षक नागरिक पुलिस–1017, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस–7115, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस–40824, आरक्षी नागरिक पुलिस–1,51,726, कन्सोल आपरेटर के 3152 एवं चतुर्थ श्रेणी के 118 सहित कुल 2,03,864 पद सृजित किये गये हैं।

जनसंख्या के मानक के अनुरूप सृजित पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में आरक्षी नागरिक पुलिस के 35844 पदों पर वर्ष 2010 में भर्ती पूर्ण कर प्रशिक्षणोपरान्त जनपदों में तैनात किया जा चुका है। द्वितीय चरण में 35500 आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती की कार्यवाही अन्तिम चरण में है जिसके पूर्ण होने पर उन्हें प्रशिक्षणोपरान्त तैनात किया जायेगा। शेष रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जायेगी। सेवा में रिक्तियां एवं उनको भरे जाने की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में आतंकी हमले की सम्भावना से निपटने हेतु दिये गये सरकार के निर्देशों का संस्थानों द्वारा पालन किया जाना

'11–श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में आतंकी हमले की सम्भावना से निपटने के कोई दिशा–निर्देश संस्थानों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? क्या इनका अनुपालन संस्थानों द्वारा पूरी तरह किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में घटित होने वाली आतंकवादी घटनाओं के दृष्टिगत विशेष सतर्कता एवं सजगता बरतने हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निम्नवत् निर्देश दिये गये :–

1–जनपद के सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रबन्धकों के साथ जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक बैठक आयोजित कर उनको संवेदित करते हुए संस्थानों की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था हेतु 'सिक्योरिटी आडिट' सम्पादित करायें।

2–शैक्षणिक संस्थानों के प्रबन्धकों को अपने संसाधनों से संस्थान के परिसर की पेरीमीटर सिक्यूरिटी इन्ट्री प्वाइंट पर प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की तैनाती तथा सभी महत्वपूर्ण संस्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने के बारे में परामर्श दिया जाये।

3–कई निजी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा छात्र/छात्राओं को प्राइवेट ट्रान्सपोर्ट (कालेज/स्कूल बसें) के माध्यम से ले जाया जाता है। इन वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबन्धकों से वार्ता की जाय तथा वाहन सहित वाहनों के चालक/क्लीनर एवं सहयोगी अन्य स्टाफ का पुलिस वेरीफिकेशन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु संस्थान के प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाये।

4–उपरोक्त के अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने उपलब्ध संसाधनों से सभी शैक्षणिक संस्थानों के आस–पास सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के यथोचित प्रबन्ध जैसे–पिकेट व्यवस्था, पेट्रोलिंग गश्त को बढ़ाने तथा समय–समय पर आकस्मिक रूप से संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की तलाशी का अभियान भी चलाने के निर्देश दिये गये हैं।

अर्न्तराष्ट्रीय परिदृष्य में घटित होने वाली आतंकवादी घटनाओं के दृष्टिगत अराजक तत्वों के मंसूबों को समय रहते असफल करने हेतु नियमित रूप से असूचना का संकलन, स्थानीय अभिसूचना इकाइयों, जन सामान्य एवं अन्य श्रोतों से किये जाने तथा प्राप्त होने वाली सूचनाओं का मूल्यांकन करते हुए यथा आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही के भी निर्देश दिये गये हैं। अनुपालन किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में मलिन बस्तियों में निर्वासित गरीबों के पुनर्वासन

विषयक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा संगम क्षेत्र मलिन बस्ती संघ बनाम रक्षा विभाग भारत सरकार, उ0 प्र0 राज्य सरकार आदि की याचिका

सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में मलिन बस्तियों में निर्वासित गरीबों के पुनर्वासन विषयक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा संगम क्षेत्र मलिन बस्ती संघ बनाम रक्षा विभाग भारत सरकार, उ0 प्र0 राज्य सरकार आदि याचिका संख्या–15530/2000 में दिये

गये निर्णय के अनुपालनार्थ, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 25–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अभी तक की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

संगम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थिति मलिन बस्तियों–कीडगंज, धरकार बस्ती (निकट मिण्टो पार्क) के निवासियों को बेसिक सर्विसेज फार अर्बन पुअर (बी0एस0यू0पी0) योजना के अन्तर्गत उत्तरी लोकपुरी नैनी में निर्माणाधीन 233 आवासों में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। राजीव आवास योजना एवं राज्य सरकार की ''आसरा'' निःशुल्क आवासीय योजना के अन्तर्गत नगर निगम सीमा में भूमि की उपलब्धता न होने के कारण रिलोकेशन की परियोजनाएं प्रारम्भ नहीं हो पायी हैं। जिला नगरीय विकास अभिकरण, इलाहाबाद द्वारा इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रेषित है। राजीव आवास योजना की गाइड लाइन के अनुसार केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार उपक्रमों/रक्षा मंत्रालय/रेलवे इत्यादि की भूमि पर स्थित स्लम के निवासियों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराने का प्रत्यक्ष अधिकार उक्त संस्थाओं को दिया गया है जिसके अनुसार डी0पी0आर0 सीधे केन्द्र सरकार को सम्बन्धित मंत्रालय को सन्दर्भित किया जाना प्राविधानित है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 14–08–2014 द्वारा रक्षा सम्पदा अधिकारी, छावनी परिषद्, इलाहाबाद से पत्राचार कर अनुरोध भी किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राजीव आवास एवं आसरा योजनान्तर्गत मलिन बस्तियों में निवासरत पात्र परिवारों हेतु स्वयं की भूमि पर इन–सीटू परियोजनाओं द्वारा भी आवास निर्मित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश शासन ने नगर क्षेत्र के निवासियों से यूजर्स चार्ज लेने हेतु उ0 प्र0 नगर निगम (प्रयोक्ता प्रभार का उद्ग्रहण तथा उसकी प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन का विनियमन) नियमावली, 2014 जारी हो जाने के फलस्वरूप गुणवत्ता बनाये रखने सम्बन्धी प्राविधान को बनाये रखना

02–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश शासन ने नगर क्षेत्र के निवासियों से यूजर्स चार्ज लेने हेतु उ0 प्र0 नगर निगम (प्रयोक्ता प्रभार का उद्ग्रहण तथा उसकी प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन का विनियमन) नियमावली, 2014 जारी की गयी है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत यूजर्स चार्जेज लेने के साथ ही साथ उसके लिये दी जाने वाली सेवाओं/सुविधाओं को भी निरन्तर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने सम्बन्धी प्राविधान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

उ0 प्र0 नगर निगम (प्रयोक्ता प्रभार का उद्ग्रहण तथा उसकी प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन का विनियमन) नियमावली, 2014 के नियम–3 में प्रयोक्ता प्रभार के उद्ग्रहण का तर्काधार निम्न प्रकार है :–

(क) दक्ष सेवायें प्रदान करना और सेवाओं को बनाये रखने के लिये उनकी लागत की प्रभावी वसूली सुनिश्चित कराना।

(ख) सेवाओं के उपयोग में मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना और अपव्यय का परिवर्जन करना।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के कैन्ट विधान सभा के रानीपुर व सरायसुर्जन वार्ड में पेयजल की सुविधा प्रदान करने तथा शिवपुरवा में पाइप लाइन बिछी होने के बावजूद पानी न आने के बाद भी टैक्स का वसूला जाना

03–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के कैन्ट विधान सभा के रानीपुर व सरायसुर्जन वार्ड की सीमा पर एक बड़े भू–भाग पर पेयजल पाइप लाइन नहीं बिछी है एवं शिवपुरवा के शिवपुरम् में पाइप लाइन बिछी भी है तो भी पानी नहीं आता है लेकिन टैक्स की वसूली होती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वाराणसी कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के रानीपुर व सरायसुर्जन तथा शिवपुरवा के शिवपुरम् में पेयजल आपूर्ति महाप्रबन्धक जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी द्वारा गंगा नदी के जल का आवश्यक ट्रीटमेन्ट करने के उपरान्त करायी जा रही है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल पुनर्गठन योजनाओं में गंगा नदी से सिस–वरुणा क्षेत्र में 125 एम0एल0डी0 अतिरिक्त पानी लेकर आवश्यक ट्रीटमेन्ट के उपरान्त शीघ्र ही जनता को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। वर्तमान में कुल नई वितरण प्रणाली 458.411 कि0मी0 के सापेक्ष 139.709 कि0मी0 पाइप लाइन जनोपयोगी की जा चुकी है। शेष पाइप लाइन की टेस्टिंग कर जनोपयोगी किये जाने का कार्य प्रगति पर है। टूटी क्षतिग्रस्त लाइन को ठीक करने एवं पेयजल पाइप लाइनों की मरम्मत कराने का कार्य भी जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी द्वारा कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में बालू बदरपुर के वाहनों के स्टैण्ड के लिये नियत स्थान पर ठेके के नाम से की जा रही अवैध वसूली को रोका जाना

04–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में बालू बदरपुर के वाहनों के स्टैण्ड के लिये नियत स्थान है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त ठेके के नाम पर पूरे जनपद में अवैध वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध वसूली रोकने हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद अलीगढ़ में स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा बालू, बदरपुर के वाहनों के स्टैण्ड के लिये स्थान रिक्त नियत नहीं है।

जिला प्रशासन द्वारा राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी परिसर में बालू, बदरपुर व रोड़ी के ट्रकों को नियत स्थान पर खड़ा कराये जाने के लिये ठेका उठाया जाता है। उक्त स्थान पर कोई अवैध वसूली नहीं की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

05–श्री सुदेश शर्मा–

स्थगित शुक्रवार के अता0प्र0सं0–25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद इलाहाबाद के ममफोर्डगंज मुहल्ले में स्टैनली रोड पर भारी जलभराव की समस्या से निजात दिलाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

06–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के ममफोर्डगंज मुहल्ले में स्टैनली रोड पर भारी जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिये एक रेगुलेटर गेट के निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31–12–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भगत पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत कार्य की आकलित लागत सम्बन्धित समिति से अनुमोदित है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के उपरान्त उक्त कार्य करा दिया जायेगा।

इलाहाबाद नगर निगम में सफाई कर्मियों की बस्ती को नगर निगम 1995 के संकल्प के अनुसार हायर परचेज पर देने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र तथा दिसम्बर, 2014 तक की गई कार्यवाही की जानकारी

07–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर निगम में सफाई कर्मियों की बस्ती को नगर निगम 1995 के संकल्प के अनुसार हायर परचेज पर देने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09–10–13 प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त

हुआ है ? यदि हां, तो उस पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि करेलाबाग, खुल्दाबाद अस्पताल, ममफोर्डगंज, मलाकराज, साउथ मलाका एवं मधवापुर स्थित स्वच्छकार सफाई कर्मचारियों को मा0 सदन के संकल्प सं0–193 दिनांक 01–07–99 द्वारा सफाई कर्मचारियों की बस्ती को हायर परचेज पर दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। नगर निगम द्वारा उक्त नियमित आवासों का मूल्यांकन कराया गया निर्मित आवासों का कार्पेट एरिया भिन्न–भिन्न है, जिसके कारण उनका निर्धारण अलग–अलग दर्शाया गया है। सभी आवंटित कर्मचारियों को आवास मूल्य निर्धारित करते हुए दस प्रतिशत धनराशि जमा करने हेतु नगर निगम के पत्र दिनांक 26–09–01 द्वारा निर्देशित किया गया, परन्तु कर्मचारियों द्वारा इस मूल्यांकन के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की गयी है। धनराशि कम किये जाने अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अन्य अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आदिवासियों पर हो रहे सामूहिक हमलों के दृष्टिगत उनकी सुरक्षा एवं पुनर्वासन एवं उक्त हमलों के दोषियों को दण्ड देने का प्रकरण

08–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्य अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आदिवासियों पर हो रहे सामूहिक हमलों के दृष्टिगत उनकी सुरक्षा एवं पुनर्वासन एवं उक्त हमलों के दोषी अपराधियों को दण्ड देने हेतु कोई कानून सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में अन्य अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आदिवासियों पर हमलों के दोषी अपराधियों को दण्ड देने का प्राविधान भारतीय दण्ड संहिता में विद्यमान है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम, 1989 वर्तमान में प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के असोथर थानान्तर्गत तेलानाबाबा सरकंडी जंगल में इनामी डकैत शंकर केवट को मार गिराने वाले पुलिस कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रमोशन दिलाने का प्रकरण

09–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के असोथर थानान्तर्गत तेलानाबाबा सरकंडी जंगल में 31–5–2006 को 50 हजार रुपये का इनामी डकैत शंकर केवट को मुठभेड़ में मार गिराया गया था ? यदि हां, तो उस मुठभेड़ में कौन–कौन से अधिकारी/उप निरीक्षक व आरक्षी शामिल रहे तथा साहस एवं शौर्यपूर्ण कार्य के लिये वन रैंक आउट आफ टर्न प्रमोशन हेतु जारी शासनादेश सं0–665 (1) छ–पु–1–24/93, दिनांकित 3–2–1984 के अनुसार क्या मुठभेड़ में शामिल उप निरीक्षक राधारमण सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों को पुरस्कार व प्रमोशन दिया गया है ? यदि हां, तो किसे और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

1–श्री आनन्द कुमार सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष, असोथर।

2–श्री अजय सेठ तत्कालीन थानाध्यक्ष, किशनपुर।

3–श्री राधारमण सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष, धाता।

4–श्री राम कुमार मलिक तत्कालीन थानाध्यक्ष, गाजीपुर।

5–आरक्षी 597 कमलापति त्रिपाठी थाना असोथर।

6–आरक्षी 93 विजेन्द्र प्रताप सिंह थाना असोथर।

7–आरक्षी 137 प्रदीप कुमार यादव थाना किशनपुर।

8–आरक्षी 260 विजय कुमार थाना किशनपुर।

9–आरक्षी 475 शिवनारायण त्रिपाठी थाना गाजीपुर।

आउट आफ टर्न प्रमोशन के सम्बन्ध में विभागीय प्राधिकृत समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को शासनादेश दिनांक 03–02–1994 से आच्छादित नहीं पाया गया। अतः पुरस्कार दिया गया किन्तु आउट आफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया गया।

मुठभेड़ में शामिल निम्नलिखित उप निरीक्षक/आरक्षीगणों को पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–डीजी–सात–एस–8(295)/2003, दिनांक 22–01–09 द्वारा धनराशि रु0 50 हजार का नकद पुरस्कार दिया गया है जिसमें वितरण का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	उपनिरीक्षक/आरक्षीगण का नाम	पुरस्कृत धनराशि	वितरण की तिथि
1	उ0नि0 ना0पु0 श्री आनन्द कुमार सिंह	7000/–	22–01–09
2	उ0नि0 ना0पु0 श्री अजय सेठ	7000/–	22–01–09
3	उ0नि0 ना0पु0 श्री राधारमण सिंह	7000/–	22–01–09
4	उ0नि0 ना0पु0 श्री राम कुमार मलिक	7000/–	22–01–09

5	आरक्षी ना0पु0 श्री कमलापति त्रिपाठी	4400/–	22–01–09
6	आरक्षी ना0पु0 श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह	4400/–	22–01–09
7	आरक्षी ना0पु0 श्री प्रदीप कुमार यादव	4400/–	22–01–09
8	आरक्षी ना0पु0 श्री विजय कुमार	4400/–	22–01–09
9	आरक्षी ना0पु0 श्री शिव नारायण त्रिपाठी	4400/–	22–01–09

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ऊंचवागढ़ी, राजापुर आदि अधिकांश मलिन बस्तियों में नाली, गली इण्टरलॉकिंग शौचालय आदि के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

10–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के ऊंचवागढ़ी, राजापुर, गंगानगर, ओमनगर, शान्तिनगर, डोमनीमऊ, फाफामऊ, ढरहरिया, ममफोर्डगंज स्वीपर कालोनी, शान्तिनगर, कर्नलगंज थाने के पीछे मलिन बस्ती, गल्ला बाजार, ओम गायत्रीनगर पसियाना, बक्शीखुर्द दारागंज (बक्शीबांध के नीचे पूर्वी भाग), अल्लापुर–शिवनगर कालोनी, बजरंग बस्ती, हादीगंज, पूरा दलेल अल्लापुर, जोंघवल, रसूलाबाद, आजादनगर, मेंहदौरी, बेलीगांव व एवेन्यू आदि मलिन बस्तियों में नाली, गली इंटरलाकिंग शौचालय आदि के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का निदेशक, राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण को सम्बोधित पत्र दिनांक 9–10–2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जनपद इलाहाबाद के ऊंचवागढ़ी, गंगानगर, रसूलाबाद एवं आजाद नगर, बक्शीखुर्द दारागंज, बेलीगांव, ममफोर्डगंज स्वीपर बस्ती, जोंधवल, पूरा दलेल, कर्नलगंज थाने के पीछे एवं ओम गायत्री नगर की परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। राजापुर ढरहरिया, गल्ला बाजार की बस्तियों की परियोजनायें प्रक्रियाधीन हैं। ओमनगर, शान्ती नगर, ढोमनीमऊ, अल्लापुर–शिवनगर कालोनी, बजरंग बस्ती, हादीगंज व एवेन्यू मलिन बस्तियां जिला नगरीय विकास अभिकरण, इलाहाबाद के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। फाफामऊ बस्ती पूर्व से संचालित बेसिक सर्विसेज फार अर्बन पुअर (बी0एस0यू0पी0) योजना से आच्छादित है तथा इस योजनान्तर्गत अवस्थापना कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र/नगर पंचायत क्षेत्र डुमरियागंज में आसरा आवास योजनान्तर्गत आवास बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

11–श्री कमाल युसुफ मलिक–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र/नगर पंचायत क्षेत्र डुमरियागंज में आसरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15–12–2013 के क्रम में निदेशक, सूडा के पत्रांक 2898, दिनांक 27–12–2013 एवं जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पृष्ठांकित आदेश दिनांक 31–12–2013 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

आसरा योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर द्वारा शासी निकाय की बैठक में पारित प्रस्ताव के माध्यम से निःशुल्क भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डुमरियागंज से अनुरोध किया गया था। अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डुमरियागंज द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं होने की सूचना दी गयी। फलस्वरूप आवास निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। इसके अतिरिक्त आसरा योजना के अन्तर्गत इन सीटू आवासों के निर्माण हेतु डुमरियागंज नगर पंचायत क्षेत्र में आच्छादित बस्तियों में लाभार्थी चयन हेतु सर्वेक्षण की कार्यवाही नगर पंचायत के माध्यम से प्रारम्भ की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत बाल्मीकि समाज बस्ती में कम्युनिटी हाल का निर्माण कराया जाना

12–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत कोई कम्युनिटी हाल नहीं है ? यदि हां, तो सरकार बाल्मीकि समाज बस्ती में कम्युनिटी हाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद लखीमपुर खीरी में नगर पालिका परिषद् लखीमपुर के मोहल्ला निर्मलनगर, सिकटिहा, थरवरनगंज एवं नौरंगाबाद तथा खीरी टाउन व बरबर नगर पंचायत परिसरों एवं मोहम्मदी नगर पालिका परिषद् परिसर में सामुदायिक केन्द्र निर्मित है।

वर्तमान में जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र निर्माण किये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निकायों (नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों) के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों एवं निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान पेंशन, पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्रदान किया जाना

13–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निकायों (नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों) के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों एवं निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान पेंशन, पारिवारिक पेंशन की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? क्या यह भी सही है कि शासन द्वारा प्रस्तावित पेंशन संशोधन नियमावली का प्रकाशन दिनांक 04–03–14 को कराके आपत्ति आमंत्रित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद भी प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण न कराके अन्तिम अधिसूचना भी अभी तक प्रकाशित नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण करते हुए अन्तिम अधिसूचना निर्गत किये जाने के क्रम में नियमानुसार परामर्शी विभाग (वित्त विभाग) को संदर्भित किया गया था। परामर्शी विभाग/वित्त विभाग द्वारा कतिपय पृष्छाएं की गयी हैं, जिनके निस्तारण तथा उनकी सहमति प्राप्त होने के पश्चात् उक्त नियमावली का अन्तिम प्रकाशन सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में खराब यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार की प्रभावी कार्य योजना

14–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में खराब यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

कानपुर नगर में इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम के अन्तर्गत प्रथम चरण में ट्रैफिक सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कानपुर नगर में यातायात व्यवस्था को एवं दुरुस्त रखने के लिये अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालान एवं शमनशुल्क की कार्यवाही की जा रही है तथा नो पार्किंग पर खड़े होने वाले वाहनों के विरुद्ध क्रेनों के माध्यम से लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिन स्थानों पर ओवरब्रिज/समानान्तर पुल निर्माण का कार्य हो रहा है वहां पर पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर सुगम यातायात संचालन की व्यवस्था की जा रही है। रामादेवी से आईआई0टी0 तक तथा जरीब चौकी से विजय नगर तक सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। समय–समय पर चिन्हित किये गये स्थानों पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में आवास विकास कालोनी सिकन्दरा योजना सेक्टर–16 एरिया पार्क में बाउन्ड्रीवाल व पैदल पथ का निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाना

15–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में आवास विकास कालोनी सिकन्दरा योजना सेक्टर–16 एरिया पार्क में बाउन्ड्रीवाल व पैदल पथ विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कराने, समरसेविल, पैदल पथ तथा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आगरा में आवास विकास कालोनी सिकन्दरा योजना सेक्टर–16 का निरीक्षण किया गया। पार्क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

पार्क के निर्माण कार्य हेतु लोहा मण्डी वार्ड कक्ष संख्या–59 आवास विकास सिकन्दरा सेक्टर–16 में ए–9 श्री शिवकुमार के सामने पार्क की बाउण्ड्रीवाल, ग्रिल एवं पाथ–वे का निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में माधोगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कस्बा कोंच में जनधन हानि रोकने के लिये मलंगा नाला की खुदाई एवं मथुरा प्रसाद डिग्री कालेज से मलंगा के मेन रोड पुल के बीच टूटी पुलियों का निर्माण कराया जाना

16–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013–14 में भारी बारिस एवं करूई बांध के पानी खोले जाने से जनपद जालौन के कस्बा कोंच में तीन लोगों की मौत एवं पूरे नगर की धनहानि हुई थी ? क्या सरकार माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कस्बा कोंच में जन–धन हानि रोकने के लिये मलंगा नाला की खुदाई एवं मथुरा प्रसाद

डिग्री कालेज से मलंगा के मेन रोड पुल के बीच टूटी तीन पुलियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

सन्दर्भित कार्यों हेतु कार्य योजना बनाई गई है। कार्य योजना की स्वीकृति व धन की उपलब्धता पर प्रश्नगत कार्य कराये जा सकेंगे।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के दयालबाग क्षेत्र में श्री विष्णु अग्रवाल के म0 नं0–1 तुलसीबाग फेस–2 से पुष्पांजलि रोड तक जर्जर व गड्ढायुक्त को सी0सी0 सड़क के रूप में कराया जाना

17–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के दयालबाग क्षेत्र में श्री विष्णु अग्रवाल के म0 नं0–1 तुलसीबाग फेस–2 से पुष्पांजलि रोड तक सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर व गड्ढायुक्त हैं जिसका जनहित में सी0सी0 सड़क का निर्माण अति आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का सी0सी0 निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त मार्ग आंशिक रूप से जगह–जगह क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य हेतु लोहा मण्डी वार्ड बैनारा फैक्ट्री के गेट से लच्छों के मकान तक हाटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य का आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ मण्डल मुख्यालय पर पुलिस विजिलेंस कार्यालय की स्थापना सम्बन्धित प्रश्नकर्ता को पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

18–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ मण्डल मुख्यालय पर पुलिस विजिलेंस कार्यालय की स्थापना सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र आपके कार्यालय में दर्ज पत्रांक–सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0–0244915/2013, दिनांक 3–4–2013 पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सतर्कता अधिष्ठान का सेक्टर कार्यालय जनपद आगरा में स्थित होने के कारण अलीगढ़ मण्डल मुख्यालय में सेक्टर कार्यालय स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत अगवानपुर विकास खण्ड मुरादाबाद की जनसंख्या के आधार पर नगर पंचायत बनाये जाने का प्रकरण

19–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अगवानपुर ब्लाक व जिला मुरादाबाद की जनसंख्या लगभग 30000 है ? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

ग्राम पंचायत अगवानपुर विकास खण्ड मुरादाबाद की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 23000 है।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद से उक्त ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या–2934/9–1–2014–426सा/2014, दिनांक 28–8–2014 के अनुरूप प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा शासन के पत्र दिनांक 30–12–2014 द्वारा की गयी है। शासनादेश दिनांक 28–8–2014 के अनुरूप मानकों की पूर्ति होने पर नगर पंचायत बनाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

तहसील सदर मथुरा सहित नगर पालिका परिषद् मथुरा के सीमान्तर्गत होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से विगत तीन वर्षों में पालिका को प्राप्त धनराशि का विवरण

20–श्री पूरन प्रकाश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की तहसील सदर में होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से प्राप्त 2 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में पिछले तीन वर्षों में कितनी धनराशि नगरपालिका परिषद्, मथुरा को प्राप्त हुई ? क्या यह सही है कि इस मद में प्राप्त धन को प्राप्त रजिस्ट्रियों के क्षेत्र में विकास न कराकर अन्य मदों में लगा दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

तहसील सदर मथुरा सहित नगर पालिका परिषद् मथुरा के सीमान्तर्गत होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से विगत तीन वर्षों में पालिका को प्राप्त धनराशि निम्नवत् है :–

वर्ष	प्राप्त धनराशि
2011–12	100.30 लाख
2012–13	157.02 लाख
2013–14	159.77 लाख

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

21–श्री पूरन प्रकाश–

ख्ले बुधवार के अता0प्र0सं0–182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

22–श्री पूरन प्रकाश–

ख्मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

23–श्री दलवीर सिंह–

ख्दिनांक 19–02–2015 को अता0प्र0सं0–50 द्वारा उत्तरित,

24–श्री मुसर्रत अली बिट्टन

ख्ले बुधवार के अता0प्र0सं0–186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद लखनऊ के मायानगर मोहल्ले की माया नगर महल वाली रोड पर लगे इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाना

25–श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के मायानगर मोहल्ले की माया नगर महल वाली रोड पर लगे इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प विगत दो वर्षों से खराब पड़े हैं, जिससे वहां के निवासियों की पानी की असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

लखनऊ नगर के मायानगर मोहल्ले की माया नगर महल वाली रोड पर कुल 04 इण्डिया मार्का–ष्ष हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनमें से वर्तमान में 03 कार्य कर रहे हैं, एक हैण्डपम्प खराब है।

जलकल विभाग नगर निगम से खराब हैण्डपम्पों की सूचना प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता के पश्चात् खराब हैण्डपम्प ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ नगर के मायानगर मोहल्ले के माया नगर महल वाली रोड पर पानी हेतु लगी टी0टी0एस0पी0 टंकी का समरसेबिल ठीक कराकर जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना

26–श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के मायानगर मोहल्ले के माया नगर महल वाली रोड पर पानी हेतु लगी टी0टी0एस0पी0 टंकी का समरसेबिल खराब होने के कारण उक्त टंकी से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे निवासियों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टी0टी0एस0पी0 टंकी से जुड़े समरसेबिल को जनहित में ठीक कराकर जलापूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद के नगरीय क्षेत्रों में टी0टी0एस0पी0 टंकी एवं उक्त पर समरसेबिल पम्पों के अधिष्ठापन उनके रख–रखाव का दायित्व नगर निगम, लखनऊ का है। तद्नुसार मायानगर मोहल्ले के मायानगर महल वाली रोड पर अधिष्ठापित समरसेबिल पम्प को ठीक कराने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जी हां।

दो सप्ताह में खराब समरसेबिल को ठीक करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में वृद्ध नागरिकों की हत्या में वृद्धि होने की दशा में प्रत्येक वृद्ध को सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक

27–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में वृद्ध नागरिकों की हत्या में वृद्धि हई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेगी कि लखनऊ नगर के प्रत्येक थाने पर वृद्ध नागरिकों के पते की सूची रहे तथा घटना प्रभारी उनसे समय–समय पर सम्पर्क करते रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा के लिये बीट अधिकारी/कर्मचारीगण को वृद्ध नागरिकों की सूची बनाकर उनके निवास स्थान के आस–पास सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा हेतु उनकी सूची थाना स्तर पर तैयार करायी गयी है तथा समय–समय पर प्रभारी अधिकारी द्वारा कुशलता की जानकारी की जाती है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तरपर वरिष्ठ/वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा हेतु वरिष्ठ नागरिक सेल का भी गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर शहर में स्थित म0नं0 66/1 निकट लक्ष्मणपुर चौकी, थाना कोतवाली के पास पुराने शिव मन्दिर से 50 फिट लम्बा व 12 फिट चौड़े क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण हेतु स0वि0स0 का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

28–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर शहर में स्थित म0नं0 66/1 निकट लक्ष्मणपुर चौकी, थाना कोतवाली के पास पुराने शिव मन्दिर से 50 फिट लम्बा व 12 फिट चौड़े क्षतिग्रस्त मार्ग को सी0सी0 मार्ग बनवाने विषयक श्री सुनील कुमार सिंह यादव, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 21–11–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

संदर्भित पत्र दिनांक 21–11–2013 व्यक्तिगत सम्पर्क कर प्राप्त किया गया जिसमें उल्लिखित स्थल के खड़ण्जे मार्ग को आर0सी0सी0 रोड के निर्माण की संस्तुति की गई थी।

शासनादेश संख्या–2087/नौ–5–2013–120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार आर0सी0सी0 रोड बनाया जाना अनुमन्य नहीं है। संदर्भित स्थल के निरीक्षण के पश्चात् ज्ञात हुआ कि वहां कोई क्षतिग्रस्त मार्ग विद्यमान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में नये बाईपास स्थित ककरऊ की कोठी चौराहे की परिधि में आने वाले बहुत बड़े आवासीय एवं भारी यातायात से युक्त क्षेत्र के आसपास कोई पुलिस रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना का प्रकरण

29–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में नये बाईपास स्थित ककरऊ की कोठी चौराहे की परिधि में आने वाले बहुत बड़े आवासीय एवं भारी यातायात से युक्त क्षेत्र के आसपास कोई पुलिस रिपोर्टिंग चौकी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस घनी आबादी क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एक नई पुलिस रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

नगर फिरोजाबाद के थाना उत्तर के अन्तर्गत स्थित ककरऊ आता है। घनी आबादी की सुरक्षा एवं भारी यातायात को दृष्टिगत रखते हुए ककरऊ की कोठी पर

जनपद स्तर से पुलिस चौकी स्थापित है। अतः नई पुलिस रिपोर्टिंग चौकी का औचित्य नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद में पेयजल की समस्या के निदान हेतु झेड़ाझाल से सतही जल लाकर नगर फिरोजाबाद में जलापूर्ति हेतु बनी योजना की डी0पी0आर0 तैयार किया जाना

30–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में पेयजल की समस्या के निदान हेतु झेड़ाझाल से सतही जल लाकर नगर फिरोजाबाद में पेयजल आपूर्ति हेतु बनी योजना की डी0पी0आर0 तैयार हो गई है ? यदि नहीं, तो कब तक तैयार करा दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। फिरोजाबाद नगर में 13 ग्राम सभायें सम्मिलित होने एवं गिरते हुए भू–जल स्तर एवं भू–जल की गुणवत्ता उपयुक्त न होने के कारण सतही स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जसराना नवीन नहर परियोजना से 50 क्यूसेक जल सिंचाई विभाग द्वारा झेड़ाझाल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। सिंचाई विभाग द्वारा नहर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा अगले वर्ष के प्रारम्भ तक कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना के दृष्टिगत फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना लागत रु0 43281. 56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में रु0 25.00 करोड़ की धनराशि शासनादेश दिनांक 21–01–2015 द्वारा जारी की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–मुरादाबाद की तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना का प्रकरण

31–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मुरादाबाद की तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के लिये ग्राम सिरसा ठाट में आरक्षित भूमि पर जनवरी, 2015 तक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना नहीं हुई है ? यदि हं, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2015–2016 में तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोमतीनगर, लखनऊ में स्थित कठौता झील में अक्टूबर, 2014 में डूबकर हुई छात्रों की मौत का ध्यान में रखकर सुरक्षा के इन्तजाम तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना

32–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमतीनगर, लखनऊ में स्थित कठौता झील में अक्टूबर, 2014 में दो स्कूली बच्चों की डूबने से मौत हो गई ? क्या यह सही है कि उक्त झील में डूबने से पहले भी मौतें हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त झील में नहाने पर रोक लगाने तथा सुरक्षा के कोई इन्तजाम किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि उक्त दोनों बच्चों की मौत होने के उपरान्त सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां, अक्टूबर, 2014 में कठौता झील के पास तीन बच्चे आये तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र के अन्दर जाली लगी रेलिंग को फांदकर झील के अन्दर गये तथा बच्चे नहाने के लिये झील के पानी में चले गये जिसके कारण डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गयी।

जी हां।

कठौता झील की सुरक्षा हेतु पूर्व से ही रेलिंग व जालियां लगी हुई हैं तथा प्रतिबन्धित/प्रवेश निषिद्ध स्थान अंकित है। कठौता झील की सुरक्षा हेतु गार्ड भी तैनात है। पुलिस गस्त दिन व रात्रि में लगाने हेतु सम्बन्धित पुलिस स्टेशन को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

गोमती नदी की सफाई एवं लखनऊ में उनके दोनों तटों पर सुन्दरीकरण करने की सरकार की योजना

33–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी की सफाई एवं लखनऊ में उसके दोनों ओर के तटों पर सुन्दरीकरण करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है, तथा उस पर कुल कितना व्यय प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

गोमती नदी तट विकास परियोजना (प्रथम चरण) के अन्तर्गत गऊ घाट से गोमती बैराज तक गोमती नदी की सफाई एवं तटों के सुन्दरीकरण हेतु धनांक रु0 2894. 48 लाख की स्वीकृति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रदान की जा चुकी है जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सुन्दरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से बन्धों के समानान्तर पाथ–वे, जॉगिंग ट्रैक, लाइटिंग, हार्टीकल्चर कार्य एवं उसके सिंचाई प्रबन्धन, पार्किंग, घाट, लॉचिंग एप्रेन एवं शौचालय के

निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान सेतु मन्दिर के पीछे बन्धा लेबिल पर पार्किंग का निर्माण कार्य सम्मिलित है। परियोजना की लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप संशोधित लागत धनांक रु0 3997.54 लाख स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

34–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

खविस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

जनपद फिरोजाबाद की पुलिस चौकी नालाबन्द एवं स्टेशन रोड थाना उत्तर थाना दक्षिण की पुलिस चौकी के पुराने भवनों एवं वहां की जर्जर आवासीय परिसरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाना

35–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के थाना उत्तर थाना दक्षिण की पुलिस चौकी, नालाबन्द एवं स्टेशन रोड पुलिस चौकी के पुराने भवनों एवं वहां की जर्जर आवासीय परिसरों को नये सिरे से दो मंजिला आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद फिरोजाबाद की पुलिस चौकी नालाबन्द एवं स्टेशन रोड थाना उत्तर के अन्तर्गत नहीं है। यह पुलिस चौकी थाना दक्षिण के अन्तर्गत जनपद स्तर से संचालित है। स्टेशन रोड पुलिस चौकी किराये पर व चौकी नालाबन्द पुलिस विभाग की भूमि पर संचालित है। उक्त दोनों चौकियां शासन द्वारा स्वीकृत नहीं हैं। अतः उक्त भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के राजा का ताल एवं मख्खनपुर में बढ़ती आवासीय एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान किया जाना

36–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के राजा का ताल एवं मक्खनपुर में बढ़ती आवासीय एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण ये कस्बे के रूप में परिवर्तित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजा का तालाब एवं कस्बे मख्खनपुर को नगर पंचायत का दर्जा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 2014 द्वारा नगर पंचायत के सृजन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति न करने के कारण राजा का तालाब एवं मक्खनपुर को नगर पंचायत बनाया जाना सम्भव नहीं है।

कानपुर महानगर स्थित गुंजन विहार कालोनी के सेक्टर जे एवं के में ओवर हेड टैंक को चालू कराया जाना

37–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर स्थित गुंजन विहार कालोनी के सेक्टर जे एवं के में ओवर हेड टैंक को कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम में कानपुर पेयजल योजना फेज–2 के अन्तर्गत कानपुर महानगर स्थित गुंजन विहार कालोनी के सेक्टर ''के'' में 700 के0एल0/22 मी0 स्टेजिंग क्षमता का 01 अवर जलाशय का निर्माण उ0 प्र0 जल निगम द्वारा वर्ष 2010–11 में किया गया है तथा सेक्टर ''जे'' में कोई अवर जलाशय प्रस्तावित नहीं है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम में कानपुर पेयजल योजना फेज–1 के अन्तर्गत बैराज पर निर्माणाधीन 200 एम0एल0डी0 क्षमता के दो नग ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से क्लीयर वाटर फीडरमेन बिछा कर उ0 प्र0 जल निगम द्वारा निर्मित नगर के विभिन्न जोनल पम्पिंग स्टेशनों के साथ–साथ 700 कि0ली0/22 मीटर क्षमता के ओवर हेड टैंक से गुंजन विहार कालोनी के निवासियों को जलापूर्ति की जायेगी। वर्तमान में गुंजन विहार स्थित 57 एम0एल0डी0 ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पर उपलब्ध सरप्लस 29 एम0एल0डी0 पानी से कानपुर महानगर की क्षेत्र की जनसंख्या जिसमें गुंजन विहार कालोनी के सेक्टर ''जे'' एवं ''के'' भी सम्मिलित है, को लाभान्वित करने हेतु फिडरमेन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर महानगर में किदवई नगर बाई पास प्रताप होटल से बजरंग चौराहे का मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने से, बनवाया जाना

38–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में किदवई नगर बाई पास प्रताप होटल से बजरंग चौराहे का मुख्य मार्ग जो नगर निगम द्वारा पूर्व में बनाया गया था, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

किदवई नगर बाई पास प्रताप होटल से बजरंग चौराहे का मुख्य मार्ग जो पूर्व में नगर निगम द्वारा नहीं बनाया गया है तथा प्रश्नगत क्षेत्र निजली सोसाइटी क्षेत्र है। शासनादेश सं0–05097/9–अ–3–2001 (अ0व0) दिनांक 26–5–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास कार्य का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व विधायकों के निधन की सूचना 48 घण्टे के अन्दर भेजे जाने तथा अन्त्येष्टि के समय राजकीय सम्मान दिये जाने का आदेश शासन द्वारा दिये जाने की कार्यवाही

39–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भूतपूर्व विधायकों के निधन की सूचनायें समय पर प्राप्त हो इसके लिये शासन स्तर पर क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार पूर्व विधायकों के निधन पर अन्त्येष्टि स्थल पर किसी प्रशासनिक/पुलिस अधिकारी को सम्मान व्यक्त करने हेतु भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शासन स्तर पर मुख्य सचिव की ओर से समस्त जिलाधिकारियों को प्रदेश में भूतपूर्व विधायकों के निधन की सूचना 48 घण्टे के अन्दर विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय को उपलब्ध कराये जाने के आदेश शासनादेश दिनांक 23 जून, 2006 (प्रति संलग्न है) द्वारा पहले ही जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 2010 एवं 2013 में इस सम्बन्ध में पुनः समस्त जिलाधिकारियों को भूतपूर्व विधायकों के निधन पर उनकी अन्त्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ किये जाने के आदेश भी दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2011–12, 2012–13 व 2013–14 में रंगदारी वसूली के दर्ज प्रकरणों पर हुई कार्यवाही की जानकारी

40–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2011–12, 2012–13 व 2013–14 में रंगदारी वसूली के कितने प्रकरण दर्ज किये गये एवं ऐसे कितने प्रकरणों में गिरफ्तारी की गई है ? क्या सरकार द्वारा प्रदेश में रंगदारी की घटनाओं को सख्ती से रोकने हेतु कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

रंगदारी वसूली के दर्ज कुल प्रकरण/गिरफ्तारी की कार्यवाही–

2011–12 में दर्ज कुल प्रकरण	कुल प्रकरणों की संख्या जिसमें गिरफ्तारी की गयी है	2012–13 में दर्ज कुल प्रकरण	कुल प्रकरणों की संख्या जिसमें गिरफ्तारी की गयी है	2013–14 में दर्ज कुल प्रकरण	कुल प्रकरणों की संख्या जिसमें गिरफ्तारी की गयी है
278	230	322	255	426	364

इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु समस्त जनपद प्रभारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं कि इस प्रकार की किसी भी घटना के संज्ञान में आने पर संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाय जिससे पीड़ित पक्ष/जनता में पुलिस व्यवस्था के प्रति आस्था बनी रहे। इस प्रकार की घटित घटनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लिये जाने के विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी को उपलब्ध कराने की विशेष कार्य योजना

41–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भीषण गर्मी में पेयजल संकट को देखते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी को उपलब्ध कराने हेतु सरकार के द्वारा कोई विशेष योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में पूर्व से ही पेयजलापूर्ति की अबाध व्यवस्था हेतु योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश की 630 नागर निकायों में से 627 नागर निकायों में पाइप पेयजलापूर्ति की व्यवस्था है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यांश में पेयजलापूर्ति की क्रमशः 11 व 37 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त राज्य सेक्टर के नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत भी प्रदेश में पेयजलापूर्ति की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला योजना (नगरीय पेयजल) से भी पेयजलापूर्ति के महत्वपूर्ण कार्य कराये जाते हैं। स्पष्टतः प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को सुदढ़ रखने के हर सम्भव प्रयास पूर्व से ही किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर निगमों में विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के पदों के सृजन की कार्यवाही की मांग

42–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों में विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के कार्य (विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवा सम्बन्धित कार्य) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 की मुख्य धारा–112 ख के अन्तर्गत विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता के पदों के सृजन के मानक क्या हैं ? क्या यह सही है कि प्रदेश के मात्र 05 नगर निगमों में ही विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ता तैनात हैं जबकि 08 नगर निगमों में अन्य संवर्ग के अभियन्ता कार्य देख रहे हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं के उक्त श्रेणी के पद सृजित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–112ख के अन्तर्गत पद सृजन का मानक निर्धारित नहीं है।

जी हां।

प्रदेश की नागर निकायों के पुनर्गठन एवं मानकीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसमें विद्युत/यांत्रिक संवर्ग सम्मिलित है। निर्णयोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में 30 अक्टूबर, 2014 से 2 नवम्बर, 2014 के बीच कई हत्या और डकैती के अपराधों की संख्या की जानकारी तथा सरकार की अपराध नियंत्रण की कार्य योजना

43–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 अक्टूबर, 2014 से 2 नवम्बर, 2014 के बीच कई हत्या और डकैती हुई हैं ? यदि हां, तो प्रदेश की राजधानी में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद लखनऊ में 30 अक्टूबर, 2014 से 2 नवम्बर, 2014 के बीच 5 हत्या की घटनायें घटित हुई हैं और डकैती की कोई घटना नहीं हुई है।

लखनऊ में अपराधों पर नियंत्रण के लिये प्रभावी कार्य योजनायें बनायी गयी हैं–

1–लखनऊ में आकस्मिक रूप से आल आउट स्कीम, फ्लैस आउट स्कीम लागू कर अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी चेकिंग एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करायी जा रही है।

2–हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के वांछित अभियुक्त एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी एवं अन्य सुसंगत नियमों के तहत कठोर निरोधात्मक कार्यवाही अभियान चलाकर करायी जा रही है।

3–अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु थाना क्षेत्रों में चल रहे विवादों हेतु ''समाधान दिवस'' तथा तहसील दिवस पर प्रकरणों को संज्ञानित कर उनका समाधान कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ विवाद पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिये उभय पक्षों को भारी धनराशि से पाबन्द कराया जा रहा है।

4–जनपद के भीड़–भाड़ व महत्वपूर्ण स्थानों पर अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये गये हैं और ''आप कैमरे की नजर में हैं'' का फ्लैक्स बोर्ड जगह–जगह लगवाये गये हैं ताकि अवांछनीय तत्वों पर कड़ी निगरानी हो सके और उन पर मानसिक दबाव पड़ सके।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के थाना बड़हलगंज अन्तर्गत मधुपुर में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना की मांग तथा मधुपुर एवं घुरियापार में पुलिस चौकी स्थापित कराने विषयक

44–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के अन्तर्गत कोतवाली बड़हलगंज मुख्यालय दूर होने के कारण कछारान्चल के मधुपुर में तथा धुरियापार में एक पुलिस चौकी की स्थापना की मांग ग्रामीण वर्षों से कर रहे हैं, जिसका प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार मधुपुर एवं धुरियापार में पुलिस चौकी स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद गोरखपुर के थाना बड़हलगंज अन्तर्गत मधुपुर में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना का समुचित प्रस्ताव उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय से मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस चौकी धुरियापार की सम्बन्धित थाना उरुवा बाजार से दूरी 05 कि0मी0 है जो पुलिस चौकी के लिये निर्धारित दूरी का मानक 10 कि0मी0 का पूर्ण नहीं करती है तथा चौकी की स्थापना हेतु भूमि भी उपलब्ध नहीं है। अतः रिपोर्टिंग पुलिस चौकी धुरियापार की स्थापना का औचित्य नहीं है।

कानपुर महानगर के यशोदा नगर बाई पास से काली बाड़ी चौराहे तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

45–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के यशोदा नगर बाई पास से काली बाड़ी चौराहे तक मुख्य मार्ग, जो नगर निगम के द्वारा पूर्व में बनाया गया था, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त मार्ग कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है तथा उक्त क्षेत्र निजी सोसाइटी क्षेत्र है। शासनादेश संख्या–5097/9–अ–3–2001 (अ0व0) दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के महराजपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के गंभीर संकट को देखते हुए प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

46–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के महराजपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के गंभीर संकट को देखते हुए 200 इण्डिया मार्का–2

हैण्डपम्प मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप लगाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17–07–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप मा0 विधायकों को 100–100 हैण्डपम्प दिये जाने के अनुक्रम में शहरी क्षेत्रों के लिये आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–14/2015/30/8–1–15–10 बजट/2015, दिनांक 23 जनवरी, 2015 द्वारा रु0 1720.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रु0 8,60,17,500 (रु0 आठ करोड़ साठ लाख सत्तरह हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र में 2500 एम0एल0डी0 ओवरहेड टैंक का निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

47–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र में 2500 एमएलडी ओवरहेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26–06–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

सन्दर्भित क्षेत्र में दो ओवरहेड टैंक निर्मित हैं, जिन्हें मार्च, 2015 तक चालू किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सी0डब्लू0आर0 (क्लीयर वाटर रिजर्वायर) बनाकर चालू किया जाना

48–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत कितने सी0डब्लू0आर0 (क्लीयर वॉटर रिजर्वायर) बनाया जाना प्रस्तावित थे तथा उनमें से कितने चालू हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो सी0डब्लू0आर0 चालू नहीं है उनको कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत मिशन शहर कानपुर में कुल 76 सी0डब्लू0आर0 प्रस्तावित हैं, जिनमें से 4 चालू हैं।

शेष सी0डब्लू0आर0 को मार्च, 2015 तक चालू किया जाना लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत ओवरहेड टैंक जो चालू नहीं हैं उन्हें चालू किया जाना

49–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में जे0एन0एन0 यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत कितने ओवर हेड टैंक बनाये गये हैं तथा उनमें से कितने चालू हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो ओवर हेड टैंक चालू नहीं हैं उसको कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत मिशन शहर कानपुर में कुल 45 ओवरहेड टैंक बनाये गये हैं, जिनमें से 6 चालू हैं।

शेष ओवरहेड टैंक को मार्च, 2015 तक चालू किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में आउटर क्षेत्र में कालोनियों की बढ़ोत्तरी के कारण बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से लोहिया नगर, माधवपुरम्, शास्त्रीनगर, फफण्डा, दैनिक जागरण तिराहा आदि स्थानों पर थाना की स्थापना कराया जाना

50–श्री रविन्द्र भड़ाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में आउटर क्षेत्र में कालोनियों की बढ़ोत्तरी के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या एवं कालोनी वासियों की सुरक्षा हेतु–लोहियानगर, माधवपुरम्, शास्त्रीनगर, फफण्डा, दैनिक जागरण तिराहा आदि स्थानों पर थाना स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में आउटर क्षेत्र में कालोनियों के बढ़ोत्तरी के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या एवं कालोनीवासियों की सुरक्षा हेतु थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र एवं थाना नौचन्दी क्षेत्र के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–568 पी/छः–पु–6–13–300(37)/04, दिनांक 30–12–2013 द्वारा क्रमशः रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माधवपुरम् एवं शास्त्रीनगर की स्थापना की जा चुकी है। इस शासनादेश के अनुश्रवण में जनपद स्तर से कार्यालय–ज्ञाप

दिनांक 31–1–2014 जारी कर दोनों रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों की स्थापना की जा चुकी है। अतः उपर्युक्त स्थानों पर थाना स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं है।

मेरठ दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में काली नदी के पास थाना मेडिकल के पीछे जैभीम नगर, संजय विहार, प्रताप विहार, भोपाल विहार, उत्तराखण्ड कालोनी को तत्काल सुरक्षा की दृष्टि से थाना मेडिकल से सम्बद्ध करने विषयक

51–श्री रविन्द्र भड़ाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में काली नदी के पास थाना मेडिकल के पीछे जैभीमनगर, संजय विहार, प्रताप विहार, भोपाल विहार, उत्तराखण्ड कालोनी, थाना भावनपुर से सम्बद्ध है ? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों की थाना भावनपुर से दूरी 15–20 किमी0 बैठती है जबकि ये सभी कालोनियां थाना मेडिकल से सटी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार दूरी एवं जनता को तत्काल सुरक्षा की दृष्टि से उक्त क्षेत्रों को थाना मेडिकल से सम्बद्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जयभीमनगर, संजय विहार, प्रताप विहार, भोपाल विहार, उत्तराखण्ड कालोनी का क्षेत्र थाना भावनपुर जनपद मेरठ में आता है। इन क्षेत्रों की थाना भावनपुर से दूरी करीब 07 कि0मी0 है। यह क्षेत्र थाना मेडिकल जनपद मेरठ से 01 कि0मी0 दूरी पर है।

जनपद स्तर से प्रस्ताव प्राप्त कर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

52–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

ख्ले मंगलवार के अता0प्र0सं0–45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में संगठित विकास योजना के अन्तर्गत यातायात नगर का निर्माण का प्रकरण

53–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संगठित विकास योजना के अन्तर्गत यातायात नगर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो प्रत्येक नगर में लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी यातायात नगर स्थापित न होने से जनमानस को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इन निर्मित यातायात नगरों का उपयोग कराना प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

'संगठित विकास योजना' वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अतः अद्यतन किसी भी नगर में यातायात नगर का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

पूर्व में भारत सरकार द्वारा ऋण पोषित 11 नगरों (हाथरस, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, मैनपुरी, एटा, सुल्तानपुर, इटावा, मुजफ्फरनगर, बस्ती तथा लखीमपुर) में ट्रान्सपोर्ट नगर की योजना अनुमोदित की गई थी। उक्त 11 नगरों में से केवल मैनपुरी, एटा तथा लखीमपुर नगरों में ट्रान्सपोर्ट नगर बन चुके हैं। उक्त तीनों नगरों को छोड़कर अन्य अनुमोदित नगरों में निर्माण न कराये जाने का मुख्य कारण भूमि का विवादग्रस्त हो जाना अथवा भूमि उपलब्ध न होना, योजना हेतु भूमि का उपयुक्त न होना आदि थे, अनुदान पोषित नगरों के अन्तर्गत मात्र झांसी एवं गोला गोकर्णनाथ नगरों में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना अनुमोदित थी, जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

संगठित विकास योजना जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 में शामिल हो गया है। संगठित विकास योजना के अन्तर्गत पूर्व में बने ट्रान्सपोर्ट नगरों के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित अभिकरणों का है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वादों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्या सरकार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोलने हेतु प्रस्ताव की जानकारी

54–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वादों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्या सरकार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोलने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–1 संघ सूची की प्रविष्टि संख्या–78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है, अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

प्रदेश के नगरों में सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवर/पशुओं को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही किया जाना

55–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों में सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवर/पशुओं को रोकने की क्या नीति है ? क्या सरकार इन आवारा जानवर/पशुओं को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नागर निकायों द्वारा अपने सीमित संसाधनों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही की जाती है तथा शिकायत प्राप्त होने पर भी आवारा पशुओं को पकड़ कर कांजी हाउस में बन्द किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम बरेली में सिटी सैनिटेशन प्लान की प्रस्तावित कार्य योजना विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

56–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम बरेली में सिटी सैनिटेशन प्लान की प्रस्तावित कार्य योजना विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–नं0–270519, दिनांक 19–9–2014 नगर आयुक्त, नगर निगम बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

बरेली नगर का सिटी सैनीटेशन प्लान एडिमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया (एएससीआई) हैदराबाद द्वारा तैयार किया गया है। उक्त प्लान में कतिपय कमियों को इंगित कर संशोधित सिटी सैनीटेशन प्लान तैयार कर नगर निगम, बरेली को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली में प्रत्येक थानों पर एक महिला पुलिस अधिकारी/पुलिस कर्मी की तैनाती विषयक पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

57–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में प्रत्येक थानों पर एक महिला पुलिस अधिकारी/पुलिस कर्मी की तैनाती विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–नं0–270522, दिनांक 19–09–2014 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार उनके कार्यालय में पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

58–श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्ाले मंगलवार के अता0प्र0सं0–48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में बइ रही यौन शोषण की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कानून बनाये जाने विषयक प्रकरण

59–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाल यौन शोषण की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रोकथाम हेतु कोई कानून बनाएगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

वर्ष 2012 में बलात्कार की 1040 व वर्ष 2013 में 1381 घटनायें हुई थी। पास्को अधिनियम लागू होने के बाद एससीआरवी में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में कुल मिलाकर 222 बाल यौन शोषण से सम्बन्धित घटनायें 31–12–2014 तक प्रदेश में पंजीकृत हुई है।

वर्ष 14–11–2012 से केन्द्र सरकार द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम प्रदेश में भी लागू है। इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक माना गया है बलात्कार की परिभाषा को विस्तृत किया गया है तथा बालकों के प्रति लैंगिक हिंसा से सम्बन्धित अपराधों के दुष्प्रेरण को भी दण्डनीय बनाया गया है।

लैंगिक शोषण से सम्बन्धित मामलों की सूचना दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में भी अधिनियम में विशेष प्रावधान किये गये हैं तथा अभियोग दर्ज न करने पर दण्ड की व्यवस्था की गई है साथ ही पीड़ित बालक के अभिकथन अंकित करने एवं उनके चिकित्सीय परीक्षण हेतु विशेष उपबन्ध बनाये गये हैं।

अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है तथा जिले स्तर पर जिला किशोर पुलिस यूनिट की स्थापना भी की गई है। किशोरों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिये 1098 व 1090 हेल्पलाइन नं0 प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं जिससे ऐसे अपराधों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम परसा (अगलौवा) में बड़हलगंज फायर स्टेशन का निर्माण कार्य पुनः आरम्भ कराने विषयक

60–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम परसा (अगलौवा) में बड़हलगंज फायर स्टेशन का निर्माण कार्य एक वर्ष से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवरुद्ध कार्य को पुनः आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम परसा (अगलौवा) में बड़हलगंज फायर स्टेशन के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या–4141/6–पु–7–11–132/2010, दिनांक 08–09–2011 द्वारा रु0 208.58 लाख की स्वीककृति के सापेक्ष प्रथम किश्त रु0 59.52 लाख तथा शासनादेश संख्या–3914/6–पु–13–132/2010, दिनांक 03–10–2013 द्वारा अवशेष किश्त रु0 149.06 लाख निर्माण इकाई उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। निर्माण कार्य प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

61–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

खविस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

जनपद बरेली में अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु स्वीकृत धनराशि विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

62–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु स्वीकृत धनराशि विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–नं0–270521, दिनांक 19–09–2014 जिलाधिकारी, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रकरण में जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 14–02–2014 द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु चैम्बर्स निर्माण का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग बरेली से आगणन गठित कराकर शासन को उपलब्ध कराया गया था। उक्त प्रस्ताव के अनुक्रम में नियोजन अनुभाग–4 के शासनादेश दिनांक 04–02–2015 द्वारा रु0 211.33 लाख की प्रशासनिक

एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 105.66 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत छोटी आरा मशीन प्रियदर्शिनी इण्टर कालेज होते हुये स्वर्ण जयंती विहार के0डी0ए0 कालोनी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने विषयक

63–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत छोटी आरा मशीन प्रियदर्शिनी इण्टर कालेज होते हुये स्वर्ण जयंती विहार के0डी0ए0 कालोनी तक मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

छोटी आरा मशीन प्रियदर्शिनी इण्टर कालेज तक मार्ग निजी सोसायटी क्षेत्र है। शासनादेश सं0–05097/9–अ–3–2001 (अ0व0) दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास कार्य का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

स्वर्ण जयन्ती विहार केडीए कालोनी मुख्य मार्ग सेक्टर 6, 7 एवं 8 के मध्य का कार्य प्रगति पर।

उपरोक्तानुसार।

फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद् को अधिसूचना के अन्तर्गत उच्चीकृत कर नगर निगम, फिरोजाबाद बनाने तथा नये बोर्ड का गठन किये जाने विषयक

64–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद् को अधिसूचना संख्या 1216/नौ–7–14–01–घोषणा/2013, दिनांक 4–8–2014 द्वारा उच्चीकृत कर नगर निगम, फिरोजाबाद बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्या नवगठित नगर निगम, फिरोजाबाद के नये चुनाव करा कर नये बोर्ड का गठन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो नये बोर्ड का गठन कब तक कराया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी नहीं।

परिसीमन होने के उपरान्त चुनाव तथा बोर्ड के गठन की कार्यवाही होगी।

कानपुर महानगर के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कृष्णा धर्मकांटे से यशोदा नगर मुख्य मार्ग एवं टाटा मोटर्स से चुगैय्या गांव मुख्य मार्ग की मरम्मत का प्रकरण

65–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कृष्णा धर्मकांटे से यशोदा नगर मुख्य मार्ग एवं टाटा मोटर्स से चुगैय्या गांव मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कृष्णा धर्मकांटे कांटे से यशोदा नगर मुख्य मार्ग एवं टाटा मोटर्स से बुगरूया गांव मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। प्रश्नगत क्षेत्र निजी सोसाईटी क्षेत्र है। शासनादेश सं0–05097/9–अ–3–2001 (अ0व0) दिनांक 26–5–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के थाना माघोटाडा में पंजीकृत दहेज उत्पीड़न के सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व कार्यवाही की जानकारी

66–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के थाना माधोटाडा में पंजीकृत अभियोग सं0–865/2013 अन्तर्गत धारा 304ए, 498ए00द0सं0 एवं धारा 3, 4 दहेज उत्पीड़न में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग प्रस्तुत किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

थाना माधोटाडा पर दिनांक 30–09–13 को वादी श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री दरबारी सिंह, नि0 ग्राम भवानीगंज, थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत द्वारा अपनी पुत्री नीलम देवी उर्फ रामा की उसके ससुराल के लोगों द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबा कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0–865/13 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम अभियुक्तगण सरनाम सिंह, सूरज सिंह, सतेन्द्र सिंह पुत्रगण किशन सिंह, श्रीमती कुशमा देवी पत्नी सूरज सिंह, नि0 ग्राम रुद्रपुर थाना माधोटाडा, जनपद पीलीभीत के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त सरनाम सिंह को दिनांक 05–10–13 को व सतेन्द्र सिंह को दिनांक 26–12–13 को गिरफ्तार कर जेल भेज कर अभियुक्त सरनाम सिंह के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0–ए–193 दिनांक 23–11–13 को व अभियुक्त सतेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0 ए–193ए दिनांक 12–01–14 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है तथा श्रीमती कुशमा देवी दिनांक 19–06–14 को गिरफ्तार कर जेल भेज कर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप–पत्र सं0–ए–193 बी दिनांक 19–06–14 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका

है, जो विचाराधीन न्यायालय है उक्त अभियोग में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

67–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

ख्ालें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0–83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध और शातिर अपराधियों की संख्या में रखते हुए प्रदेश के विभिन्न थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों की फिटनेस बनाये रखने की समय–समय पर जांच आदि की कार्यवाही

68–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुये अपराध और शातिर अपराधियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार प्रदेश के विभिन्न थानों पर तैनात पुलिस कर्मी जो अनफिट हैं या ओवर वेट हैं, को फिट रखने हेतु समय–समय पर फिटनेस टेस्ट जैसी कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन में पुलिस कर्मियों का वार्षिक चिकित्सा परीक्षण कराये जाने का प्राविधान है।

थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को वार्षिक चिकित्सा परीक्षण पुलिस लाइन में स्थापित पुलिस चिकित्सालय के प्रभारी द्वारा किये जाने तथा उनके स्वास्थ्य के परीक्षण का रिकार्ड रखे जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा नगर एवं गोमती नगर कालोनी, लखनऊ में जर्जर वाटर लाइन को बदलने की योजना की जानकारी

69–श्री आशुतोष टण्डन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर एवं गोमती नगर कालोनी, लखनऊ में जर्जर वाटर लाइन को बदलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक बदलवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

गोमती नगर में पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु पुरानी पाइप लाइन को बदलने, नये क्षेत्रों में पाइप लाइन के विस्तार तथा अन्य आवश्यक कार्यों को सम्मिलित करते हुए परियोजना की अनुमानित लागत रु0 279.55 करोड़ विरचित की गई है, जिसे भारत सरकार के नवीनतम् दिशा–निर्देशों के अनुरूप पुनरीक्षित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त परियोजना के पुनरीक्षित हो जाने तथा यथाशीघ्र भारत सरकार से स्वीकृत होने की दशा में प्रस्तावित कार्य कराये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में सीवर लाइन डालने के बाद टूटी सड़कें का निर्माण कराये जाने विषयक

70–श्री आशुतोष टण्डन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना अन्तर्गत जनपद लखनऊ में पूर्वी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड–इस्माइलगंज प्रथम एवं द्वितीय, शंकरपुरवा वार्ड प्रथम व द्वितीय, लालबहादुर शास्त्री वार्ड प्रथम व द्वितीय, काल्विन कालेज वार्ड, पेपर मिल कालोनी वार्ड, निशातगंज वार्ड, इन्दिरा प्रियदर्शिनी वार्ड तथा गोमती नगर वार्ड में सीवर लाइन डालने के बाद सड़कों का निर्माण न कराये जाने से आवागमन में नागरिकों को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वार्डों के सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में पूर्वी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड–इस्माइलगंज प्रथम एवं द्वितीय शंकरपुरवा वार्ड प्रथम द्वितीय, लालबहादुर शास्त्री वार्ड, निशातगंज वार्ड इन्दिरा प्रियदर्शिनी वार्ड तथा गोमती नगर वार्ड में सीवर लाइन डालने के पश्चात् सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य अधिकांश पूर्ण करा दिया गया है। शेष सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2015 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। आवागमन बाधित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

71–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कैसरगंज जनपद बहराइच में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पीजी 10032308, पत्रांक संख्या सी0एम0/वि0को/एम/ पी0जी0 10032308/2012, दिनांक 11–05–2012 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव गृह एवं गोपन कारागार को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त पत्र पर शासन द्वारा अग्निशमन मुख्यालय से परीक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में अवगत कराया गया है कि तहसील कैसरगंज जनपद बहराइच में इस प्रयोजन के लिये अभी भूमि आवंटित नहीं हो पाई है।

प्रश्न नहीं उठता।

72–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

श्री अक्षयवर लाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुर्तिहा द्वारा एफ0आई0आर0 न लिखे जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

73–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अक्षयवर लाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुर्तिहा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखे जाने तथा हमला एवं हत्या की साजिश रचे जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पीजी 10401256, पत्र संख्या सी0एम0/वि0को/एम/पी0जी0 10401256/2014, दिनांक 04–01–2014 प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन कारागार, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

श्री अक्षयवर लाल गौड, सेमरी मलमला थाना कोतवाली जनपद बहराइच की तहरीर के आधार पर दिनांक 23–12–2013 को थाना कोतवाली मूर्तिहा पर मु0अ0सं0–497/2013 धारा–379 भा0दं0वि0 व 4/10 जी0टी0पी0 एक्ट का अभियोग कुल 11 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना उक्त अभियोग में कुल 11 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 406 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत मोहल्ला जाफरखेड़ा, चाणक्यपुरी, कृष्णानगर, हाता मिठाई लाल के सामने की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण तथा जर्जर सप्लाई पाइप को ठीक कराना

74–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ अन्तर्गत मोहल्ला जाफरखेड़ा चाणक्यपुरी कृष्णानगर लखनऊ हाता मिठाई लाल के सामने की सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है तथा पानी के सप्लाई पाइप भी जर्जर स्थिति में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी सप्लाई पाइप ठीक कराते हुये उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सड़क के पुनर्निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया है, परन्तु वर्तमान में नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण उक्त कार्यों को कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

वरदान खण्ड एवं विवेक खण्ड, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के अन्तर्गत फुटपाथों एवं कालोनियों में रैम्प व अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

75–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरदान खण्ड एवं विवेक खण्ड, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के अन्तर्गत कुछ लोगों द्वारा फुटपाथों एवं कालोनियों में रैम्प व अवैध निर्माण कराकर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर किये गये अवैध कब्जों को ध्वस्त कराकर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। वरदान खण्ड एवं गोमती नगर विस्तार नगर निगम सीमा के अन्दर है।

जहां तक विवेक खण्ड का प्रश्न है, संज्ञान में आने पर अवैध रैम्प/निर्माण को समय–समय पर हटवाया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हेल्पलाइन नं0 1090 पर प्राप्त शिकायतें तथा शिकायतों पर की गई गिरफ्तारियां तथा प्रकरणों के निस्तारण की जानकारी

76–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हेल्पलाइन नं0 1090 पर कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा कितनी शिकायतों पर एफ0आई0आर0 एवं गिरफ्तारी हुई है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि कुल कितने प्रकरणों को निस्तारित किया गया ? क्या सरकार लम्बित प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वूमेन पावर लाइन–1090 में अब तक कुल 3,16,581 शिकायतें दर्ज हुई हैं। वूमेन पावर लाइन–1090 की सूचना पर कुल 370 एफ0आई0आर0 पंजीकृत हुई हैं एवं उक्त अभियोगों में से 150 अभियोगों में 120 गिरफ्तारी हुई हैं।

अब तक कुल प्राप्त 3,16,581 शिकायतों में 3,13,670 निस्तारित हुई हैं। शेष 2911 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के कमलानगर क्षेत्र में बाईपास से ब्लाक–ई तक जर्जर सी0सी0 रोड की मरम्मत कराया जाना

77–श्री जगन प्रसाद गर्ग

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के कमलानगर क्षेत्र में बाईपास से ब्लाक–ई तक सी0सी0 रोड विगत कई वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सी0सी0 सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन में लिये गये निर्णय के क्रम में सी0सी0 सड़क निर्माण प्रतिबन्धित है। संदर्भित स्थल पर मुख्य मार्ग का निर्माण नगर निगम द्वारा हॉटमिक्स प्लांट से कराया जा चुका है। वर्तमान में संदर्भित स्थल पर कोई सड़क सी0सी0 की क्षतिग्रस्त नहीं है।

आगरा के सुल्तानगंज क्षेत्र में खड़न्जा, इण्टरलॉकिंग, नालियों आदि का निर्माण कराने सम्बन्धी

78–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के सुल्तानगंज क्षेत्र में खड़न्जा का निर्माण विगत कई वर्षों से नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर खड़न्जा, इंटरलॉकिंग व नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, आगारा द्वारा धन की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार समय–समय पर नाली एवं इण्टरलॉकिंग खड़न्जा निर्माण का कार्य कराया जाता रहता है। सुल्तानगंज क्षेत्र में अभी निकट भविष्य में ठाकुर भोजनालय के पीछे गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग फर्श का कार्य कराया गया है। यह क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसमें सभी गलियां व मार्ग पूर्व से निर्मित हैं। कच्चा भाग नहीं है। क्षतिग्रस्त मार्गों की आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धता के आधार पर मरम्मत कराई जाती रहती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण किये जाने के कारण यातायात ठीक करने के लिये अतिक्रमणों को हटवाया जाना

79–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण किये जाने के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह बाधित रहने से घण्टों जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा की मुख्य सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम द्वारा नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों यथा एम0जी0 रोड, एम0जी0 रोड–2, वी0आई0पी0 रोड (माल रोड), जमुना किनारा रोड व नेशनल हाईवे आदि पर होने वाले अस्थाई अतिक्रमण को समय–समय पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटवाया जाता है। वर्तमान में वाटर वर्क्स चौराहे नेशनल हाईवे–2 पर फ्लाई–ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण ट्रैफिक डायवर्ट किये जाने के कारण जाम की स्थिति बन जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर निगमों में स्थापित सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बन्द होने की शिकायत शीघ्र चालू कराया जाना

80–डा0 अरूण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के कितने नगर निगमों में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्थापित है तथा उनमें से कितने कार्यशील है ? क्या सरकार बन्द पड़े प्रोजेक्ट को शीघ्र कार्यशील करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश के 11 नगर निगमों के लिये सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की परियोजनायें स्वीकृत हैं, जिनमें से 04 नगर निगमों–कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ व बरेली में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्थापित हैं। इनमें से कानपुर, मुरादाबाद व बरेली के स्थापित प्रोजेक्ट संचालन हेतु सम्बन्धित नगर निगम को हस्तगत कराये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम, आगरा एवं इलाहाबाद के सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। स्थापित प्रोजेक्ट का संचालन सम्बन्धित नगर निगम के पर्यवेक्षण में अनुबन्धित कन्सेशनायर द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में अलीगढ़ सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आंशिक रूप से कार्यरत हैं एवं इलाहाबाद सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का संचालन नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जबकि अन्य प्रोजेक्ट्स विभिन्न कारणों से क्रियाशील नहीं हैं।

जी हां।

सम्बन्धित नगर निगमों द्वारा अनुबन्ध की शर्तों एवं वैधानिक पहलुओं का अध्ययन करके यथाशीघ्र प्रोजेक्ट क्रियाशील कराये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रत्येक थाने में भार साधक पदाधिकारी के स्थान पर पुलिस निरीक्षक स्तर के कर्मचारी की नियुक्ति का निर्णय लेने विषयक

81–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक थाने में भार साधक पदाधिकारी के स्थान पर पुलिस निरीक्षक स्तर के कर्मचारी की नियुक्ति का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो यह कब तक क्रियान्वित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

शासनादेश संख्या–3888/6–पु–1–13–135/2013, दिनांक 07–02–2014 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल थानों के 2/3 थानों पर निरीक्षक तथा 1/3 थानों पर उप निरीक्षक को थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है, तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु पुलिस महानिदेशक स्तर से समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अतिसंवेदनशील शहर अलीगढ़ में मानक के अनुरूप पर्याप्त पुलिस बल तैनात कराने विषयक

82–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अतिसंवेदनशील शहर अलीगढ़ में मानक के अनुरूप पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

रिक्तियों की पूर्ति हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। जैसे–जैसे भर्ती बोर्ड द्वारा चयनोपरान्त आरक्षी उपलब्ध कराये जायेंगे, तद्नुसार प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें आवश्यकतानुसार तैनात करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय उ0प्र0 के कर्मियों को दैनिक समाचार पत्र की सुविधा की निर्धारित राशि वेतन के साथ दिये जाने सम्बन्धी विवरण

83–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सचिवालय के अधिकांश कार्मिकों को प्रतिदिन एक दैनिक समाचार पत्र की सुविधा प्राप्त है ? यदि हां, तो जिन कार्मिकों को दैनिक समाचार पत्र की सुविधा प्राप्त है, क्या सरकार उन्हें प्रत्येक माह अखबार की कीमत की एक निर्धारित राशि उनके वेतन के साथ देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय में कार्यरत समीक्षा अधिकारी समकक्ष पद सहित समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों को समाचार–पत्र की सुविधा क्रमशः कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–3355/बीस–7–वि–2008– 9बी0पी0(6)/2005 दिनांक 21–08–2008 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–01/बीस–7–वि0–2009 (5)/2008 दिनांक 09–01–2009 द्वारा इस शर्त के अधीन प्रदान की गई थी कि दैनिक समाचार पत्र सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वयं क्रय किया जायेगा तथा मासिक आधार पर सत्यापित देयक भुगतान हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर कुल मूल्य के सापेक्ष अनुमन्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कार्मिक को उनके शाखा अधिष्ठान द्वारा की जायेगी। उक्त प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि को वेतन के साथ इसलिये जोड़ा नहीं जा सकता है कि इसकी धनराशि परिवर्तित होती रहती है।

कानपुर नगर निगम के वार्ड नं0 19 सीताराम नगर अहिरवां में मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने से पुनः मरम्मत कराने सम्बन्धी

84–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम के वार्ड नं0 19 सीताराम नगर अहिरवां में म0नं0 600/1डी श्री राजकुमार कुशवाहा के घर से मवैया मोड़ तक मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वार्ड नं0–19 सीताराम नगर अहिरवां में म0नं0–600/1डी श्री राज कुमार कुशवाहा के मकान से मवईया मोड तक क्षेत्र निजी सोसाइटी क्षेत्र है। शासनादेश सं0 050979–अ–3–2001 (अ0व0) दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाईटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास कार्य का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर निगम के वार्ड नं0 19 अहिरवां में श्री इन्द्रपाल के घर से श्री राकेश कुशवाहा के घर तक सीवर लाइन डालने के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

85–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम के वार्ड नं0 19 अहिरवां में श्री इन्द्रपाल के घर से श्री राकेश कुशवाहा के घर तक का मार्ग जे0एन0एन0आर0 यू0एम0 योजनान्तर्गत सीवर लाइन डालने से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। आंशिक रूप से।

जिस भाग में सीवर लाइन डाली गई है, उसकी मरम्मत करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के दयालबाग क्षेत्र में श्री अमित गोयल के मकान 12ए जयराम बाग गेट बन्द कालोनी से लेकर श्री हरीओम सिंघल के मकान तक जर्जर सी0सी0 रोड का निर्माण

86–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के दयालबाग क्षेत्र में श्री अमित गोयल के मकान 12ए जयराम बाग गेट बन्द कालोनी से लेकर श्री हरीओम सिंघल के मकान तक दयालबाग में सी0सी0 रोड विगत कई वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सी0सी0 सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

हॉटमिक्स प्लाण्ट से सड़क सुधार कार्य का आगणन तैयार किया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

87–श्री रामचन्द्र यादव–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद शामली के कैराना नगर में रंगदारी के लिये हुई वर्ष 2014–15 में व्यापारियों की हत्या, पीड़ित परिवारों की आर्थिक सहायता दिया जाना

88–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014–15 में जनपद शामली के कैराना नगर में रंगदारी के लिये हुई व्यापारियों की हत्या सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित परिवारों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद शामली के कस्बा कैराना में रंगदारी के लिये वर्ष 2014–15 में हुई 03 व्यापारियों की हत्या के सम्बन्ध में जिलाधिकारी शामली को मुख्य मंत्री राहत कोष से एक–एक लाख रुपये अर्थात् कुल 03 लाख रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता दिनांक 27–10–2014 को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर निगम के वार्ड नं0 19 अहिरवां में म0नं0 20 से श्री अरविन्द सविता के मकान आदि की कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराया जाना

89–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम के वार्ड नं0–19 अहिरवां में म0नं0 20 से श्री अरविन्द सविता के मकान तक एवं जी0टी0 रोड से कुलगांव तक एवं वार्ड नं0 39 में दलनपुर से लाल एवं तबधकपुर तक के मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत मार्गों के मरम्मत का व्ययानुमान तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के महाराजपुर क्षेत्र स्थित सेमरझाल से टिकरा चौहान तक एवं तिवारीपुर से बड़ागांव मुख्य रूप से पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने से मार्ग का मरम्मत कराया जाना

90–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के महाराजपुर क्षेत्र स्थित सेमरझाल से टिकरा चौहान तक एवं तिवारीपुर से बड़ागांव मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कानपुर महानगर के महाराजपुर क्षेत्र स्थित सेमर झाल से टिकरा चौहान तक एवं तिवारीपुर से बड़ागांव मुख्य मार्ग नगर निगम कानपुर की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली महानगर के अन्तर्गत राष्ट्रीय गंगा वैंशन प्राधिकरण की एन0जी0आर0बी0ए0 योजनान्तर्गत टूटी हुई सीवर लाइन को बदलने हेतु डी0पी0आर0 तैयार करके कार्य शुरू कराया जाना

91–डा0 अरूण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय गंगा वेंशन प्राधिकरण की एन0जी0आर0वी0ए0 योजनान्तर्गत बरेली महानगर की टूटी हुई सीवर लाइन को बदलवाने का डी0पी0आर0 तैयार हो गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित/विरचित की जाने वाली परियोजना के अन्तर्गत बरेली महानगर की टूटी सीवर लाइन बदलवाने का कार्य प्रस्तावित नहीं है। बरेली महानगर में नई सीवर लाइन बिछाने हेतु डी0पी0आर0 बनाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में योजना के विरचन हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इस योजना का विरचन माह मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

कानपुर महानगर के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0 19 सनगवां क्षेत्र के अहिरवां में म0 नं0 001 श्री बंदी लाल कुशवाहा के घर आदि की क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण

92–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0 19 सनगवां क्षेत्र के अहिरवां में म0 नं0 001 श्री बंदी लाल कुशवाहा के घर से म0 नं0 20 श्री सुशील कुशवाहा के घर तक मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत मार्गों के मरम्मत का व्ययानुमान तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत श्याम नगर बाई पास चौराहा से यशोदा नगर बाई पास चौराहे के मध्य कानपुर विकास प्राधिकरण कालोनी गंगापुर आदि मार्गों को मरम्मत कराया जाना

93–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत श्याम नगर बाई पास चौराहा से यशोदा नगर बाई पास चौराहे के मध्य कानपुर विकास प्राधिकरण कालोनी गंगापुर, आवास विकास परिषद की ओर यशोदा नगर की ओर से जाने वाला मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्याम नगर बाईपास चौराहे से यशोदा नगर बाईपास चौराहे के मध्य कानपुर विकास प्राधिकरण कालोनी गंगापुर में मुख्य मार्ग (मन्दिर से कुशवाहा आटा चक्की तक) कार्य की निविदा इत्यादि की कार्यवाही करा ली गई है तथा कार्य शीघ्र आरम्भ किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत हरि बिल्डिंग से शंकराचार्य नगर चौराहा होते हुये यशोदा नगर मुख्य मार्ग के निर्माण का प्रकरण

94–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत हरि बिल्डिंग से शंकराचार्य नगर चौराहा होते हुये यशोदा नगर मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

हरी बिल्डिंग से शंकराचार्य नगर चौराहा होते हुए यशोदा नगर मुख्य मार्ग क्षेत्र निजी सोसायटी क्षेत्र है। शासनादेश सं0–05097/9–अ–3–2001 (अ0व0) दिनांक 26–5–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास कार्य का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

इण्डिया मार्का–ॠ हैण्ड पम्प में स्वच्छ पानी न मिलने से हो रहे संक्रामक रोग के निदान विषयक स0वि0स0 का पत्र अब तक हुई कार्यवाही की जानकारी

95–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्डिया मार्का–ष्प हैण्ड पम्प में स्वच्छ पानी न मिलने से हो रहे संक्रामक रोग के निदान विषयक श्री जमीर उल्लाह खां, विधायक का पत्र दिनांक 10–10–2014 जो प्रबन्ध निदेशक/यू0पी0 एग्रो जल निगम व मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर को सम्बोधित हैं उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। श्री जमीर उल्लाह खां, मा0 सदस्य, विधान सभा, 75 कोल जिला अलीगढ़ का पत्र दिनांक 10–10–2014 प्राप्त हुआ है, जिसमें गत वित्तीय वर्ष में सदस्य, विधान सभा के कोटे से यू0पी0 एग्रो कानपुर द्वारा आवास संख्या–494/2, शास्त्री नगर, कानपुर में अधिष्ठापित कराये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प से स्वच्छ पानी प्राप्त न होने एवं उससे निकले पानी को पीकर लोगों को संक्रामक बीमारी होने के सम्बन्ध में लिखा गया है। उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु यू0पी0 एग्रो कानपुर को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

मा0 श्री मुसर्रत अली, विधायक, बिल्सी, बदायूं के परिवार के चरित्र प्रमाण–पत्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

96–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं को सम्बोधित, मा0 नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–22/ने0वि0द0/2015, दिनांक 07–01–2015, जो मा0 मुसर्रत अली, विधायक, बिल्सी, बदायूं के परिवार के चरित्र प्रमाण–पत्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

श्री मुसर्रत अली, मा0 विधायक, बिल्सी व उनके परिवार के 06 चरित्र प्रमाण–पत्र बनवाये जाने हेतु आवेदन–पत्र जिलाधिकारी बदायूं कार्यालय से दिनांक 07–08–14 को पुलिस कार्यालय बदायूं में प्राप्त हुए। समस्त चरित्र प्रमाण–पत्रों की जांच कराकर दिनांक 23–01–15 को जिलाधिकारी कार्यालय जनपद बदायूं वापस संदर्भित किये गये थे। तत्क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय, बदायूं द्वारा आवेदकों पर दर्ज अभियोगों की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी चाही गई थी। उक्त सभी आवेदकगणों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में दोषमुक्त होने के फलस्वरूप समस्त चरित्र प्रमाण–पत्र संस्तुति सहित दिनांक 20–02–15 को कार्यालय जिलाधिकारी, बदायूं को प्राप्त कराये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगरों में सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को रोकने की नीति तथा प्रभावी कार्यवाही की जानकारी

97–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों में सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को रोकने की क्या नीति है ? क्या सरकार इन आवारा पशुओं को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नागर निकायों द्वारा अपने संसाधनों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही की जाती है तथा शिकायत प्राप्त होने पर भी आवारा पशुओं को पकड़ कर कांजी हाउस में बन्द किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के मऊ में कालिन्दीपुरम् तक, हनुमान मन्दिर चौराहे से खन्दारी पुलिस चौकी तक एवं बोदला से विचपुरी आदि की नाली खण्डन्जा व सी0सी0 सड़कों की मरम्मत किया जाना

98–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के मऊ में कालिन्दीपुरम् तक, हनुमान मन्दिर चौराहे से खन्दारी पुलिस चौकी तक एवं बोदला से विचपुरी रोड (एम0जी0 रोड–2) पर मयूर गैस गोदाम के सामने इन्द्रप्रस्थ कालोनी में नाली, खड़न्जा व सी0सी0 रोड विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली, खड़न्जा व सी0सी0 सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत सड़कों में मऊ से कालिन्दीपुरम् तक की सड़क का निर्माण आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा कराया जा चुका है।

हनुमान मन्दिर चौराहे से खन्दारी पुलिस चौकी तक की सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसको पैच वर्क द्वारा ठीक कराया जा रहा है।

बोदला से बिचपुरी रोड (एम0जी0 रोड–2) मयूर गैस गोदाम के सामने इन्द्रप्रस्थ कालोनी नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नहीं आती है।

उपरोक्तानुसार।

समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी के ग्रेड पे में वेतन विसंगति का प्रकरण

99–डा0 अरूण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वैभागिक आदेश सं0 580/39/88, दिनांक 19–04–12 द्वारा समीक्षा अधिकारी का ग्रेड पे दिनांक 22–12–11 से रु0 4600/– से बढ़ाकर रु0 4800/– किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सहायक समीक्षा अधिकारी का ग्रेड पे दिनांक 27–11–2009 से रु0 2800/– से बढ़ाकर रु0 4200/– तथा वैभागिक आदेश सं0 1533/39/08, दिनांक 26–12–2013 द्वारा रु0 4200/– से बढ़ाकर रु0 4600/– किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब सहायक समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी के ग्रेड पे में मात्र रु0 200/– का अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर करने हेतु समीक्षा अधिकारी को ग्रेड पे0 रु0 4800/– के स्थान पर 5400/– दि0 22–12–2011 से करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सन्दर्भित आदेश दिनांक 19–4–2012 से नहीं बल्कि सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1 (अधि0) के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2065/बीस–1–ई–2011–516/96 टी0सी0–7 (सी), दिनांक 22–12–11 द्वारा समीक्षा अधिकारी के लिये सचिवालय भत्ते में रु0 200/– के सचिवालय भत्ते के अंश को ग्रेड वेतन में परिवर्तित करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4600/– के स्थान पर रु0 4800/– दिनांक 22–12–2011 से अनुमन्य कराया गया है।

जी हां। सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1819/बीस–1–ई–2013–603 (15)/08 टी0सी0–5, दिनांक 06–09–2013 द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ता रु0 850/– में से रु0 400/– के सचिवालय विशेष भत्ते के अंश को ग्रेड वेतन में परिवर्तित करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4200/– के स्थान पर संशोधित ग्रेड वेतन रु0 4600/– दिनांक 06–09–2013 से अनुमन्य किया गया है।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–लखनऊ की राज्य सम्पत्ति कालोनी, एल0 के0 एस0 टाइप–2 अलीगंज में सड़कें, नाली तथा विद्युत पोलों को ठीक कराने विषयक

100–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखनऊ की राज्य सम्पत्ति कालोनी, एल0 के0 एस0 टाइप–2 अलीगंज में सड़कें, नाली तथा विद्युत पोलों की स्थिति अत्यन्त खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कालोनी की सड़कें, नाली, विद्युत पोलों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन आने वाली राजकीय कालोनियों की आन्तरिक सड़कों, नालियों तथा विद्युत पोलों आदि का रख–रखाव राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लोक निर्माण विभाग, अनुरक्षण खण्ड–1 (सिविल/विद्युत) द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में प्रकाश बिन्दु प्रज्ज्वलित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मऊ के थाना मधुवन में दर्ज एफ0आई0आर0 के प्रकरण की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 अथवा एस0टी0एफ0 एजेन्सी से कराने विषयक नेता विरोधी दल का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सम्बोधित, मा0 नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–1327/ने0वि0द0/2014, दिनांक 24–12–2014, जो जिला–मऊ के थाना–मधुबन में दर्ज मु0अ0सं0–439/2014 अ0धारा–386, 507 आई0पी0सी0 की जांच जनहित में सी0बी0सी0आई0डी0 अथवा एस0टी0एफ0 एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–इलाहाबाद के अन्तर्गत नेवादा चौराहा से बर्दनी होते हुये गोविन्दपुर चौक चौराहा तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक

102–श्री अली युसुफ अली–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के अन्तर्गत नेवादा चौराहा से बर्दनी होते हुये गोविन्दपुर चौक चौराहा तक (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत नेवादा चौराहा से बर्दनी होते हुए गोविन्दपुरा चौक चौराहा नगर निगम, इलाहाबाद सीमान्तर्गत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जिला बलिया के थाना नगरा के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 अथवा स्वतंत्र एजेन्सी से कराये जाने विषयक नेता विरोधी दल का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

103–श्री अली युसुफ अली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–30/ने0वि0द0/ 2104, दिनांक 08–01–2015, जो जिला–बलिया के थाना–नगरा के अन्तर्गत दर्ज मु0 अ0सं0–393/2014 अ0 धारा–302, 380, 511 आई0पी0सी0 की जांच जनहित में सी0बी0सी0आई0डी0 अथवा स्वतंत्र एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हो, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, रसड़ा, बलिया से कराई गई। प्रश्नगत मामले में आरोप–पत्र दिनांक 25–11–14 को मा0 न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है, जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण की जांच अन्य एजेन्सी से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में मुख्य सड़कों पर स्थित तोता का ताल का कब्रिस्तान के बाहर, सदर भट्टी से मंटोला होते हुये बिजली घर रेलवे पुल आदि स्थानों पर जानवरों को काटकर व पकाकर मांस बेचने से फैल रही गन्दगी के कारण मीट मार्केटों को हटाया जाना

104–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मुख्य सड़कों पर स्थित तोता का ताल का कब्रिस्तान के बाहर, सदर भट्टी से मंटोला होते हुये बिजली घर रेलवे पुल तक तथा नौबस्ता चौराहा से हिजड़ों की मस्जिद तक स्थित मार्केट में खुले में ही जानवरों को काटकर व पकाकर मांस बेचा जाता है, जिससे गंदगी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों से मीट मार्केटों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त क्षेत्र में बनी मीट/मांस की दुकानों को विगत 15 वर्षों से अधिक समय से अनुज्ञप्ति जारी की जा रही है। नगर निगम द्वारा समय–समय पर मीट/मांस की दुकानों पर गन्दगी पाये जाने पर 148 दुकानों के चालान किये गये हैं। नगर निगम द्वारा अवैध मीट/मांस की दुकान पाये जाने पर तत्काल दुकानदार का चालान करते हुए दुकान बन्द कराई जाती है।

उपरोक्तानुसार।

आगरा के आवास विकास कालोनी, सेक्टर–1 में भवन संख्या–7, 27 व 76 डलाव घर के पास की जर्जर पुलिया को ठीक कराया जाना

105–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के आवास विकास कालोनी, सेक्टर–1 में भवन संख्या–7, 27 व 76 डलाव घर के पास पुलिया विगत कई वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

पुलिया क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत पुलिया का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

106–श्री जय प्रकाश अंचल–

खले बुधवार के अता0प्र0सं0–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में वर्ष 2014–2015 में हुए कुल धर्मान्तरण के मामलों की जानकारी तथा रोकथाम की योजना की जानकारी

107–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014–2015 में प्रदेश में कुल कितने धर्मान्तरण के मामले प्रकाश में आये हैं ? क्या सरकार द्वारा उक्त की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में वर्ष 2014–2015 में धर्मान्तरण का एक मामला प्रकाश में आया है जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0–68/14 धारा 153क (बी)/415/417 भा0द0वि0 थाना–सदर, आगरा में दिनांक 09–12–2014 को वादी श्री इस्माइल की सूचना पर नन्द किशोर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त नन्द किशोर उर्फ किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। प्रश्नगत मामले में विधिक अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 15–12–2014 द्वारा समस्त वरिष्ठ एवं जनपदीय अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रलोभन, दबाव अथवा विधि विपरीत कारणों से धर्मान्तरण की कार्यवाही को गम्भीरता से लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि किसी भी रूप में अराजक तत्व अपने इस उद्देश्य में सफल न हो सकें। इसके लिये आवश्यक है कि पुलिस तथा प्रशासन पूर्णरूप से सजग एवं सतर्क रहे तथा अपने अभिसूना तंत्र को जागरूक रखे। वरिष्ठ अधिकारी खुफिया तंत्र ने फीडबैक लेते हुए स्वयं स्थिति का आंकलन करें और यदि किसी व्यक्ति या समूह के इस प्रकार की असंवैधानिक घटनाओं में लिप्त होने की सूचना प्राप्त होती है, तो उसके विरुद्ध

कठोरतम कार्यवाही की जाय। जनपद में चिन्हित अराजकतत्वों पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाय।

उपरोक्तानुसार।

आगरा दयाल बाग के प्रगतिपुरम् में विगत कई वर्षों से टूटी पुलिया का पुनर्निर्माण कराया जाना

108–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा दयाल बाग के प्रगतिपुरम् में विगत कई वर्षों से टूटी पुलिया जर्जर होकर ध्वस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वर्तमान में प्रगतिपुरम् में कोई क्षतिग्रस्त पुलिया नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दयालबाग के प्रगतिपुरम् की टूटी पुलिया का निर्माण पूर्व में नगर निगम, आगरा द्वारा कराया जा चुका है।

आगरा में मलिन बस्ती रंधीर नगर कालोनी, दयालबाग की एम0पी0टी0 स्कूल से ट्रान्सफार्मर तक की नाली, सड़क की मरम्मत कराया जाना

109–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मलिन बस्ती रंधीर नगर कालोनी, दयालबाग की एम0पी0टी0 स्कूल से ट्रान्सफार्मर तक की नाली, सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त क्षेत्र का निरीक्षण नगर निगम, आगरा के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया गया है। सड़क क्षतिग्रस्त है।

सड़क एवं नाली का निर्माण हॉटमिक्स प्लाण्ट से कराने हेतु आगणन तैयार किया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर में मनीष नगर मलिन बस्ती में वासन फैक्टरी के बराबर 250 मी0 तक की जर्जर गड्ढायुक्त सड़क का निर्माण कराया जाना

110–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में मनीष नगर मलिन बस्ती में वासन फैक्टरी के बराबर 250 मी0 की सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर व गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सी0सी0 सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत सड़क के निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

111–श्री त्रिभुवन राम–

ख्ाले बुधवार के अता0प्र0सं0–184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बलिया के बैरिया में सी0ओ0 की तैनाती हेतु कार्यालय, आवास आदि का निर्माण कराया जाना

112–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया जो बिहार प्रान्त से लगा हुआ है के बैरिया में सी0ओ0 की तैनाती की गयी किन्तु कार्यालय एवं सी0ओ0 आवास का निर्माण न होने के कारण उन्हें दूसरे विभाग के भवन में अपना कार्यालय व आवास बनाकर रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में सी0ओ0 के लिये आवास एवं कार्यालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासनादेश संख्या–793/6–पु–7–2014–4(5)/2014, दिनांक 05–12–2014 द्वारा क्षेत्राधिकारी, बैरिया के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रु0 26.08 लाख एवं शासनादेश संख्या–3648/6–पु–7–2014–4(4)/2014, दिनांक 12–12–2014 द्वारा क्षेत्राधिकारी बैरिया के आवास निर्माण हेतु रु0 37.15 लाख की स्वीकृति निर्माण इकाई उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 के पक्ष में जारी की गई है, जिसका भुगतान निर्माण इकाई को भेजा जा चुका है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने की कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के अन्तर्गत थाना बैरिया व ऊंभाव की बिल्डिंग व उसमें बने सरकारी आवासों का मरम्मत कराया जाना

113–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत थाना बैरिया व ऊंभाव की बिल्डिंग व उसमें बने सरकारी आवासों की स्थिति जर्जर है ? यदि हां, तो ? क्या सरकार आगणन मंगाकर दोनों थानों के भवनों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

आगणन मंगाकर दोनों थानों के भवनों की मरम्मत शीघ्र कराने हेतु धनावंटन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहारदीवारी बनाने की योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में बनाई गई चहारदीवारी बनकर पूर्ण की जानकारी

114–श्री सुरेश राणा–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहारदीवारी बनाने की योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में कितने कब्रिस्तानों एवं अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2013–14 में 975 कब्रिस्तानों एवं अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी पूर्ण की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर स्थित वार्ड नं0–19 सनगवां चकेरी हवाई अड्डा गेट के बगल म0नं0–27ए प्रजा विहार आदि के जर्जर सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाना

115–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर स्थित वार्ड नं0–19 सनगवां चकेरी हवाई अड्डा गेट के बगल म0नं0–27ए प्रजा विहार से म0नं0 499 तक सम्पर्क मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाइटियों के विनियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास कार्य का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तानों की चहारदीवारी बनाये जाने विषयक

116–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कितने कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण हो चुका है और कितने शेष रह गये हैं ? शेष कब्रिस्तानों की चहारदीवारी कराये जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजनान्तर्गत जिला कार्यान्वयन/चयन समिति द्वारा जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में 23 कब्रिस्तानों को चिन्हित कियाग या है, जिसके सापेक्ष 01 कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण है, 05 पर कार्य निर्माणाधीन हैं तथा 17 पर कार्य अनारम्भ है।

जी हां।

मेरठ के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में हापुड़ रोड पर ग्राम जाहिदपुर के सामने बख्शी दास इण्टर कालेज के पास शहर का सारा कूड़ा–कचरा डालने से फैल रही दुर्गन्ध को देखते हुए रोकने की व्यवस्था कराने सम्बन्धी

117–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में हापुड़ रोड पर ग्राम जाहिदपुर के सामने बख्शी दास इण्टर कालेज के पास शहर का सारा कूड़ा कचरा डालने से इण्टर कालेज में पढ़ने आने वाले छात्रों एवं उसकी दुर्गन्ध से पास–पड़ोस के इलाके में नागरिकों का रहना दूभर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां कूड़ा करकट डालने से रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरठ महानगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में हापुड़ रोड पर ग्राम जाहिदपुर के सामने बख्शी दास इण्टर कालेज से लगभग 500 मीटर दूर कूड़ा भट्ठे की जमीन में डाला जा रहा था, जिसे माह दिसम्बर, 2014 से बन्द कर दिया गया है। माह दिसम्बर, 2014 से शहर का कूड़ा धनी आबादी से दूर कूड़ा निस्तारण हेतु नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि किला परीक्षतगढ़ रोड स्थित ग्राम जलालुद्दीन मसूदपुर उर्फ गांवड़ी में डम्पिंग किया जा रहा है।

प्रदेश में लोअर जुडीशियरी में मुंसिफ तथा दीवानी न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों को भरा जाना

118–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोअर जुडीशियरी में मुंसिफ तथा दीवानी न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां, सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली जनपद के फतेहगंज में मकर संक्रान्ति पर्व के अवसर पर दो संप्रदायों के बीच हुए संघर्ष में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

119–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद के फतेहगंज में मकर संक्रान्ति पर्व के अवसर पर दिनांक 14–01–2014 को दो संप्रदायों के बीच संघर्ष हुआ ? यदि हां, तो संघर्ष के क्या कारण थे और इसमें कितने लोग घायल हुये ? सरकार द्वारा इसमें अभी तक क्या–क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

दिनांक 14–01–15 को मो0 माली फतेहगंज पश्चिम में पशु अवशेष मिलने के बाद एक समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन एवं हाई–वे जाम कर दिया गया था तथा श्री राजेश अग्रवाल पुत्र मुरारी लाल की तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने पर अपराध सं0–10/15 धारा–3/5/8 गोवध अधिनियम व 295क भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जनपद पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही/पतारसी–सुरागरसी करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, तथापि कतिपय अराजकतत्वों द्वारा दिनांक 15–01–15 को सुबह 10.00 बजे से ही पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू कर दिया जिससे चौकी पर खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गये तथा करीब एक दर्जन पुलिस कर्मी घायल हो गये।

उक्त के सम्बन्ध में थाना हाजा पर अपराध सं0–11/15 व 12/15 धारा 147, 148, 149, 307, 332, 336, 342, 504, 506, 427 भादवि व 7 क्रि0 ऐक्ट लॉ अमेंडमेंट अधिनियम बनाम चक्रवीर चौहान आदि 500 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसमें अब तक 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

जनपद झांसी के बरुआसागर बेतवा नदी में लावारिश लाश तथा शव विसर्जन के कारण वहां का पीने योग्य पानी खराब हो जाने से झांसी शहर के मध्य स्थित मुक्ति धाम में शव विसर्जन हेतु विद्युत शव गृह स्थापित कराने विषयक

120–श्री रवि शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में झांसी के बरूआसागर बेतवानदी में लावारिश मानव–शवों के जल प्रवाह का विषय प्रकाश में आया है ? क्या यह सही है कि उक्त नदी का जल पीने के पानी के रूप में प्रयोग में आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी में शव विसर्जन पर रोक लगाते हुये झांसी शहर के मध्य स्थित मुक्तिधाम (शवदाह गृह) में विद्युत शवदाह गृह स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

बेतवा नदी में शवों के प्रवाह का विषय पूर्व में प्रकाश में आया था लेकिन वर्तमान में शवों का जल प्रवाह नहीं हो रहा है।

जी हां। नदी से कच्चा जल लेकर शोधन प्रक्रिया के उपरान्त जलापूर्ति की जाती है। जलापूर्ति के पूर्व जल की नियमित गुणवत्ता की जांच भी कराई जाती है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत यू0डी0आई0एस0एम0टी0 कार्यान्श से वर्ष 2006–2007 में अनुमानित लागत की नगर निगम झांसी हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की शिथिलता के कारण लगाये गये अर्थदण्ड दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

121–श्री रवि शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत यू0डी0आई0एस0एम0टी0 कार्यान्श से वर्ष 2006–07 में अनुमानित लागत रु0 1216.00 लाख की नगर निगम, झांसी हेतु सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की स्वीकृत प्रदान की गयी थी ? क्या यह सही है कि कार्य में शिथिलता के कारण रु0 48.50 लाख का अर्थदण्ड लगाया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही के उपरान्त नागरिकों को उस योजना का लाभ कब तक प्राप्त हो सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

चयनित कन्सेशनायर मेसर्स यू0पी0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा कार्यों में शिथिलता के फलस्वरूप दोषी फर्म के साथ निष्पादित कन्सेशन अनुबन्ध निरस्त करते हुए फर्म की परफार्मेंस बैंक गारण्टी रु0 130.00 लाख को जब्त कर लिया गया है। वैकल्पिक कन्सेशनायर के चयन हेतु नये सिरे से निविदा आमंत्रणा प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए नागरिकों को इस योजना का लाभ अक्टूबर, 2016 तक प्राप्त कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की ए0डी0ए0 कालोनी एवं आई0टी0आई0 कालोनी नैनी की सड़कें एवं नालियों की समुचित सफाई कराने विषयक

122–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की ए0डी0ए0 कालोनी एवं आई0टी0आई0 कालोनी नैनी की सड़कें एवं नालियां अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं तथा वहां स्थित नाली की समुचित सफाई न होने के कारण पूर्णतया भर गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करवाकर नाली की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की ए0डी0ए0 कालोनी एवं आई0टी0आई0 कालोनी नैनी नगर निगम इलाहाबाद सीमान्तर्गत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक डिलारी के ग्राम सिहाली खादर में एम0एस0डी0पी0 योजना अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में दो इण्टर कालेजों का निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाना

123–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक डिलारी के ग्राम सिहाली खादर में एम0एस0डी0पी0 योजना अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में दो इण्टर कालेज स्वीकृत हुए थे परन्तु अब तक उक्त दोनों कालेजों का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों इण्टर कालेजों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड डिलारी में स्वीकृत 02 राजकीय इण्टर कालेजों में से विकास खण्ड डिलारी के राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा सिहाली खादर में स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि का विवाद था, जिसका निराकरण करा लिया गया है तथा शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–कासगंज, विधान सभा क्षेत्र अमांपुर में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत स्वीकृत सहावर से सोरों मार्ग का निर्माण पूरा कराया जाना

124–श्री ममतेश शाक्य–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अमांपुर, जनपद–कासगंज में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत स्वीकृत सहावर से सोरों मार्ग के निर्माण में लगभग 10 कि0मी0 लम्बी सड़क को खोदकर पत्थर डाल दिया गया है जिससे नागरिकों को आने–जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

सड़क का निर्माण कार्य प्रगति में है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देने हेतु प्रस्ताव लाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

अब नियम–301 की सूचनायें ले लेने दीजिए।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल की ओर से प्रस्ताव..

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है यह विधान मण्डल दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों की आम सहमति से आपस में बात करके होता है.... (व्यवधान) आप तो नेता हैं आपको मालूम होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन की आम सहमति से प्रस्ताव जाता है आपके प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर–

मैं भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आप बैठिए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

(श्री प्रदीप माथुर एवं श्री अखिलेश प्रताप सिंह दोनों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी जा रही है जब नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आपस में सहमत हो जाएंगे तो प्रस्ताव रखा जाएगा। अब आपका लिखा नहीं जाएगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए। व्यवस्था यह है कि 20 प्रश्न प्रश्नकाल में लिए जा सकते हैं अल्पसूचित प्रश्न और तारांकित प्रश्न, बारह प्रश्न आज लगे थे। हम दोनों पक्षों की बात रख रहे हैं बड़ी मुश्किल से प्रश्न आते हैं आज सात–आठ प्रश्न ही आ पाए। आप ऐसी व्यवस्था बनायें कि सारे प्रश्न आ जाएं। प्रश्न जो लोग पूछते हैं वह प्रश्न कम पूछते हैं भाषण ज्यादा देते हैं और जवाब में भी भाषण का ज्यादा रूप आता है तो

व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जितने प्रश्न लगे हों उनके अनुपूरक प्रश्न पूछने का सबको अवसर प्रदान हो जाए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से प्रश्न लगते हैं बड़ी तैयारी से विपक्ष के लोग आते हैं इसमें संरक्षण चाहते हैं जैसे आज चार–पांच प्रश्न रह गए तो भविष्य में जितने प्रश्न आप लगाएं उतने आ जाएं हम यही संरक्षण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

देखिए मेरा हमेशा प्रयास यह रहता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाएं और आप देखते भी होंगे कि मैं बीच में टोकता भी हूं केवल सीधे प्रश्नों पर आइए लेकिन यह लोग इस तरह से करते हैं हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्न आ जाया करें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, पहले दो प्रश्न में 40–42 मिनट लगे थे। हमारा अनुरोध यही था कि सबको अवसर मिल जाए अनुपूरक प्रश्न का जबाव आ जाए। हम इसी पर व्यवस्था चाहते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी जो प्रश्न नहीं आ सका जो गृह विभाग से संबंधित था उसमें, सतीश महाना जी, हमारी पार्टी के हैं हमारे प्रिय हैं, लेकिन एक सवाल है कि मूल प्रश्नकर्ता मैं था और मेरे प्रश्न का उत्तर वही आया है जो वरवेटम प्रश्न मैंने दिया था और ऐसा हो नहीं सकता है कि दो–तीन मा0 सदस्य हूबहू वही प्रश्न दे दें। मान्यवर, ऐसा नहीं हो सकता कि दो–तीन सदस्य हूबहू वही शब्द के प्रश्न दे दें। मेरा प्रश्न यह है कि मैंने वह प्रश्न दिया था पता नहीं कैसे प्रश्न अनुभाग में मेरे प्रश्न को पीछे कर दिया गया और सतीश महाना जी का पता नहीं क्या वहां सम्बन्ध है कि उनका नाम ऊपर कर दिया और दुर्भाग्य से जब आपने पुकारा, आपको मालूम था कि उत्तर आना नहीं है, क्योंकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी पूरा प्रश्न पढ़ रहे थे तो आपने मेरा नाम भी गायब कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है कि तीन नाम थे। पहला नाम पुकारा तो मा0 महाना जी खड़े हो गए। जब समय बचता और अनुपूरक पूछते तो उनके बाद आपको अनुपूरक का मौका मिलता, लेकिन समय खत्म हो गया तो क्या किया जाए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि जितने प्रश्न हैं यदि उनको एक घंटा बीस मिनट में आप डिवाइड कर दीजिये और प्रत्येक प्रश्न को उससे ज्यादा समय मत दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

मैं सहमत हूं, लेकिन सदन इससे सहमत हो जाए। अभी स्पीकर्स कान्फ्रेन्स थी तो हमनें मध्य प्रदेश में पूछा। मध्य प्रदेश में तो यह व्यवस्था है कि केवल जिसका मूल प्रश्न रहता है वही सप्लीमेंट्री करता है दूसरे को अलाऊ नहीं करते।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, चूंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश की राजनीति के लिये नजीर है तो ऐसा बना दें कि टाईम फ्रेम हो जाए और सबका उत्तर आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों पर भी डिपेन्ड करता है। कोई प्रश्न एक ही मिनट में आ जाता है किसी प्रश्न में दस मिनट लग जाता है। कोशिश यह की जाए कि प्रश्नों को अधिक से अधिक लिया जाए। आप लोगों में थोड़ी सदाशयता हो कि तैयार होकर आयें और सीधे मूल प्रश्न पर जो सप्लीमेंट्री बनती है वह करें। यहां सप्लीमेंट्री पूछने के पहले कैसे बनता है उसकी व्याख्या कर डालते हैं। सप्लीमेंट्री एक सेकेण्ड में और उसकी व्याख्या पांच मिनट में, तो इसमें सब लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। नेता विरोधी दल खड़े हो गए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, नेता विरोधी दल का प्रश्न लगाते ही नहीं हैं वह खड़े क्यों हो गए।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल प्रश्न नहीं लगाते, लेकिन उन्हें हर मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, मैं 'दादा' की पीड़ा रखने के लिये खड़ा हूं। जैसाकि उन्होंने कहा कि मेरा नाम छूट गया तो मान्यवर, आपके स्तर से ही जैसे एक प्रश्न में जितने मा0 सदस्यों के नाम हैं एक ही साथ सभी मा0 सदस्यों का नाम यदि पुकार लिया जाए तो किसी भी सदस्य का नाम छूटने का प्रश्न नहीं उठेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप ठीक कह रहे हैं। मैंने पहले भी कई नाम पुकारे। चूंकि महाना जी खड़े हो गए और उत्तर देने की स्थिति आ गई तो दोबारा नाम नहीं आया।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मा0 श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने यह कहा कि मैं प्रश्न अनुभाग में कुछ करके प्रश्न लगवाता हूं। मान्यवर, मैंने जो कुछ भी सीखा है इन्हीं से सीखा है।

ख12.30 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23–2–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री बृजलाल सोनकर की प्रदेश के सीमावर्ती चेक–पोस्टों पर फल–फूल आदि कच्चा माल ढोने वाले वाहनों हेतु अलग से लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में। (स्वीकृत)

दूसरी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रदेश की मण्डी समिति में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पंचम एवं छठा वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में। (स्वीकृत)

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शहजहांपुर के मोहल्ला ककरा में शवों को जलाने के लिये एक व्यवस्थित शवदाहगृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। (स्वीकृत)

चौथी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी महानगर के पौराणिक लक्ष्मीकुण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में। (स्वीकृत)

पांचवी सूचना श्री योगेन्द्र उपाध्याय की जनपद आगरा की कतिपय मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। (स्वीकृत)

छठी सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की है, नहीं हैं।

सातवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में मंडी समिति द्वारा बनाई गई सड़कों की विशेष मरम्मत/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। (स्वीकृत)

आठवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की है, नहीं हैं।

नौवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया की है, यह भी नहीं हैं।

दसवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की है, यह भी नहीं हैं।

ग्यारहीं सूचना श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह की गोरखपुर समेत प्रदेश के समस्त सरकारी अस्पतालों में स्वाइनफ्लू की दवा पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। (स्वीकृत)

बारहवीं सूचना श्री कुंवर कौशल सिंह की है नौतनवां से सोनौली एवं सोनौली से नेपाल के मध्य बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में। (स्वीकृत)

तेरहवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद रायबरेली में मुख्य डलमऊ नहर (ए) में ग्राम धैताली का पुरवा में लिफ्ट पम्प लगाकर सिंचाई की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में। (स्वीकृत)

चौदहवीं सूचना श्री अमरपाल शर्मा की है, यह नहीं हैं।

पन्द्रहवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल जी की है जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। (स्वीकृत)

अब श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की सूचना के स्थान पर श्री ममतेश शाक्य की सूचना ली जाती है। श्री बब्बन सिंह चौहान जी नहीं हैं, इनकी सूचना के स्थान पर ठाकुर दलवीर सिंह की सूचना को ले रहे हैं, क्योंकि पं0 सुदेश शर्मा भी नहीं हैं। श्री राजनारायण सिंह बुधौलिया भी नहीं हैं, क्या पूरन प्रकाश जी हैं ? यह भी नहीं हैं,

बुधौलिया जी के स्थान पर श्री सतीश महाना जी की सूचना लेते हैं। श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की सूचना के स्थान पर श्री सन्त प्रसाद की सूचना ले रहे हैं और श्री अमरपाल शर्मा की जगह पर डा0 अरुण कुमार की सूचना ली जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनार्थ अस्वीकार की गईं :–

पं0 सुदेश शर्मा, श्री पूरन प्रकाश, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री राजीव गुम्बर, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री राम चन्द्र यादव, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री कालीचरण सुमन, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री पंकज मलिक, श्री दलजीत सिंह, श्री मदन चौहान, श्री प्रदीप माथुर, श्री विजय कुमार दुबे, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री रोशनलाल वर्मा और श्री रामहेत भारती।

(सदन की सहमति से सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी मानी गयीं)

प्रदेश के सीमावर्ती चेक–पोस्टों पर फल–फूल आदि कच्चा माल ढोने वाले वाहनों हेतु अलग से लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजलाल सोनकर–

ख्महोदय, उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि प्रदेश की सीमा पर लगे हुए चेक–पोस्टों पर भारी भीड़ और लम्बी कतारों की वजह से कच्चा माल ढोने वाले वाहनों की कागज पत्रों की चेकिंग में काफी समय लगने के कारण धूप में खड़े माल को खराब होने के तथा उनकी मण्डी छूट जाने के कारण व्यवसायियों को लम्बा नुकसान होने की सम्भावना रहती है।

अतः आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि व्यापारियों के व जनता के हित में कच्चा माल ढोने वाले सभी वाहनों की कागज पत्रों की जांच वरीयता के आधार पर करते हुए यथाशीघ्र इन्हें पास करने तथा सम्भव हो तो ऐसे वाहनों के लिये एक अलग चेक–पोस्टों पर लेन–देन अथवा बी0आई0पी0 लेन खाली होने पर उससे निकालने हेतु सम्बन्धित परिवहन/अन्य चेकिंग अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। ऐसे कच्चा माल के उत्पादकों व व्यवसायियों पर महती कृपा होगी।,

प्रदेश की मण्डी समिति में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पंचम एवं छठा वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्महोदय,प्रदेश की विभिन्न मण्डी समितियों में चतुर्थ श्रेणी में चपरासी, चौकीदार, मण्डी अभिरक्षा एवं वाटर मैन की नियुक्ति की गयी थी। यह अत्यन्त दुखद है कि एक ओर तो इन पदों पर नयी नियुक्तियां न होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं और दूसरी तरफ इन चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अभी तक पंचम एवं षष्ठम् वेतनमान न दिये जाने से इन सभी कर्मियों को भीषण कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और इनमें बहुत असन्तोष व्याप्त है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह दुःखद है कि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मी अभी भी 1350–2600 वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, जबकि चतुर्थ श्रेणी को पंचम वेतन में 4500/ तथा षष्ठम् वेतन में 5000–8000 वेतनमान का प्राविधान किया गया है। शासनादेश संख्या–522/80–1–2010–2/98 टी0सी0, दिनांक 13 अप्रैल, 2010 के द्वारा वैयक्तिक वेतनमान तथा समय वेतनमान का अन्तर्विरोध समाप्त करते हुए यह सुस्पष्ट आख्या कर दी गयी है कि यदि समय वेतनमान व्यैक्तिक वेतनमान से होगा तो समय वेतनमान लागू नहीं होगा और यदि समय वेतनमान व्यैक्तिक वेतन से अधिक है तो समय वेतनमान लागू होगा।

मण्डी समिति उत्तर प्रदेश की ओर से इस संवर्ग में 4–5 बार प्रस्ताव शासन को भेजे गये लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर नियम–301 के तहत सरकार को पटल पर रखने के लिये निर्देशित करने की कृपा करें।,

जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला ककरा में शवों को जलाने के लिये एक व्यवस्थित शवदाहगृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्महोदय, शाहजहांपुर नगर के ककरा क्षेत्र में एक शवदाह गृह बनना प्रस्तावित है। लगभग 20,000 लोगों की आबादी जो गरीब व पिछड़े हैं, के लिये कोई शवदाह स्थान नहीं है। बरसों से यहां पर शवों को खुले आसमान के नीचे जलाया जाता है लेकिन उसके लिये कोई न प्लेटफार्म (चबूतरा) है न ही शेड है और न ही ठीक प्रकार की बाउन्ड्री है। इस स्थल को जाने का मार्ग भी कच्चा है। शासन की योजना के अनुसार इसका निर्माण कराया जाना है। नगरपालिका परिषद् शाहजहांपुर की ओर से इसका प्रस्ताव वर्ष 2014 में नगर विकास विभाग को प्राप्त हुआ है लेकिन अभी इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही नहीं बढ़ पायी है। जनहित में शवों को जलाने के लिये एक व्यवस्थित शमशान (शवदाह) स्थल की आवश्यकता है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मोहल्ला ककरा में शवों को जलाने के लिये एक व्यवस्थित शवदाह गृह (शमशान स्थल) का निर्माण शीघ्र कराया जाये।,

वाराणसी महानगर में पौराणिक लक्ष्मीकुण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

ख्महोदय, वाराणसी के महानगर में 'लक्ष्मीकुण्ड' एक बहुत पुरानी व पौराणिक कुण्ड है। इस कुण्ड के किनारे महालक्ष्मी जी का मन्दिर है जहां बड़े पैमाने पर लक्ष्मी जी की पूजन का आयोजन होता है इसके अलावा महिलाओं द्वारा सामूहिक पूजा ललई छठ उत्सव तथा 'सिवरिहा पूजन' बच्चों के लिये होता है। पहले इस कुण्ड की व्यवस्था बहुत

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वैज्ञानिक थी। अन्दर ही अन्दर पाइप के द्वारा पानी को बदलने की व्यवस्था थी। अतः गन्दे पानी के इकट्ठा होने की समस्या नहीं होती थी।

कालान्तर में यह व्यवस्था किसी कारण ध्वस्त हो गई। अब पानी अपने आप बदलती नहीं है सिवरिहा पूजन उत्सव के बाद पानी में मूर्ति विसर्जन होता है। आजकल मूर्तियों में केमिकल मिला रंग लगाई जाती है जिससे विसर्जन के बाद पानी में कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और पाली गई मछलियां मर कर ऊपर बहने लगती हैं जिससे सड़न व दुर्गन्ध पैदा होती है। मछलियों के मरने से नगर निगम को इसकी सफाई करनी पड़ती है।

अतः लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण अति संवेदनशील विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि पहले की तरह लक्ष्मीकुण्ड के अन्दर पानी के बदलाव की व्यवस्था को पुनः पुनर्जीवित किया जा सके क्योंकि लक्ष्मीकुण्ड के प्रति जनता में अथाह श्रद्धा व भक्ति है। अतः इस घनी आबादी वाले हिस्से में लक्ष्मीकुण्ड की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना अति आवश्यक है।,

जनपद आगरा की कतिपय मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

ख्महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा दलित, निर्धन व पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन मलिन बस्तियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां के नागरिक विकास के अभाव में नारकीय जीवन जीने के लिये मजबूर हो गये हैं। आगरा की ऐसी मलिन बस्तियां, गढ़ी भदौरिया, नाथ का बाग, जोन्स मिल, ऐरिया, लंगड़े की चौकी, फ्रीगंज, सिन्धी कालोनी (अशोक नगर), बाल्मीकि बस्ती मोती कटरा ऐसी मलिन बस्तियां हैं जहां दैनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और सड़क व नालियों की असुविधायें व सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में इन क्षेत्रों को नरक से भी बदतर बना दिया है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मलिन बस्तियों के सम्पूर्ण विकास, सीवेज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने, सड़क निर्माण, कम्यूनिटी हाल का निर्माण, शौचालय निर्माण सरकार से डूडा द्वारा कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में मंडी समिति द्वारा बनाई गई सड़कों की विशेष मरम्मत/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र 13, पुरकाजी में मण्डी समिति के द्वारा बनायी गयी सड़कें निम्नलिखित हैं :–

1–बड़कली फाटक से ग्राम बहेड़ी तक सम्पर्क मार्ग।

2–रोहाना चरथावल मार्ग से कलिया सम्पर्क मार्ग।

3–मु0 नगर बाईपास से ग्राम बागोवालो सम्पर्क मार्गों आदि की विशेष मरम्मत/नवनिर्माण कार्य एवं रख–रखाव न होने के कारण बहुत ही जर्जर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, सड़क में बहुत बड़े–बड़े गड्ढे हैं जिससे आवागमन पूर्णतः बाधित रहता एवं क्षेत्रीय किसानों को आने–जाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती हैं जिसके कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से एवं वर्तालाप से शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त सड़कों का निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

गोरखपुर समेत प्रदेश के समस्त सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की दवा पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। आये दिन मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। गोरखपुर मेडिकल कालेज में प्रतिदिन मरीजों की लाइन लगी रहती है। प्राइवेट हास्पिटल में मरीजों की संख्या अधिक है। अभी तक उ0 प्र0 में वैक्सीन की सप्लाई अभी तक नहीं हुई है। इस गम्भीर बीमारी से लगभग हजारों लोग त्रस्त हैं। वैक्सीन की सप्लाई न होने से मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता एवं मरीजों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसकी तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं।,

नौतनवां से सौनोली एवं सौनोली से नेपाल के मध्य बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशल सिंह कुंवर–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नौतनवां मित्र राष्ट्र नेपाल के समीप में स्थित है। पर प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल व गैस की गाड़ियों का आना–जाना लगा रहता है। सोनौली कस्बे में देश के आजादी के बाद से व्यापारियों का मकान बना हुआ है, जबकि मकान बनाने के लिये विनियमित क्षेत्र से नक्शा भी पास हुआ है। एन0एच0ए0आई0 के द्वारा व्यापारियों का घर गिराने का काम किया जा रहा है। पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा सड़क बनाने हेतु ली गयी जगह के बाद एन0एच0ए0आई0 जो भी सड़क के लिये जगह अधिग्रहीत कर रही है उसका कस्बे के निवासियों को मुआवजा भी नहीं दे रही है। इस क्षेत्र को सरहद के समीप का होने के कारण आतंकवादी गतिविधियों की दृष्टि से भी देखा जाता है। किसी भी समय यहां पर दुर्घटना घट सकती है। ऐसी स्थिति में सोनौली कस्बे में पुराने बसे क्षेत्र को छोड़ते हुए नौतनवां से सोनौली एवं सोनौली से नेपाल जाने वाले मार्ग पर बाईपास रोड बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित, लोकमहत्व का है तथा अविलम्बनीय है।

अतः अविलम्बनीय, लोकमहत्व एवं जनहित के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नौतनवां से सोनौली एवं सोनौली से नेपाल जाने वाले मार्ग पर सोनौली कस्बे में बाईपास रोड बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद रायबरेली में मुख्य डलमऊ नहर (ए) में ग्राम धैताली का पुरवा में लिफ्ट पम्प लगाकर सिंचाई की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

ख्महोदय, 182 सरेनी वि0स0 क्षेत्र जनपद रायबरेली में मुख्य डलमऊ नहर (ए) के सन्निकट 25–26 ग्रामों की 800 एकड़ कृषक भूमि असिंचित है। यदि उक्त मुख्य नहर के समीप ग्राम धैताली का पुरवा में ''लिफ्ट पम्प'' लगा दिया जाय तो नहर से पूर्वी व पश्चिमी दिशा पर पूर्व से निर्मित पक्के नाले से जल आपूर्ति द्वारा किसान अच्छी उपज पैदा कर पाएगा।

अतः मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दें एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करें।,

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 मानिकपुर के अन्तर्गत ग्राम चमन्धन पुरवा मजरा ऐंचवारा, ग्राम बेलहा मजरा कोबरा, ग्राम मारकुण्डी स्थित डीपू कोलान अनुसूचित जाति बस्ती, ग्राम खण्डेहा महर्षि बाल्मीकि इण्टर कालेज, ग्राम पंचायत ताड़ी में हरिजन बस्ती, ग्राम पंचायत किटहाई मजरा खोहर, ग्राम पंचायत सुरौधा के मजरा सुरजी पुरवा, ग्राम पंचायत कोलगदहिया में कर्वी–इलाहाबाद रोड स्थित शिव अवधेश मास्टर के घर से छेदिहाई नाला एक्सचेन्ज तक

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्युत विभाग द्वारा एक वर्ष पूर्व विद्युत लाइन खींचने के पश्चात् आज तक विद्युत सप्लाई नहीं की गयी है। जबकि पांच ट्रांसफार्मर पोलों में लगे हुए हैं। चूंकि स्थल राष्ट्रीय राजमार्गों (एन0एच0 76) होने के कारण किसी भी समय पोलों पर टंगे ट्रांसफार्मर चोरी जा सकते हैं। मेरे द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं अवर अभियन्ता विद्युत से दूरभाष से उक्त विद्युत लाइन में सप्लाई चालू कराने हेतु कहा गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई एवं न ही विद्युत सप्लाई हो सकी। जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त, स्थिति कभी भी आन्दोलन का रूप ले सकती है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त विकास खण्ड के ग्रामों का विद्युतीकरण यथाशीघ्र कराये जाने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।,

जनपद कासगंज में सहावर से सोरों के मध्य प्रस्तावित मार्ग के मरम्मत कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद कासगंज में पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत प्रस्तावित सहावर से सोरों के मध्य मार्ग जिसका दिनांक 13 जनवरी, 2013 को टेण्डर हुआ था एवं अप्रैल, 2013 में कार्य आरम्भ होकर अप्रैल, 2014 में पूर्ण होना था, किन्तु खेद का विषय है कि लगभग दो वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी उक्त कार्य अभी भी लम्बित पड़ा है।

यह भी अवगत कराना है कि सम्बन्धित ठेकेदार ने 02 वर्ष पूर्व मार्ग में जहां–तहां जे0सी0बी0 से उखाड़ कर मिट्टी और पत्थर डलवा दिये हैं जिससे स्थानीय निवासियों और किसानों को आवागमन में अत्याधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आये दिन दुर्घटनायें भी होती रहती हैं।

अतः जनहित के इस विषय पर तत्काल उक्त मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने एवं दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गभाना–बरौली सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

ख्महोदय, जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गभाना बरौली सम्पर्क मार्ग (लोक निर्माण विभाग) पर स्थित सौंगरा ग्राम में सम्पर्क मार्ग की स्थिति अत्यन्त खराब है जिसमें जगह–जगह पर गड्ढे हो गये हैं। रास्ते के बीचोबीच काफी

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पानी भरा रहता है। गन्दे पानी के कारण बस्ती में गम्भीर बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। जिसके कारण आम जन को चलने में काफी कठिनाई होती है।

अतः मैं चाहूंगा कि इस सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर के राजस्व ग्राम अहिरवा में जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने एवं मुख्य मार्गों को बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर का राजस्व ग्राम अहिरवा, जो कि नगर निगम के वार्ड सनिगवां के अन्तर्गत आता हैं में जल निकासी न होने एवं मुख्य सड़कों के न बनने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में ग्राम अहिरवा एवं उसके साथ ही लगे क्षेत्र सैनिकनगर, पटेलनगर, सदानन्द नगर एवं राजीव नगर में जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराया जाना एवं मुख्य मार्गों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

मैं उपरोक्त क्षेत्रों में समस्त कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के कतिपय चौराहों पर जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद–

ख्महोदय, खजनी–सिकरीगंज एवं सिकरीगंज, बेलघाट, कूरी मार्ग का चौड़ीकरण होने के कारण पानी सड़कों पर जमा रहता है जिससे सड़कें टूट जा रही हैं एवं पानी रुकने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है तथा जलजनित बीमारियां फैल रही हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए महादेवा, भैसा बाजार, खजनी, सिकरीगंज, बेलघाट, कुरी बाजार, माल्हनपार आदि चौराहों पर जल निकासी हेतु तत्काल नाली का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

महानगर बरेली में श्यामतगंज रोड पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार–

ख्महोदय, महानगर बरेली में बढ़ती हुई यातायात समस्या को दूर करने के लिये शहर के उत्तरी भाग को शहर के प्रमुख दक्षिणी भाग को जोड़ने वाली श्यामतगंज की सड़क के ऊपर एक उपरिगामी ब्रिज थाना बरादरी से बरेली कालेज तक बनाना नितान्त आवश्यक है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

ख12.34 बजे, औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 फरवरी, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत 04 सूचनायें प्राप्त हुई थीं। इसमें से एक भी सूचना पोषणीय नहीं है।

पहली सूचना श्री सतीश महाना जी की है।

(श्री सतीश महाना के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

हम पढ़ दे रहे हैं, आप क्यों बोलेंगे। जिस प्रश्न पर आपने उत्तर मांगा है, आपने इसमें कहा है कि 'मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर, 2014 को दी गई सूचनाओं पर वक्तव्य दिये जाने हेतु निर्देश दिये जाने के बावजूद मा0 सदस्य को उनका उत्तर न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इसमें हमने कार्यवाही निकलवाई थी, उसमें 18 और 19 नवम्बर, 2014 को दी गयी दोनों सूचनाएं स्वीकार नहीं की गई थी, इसलिए उसका उत्तर नहीं आया।

दूसरी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की है, यह भी नहीं सुनी जायेगी।

तीसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की है, यह भी नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

चौथी सूचना श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत की है, यह सूचना भी नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है।

(श्री मुकुट बिहारी वर्मा के कुछ बोलने पर)

यदि कुछ होगा तो बता दीजिएगा, बैठिए।

ख12.35 बजे, जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गोला अन्तर्गत ग्राम बेवरी के निकट सरयू नदी पर गोला–गोरखपुर से रौनापार–आजमगढ़ को जोड़ने हेतु पीपा पुल/पक्का पुल का निर्माण जनहित में कराये जाने विषयक श्री विद्याधर पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गोला अन्तर्गत ग्राम बेवरी के निकट सरयू नदी पर गोला–गोरखपुर से रौनापार–आजमगढ़ को जोड़ने हेतु पीपा पुल/पक्का पुल का निर्माण जनहित में कराये जाने विषयक श्री विद्याधर पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गोला अन्तर्गत ग्राम हरपुर (चीनी मिल रोड) से प्रेम नगवा होते हुए पठखौली (राम जानकी राज्य मार्ग, गोला–उरुवा रोड) तक के कच्चे मार्ग

को जनहित में पिच सड़क बनवाये जाने विषयक श्री राजकुमार तिवारी आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राजेश त्रिपाठी–

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गोला अन्तर्गत ग्राम हरपुर (चीनी मिल रोड) से प्रेम नगवा होते हुए पठखौली (राम जानकी राज्य मार्ग, गोला–उरुवा रोड) तक के कच्चे मार्ग को जनहित में पिच सड़क बनवाये जाने विषयक श्री राजकुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 जय प्रकाश निषाद।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर एवं विकास खण्ड खोराबार के अन्तर्गत बोहाबार से रामपुर चौराहे तक क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री कालीचरन व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जय प्रकाश निषाद–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से–

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रहम्पुर एवं विकास खण्ड खोराबार के अन्तर्गत बोहाबार से रामपुर चौराहे तक क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री कालीचरन व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा हरैइया में मझने नाला पर स्थित झिरझरवा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राज बहादुर निषाद व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जय प्रकाश निषाद–

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रहम्पुर के अन्तर्गत ग्राम सभा हरैइया में मझने नाला पर स्थित झिरझरवा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राज बहादुर निषाद व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत गोहडौर चौराहे से टमठा तक की जर्जर सड़क का जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री कालीचरन व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जय प्रकाश निषाद–

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रहम्पुर के अन्तर्गत गोहडौर चौराहे से टमठा तक की जर्जर सड़क का जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री कालीचरन व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के अन्तर्गत कुसम्ही बाजार से मोती राम अड्डा तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री गोपाल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जय प्रकाश निषाद–

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के अन्तर्गत कुसम्ही बाजार से मोती राम अड्डा तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री गोपाल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत गोहटा बन्धा पर रैंप के नीचे दबे रेगुलेटर को जनहित में यथाशीघ्र चालू कराये जाने विषयक श्री शब्बीर व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जय प्रकाश निषाद–

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रहम्पुर के अन्तर्गत गोहटा बन्धा पर रैंप के नीचे दबे रेगुलेटर को जनहित में यथाशीघ्र चालू कराये जाने विषयक श्री शब्बीर व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ख्12.37 बजे, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव [४]

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6, 7, 8 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–9 लेते हैं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया शुरू कर दिए थे बोले नहीं थे शुरू कर दीजिए।

'श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुति पेश किया गया उस पर संशोधन रखते हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या जी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए परसों चर्चा जारी हुई थी उसको आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, यह डेढ़ सौ पेज का जो अभिभाषण महामहिम महोदय का था इसको हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद इसमें एक खास चीज देखी गई कि इसमें किसानों के लिए कोई खास तवज्जों नहीं किया गया और किसानों में भी खासकर गन्ना किसानों के बारे में एक लफ़्ज अध्यक्ष महोदय नहीं कही गई बल्कि चीनी मिल मालिकों के लिए तो जिक्र किया गया है कि इनको यह अनुदान दिया गया है इनको वह अनुदान दिया गया है लेकिन अगर एक शब्द भी महामहिम द्वारा गन्ना किसानों के बारे में कह दिया जाता तो मुझे कष्ट न हुआ होता। मुझे हार्दिक कष्ट हुआ क्योंकि मैं भी पेशे से किसान हूं और गांव में रहता हूं और यहां पर बैठे अधिकांश सदस्यगण चाहे वह इस तरफ के हैं चाहे उस तरफ के हैं चाहे जिस तरफ के हैं 80 प्रतिशत सदस्य यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आए हैं पेशे से किसान हैं जैसा कि

[४] दिनांक 19 फरवरी, 2015 की कार्यवाही से।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपको पता है अध्यक्ष जी कि तीन सालों से गन्ने के मूल्य में एक रुपये की वृद्धि नहीं की गई है। 2012 से जब से यह सरकार निर्वाचित हुई थी उस समय से गन्ने का जो रेट 275 रुपये, 280 रुपये और 290 रुपये था। तीन पेराई सत्र बीत गए एक रुपये भी गन्ने के मूल्य में इजाफा नहीं हुआ जब कि घोषणा–पत्र में अपने चुनावी वायदे में समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा यह कहा जाता था और उसमें लिखा भी था कि हम गन्ने का मूल्य 350 रुपये कर देंगे लेकिन मुझे यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि डीजल का दाम डेढ़ गुना हो गया है खाद के दाम डेढ़ गुने हो गए हैं मजदूरी श्रमिक डेढ़ गुने हो गए हैं पेशे उपकरण डेढ़ गुने हो गए हैं और पेस्टीसाइड जो उसमें लगता है जो इस्तेमाल होता है उसके दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है लेकिन गन्ना किसानों का जो मूल्य लगता है उसमें वृद्धि नहीं हुई बल्कि चीनी मिल मालिकों द्वारा इस वर्ष 40 रुपये कम करके 240 रुपये में गन्ने की खरीद की जा रही है। उनको कभी केंद्र सरकार छूट दे रही है चार हजार करोड़ की कभी प्रदेश सरकार छूट दे रही साढ़े चार हजार करोड़।

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।)

कभी प्रदेश में 12 रुपये प्रति कुं0 की दर से उनको छूट देने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, गन्ने की फसल पर ही अन्य फसलें निर्भर हैं। जब गन्ने की कटाई होती है तो उसके बाद उसमें गेहूं, दलहन, तिलहन, सब्जियां इत्यादि उसमें बोई जाती हैं। मान्यवर, आज घटतौली चरम पर है। आज किसानों का गन्ना 05–10 कु0 प्रति ट्राली कम करके तौला जा रहा है। उनको सीधी पर्चियां नहीं मिल रही हैं उनको भुगतान नहीं मिल रहा है। आजकल शादियों का दौर चल रहा है, हम सभी लोग शादियों में जाते हैं। आज देखें तो 30–40 लाख गन्ना किसान परिवार हैं। उनको आज पैसा नहीं मिल रहा है। वह अपने यहां शादी–ब्याह कैसे करें। अपनी बीमारी का इलाज कैसे करायें। मान्यवर, किसानों के गन्ने की घटतौली बंद होनी चाहिए, किसानों को पर्चियॉ सुलभता से मिलनी चाहिए। किसानों को भुगतान होना चाहिए। मान्यवर, इस पर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, आज आप देखें कि सरकार आज विभागों में भर्तियॉ नहीं कर रही है। शिक्षा विभाग में भर्ती करने का काम तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने वर्ष 2011 में शुरू किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए यह लोग अभी भी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। चाहे न्यायालय का स्थगन आ जाता है या अन्य सरकारी अड़चनें आ जाती हैं। मान्यवर, आज एक पंचायत सक्रेटरी 10–10 गांवों में कार्य देख रहा है।

आज पंचायत सेक्रेटरी की बहुत कमी है। ए0डी0ओ0 की कमी है। खण्ड विकास अधिकारियों, प्राथमिक शिक्षकों की कमी है। इण्टर कालेज के पांच हजार से ज्यादा प्रधानाचार्य, 50 हजार से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। जब इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य, शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी। गन्ना विभाग में गन्ना पर्यवेक्षकों की कमी है, सी0डी0आई0 की कमी है। लेखपालों की कमी है। पुलिस कान्स्टेबलों की कमी है। खाद्य मंत्री जी बैठे हैं पूर्ति निरीक्षकों की कमी है। एक–एक जिले में दो–तीन पूर्ति निरीक्षक हैं। मान्यवर, अगर पूर्ति निरीक्षक पूरे हो जायें तो गरीबों को मिलने वाला जो खाद्यान्न है वह उन तक सुगमता से पहुंच सके। उनकी कमियों को

दूर होना चाहिए। मान्यवर, आज देखा जाये तो जो शिक्षक स्कूलों में जाते हैं। देखा जाता है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई के लिए क्यों नहीं जाते। महोदय, आज स्थिति यह है कि आज उनसे वहां पर कितने काम लिये जाते हैं। मिड डे मील का खाना बनवाने का काम उनसे लिया जाता है। निर्वाचन की वोटर लिस्ट बनवाने का काम उनसे लिया जाता है। चपरासी का काम वह करते हैं। तो उनको अगर इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त करके सिर्फ शिक्षा का काम दिया जाये तो वह वहां पर उन बच्चों को पढ़ायें। आज देखें तो जो एम0बी0बी0एस0 का एडमीशन होता है उसमें हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों का आज प्राइवेट सेक्टर के लोग मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि उन पर हमारा ध्यान है डाक्टर, इंजीनियर बनाने पर हमारा ध्यान है। मान्यवर, जो बुनियादी नींव है उनको बनाने में हम उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। इसी वजह से ढाई–तीन हजार रुपये में जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं हम अपने बच्चों को शिक्षकों को 30 हजार रुपये देने के बाद पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन 30 हजार रुपये प्राथमिक शिक्षक को हम लोग सैलरी देते हैं। यह एक बुनियादी अंतर है।

मान्यवर, हमारा जिला लखीमपुर खीरी बाढ़ प्रभावित जिला है। दो नदियां घाघरा और शारदा वहां से गुजरती है। हर वर्ष बाढ़ आती है और उस बाढ़ में हर वर्ष हजारों किसान बेघर हो जाते हैं उनकी जमीनें कट जाती हैं फसलें तबाह हो जाती हैं। वह बेघर होकर सड़क पर पड़े रहने को मजबूर होते हैं। लेकिन इन तीन सालों में हमने देखा है कि उनके रहने की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी। राज्यपाल महोदय ने इसका जिक्र नहीं किया। उनके रहने के लिए घर की जगह देनी चाहिए। उनकी फसलों का मुआवजा देना चाहिए। उनकी जमीन जो कटकर नदी में गिर रही है उसका मुआवजा उनको देना चाहिए। कहीं–कहीं तटबंध जब कट जाता है। अधिकारी लोग तब दौड़ते हैं जब तटबंध कट जाते हैं। आज तटबंधों की हालत क्या है। जहां पर तटबंध पूरे नहीं हैं उनको पूरा कराया जाये। तटबन्धों को पूरा कराने के बाद सड़के बनाई जाये जिससे कटान की यह त्रासदी न होने पाये। मान्यवर, कटान आने के बाद जो बाढ़ का पानी आता है, बाढ़ का पानी जब निकल जाता है तो महामारी लेकर आता है। अक्सर इस सदन में चर्चा होती है कि जापानी इनसेफलाइट्स, मस्तिष्क ज्वर पूर्वान्चल में फैलता है, हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में भी मस्तिष्क ज्वर फैलता है। इसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। यहां पर सदन तब चिन्तित होता है जब हजारो बच्चे गोरखपुर से लेकर लखीमपुर खीरी तक अपने प्राणों की बलि दे देते हैं उनके गरीब मां–बाप जो इलाज के लिए दर–दर भटकते हैं, इसको हमें देखना चाहिए, इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। स्वाइन फ्लू दस्तक दे चुका है। ग्यारह, बारह हजार से ऊपर मरीज इससे प्रभावित हैं। सात–आठ सौ से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पुलिस अधीक्षक जम्मू कश्मीर में मरते हैं। शाहजहांपुर की डी0एम0 और एक और डी0एम0 साहब तथा सी0एम0ओ0 को स्वाइन फ्लू हुआ है। ऐसे में अधिष्ठाता महोदय अगर गरीब का बच्चा स्वाइन फ्लू से प्रभावित होता है तो वह इतना मंहगा इलाज कहां से कर पायेगा। आपके माध्यम से हमारा सरकार से यह निवेदन है कि इसको रोकने के लिए सरकार भरसक प्रयास करें

और जो इसके टीके हैं, इन टीकों को लगवाने के लिए, चूंकि मंहगा टीका है, आम आदमी, गरीब आदमी नहीं लगवा सकता तो उस टीके को लगवाने की भी व्यवथा की जाये।

अधिष्ठाता महोदय इस पुस्तिका को हमने पढ़ा, 150 पन्नों की इस पुस्तिका में प्रष्ठ संख्या– 97 में लिखा हुआ है कि सहारनपुर की घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना को छोड़कर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मान्यवर, मुजफफरनगर की घटना कितनी दर्दनाक घटना थी कि उसी से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दशा और दुर्दशा दोनों बदलने का काम किया। जिस तरीके से अफवाहें फैलाकर, जिस तरीके से दंगा फैलाकर किस तरीके से गरीब परिवारों को बेघर किया गया, किस प्रकार से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा गया। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, हजारों लोग बेघर हुए। सरकार के प्रयासों के बाद जिले में जाकर शिविर कैम्पों में रहें। शिविर कैम्पों में भी उनको इतनी बीमारी आयी। बारिश के पानी से वे लोग बीमार हुए, यह चीज किसी से छिपी हुई नहीं है। अधिष्ठाता महोदय इसके साथ बरेली में, मथुरा में, फैजाबाद में छोटे–बड़े 150 दंगे हुऐ। यह कहना कि सिर्फ एक दंगा हुआ, गलत है। आज कारागार की स्थिति देखें अधिष्ठाता महोदय कारागार में क्षमता से अधिक कैदी हैं। इसमें 101 पृष्ठ में कहा गया है खुद राज्यपाल महोदय ने यह स्वीकारा है कि कम से कम 24000 अतिरिक्त कैदी हैं। इतने ज्यादा कैदियों के होने की वजह से जेल प्रशासन कन्ट्रोल नहीं कर पाता। आये दिन जेल से कैदी फरार होते हैं, कोई सुरंग बनाकर फरार होते हैं, कहीं बम लगाकर बाहर गये हैं और हमारे लखीमपुर खीरी में तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में तमन्चा लगाकर दो कैदी उस जेल से सुबह 08.00 बजे फरार हुए। मान्यवर मैं एक और चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने जो योजनायें चलाई थी, चाहे वह महामाया बालिका आदर्श योजना हो, चाहे वह महामाया आवास योजना हो, चाहे डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया आर्थिक मदद योजना हो, चाहे मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना हो, चाहे कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना हो इन सब योजनाओं को इस सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बन्द कर दिया है। हर राजनीतिक दल के अपने महापुरुष होते हैं। आज हमारे दलित समाज के लोग इसी में गर्व महसूस करते हैं कि उनके महापुरुषों के नाम पर पार्क बनाये गये। पार्कों की नकल आपने की जो जनेश्वर मिश्र पार्क हम लोगों ने जमीन चिन्हित की थी, उस पर आपने पाक्र बनाने का कार्य किया हैं। उस समय बड़ी आलोचना की गयी थी जब यमुना एक्सप्रेस–वे हमारी नेता बहन मायावती जी ने बनाया था, बड़ा विरोध हुआ था जब उसी तरीके से गंगा एक्सप्रेस–वे बनाने की बात रखी थी। लेकिन आज आप वही योजायें जो बहन कुमारी मायावती जी ने चलाई थी, उन्हीं का नाम बदलकर, उन्हीं का स्वरूप बदलकर, वहीं योजनाएं जन कल्याणकारी योजनायें आप चलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भौरारा से सुजई जाने वाले मार्ग पर दहोरा नाले पर एक पुल की बहुत आवश्यकता है। उस पुल को बनाया जाये। हमारे क्षेत्र

में जितनी गन्ना विभाग की सड़के बनी हुई हैं जो कि गन्ना विभाग में जैसा कि श्री दलवीर सिंह जी ने बताया था कि आर0ई0एस0 विभाग की तरह रिपेयरिंग का बजट नहीं होता है, तो इसलिए हमारे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में जितनी गन्ना विकास विभाग द्वारा बनी हुई सड़कें हैं, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के द्वारा बनी हुईं सड़कें हैं, उन सबकी रिपेयरिंग कराई जाय और रमिया बेहड़ से परौरी तक का मार्ग पक्का किया जाय और खमरिया से ईसानगर तक के रोड का चौड़ीकरण किया जाय और इस मार्ग को भी पक्का किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, मा0 मदन चौहान जी आप अपनी बात शुरू करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

'श्री मदन चौहान–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर जो मा0 सदस्य डा0 संग्राम सिंह यादव जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा, उसके समर्थन में मैं भी शामिल हुआ हूं। मान्यवर, आज राजनीति करने के कई उद्देश्य हो गये हैं। मान्यवर, राजनीति करने का उद्देश्य हम सब लोगों का मतदाता और आम जनता के द्वारा चुने जाने के बाद हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम उस गरीब, कमजोर और मजलूम की सेवा करके इस तरह की नीतियां बनायें ताकि उनको राहत मिल सके, उनको जो जरूरत है, उन सुविधाओं की पूर्ति हो सके। इसी प्रकार से जो लोग वंचित रह गये हैं, जो सुविधायें आज उनको नहीं मिल पा रही हैं, उनको मुहैया कराना हम सब लोगों का नैतिक दायित्व बन जाता है। मान्यवर, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया, सदन के नेता युवा मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो दूरदर्शिता से इस तरह के प्रयास किये गये हैं उसमें कई योजनाएं ऐसी हैं, जिसमें श्रमिकों को फायदा मिल रहा है, किसानों को फायदा मिल रहा है, जो वंचित लोग रह गये हैं, उनको बराबरी में आने का मौका दिया जा रहा है। मान्यवर, उस तरह की नीतियां जिस तरह श्रमिक विभाग की कई योजनाएं हैं, उसमें अगर श्रम विभाग में कोई भी श्रमिक अपना पंजीकरण करा देता है, तो उसको बहुत सारी सुविधायें मिलना शुरू हो जाती हैं, उसमें जिस तरह से 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच में आयु होनी चाहिए और 12 महीने के कार्यों का समय होना चाहिए, उसका पंजीकरण 50 रुपये देकर के किया जाता है, उससे बहुत सारी ऐसी सुविधायें हैं जो श्रमिक को प्राप्त हो जाती हैं, चाहे साईकिल की हो, चाहे दुर्घटना की हो, चाहे शिशु हित लाभ की योजना हो, मृत्यु व अन्त्येष्टि पर इस तरह की बहुत सारी सुविधायें हैं जो उनको प्राप्त होती हैं। मान्यवर, श्रमिक से लेकर के किसान, जो किसान हमको अन्न देता है, खेत जोत कर के हमको तमाम चीजें देता है, दाल, रोटी, दूध तमाम सुविधायें देता है, उसके लिए बहुत सारी योजनायें हमारी सरकार ने शुरू की हैं।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुर्घटना बीमा उसी के अन्तर्गत आती है, किसान के लिए सिंचाई की जो मुफ्त सुविधा दी है वह भी अपने आप में एक उदाहरण है। मान्यवर, उसी तरह से कई और योजनायें चलाईं, जैसे समाजवादी पेन्शन योजना, मान्यवर जो ऐसे लोग थे, जो किसी भी सुविधा में नहीं आ पाये, उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनको सरकार ने समाजवादी पेन्शन के दायरे में लाकर के 40 लाख लोगों के लिए फायदे की योजना बनाई है। उसी प्रकार से मान्यवर चिकित्सा सुविधा में अगर हम लोग जायें तो आज 108, 102, 1090 तमाम वह सुविधायें हैं जो आम आदमियों से लेकर के महिलाओं तक दी जाती हैं। इसी प्रकार से मान्यवर बहुत असाध्य रोगों में जो गरीब, कमजोर, किसान और मजदूर आदमी हैं उसका इलाज नहीं हो पाता, उसके लिए आज हृदय के लिए, किडनी के लिए सरकार ने मुफ्त इलाज करने की जो मुहिम शुरू की है वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के लिए जो 20 प्रतिशत आरक्षित कर के हर योजना में लाभ दिये जाने की योजना शुरू की है, वह गरीब अल्पसंख्यक के लिए है।

मान्यवर, दो उपलब्धियां बहुत मजबूत हैं, सरकार ने जो आज हम सब लोगों को दी हैं, एक तो मैट्रो रेल परियोजना है, उसकी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो शुरूआत हो रही है वह अपने आप में अभूतपूर्व उपलब्धि है। मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व में भी सबसे पहले समाजवादी सरकार ने ही नोएडा में मैट्रो रेल परियोजना को शुरू किया था, आज यह कई शहरों में शुरू होने जा रही है, तो यह हम सबके लिए गरीब, कमजोर और मध्यम वर्ग के लिए बहुत लाभ देगी। मान्यवर, एक सबसे बड़ी जो दूसरी योजना है, उसमें लखनऊ से आगरा तक का जो 15 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट छः लाईन की योजना निर्माणाधीन होने जा रही है, उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। पूरे देश को मिलेगा और राजधानी लखनऊ से राजधानी दिल्ली तक जोड़ने का यह कार्य एक अभूतपूर्व कार्य है। मान्यवर, इस तरह से ये तमाम योजनायें शुरू करके किसानों को भी फायदा मिला है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण को लेकर पहले कई घटनायें हो गईं हैं। ग्रेटर नोयडा में हुई थी, एक टप्पल में हुई थी, वह गौतम बुद्ध नगर में थी और एक भट्टा पारसौल में हुई थी। आज किसान कम से कम राहत की सॉस ले रहा है कि उसे इस तरह का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मान्यवर, इसी तरह से समग्र ग्राम विकास की योजना है जिसमें गांवों का चयन करके हर सुविधा देने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह एक आम आदमी तक जाता है। चाहे सड़क का हो, चाहे सौर ऊर्जा का हो तो मान्यवर, हम उन सब योजनाओं को लेकर के अगर सच्ची नियत से क्रियान्वयन हो जायेगा तो निश्चित तौर से आम आदमी को फायदा मिलेगा, वंचित लोगों को फायदा मिलेगा। जो लोग वंचित रह गये हैं उनको फायदा मिलने जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गढ़मुक्तेश्वर गंगा किनारे एक पवित्र स्थान है, पैराणिक स्थल है और हरिद्वार के बाद दूसरी जगह ऐसी है जो हमारे प्रदेश को सुशोभित करने के लिये काफी है। इसमें हमारी सरकार ने कई करोड़ रुपये का प्रोविजन करके एक बहुत बड़ी योजना तैयार करने की जो पहल की है तो वहां बहुत दूर–दूर से पर्यटक आते हैं, तमाम विदेशी लोग भी आते हैं। गंगा स्थल पर वहां एक पौराणिक मेला नवम्बर में लगता है। मेरा यह एक सुझाव है

कि अगर उस मेले का नाम प्रान्त के स्तर पर शामिल कर लिया जाये और उसकी वह तमाम सुविधायें प्रान्त के स्तर से हों तो आम जनता को लाभ मिलेगा। वहां के नजदीक के रहने वाले क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। मान्यवर, सरकार की जितनी योजनायें हैं वे वंचित लोगों के लिये काफी नहीं हैं बल्कि और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे अपने सुझावों को सम्मिलित कराने का मौका मिला।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अधिष्ठाता जी, मेरे पूर्व वक्ता बहुजन समाज पार्टी के नेता प्रतिपक्ष मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता खन्ना जी और विपक्ष के अन्य साथियों के साथ अपने आप को सम्बद्ध करते हुये मैं सरकार के द्वारा रखी गई कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी महामहिम के अभिभाषण में जो एक पुस्तिका मिली है, मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की है कि प्रदेश में पेंशन के पात्र सभी व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन का लाभ उपलब्ध कराया जाये। किसी भी सरकार की हर योजना बहुत अच्छी होती है। जनता के हित में बनाई जाती है, चाहे ये सरकार हो, चाहे पहले की सरकार हो, चाहे आगे आने वाली सरकार हो। किसी की योजनाओं में कमी नहीं है। हर सरकार योजनायें जनता के हित में बनाती है लेकिन कुछ योजनायें ऐसी होती हैं जो सिम्बॉलिक होती हैं, मात्र दिखावे के लिये होती हैं। आम जनता को उनसे कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे समाजवादी पेंशन योजना है। इसमें बजट का प्राविधान बहुत कम किया गया है। अगर ये गरीब, बेसहारा सब लोगों को उपलब्ध हो जाती तो बहुत अच्छी योजना है लेकिन ऐसा महामहिम के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में काफी योजनाओं को चलाने की बात तो कही है। जैसे अलीगढ़ में 660 मेगावाट की एक योजना, जब से यह सरकार बनी है तब से प्रस्तावित है लेकिन आजतक उसके लिये कोई धन आवण्टन नहीं किया गया है। वहां ऑलरेडी, पहले से एक परियोजना चल रही है और इतनी जमीन उपलब्ध है वहां कि इस तरह की 660 मेगावाट का बिजली घर स्थापित किया जा सकता है।

मैं सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में अब भी आकर्षित करूंगा और आने वाले बजट में भी करूंगा। सरकार द्वारा एक आश्वासन दिया गया कि प्रदेश में जितने भी मण्डल हैं तो सभी मण्डलों में एक राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। उसमें जवाब में सरकार ने अलीगढ़ का भी उल्लेख किया था लेकिन महामहिम के इस अभिभाषण की पुस्तिका में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि अलीगढ़ में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जिसका मा0 मुख्य मंत्री जी ने कई बार बड़े गर्व और कॉन्फिडेंस के साथ अलीगढ़ में भी घोषणा की और लखनऊ से भी घोषणा की लेकिन आज तक उसका उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे। गौतमबुद्ध नगर विश्वविद्यालय अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो और मुझे भी देखने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में वह एक बहुत ही अच्छे ढंग का विश्वविद्यालय बना हुआ है। जब मैं वहां गया और मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चे वहां से क्लासेज छोड़कर चले गये। वहां स्टाफ नहीं है, वहां पर कोई पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। जितने भी लोग थे

उनको स्थायी नहीं किया गया। इस चक्कर में वे सब लोग पूरे विश्वविद्यालय को छोड़कर चले गये। जिनका चयन हुआ है विभिन्न–विभिन्न सरकारों में आए, वे बच्चे आज बिल्कुल हताश और निराश हैं। मैं चाहूंगा कि उसके बारे में उल्लेख किया जाए, इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार इस पर भी ध्यान दें अभी खाद के सम्बन्ध में सरकार ने बड़े लंबे–चौड़े वायदे किये हैं कि हमारी सरकार पूरा खाद उपलब्ध कराएगी। मैं आज की तारीख में भी कह रहा हूं, मुझ जैसा आदमी जो खेत, किसान, गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मैं एक–एक व्यक्ति के खाद गोदाम का ध्यान रखता हूं। इतने सब के बाद, भारी विरोध करने के बाद अब भी यूरिया 400/– रुपये के हिसाब से बिक रहा है। यह सरकार यूरिया उपलब्ध नहीं करा सकी। चाहे यह राज्य सरकार की कमी हो, चाहे भारत सरकार की कमी हो लेकिन जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की बनती है। यह व्यवस्था राज्य सरकार को करनी है, मैं चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था पर भी कुछ विचार किया जाए। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना एक बहुत अच्छी योजना है। इस सरकार की अगर कोई अच्छी योजना है तो केवल यह एक अच्छी योजना है।

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

समाजवादी पेंशन योजना अच्छी नहीं है ?

श्री दलवीर सिंह–

अच्छी तो है, लेकिन सबको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। दिखाने के लिए पेंशन तो आपने दे दी, जैसे आपने बैंकों का कर्ज माफ कर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप पीठ को सम्बोधित करते हुए अपनी बात रखें।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं माननीय मंत्री जी बहुत सीनियर हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि योजना तो कोई बुरी नहीं है। योजना तो आपने जितनी चलाई हैं, वह सब एक से एक बढ़िया योजनाएं हैं, लेकिन योजना मात्र दिखावे की नहीं होनी चाहिए, उससे लाभ होना चाहिए। अभी सिंचाई की योजना में आपने सिंचाई मुफ्त की, माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, जो सिंचाई मुफ्त की है वह नलकूपों की और नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, वह खत्म की गई है। यह मात्र 18 परसेन्ट प्रदेश में सिंचाई होती है, 82 परसेन्ट किसान जो सिंचाई करता है वह व्यक्तिगत साधनों से करता है, उसके लिए कोई भी प्राविधान नहीं किया गया है। जनेश्वर मिश्र योजना बहुत अच्छी है, कोई भी अधिकारी सुन रहे हो, सरकार में बैठे कई महत्वपूर्ण मंत्री और विशेष रूप से माननीय शिवपाल सिंह जी बहुत सीनियर हैं, जो एक तरह से सरकार को चला रहे हैं। उनके संज्ञान में मैं यह लाना चाहता हूं कि यह योजना बहुत अच्छी है, हम खड़े होकर बनवा रहे हैं, देख रहे हैं। वहां से विभाग द्वारा जो सीमेंट दी जा रही है, ये जितने भी हमारे साथी हैं, ये खुद आज महसूस कर रहे होंगे कि इतनी घटिया सीमेंट दी जा रही है। आज भी मैंने अपने कलेक्टर से कहा है, ये सैम्पिल भर कर लखनऊ ट्रक भेजो। हम खड़े होकर सीमेंट मिलवा भी रहे हैं, लेकिन सीमेंट दो कौड़ी की है। सीमेंट घटिया होने की वजह से मैं कहूंगा कि इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कराना ही बेकार

है। आप लोग इस पर ध्यान दें, आप लोग सरकार में मंत्री पद पर बैठे हैं। आपके यहां भी काम हो रहा होगा। हो रहा है काम ? काम तो हो रहा है लेकिन सीमेंट के बारे में क्या कहेंगे ? आप लोग इसे देख लें अच्छा रहेगा। इसके अलावा यह किसान भाइयों के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत अच्छी योजना है। आप किसाना बीमा के रूप में 5 लाख रुपया दे रहे हैं। मंडी की तरफ से 3 हजार से लेकर 2 लाख तक का प्राविधान है किसानों को उपलब्ध कराने के लिए लेकिन प्रचार–प्रसार की इतनी कमी है। इस योजना के बारे में किसानों को ज्ञान नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसका प्रचार–प्रसार हो जिससे निश्चित रूप से इस योजना का फायदा होगा। इसका प्रचार–प्रसार करने पर भी जोर दें। आलू के सम्बन्ध में कहना है कि अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को आलू उपलब्ध कराता है, लेकिन आलू की इतनी दुर्दशा है, कोल्ड स्टोरेजों की इतनी दुर्दशा है, कोल्ड स्टोरेज मालिक इतना भारी किराया लेते हैं किसानों से की उसको दो पैसा नहीं मिलता है।

मैं चाहूंगा कि इसमें एक नीति बनाई जाए। सरकार आलू नीति जब तक नहीं बनायेगी, तब तक किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा और यह बिल्कुल निश्चित है कि आलू नीति ढंग से बना दी और सरकार ने उस पर ध्यान दिया, तो उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को, ये चार–पांच जिले आलू खिलाने की ताकत रखते हैं। यह पौधारोपण के सम्बन्ध में अच्छी योजना है, चलनी चाहिए। योजना में किसी में कोई कमी नहीं है लेकिन अगर हम खड़े होकर इसका इम्प्लीमेंट सही से करा दें, खड़े होकर इसमें बेईमानी को रोक दें, तो निश्चित रूप से यह बहुत सफल है। मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया जाए। डार्क जोन के सम्बन्ध में एक सवाल भी था, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसे विस्तार से बताया। प्रश्नकर्ता का एक बहुत अच्छा सवाल था, जिसमें एक बहुत अच्छी योजना आपकी सरकार चला रही है। सरकार ने आर0आर0आर0 योजना जो बनाई है, अगर यह योजना ढंग से लागू की जाए तो इससे बहुत लाभ होगा। मान्यवर, इसमें अभी मैनें इस पर पूछा था बताया गया कि इसमें बजट पर्याप्त है। अगर इसमें समय रहते धन का उपयोग नहीं हुआ तो वह धन लैप्स हो जायेगा। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें वहां से प्रस्ताव मंगवा ले ताकि इस कार्य के लिये जो बजट का एलोकेशन हुआ है उसका उपयोग हो। मान्यवर, सौर ऊर्जा संचालित योयना अच्छी है किसानों के हित है। परन्तु दो हार्स पावर चलित 300 नलकूप तथा 5 हार्स पावर चालित 50 नलकूप इतने बड़े प्रदेश में काफी कम है। प्रदेश में प्रति ब्लाक एक नलकूप भी नहीं आता है। मान्यवर पूरे प्रदेश में 900 ब्लाक हैं इस तरह से 3 ब्लाकों के बीच में एक नलकूप आयेगा। मान्यवर योजना अच्छी है हम चाहेंगे कि इस योजना का विस्तार करके हर ब्लाक को इसकी सुविधा दिलायी जाय और इसमें अधिक बजट का प्रावधान कराया जाये और किसानों को इसका समुचित लाभ दिलवाया जाये। मान्यवर, इस तरह आलू भण्डारण का किराया डीजल की दर कम होने के बावजूद इस वर्ष भण्डार मालिकों ने बढ़ा दिया है। इस पर सरकार ध्यान दे। इसी तरह से मान्यवर लोहिया ग्रामों में सीसी

कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण लगभग प्रत्येक गांव में सी0सी0 कार्य अधूरा रह जाता है। इसे संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, इस पर आप अधिक बजट दिलाये ताकि यह योजना सफल हो सके और सभी चयनित लोहिया ग्राम इस योजना से आच्छादित हो सकें। मान्यवर यह सरकार गड्ढा मुक्त सरकार की बात कहती है माननीय लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं सरकार में बहुत सीनियर मंत्री हैं, हम तो आपको भी मुख्य मंत्री मानते हैं। आप मुख्य मंत्री हो। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप सरकार में मालिक हैं। आपने सदन में कई बार कहा है कि प्रदेश की गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त सरकारों में तब्दील कराया जायेगा। आपने कोशिश भी की है। मान्यवर हमारे जनपद अलीगढ़ की खैर सोमना मार्ग की जो दो तहसीलों को जोड़ती है, पर इस सदन में तीन बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन उस सड़क का आज तक सुदृढ़ीकरण नहीं हो पाया है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी इस मार्ग पर आप ध्यान देकर इस मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराने का काम करें। मान्यवर, इस अभिभाषण में चर्चा आयी है कि मेट्रो परियोजना की जनेश्वर मिश्र पार्क की आयी है इसमें आपने बड़ी धनराशि का प्रावधान किया है।

मान्यवर यमुना एक्सप्रेस–वे परियोजना प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनायी गयी इसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगा। लेकिन जिन्होंने उसको बनाया उन्होंने पैसे की लूट की है। यह 15 हजार करोड़ रु0 की योजना थी। मान्यवर अगर 403 विधायकों में यह धनराशि बांट दी जाये तो कितना विकास हो जाता। मान्यवर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बजट के अभाव में अधूरी पड़ी है। और जो बनी है वे बनते ही ऊखड़नी शुरु हो जाती है। मान्यवर अधूरी सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है। आप बराबर केन्द्र सरकार को पैसा देने के लिए पत्र लिख रहे हैं लेकिन वहां से पैसा मिलने वाला नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि आप इन सड़कों को अपने लोक निर्माण विभाग के अधीन लेने का काम करें। मान्यवर, जो ठेकेदार थे पिछली सरकार में उन्होंने काम किया और अपना लागत ले ली लाभ ले लिया और कमीशन का पैसा निकाल लिया। अब उन्होंने काम करने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिये हैं। जब उनसे बात करुं तो कहते हैं कि भाई दलबीर जी चाहे आप इसमें एफ0आई0आर0 करा दें हम काम नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, आपने इस हाउस में किसानों के लिये विद्युत का अलग फीडर की बात कही थी। परन्तु इस योजना पर प्रभावी रुप से कार्य नहीं हो रहा है। आपकी सरकार माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ध्यान दे और इस योजना को किसानों के हित में आगे बढ़ाये।

मान्यवर हमारे यहां हरदुआगंज तापीय परियोयजना है जनपद अलीगढ़ में है इसमें लगभग 70 हेक्टेअर भूमि बेकार पड़ी हुई है इस भूमि पर एक और 660 मेगावाट की परियोजना स्थापित की जा सकती है। जो परियोजना 660 मेगावाट की है भी उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि वह सही तरीके से आगे बढ़ सके। वहां प्रर्याप्त जमीन है एक इसी तरह का 660 मेगावाट का बिजली घर और स्थापित किया जा सकता है इसी पावर हाउस में आप ही की जमीन है मैं चाहूंगा कि इसको और चालू

करा दें और नया बिजली घर जो बनाना चाहे सरकार तो वहां जगह उपलब्ध है। यह बहुत सी चीजे ऐसी है। योजनाओं में कोई कमीं नहीं है सरकार की योजना बहुत अच्छी है मैं हर योजना से संतुष्ट हूं लेकिन योजना मात्र दिखावे के लिए है अभी माननीय मंत्री जी ने बैंकों का ऋण माफ किया तो सहकारी बैंकों का माफ किया क्योंकि सहकारी बैंक के यह खुद मालिक हैं। यह जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनका भी ऋण माफ किया जाता तो किसानों को कुछ लाभ मिलता। आपने माफ किये अच्छा काम किया चाहे कम किया लेकिन उसे अच्छे स्तर पर कर दिया जाय जैसे आपने ट्यूबवेलों की माफ की जैसे आपने सिंचाई नहरों की माफ की लेकिन यह सिंचाई ट्यूबवेल और नहरों की केवल 18 प्रतिशत होती है प्रदेश में किसानों की, 82 प्रतिशत किसान ऐसा है जो प्राइवेट ट्यूबवेलों से, इंजनों से, रहटों से नलकूप और कुंओं से सिंचाई करता है शेष जो बचे हैं 82 प्रतिशत किसान उनके लिए भी कुछ किया जाय। गन्ना के सम्बन्ध में हमारे साथी बहुत अच्छे ढंग से कह रहे थे यह पहली सरकार है आपकी 2 रुपया, 5 रुपया सब गयी गुजरी सरकारों ने बढ़ाये हैं आपने जब से सरकार सम्भाली है गन्ना का रेट बिलकुल नहीं बढ़ाया, 5–10 रुपया तो हरेक सरकार ने बढ़ाये हैं। मारामारी इस बार इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादा गन्ना नहीं था भुगतान की स्थिति यह है कि आप अगर सख्ती करें तो भुगतान किया जा सकता है किसानों का भुगतान बहुत पेन्डिंग है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर निश्चित रूप से ध्यान दे। कई मिलें ऐसी है छाता मथुरा की बहुत महत्वपूर्ण मिल है आज तक बन्द पड़ी है। अलीगढ़ में एक मात्र मिल है साथा, आपकी सहकारी एक मिल है साथा उसकी क्षमता उत्तर प्रदेश में सबसे कम है मैं चाहता हूं कि उसकी क्षमता बढ़े। जितनी प्रदेश में मिल है जो बन्द पड़ी है उसको चलवाया जाय किसानों के हित में जो भी अच्छी योजना आप लागू कर सके उसको लागू करायें यह मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी–

मान्यवर, आपने हमें डा0 संग्राम सिंह यादव द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आभारी हूं मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं माननीय अधिष्ठाता जी, इस चर्चा की शुरूआत नेता विरोधी दल ने बहुत ही विस्तार से शुरू की उस पर हमें बहुत दूर तक नहीं जाना लेकिन सिर्फ यह बात कहना मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि पिछली सरकार जो हमारी इस विकासशील और अच्छी सरकार को अपने तरीके से, अपने अंदाज में गलत साबित करने की कोशिश कर रही है मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सिर्फ लखनऊ गाजियाबाद और अन्य जगहों पर, करोड़ों करोड़ों रुपये के पत्थर के हाथी के मुजस्समें खड़ा करके सूबे के गरीब, किसान, मजदूर, अक्लियत, मजलूमों के पैसे का दुरुपयोग करके हाथी का मुजस्समा खड़ा किया और इस कदर टेरर बनाया गवर्नमेन्ट चलाने का मान्यवर, उस जमाने में बिजली नहीं आती थी दावे तो बहुत किये उस हुकूमत में खाद नहीं थी, गन्ना किसानों का शोषण हो रहा था, विद्यार्थियों का दमन हो रहा था, अस्पताल में दवाई का कोई इंतजाम नहीं था। आज मैं

बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि श्री राज्यपाल जी का यह अभिभाषण और उत्तर प्रदेश की सरकार जिसके मुखिया नेता सदन माननीय अखिलेश यादव जी हैं, डा0 राम मनोहर लोहिया जी का सपना, रफीकुलमुल्क हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का वह सपना कि एक गरीब की झोपड़ी तक रोशनी हो, गरीब के बच्चे को शिक्षा मिले, मजलूमों का हक उन्हें मिले, जो गरीब तबके की बड़ी तादाद में आबादी है, उनको उनका हक मिले, को पूरा करके यह सरकार उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा रही है। यही नहीं सड़कों का जाल पूरी तरह से बिछाया गया है। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 12 से 14 घण्टे तक से अधिक की बिजली आज उपलब्ध हैं। यह आईना दिखाने का काम करते हैं, जरा पिछली सरकार के कार्यकाल को देख लीजिये। अगर कोई विधायक अपनी जनसमस्याओं को लेकर धरने पर बैठता था तो उस पर मुकदमें लाद दिये जाते थे। लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलन्द करने का सबको हक है। उस सरकार के समय हम लोग विपक्ष में थे, हमारी विधायक श्रीमती सादाब फातिमा पर बिजली के मामले को लेकर उस सरकार ने 07 क्रिमिनल लॉ ऐक्ट का मुकदमा लगा दिया। एक महिला मुख्य मंत्री होते हुए भी एक महिला का उत्पीड़न किया गया, ऐसी इनकी सरकार थी। मान्यवर, इसी सदन में हमने सवाल उपस्थित किया था कि सहकारिता के क्षेत्र में सारी सोसाइटी उत्तर प्रदेश में बंद हो गई हैं, वह घूसघोरी और भ्रष्टाचार का शिकार हो गई हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। यूरिया का हाहाकार मचा हुआ था, उस सरकार में यूरिया नेपाल जा रही थी। किसान त्राहि–त्राहि कर रहे थे, रात को कहीं चुपके से धन्नासेठों के यहां, जो बड़े स्टाकिस्ट थे, लाईन लगाते थे, तो पुलिस पकड़ लेती थी और कहती थी कि तुम खाद चोरी से लाये हो हम तुमको जेल में डाल देंगे। ऐसी इनकी सरकार थी। नेता विरोधी दल तब सहकारिता मंत्री थे, इसी विधान सभा में मैंने सवाल उपस्थित किया था कि आप सहकारिता के क्षेत्र में समितियों को चालू करवा दीजिये, लेकिन इन्होंने नहीं किया। हम बधाई देंगे माननीय शिवपाल भइया जी को, अपने माननीय सहकारिता मंत्री जी को, हम इनके दीघार्यु होने की कामना करेंगे क्योंकि माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सारी सहकारी समितियों को चालू कराया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, यह हमारी सरकार का विजन है, यह सरकार की सोच है। हर क्षेत्र में खूब काम हो रहा है। विकास का काम हो रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किये जा रहे हैं, मेडिकल कालेज के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग कालेज के क्षेत्र में काम हो रहा है। डा0 लोहिया जी का सपना था कि कि ''रोटी, कपड़ा, सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो।'' हमारे नेता ने जो काम उत्तर प्रदेश में शुरू किया था, रिक्शा चालक से लेकर, गरीब मजदूर से लेकर, मजलूम बेबस से लेकर सबको हक और न्याय दिलाने का काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दरोगा, इन्सपेक्टर, दीवान और न जाने किन–किन विभागों में प्रोमोशन दे दिया गया है, पिछली सरकार में अगर एक कोई प्रमोशन होता था, तो उसकी बोली लगाई जाती थी। यदि एक ट्रांसफर होता था, तो उसकी फाइल पंचम तल

तक जाती थी और वहां बैठे हुये लार्ड जब देखते थे कि ठीक है, ओ.के. है, और अगर नहीं तो पत्रावली नीचे लौटा दी जाती थी। मान्यवर, इस कदर रिश्वतखोरी और अराजकता का माहौल था कि उत्तर प्रदेश कराह रहा था, उत्तर प्रदेश की बहादुर जनता को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने उस काले अध्याय को समाप्त किया और एक ऐसी सरकार बनाई और एक लोकप्रिय युवा मुख्य मंत्री को उत्तर प्रदेश की सबल बागडोर सौंपी, जिनका विजन है कि हर क्षेत्र के लोगों का विकास।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, थोड़ा और आ जाने दीजिये। बहुत जरूरी चीज है, अभी एक ही दल की बात हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आपको दल के ऊपर नहीं, बल्कि श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलना है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

जी मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, खन्ना जी इसको 152 पेज का दस्तावेज बता रहे थे, एक पुलिन्दा कह रहे थे मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सरकार बनाये थे, क्या–क्या वायदे किये थे और अभी रिजल्ट क्या आया है। मैं कहना चाहता हूं कि :–

सुकूं की धुएं में मचाने वालों ये हर तरफ इंतसार क्यों हैं,
बरस चुकी हो अगर घटाये हवा में गर्दे–गुबार क्यों है ?

आप ही का सवाल उपस्थित हुआ मान्यवर, आपने एक सवाल उठाया और फिरकापरस्ती की तरफ बात ले जाकर के धर्म, मजहब और पंथ के नाम पर उत्तर प्रदेश के विकास में जो रोड़ा बन रहे हैं, उनके लिये हम कहना चाहते हैं कि–

''हिन्दू और मुस्लिम के अहसासात को मत छेड़िये,
और अपनी कुर्सी के लिये जज़बात को मत छेड़िये,
है कहां हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां,
मिट गये, सब कौम की औकात को मत छेड़िये,
छेड़िये इक जंग मिलजुलकर गरीबी के खिलाफ,
दोस्त मेरे मजहबी जज़बात को मत छेड़िये।''

तो मान्यवर, यह मजहब की बात करके, नफरत की बात करके उत्तर प्रदेश का विकास रोकना चाहते हैं। मान्यवर, मैं पूर्वाचंल से आता हूं पूर्वाचंल से हवा उठती है कि ऐसा हो गया। वहां के विधायक हैं डा0 साहब, इस समय सदन में नहीं हैं। वहां एक स्वास्तिक यूरिया बनाने का कारखाना था। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कारखाना

बंद हो गया। आज इनकी दिल्ली में सरकार है, मैं मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली से पैसा लावे और वह कारखाना जहां हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गये, वह मर्ज से पीड़ित हो गये, बरबाद हो गये। इंसेफ्लाइटिस का रोग, जिसकी हमारी सरकार दवा कर रही है, दिल्ली की सरकार को भी इस पर सोचना चाहिये। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी लोकप्रिय सरकार पर आरोप लगा करके अपना मुँह छिपाना चाहते हैं। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा दिल्ली से आता है, हम मॉग करेंगे और कहेंगे कि हमारे साथी इस सदन के लोग दिल्ली की सरकार से मांग करें कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल हो। हम बधाई देंगें, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को कि इन्होंने इतने पुल बनवाये, इतनी सड़कें बनवाई। इसके अलावा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बधाई देंगे कि उन्होंने अकलियतों के पढ़ने के लिये उन्होंने मान्यवर, कक्षा–12 तक की व्यवस्था की है और 20 प्रतिशत अकलियती तबके के लोगों को न्याय और सम्मान तथा कौशल विकास योजना में स्थान दिया है। कृषि के क्षेत्र में, गन्ना के क्षेत्र में, हमारी सरकार ने जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, बस एक बात कहकर अपनी बात खत्म करेंगे। कृषि के क्षेत्र में, गन्ना उद्योग को बचाने के लिये हमारी सरकार ने खजाने से पैसा देकर गन्ना उद्योग को बचाया और किसानों की अस्मिता बचाई। यह लोकप्रिय सरकार है और अच्छी सरकार है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर पुनः समर्थन करते हुये और आपका शुक्रिया अदा करते हुये अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।

'श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, श्री राज्यपाल जी का जो 152 पेज का अभिभाषण है, इस पर सम्मानित नेता प्रतिपक्ष, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, नेता भाजपा, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नेता लोकदल, श्री दलवीर सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं और जो विचार रखे हैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुये कांग्रेस पार्टी द्वारा रखे गये सारे संशोधनों को जोड़ते हुये उन पर मैं बल देता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कई वर्षो से यह देख रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्रतिवर्ष पेजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछली बार 102 पेज का अभिभाषण था, इस बार 152 पेज का है और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में यह 300 पेजों का न हो जाय। तो मैं चाहता हूं कि पन्नों की रफ्तार ऐसे ही न बढ़ती रहे और जो कुछ भी इस अभिभाषण में लिखा गया है वह मैदान में भी नजर आये। चूंकि वह मैदान में नजर नहीं

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आता इसलिये वह इतने पेज का भाषण झूठ का पुलिन्दा लगता है इसलिये मान्यवर यह जरूरी है कि पेजों की संख्या उस रफ्तार से न बढ़ें, बल्कि कामों की रफ्तार उस रफ्तार से बढ़े, जिससे जनता भी संतुष्ट हो, इस पक्ष के बैठे हुये लोग भी संतुष्ट हों और उस पक्ष के लोग भी संतुष्ट हों।

मान्यवर, अधिष्ठाता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो उसने एक विजन रखा है, उसने एक सोच रखी है और काम करने का तरीका बदलने की कोशिश की है युवा मुख्य मंत्री के नेतृत्व में। उस नेतृत्व में माननीय शिवपाल जी, माननीय आजम खां साहब सहित तमाम मंत्री अपना सहयोग कर रहे हैं परन्तु स्थिति क्या है ? इनके तमाम सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब निरंकुश अफसरशाही मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशों की अवहेलना करती है मा0 मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना करती है जो आदेश होते हैं वह रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। जगह–जगह ऐसे बैरियर्स लगाये गये हैं कि इन सम्माननीय मंत्रियों और मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशों को रोक दिया जाए। समझ में नहीं आता सारे विधायक चाहे वह इस तरफ के हों या उस तरफ के हों वह मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलने जाते हैं और जब वह निकलते हैं तो बड़े खुश–खुश निकलते हैं कि हमने यह आदेश करा दिया, मा0 मुख्य मंत्री जी से यह आदेश करा दिया। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी का आदेश जब सम्बन्धित विभाग को भी नहीं पहुंचता तो हम लोग उन कागजों को ढूंढते हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश कहां गये। आप अपने विधायक प्रकोष्ठ में जा करके देखिये उधर के लोगों के साथ भी यही होता है। आखिर वह कागज कहां गायब हो गये, मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो आदेश किये थे वह तो ये किये थे पर अफरसरशाही जो आदेश करती है वह उसमें लिखती है कि पत्रावली को एक्जामिन करें और आख्या प्रस्तुत करें। मान्यवर, हमने मा0 मुख्य मंत्री जी से आदेश कराया कि यह काम कर दिया जाए, इसको सिक्योरिटी दे दी जाए, यह सड़क बना दी जाए, यह बिजली दे दी जाए, इन नहरों में पानी दे दिया जाए लेकिन मान्यवर, बड़े खुश–खुश आये और बड़े बे–आबरू हो करके तेरे कूचे से निकले। मान्यवर, स्थिति यह हो जाती है कि हम लोग जनता को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, सदन में मा0 शिवपाल जी बैठे हुए हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि आप और मा0 मुख्य मंत्री जी जो भी आदेश किया करें, मुझे पता है कि आपके डंडे में दम है, आपका डंडा चलना चाहिए जिससे कि अफसर लोग उन आदेशों का अनुपालन करें जो आप लोगों के मुखारबिन्दु से निकले हों। चूंकि मुखारबिन्दु से निकले हुए आदेश कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं इसलिए हमें बड़ा खेद होता है और सभी विधायक कहते हैं कि भाई यह क्या हो रहा है। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, हम सभी चाहते हैं कि सरकार अच्छी तरीके से काम करे और आपके कार्य जनता तक पहुंचे। मैंने कानून–व्यवस्था की बात की, आप तीन सालों का इतिहास उठा करके देखें, अगर मैं घटनाओं को सुनाना शुरू करूंगा तो पढ़ता ही चला जाऊंगा। आप स्वयं देख लीजिए सहारनपुर में तनिष्क के शो–रूम में दिन–दहाड़े 10 करोड़ की डकैती पड़ती है, आपने एस0एस0पी0 को सस्पेंड कर दिया,

आपने दारोगा को हटा दिया। आपके मथुरा में कारागार में गोलियां चलती हैं और जब अपराधी को लेने के लिए आगरा जाते हैं तो पुलिस स्कार्ट के बीच में बदमाश आते हैं और उस अपराधी को मार देते हैं और आप फिर कोई ऐक्शन ले लेते हैं।

इसी तरह से मुजफ्फरनगर में कोर्ट के अन्दर जज साहब के सामने एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को जान से मार देता है। अपराधियों के कितने हौसले बुलन्द हैं, पुलिस का तो कोई डर ही नहीं रह गया है, पुलिस का तो इकबाल ही खत्म हो गया है। एस0एस0पी0 नाम का दफ्तर खत्म हो चुका है जिले स्तर पर, एस0एस0पी0 दारोगाओं से घबराते हैं। मुझे पता है एक हमारे थाने का इन्स्पेक्शन था, एक अधिकारी ने कहा कि भाई आज डी0आई0जी0 साहब इन्स्पेक्शन पर आ रहे हैं। सिपाही मंजन कर रहा था तो उससे उसने कहा कि अरे लुंगी तो बदल लो डी0आई0जी0 साहब इन्स्पेक्शन पर आ रहे हैं तो उसने कहा डी0आई0जी0 आ रहा है तो क्या हुआ सरकार तो हम ही चला रहे हैं। तो मान्यवर स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है इसे देखने की जरूरत है जो आप कानून–व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून–व्यवस्था खत्म हो गई है क्योंकि ग्रासरूट पर दारोगाराज चल रहा है। आपके एस0एस0पी0, डी0आई0जी0, एडिश्नल डी0जी0 और डी0जी0पी0 फेल हो जाते हैं। आपका चीफ सेक्रेटरी काम्पीटेंट, आपका डी0जी0पी0 काम्पीटेंट, मुख्य मंत्री जी काम्पीटेंट, मा0 शिवपाल जी काम्पीटेंट तो इकबाल क्यों खत्म हो रहा है इस बात का जवाब जितने भी वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं उनसे मैं चाहता हूं। मा0 अधिष्ठाता जी, आप कानून–व्यवस्था के मामले में कितना भी कह डालिये कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस पर जब होम डिपार्टमेंट का बजट आयेगा उस समय कहेंगे। यदि आप देखें तो पायेंगे कि ए0टी0एम0 को गुण्डे बदमाश ऐसे ही उखाड़कर ले जाते हैं। बैंकों में खुलेआम डकैती पड़ जाती है उनका कुछ पता ही नहीं लग पाता है और आप तीन वर्षों में प्रदेश की स्थिति देखिये, बलात्कार की 3680 घटनायें, चोरी की 42,655 घटनायें, अपहरण और फिरौती की 6374 घटनायें घटित हुई, साम्प्रदायिक घटनायें 150 घट चुकी हैं, पुलिस का प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण ये घटनायें बढ़ी हैं और इनमें अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हो रही है। सरकार को सजग होना चाहिए, अब तो प्रदेश में अपराध का दर हर घण्टे गिना जा सकता है। आप दूर क्यों जा रहे हैं बहराइच में एक शेखर इन्जीनियर, जिसके पिताजी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष होते थे उसकी हत्या कर दी जाती है, जो भी इसमें शामिल है, सीबी0सी0आई0डी0 की जांच बिठा दी जाती है। उसके बुजुर्ग पिता जी कहते हैं कि केस को सी0बी0आई0 को ट्रान्सफर कर दीजिए, चाहे कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो सरकार को मैंने पत्र लिखा लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। शेखर इन्जीनियर की हत्या का मामला कितना गंभीर है लेकिन उसका खुलासा हो ही नहीं पा रहा है। मान्यवर, बिजली के लिए आपने पिछले साल बहुत बड़ा बजट रखा पर आज पूरे प्रदेश में बिजली कटौती के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, बच्चों के इम्तियान चल रहे हैं, हर शहर में जबरदस्त कटौती हो रही है, कुछ वी0आई0पी0 शहरों की बात छोड़ सकते हैं। ताज ट्रिपेजियम जोन जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखे हैं कि वहां बिजली की कटौती नहीं की जायेगी, वहां पर आठ–आठ, दस–दस घण्टे बिजली जा रही है। ठीक है, आप इम्प्रूवमेण्ट की बात कर

रहे हैं, आप ऊर्जा के नये स्रोत डेवलप करने की बात कर रहे हैं लेकिन वर्तमान स्थिति की भी बात तो करिये। आप नई योजनायें बना रहे हैं लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है उससे जनता का मतलब है, आप आगे की बात सोच रहे हैं लेकिन वर्तमान की सोच नहीं रहे हैं। बिजली के मामले में मॉनीटरिंग करने की जरूरत है, बिजली आप खरीदिये, सब जिलों में बिजली दीजिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमको दीजिए या आपको दीजिए। 403 विधान सभा क्षेत्रों में बिजली मिलनी चाहिए तभी तो आप इण्डस्ट्री चलायेंगे, कानून–व्यवस्था कण्ट्रोल करेंगे तभी तो औद्योगीकरण होगा। आज स्थिति यह है कि यदि आप सड़कों पर जांए मा0 शिवपाल जी बहुत कोशिश करते हैं सड़कें बनें, सड़कें बनती भी हैं परन्तु बार–बार मैं कहता हूं कि जब आप समग्र विकास की बात करते हैं तो 403 विधान सभा क्षेत्रों में काम होना चाहिए।

प्रदेश गड्ढामुक्त तभी होगा जब 403 विधान सभा क्षेत्रों की सड़कें गड्ढामुक्त हो जायेंगी, तब आम जनता को लगेगा कि शिवपाल जी लोक निर्माण मंत्री हैं और वह चाहते हैं, पर आई डोन्ट नो क्यों नहीं हो पाता है स्थिति यह है कि सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, क्वालिटी में इम्प्रूवमेण्ट हुआ है। माननीय मंत्री जी जरा नजरें इनायत इधर के लोगों पर कर दीजिए। आप आदेश कर देते हैं स्वीकृत, आप आदेश कर देते हैं कि धन आवंटित करें, आप आदेश कर देते हैं कि आगणन बनायें परन्तु स्थिति क्या है कि आपके कहने के बावजूद भी जो प्रमुख सचिव रहते हैं, जो इन्जीनियर इन चीफ रहते हैं अब पता नहीं क्या ऐसा मानक है या बाद में कोई इशारा होता है परन्तु मैं नहीं समझता शिवपाल सिंह जी में कोई डुप्लीकेसी की बात नहीं है, जो कहते हैं वह करते हैं, परन्तु वह हो क्यों नहीं रहा है? इसके लिए मैं सदन में बात कर रहा हूं। अगर शिक्षा की बात करें तो बेसिक शिक्षा का आलम यह है कि स्कूल सारे केन्द्र सरकार के सहयोग से खुल चुके हैं परन्तु अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते, अधिकतर समय मिड–डे–मील के चक्कर में निकल जाता है। अभी आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की उसमें स्थिति क्या है कि कुछ मॉडल स्कूल्स बने वहां के अध्यापकों ने मेहनत करके काम किया लेकिन अब आप वहीं के अध्यापकों को हटा रहें हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी क्या पॉलिसी है जिनकी वजह से मॉडल स्कूल चल रहे हैं। बहरहाल बेसिक शिक्षा में इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा की बात करूं। नकल माफियाओं के ऊपर आज हम लोगों ने मुद्दा उठाया। नकल माफियाओं ने हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में हद कर रखी है, पुलिस मिलकर नकल करा रही है, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो नकल करके हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट पास करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, वह एक अप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते। नकल कराने उनके पैरेंट्स भी चले जाते हैं, पुलिस की मद्द रहती है स्कूल वाले मिले होते हैं, सरकार को सख्ती से निपटना होगा। आज उच्च शिक्षा का तो बेड़ा गर्क हो गया है वाइस चासन्लर्स का इन्स्टीट्यूशन एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बन गयी है। आज प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको उठाकर देख लीजिए फर्जी मार्कशीट का घोटाला फर्जी डिग्रीज का घोटाला, रिजल्ट का देर से आना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना आपके डिग्री कालेजेज में प्रोफेसर पढ़ाते नहीं हैं उनकी स्थिति यह है कि तनख्वाह मिल रही है

80 हजार लेकिन एक घंटे के लिए जाते हैं लेक्चर ही नहीं देते बच्चे गायब फर्जी अटेंडेंस क्या होगा इस प्रदेश का जहां उच्च शिक्षा का यह हाल है। हमें अपने देश और प्रदेश के भविष्य की चिन्ता करनी है तो शिक्षा के ऊपर नैतिकता के आधार पर ईमानदारी के आधार पर हम लोगों को विचार करना होगा यह खाली 152 पेज के पन्नों पर लिखने से काम चलने वाला नहीं है।

यह नैतिकता का प्रश्न है मान्यवर, स्थिति यह है कि जब हम पर्यटन की बात करते हैं कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगरा में हेरिटेज मार्ट की बहुत बड़ी कांफ्रेस की दुनियां भर के लोग आए अच्छी बात है पर आप क्या फारेन टूरिस्ट की बात करते हैं आगरा में फारेन टूरिस्ट ताज देखने आता है इसी तरह से फारेन टूरिस्ट बनारस में घाटों को देखने आता है हम लोकल टूरिस्ट के बारे में कोई विचार ही नहीं करते आपका रिलीजियस टूरिस्ट है जो धार्मिक पर्यटक हैं आज उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड के जाने के बाद अपार संभावनाएं हैं फिर भी यदि पर्यटन के बजट को देखें तो कुल 80 करोड़ जबकि पर्यटन का बजट कम से कम 500 करोड़ का होना चाहिए। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर कोई काम होना चाहिए। स्थिति यह है कि लोकल टूरिस्ट के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है ठीक है पर्यटन नीति आपने बनाई है आप मथुरा वृन्दाबन, नन्दगांव, बरसाना हेरिटेज जोन है लेकिन आपने मथुरा जनपद का नाम ही नहीं लिया। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा कि मुख्य मंत्री जी आपने नाम नहीं लिया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ले रखा है परन्तु जब आगरा में समिट हुई तो वहां बात हुई बनारस की वहां बात हुई आगरा की वहां बात हुई लखनऊ की लेकिन मथुरा नदारद, इलाहाबाद नदारद। खाली हम विदेशी पर्यटकों को बढ़ाने के लिए कि हमारा फारेन रिजर्व आ जाएगा जितनी आमदनी आपकी लोकल टूरिस्ट से होती है रिलीजिएस टूरिस्ट से होती है उसके लिए हमें लोकल टूरिस्ट और रिलीजिएस टूरिस्ट के लिए इंतजामात करने होंगे। उनके लिए अच्छे आवासीय गृह बनाने होंगे यदि पर्यटक आवास गृह की बात देखी जाय तो वहां पर सुअर घूमते रहते हैं। प्रदेश के कुछ चुनिन्दा आवास गृह ही ऐसे हैं जिनकी स्थिति ठीक है वरना प्रदेश के पर्यटक आवास गृह उठाकर देखेंगे कि उनका वह पुरसाहाल है कि बिल्कुल बरबाद हो गए हैं आप क्या पर्यटन ठीक करेंगे जब आप पर्यटकों को बेसिक सुविधा नहीं दे सकते।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, अभी सात मिनट ही हुए हैं। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने हेरिटेज सिटीज की बात की है मान्यवर उत्तर प्रदेश में हमारे पास कोई ऐसा विभाग नहीं है जो प्रोजेक्ट रिपोर्टस बनाना जानता हो। कोई टेक्निकल आदमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना नहीं जानता जो यहां से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर जाती है वह बिल्कुल फेल हो जाती है केन्द्र सरकार में हम पिछड़ जाते हैं जबकि साउथ के राज्य अपनी डी0पी0आर0 एडवांस में बनाकर रखते हैं वह हायली टेक्नोक्रेट लोगों से अपनी रिपोर्ट बनवाती है लेकिन यहां पर आपके विभाग हैं जिनमें जे0ई0 जो चीफ बने बैठे हैं वह डी0पी0आर0 बनाते हैं जो वहां स्वीकार नहीं होता। जब तक आप अपना डी0पी0आर0 ठीक से बनाने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब

तक आप केन्द्र सरकार क्या दुनियां से कहीं से भी पैसा नहीं ला सकते हैं। इस व्यवस्था को सुधारिए जवाहर लाल नेशनल अरबन रेन्युअल मिशन क्यों नहीं सफल हुआ 1800 करोड़ की योजना बनी लेकिन कुल 280 करोड़ आया इलाहाबाद की यही पोजीशन रही बनारस की यही पोजीशन रही सात शहरों की यही पोजीसन रही मान्यवर, खेलकूद विभाग की हालत देखिए आपने बड़े बड़े शहरों में अच्छे स्टेडियम बनाने की बात की है आपने सैफई में अच्छा स्टेडियम बनाया आप लखनऊ में बढ़िया स्टेडियम बनाने जा रहे हैं परन्तु प्रदेश के उन स्टेडियमों की बात करिए जहां गधे घास खा रहे हैं स्थिति यह है कि वहां का स्वीमिंग पुल माननीय मुख्य मंत्री जी उद्घाटन कर देते हैं लेकिन मथुरा में बिजली की कनेक्टिविटी नहीं है पानी की बोरिंग नहीं है उद्घाटन हो गया माननीय मुख्य मंत्री जी का फोटो छप गया लेकिन स्थिति वहीं की वहीं रही। माननीय मुख्य मंत्री जी को यह चीजें अगर पता होंगी तो वह क्यों उद्घाटन कर देंगे स्थिति यह है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आप फारेन कम्पनीज से उन स्टेडियम का टाईअप कराइए प्रदेश में गांवों में खेलनीति लागू करिए इसी तरह से नगर विकास विभाग।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर पांच मिनट। मान्यवर आज स्थिति यह है कि सारे शहरों में सफाई अभियान चला रहे हैं। मोदी जी खुद झाड़ू उठाये खड़े हैं। इनके नगर पालिका, नगर महापालिकाएं, महाना जी बता रहे थे कानपुर के बारे में। बड़ी खराब स्थिति है।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री शारदा प्रताप शुक्ला जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य प्रदीप माथुर व सदस्य शारदा प्रताप शुक्ला जी के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माथुर साहब अब आप बन्द करिये। शुक्ला जी आप कहिये।

'श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डा0 संग्राम सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन पर जो बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिये आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मौजूदा प्रस्ताव में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो आया है यह बहुत आयामी है और इसमें समस्याओं का समाधान मिलता है। मान्यवर, जहां से मैं चुनकर आता हूं। 1985–86 में मैं निर्दलीय चुनाव जीतकर आया था। सरकार की तरफ से हमारे क्षेत्र से लगी एक अंसल हाउसिंग कालोनी का निर्माण किया गया जिसमें कई सेक्टर जे0 एच0आई0एल0एम0एन0 यह सब बनाये। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि सेक्टर एम, सेक्टर आई की कि वहां पर न तो सड़कें हैं, न सीवर है, न पानी है। आज वहां का इंसान बद से बद्तर जिन्दगी जीने को मजबूर है। कीड़े जैसी उसकी जिन्दगी है उससे बेहतर तो हमारे गांव हैं जहां हमारी सरकार ने

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था की है। मैं चाहता था मान्यवर कि इस कालोनी को, आशियाना कालोनी को, जिसको बने 26 साल हो गये जो आज तक नगर निगम में ट्रांसफर नहीं हुई। मैं चाहता हूं सरकार का ध्यान आकष्ट करते हुए कि.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अरे आप लोग शान्त रहिये। उनको बोलने दीजिये। आप बोलिये ना।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

मान्यवर, जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल जी का आया उसको मैंने पढ़ा। वह बहुआयामी है और उसमें तमाम ऐसी चीजें आई हैं जिनको सरकार करना चाहती है, माननीय मुख्य मंत्री जी जिसको आयाम देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यह अभिभाषण जिसमें पंचायती राज विभाग और तमाम चीजें इसमें जुड़ी हैं। मेट्रो का मामला, हमारे शहर में बड़ी समस्या थी बड़ी बुरी हालत थी जाम की। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेट्रो देकर हमारे लखनऊ शहरवासियों का, हमारे लखनऊ शहर का, बहुत उद्धार किया है। तमाम चीजें इन्होंने दी हैं। बिजली के तमाम पावर हाउस बनाये जा रहे हैं। कारागार विभाग की भी यही स्थिति है। मैं चाहता हूं कि यह सब काम हो रहे हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

'श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अधिष्ठाता जी, अभी यह जो माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण है यह सच में पूरा असत्य का संग्रह है। इसमें पहले ही पेज पर इन्होंने कहा है कि जनता से जो भी वायदे किये गये थे उनको पूरा किया जाये और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने लगभग सभी वादे पूरे भी कर लिये हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं इसी बात पर, अपने नेता विधान मण्डल दल श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा जो बोला गया है उस पर बल प्रदान करने के लिये खड़ा हुआ हैं। मान्यवर, प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है। इस अभिभाषण में सरकार द्वारा इस वर्ग को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है और मान्यवर सच कहा जाए तो यह सरकार किसान विरोधी है किसानों का अभी धान खरीदा नहीं गया तौल केन्द्र नहीं खोले गए हैं। आलू का बीज उपलब्ध नहीं हुआ है। खाद, पानी, डीजल ,बिजली यह किसानों का मौलिक अधिकार है। मान्यवर, प्रदेश में किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है तो सरकार ने जो भी कहा है वह असत्य कहा है। मान्यवर, मैं कुछ चीजों को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। सरकार के तीन वर्ष हो गए हैं इन तीन वर्षों में जो सरकार ने चुनावी वायदे किए उनको पूरा नहीं किया। इन्होंने

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा था कि हम किसानों का एक लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। मान्यवर, इन तीन सालों में किसी किसान का एक लाख तक का क्या किसी तरह का कर्जा माफ नहीं किया गया।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ कुछ बोलने पर शोर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाए रखें।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने दी जाए। मान्यवर, सरकार ने यह वायदा किया था कि हम गरीबों को कम्बल और साड़ी का वितरण करेंगे। मान्यवर, आप भी जानते हैं कि इन तीन वर्षों में वी0पी0एल0 कार्ड धारक किसी भी गरीब महिला को साड़ियॉ वितरित नहीं की गईं और 65 साल की उम्र जिसने पूरी कर ली है ऐसे किसी वृद्ध को कम्बल नहीं दिया गया। मान्यवर, यह सब चीजें हम सदन में बताना चाह रहे हैं अभी भी अवसर सरकार के पास है, इसलिए हम इस बात को संज्ञान में लाना चाहते हैं कि सरकार ने जो वायदे किए हैं उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े जोर–शोर से पहले साल तो सरकार ने हाई स्कूल पास विद्यार्थियों को कम्प्यूटर और टेबलेट बांटने का काम किया था। अब किसी को भी, जो हाई स्कूल पास हैं उनको कम्प्यूटर और टेबलेट नहीं दिया जा रहा है। कहां गए सरकार के वायदे, उत्तर प्रदेश में अब हाई स्कूल पास किसी भी विद्यार्थी को टेबलेट या कम्प्यूटर का वितरण नहीं हो रहा है। मान्यवर, इन्होंने वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में 35 वर्ष की आयु जिसने पूरी कर ली है ऐसे बेरोजगार युवाओं को हम एक हजार प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। साल में बारह हजार बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। किसी भी नौजवान को एक वर्ष के बाद से बेरोजगारी भत्ता देने का काम नहीं हो रहा है इन्होंने जोर–शोर से वायदा किया था कि जो रिक्शा चालक हैं इनको बैटरी चालित इनर्जी वाली रिक्शा देने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में किसी भी गरीब को बैटरी चालित रिक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया।

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन्होंने कहा था कि गैर अनुदानित स्कूलों में जो अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं उनका जीवन यापन करने के लिए उनको मानदेय देने का काम करेंगे। मान्यवर, शिक्षा किसी भी प्रदेश की महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है और शिक्षा एक तरीके से उजाला करने की व्यवस्था होती है। उसका भी गला घोंटने का काम किया गया है। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सरकार की दो प्राथमिकतायें हुआ करती हैं नम्बर एक सुरक्षा दूसरे नम्बर पर विकास, मान्यवर, यह सरकार सुरक्षा में भी फेल है और सच में सुरक्षा में घर में रहने वाला व्यक्ति सड़क पर चलने वाला व्यक्ति, खेत में काम करने वाला व्यक्ति,जहां भी व्यक्ति बैठा हो सुरक्षित हो तो अपना विकास कर लेगा। मान्यवर, पांच साल की अबोध बालिका से लेकर 60 साल की वृद्धा से बलात्कार की घटनायें हो रही हैं। कत्ल, डकैती, बलात्कार, अपहरण निरन्तर इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है। प्रदेश सरकार

कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जब विकास है ही नहीं प्रदेश की सड़कें सब टूटी हैं, बिजली में, सुरक्षा में,अस्पताल में, डाक्टर में,दवायें उपलब्ध कराने में, विद्यालय में अध्यापक पढ़ाने में, कहां तक बात की जाए यह सच में जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है इसको असत्य का संग्रह कहा जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति न होगी।

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। सपा सरकार ने यह वायदा किया था कि बसपा राज्य में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उन भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिये एक आयोग का गठन किया जायेगा। लोकायुक्त ने बसपा के भ्रष्टाचारियों की एक फेहरिस्त बनाकर दे दी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि बसपा सरकार में जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई ? आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया ? मान्यवर, दो–तीन बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे आंवला विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातों को जोड़ लिया जाए। रामगंगा नदी पर एक पुल का निर्माण कराया जाए। बुलड़िया गौरी शंकर में एक बिजलीघर का निर्माण करा दिया जाए। आंवला में रोडवेज डिपो का निर्माण कराया जाए। बेंदनखुर्द में राम नगर ब्लाक में राजकीय इण्टर कालेज का गठन किया जाए।

(श्रीमती रूबी प्रसाद के बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

धर्मपाल जी, अब आप खत्म करिये। बजट में भी आपको मौका मिलेगा।

'श्रीमती रूबी प्रसाद–

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मा0 मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने तीन साल के अन्तर्गत अपने चुनावी वायदे पूरे किये हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार जो कि किसानों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, पिछड़ों और दलित आदिवासियों की सरकार है और महिलाओं को सुरक्षा देने वाली सरकार हैं। किसानों को हम इसलिये कह रहे हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने किसानों के हित के लिये कामधेनु योजना एवं कुक्कुट जो योजना है उसकी शुरूआत की, ताकि समाज के जो सबसे अन्तिम व्यक्ति किसान हो, नौजवान हों, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। दूसरी बात नौजवानों से सम्बन्धित इसलिये कहती हूं कि उन्होंने सोचा कि नौजवानों को कैसे रोजगार मिले। इसके लिये उन्होंने कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने का काम किया ताकि इन नौजवानों को छोटे उद्योगों, लघु उद्योगों में काम करने का मौका मिले। चूंकि मैं महिला विधायक हूं इस नाते मैं बताना चाहती हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने महिलाओं के सम्मान के लिये, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष एवं आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना की ताकि हमारी महिलाएं सशक्त हों और उनको सम्मान मिल सके। महिला उद्योग योजना कैसे क्रियान्वित हो, इसके लिये उन्होंने इस योजना की शुरूआत

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की और जो पहले महिलाओं के लिये छोटे–छोटे उद्योग लगाने के लिये इण्टरमीडिएट की शर्त थी उसको उन्होंने कम करके दसवीं की शिक्षा निर्धारित की। निश्चित तौर पर आधी आबादी की सुरक्षा हेतु पूरे भारत में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु 1090 वूमन पॉवर लाईन की शुरुआत की गई है। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि जो बिजली के बारे में आए दिन हम लोग सुनते हैं इसके लिये हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने अथक प्रयास करके जनपद सोनभद्र का दुद्धी तहसील जो अकेले उत्तर प्रदेश का 60 प्रतिशत उत्पादन करता है हमारी पार्टी ने इस अनपरा 'सी', अनपरा 'डी' और ओबरा 'सी' परियोजना जो वर्षों से लंबित पड़ी थी उसकी शुरूआत करवाई ताकि बिजली की कमी को दूर किया जाए। उन्होंने बिजली की कमी को दूर करने के लिये कई जगहों पर सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण करवाया। जनपद सोनभद्र के हमारे विधान सभा के म्योरपुर ब्लॉक के जामपानी गांव में उन्होंने सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण करवाने का कार्य किया। निश्चित तौर पर 2012 से लेकर 2014 तक यदि देखा जाए तो 2012 से लेकर अभी तक 20 प्रतिशत ऊर्जा में वृद्धि हुई ताकि गांव की गरीब जनता को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सके। इसलिये उन्होंने ऐसा काम किया। तीसरी बात मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को और सिंचाई मंत्री, मा0 शिवपाल जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने हमारा विधान सभा दुद्धी जो है, वहां पर कनहर बांध बनना था, जो परियोजना 34 वर्षों से धनाभाव के कारण लम्बित थी, रुकी पड़ी थी, कई सरकारें आईं और गई, वहां पर शिलापट लगाने का काम किया लेकिन किसी ने नहीं सोचा, वहां के किसान भगवान भरोसे खेती करते थे लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री, शिवपाल जी के माध्यम से जो परियोजना 34 वर्षों से लम्बित पड़ी थी, नाबार्ड से कर्ज लेकर उन्होंने उस परियोजना की शुरूआत करवाने का काम किया। क्योंकि हमारी सरकार किसानों की सरकार है और किसानों के बारे में हमेशा सोचती है। निश्चित तौर से इस परियोजना के प्रारम्भ होने से 108 गांव और 02 ब्लाक लाभान्वित होंगे और 10 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे हमारे प्रदेश के किसान ही नहीं, हमारे बगल के जो पड़ोसी राज्य झारखण्ड और छत्तीसगढ़ हैं, वहां के किसान भी इस परियोजना के बनने से लाभान्वित होंगे। निश्चित तौर पर हम इस सदन के माध्यम से युवा मुख्य मंत्री और मा0 सिंचाई मंत्री, श्री शिवपाल जी को बहुत–बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। दूसरी बात हमारा जनपद सोनभद्र दलित आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पर सरकार ने स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत एस0सी और एस0टी0 के लिए स्टेडियम बनवाने का काम किया जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इंडीकेट है। निश्चित तौर पर इन्होंने दलित आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों आदि के लिए, मैं मजदूर इसलिए कह रही हूं कि जो समाज के सबसे अन्तिम व्यक्ति मजदूर होते हैं, जो घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, कोई भी योजना अगर मजदूर न हों तो सम्भव नहीं है। हमारे जनपद सोनभद्र में माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से सबसे ज्यादा 42 हजार मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 7 हजार साइकिलें बंटी, 2 हजार सौर–ऊर्जा बंटी और जो मृतक आश्रित चेक होता है, वह भी

1500 से लेकर 2000 लोगों को बंटा। इस प्रकार से यह मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, महिलाओं को सुरक्षा देने वाली यह सरकार है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती रूबी प्रसाद–

मान्यवर, एक लाइन बोल कर खत्म कर दूंगी। मान्यवर, निश्चित तौर पर मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि आए दिन हम लोग सुनते हैं कि महिलाओं के साथ यह हो रहा है, वह हो रहा है। निश्चित तौर पर यदि अनुमति मिलती तो मैं आंकड़े प्रस्तुत करती। हमारे प्रदेश की आबादी 21 करोड़ है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में यहां घटनाएं बहुत कम होती हैं लेकिन इसको बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करती हूं।

'श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं नेता, प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी और तमाम हमारे वरिष्ठ साथी जो बोले हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मान्यवर, जब चर्चा प्रारम्भ हुई तो हमारे दो भाई आदरणीय संग्राम सिंह यादव और श्री तेज नारायण पाण्डेय जी ने बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा। बात की शुरुआत करते हुए दो बातों पर बहुत जोर दिया। एक बदायूं रेप काण्ड पर और दूसरा मुजफ्फरनगर के साम्प्रदायिक सौहार्द पर। मान्यवर, बदायूं रेप काण्ड से मैं शुरूआत करना चाहता हूं। शायद पूरी जानकारी नहीं रही होगी, बदायूं रेप काण्ड में हुआ क्या कि दो लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाही शुरू की, पूरा विपक्ष और प्रदेश की जनता मांग कर रही थी कि आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है, आप जांच सी0बी0आई0 को सौंप दीजिए। लेकिन माने नहीं। किया क्या कि 04 लोगों को आनन–फानन में जेल में डाल दिया ताकि जनता और विपक्ष की आवाज बन्द हो जाए लेकिन जब बहुत मजबूरी हो गई तो सी0बी0आई0 को जांच सौंपनी पड़ी और उसके बाद जो रिजल्ट आया, इन्होंने निर्दोषों को फांसी पर लटकाने की पूरी व्यवस्था कर दी थी। उनकी फांसी भी हो जाती क्योंकि यह हो गया था कि बलात्कार के बाद हत्या करने पर फांसी तय है। इन्होंने तो उनको फांसी पर लटकाने की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन यह कहिए कि विपक्ष ने मांग किया और सी0बी0आई0 ने जांच की और उनकी जान बच गयी। आपको अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए, बल्कि आपको विपक्ष और प्रदेश की जनता की पीठ थपथपानी चाहिए, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी मोहनलालगंज की घटना है। पूरा सदन बैठा हुआ है और आप भी बैठे हुए हैं जो घटना सरकार की नाक के नीचे जिस तरफ मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट था पूरी सरकार लगी हुई थी वहां एक किडनी के बजाए दो किडनी कर दी गई एक किडनी से दो किडनी कर दी गई।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर थोड़ा सा और मौका मिला होता तो तीन किडनी कर देते। इतना ही नहीं सुनेगें तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब मोहनलालगंज घटना का पोस्टमार्टम हो रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी सरकार से कहने लगे कि पूरे पोस्टमार्टम की रिकार्डिंग होनी चाहिए। एक घण्टा बीस मिनट का पूरा पोस्टमार्टम हुआ जिसकी रिकार्डिंग बारह मिनट की हुई क्योंकि रिकार्डिंग करने वाले की बैटरी खत्म हो गई थी। यह सरकार की पोजीशन है। नीति बनाने से सरकार नहीं चलती नीति कानून–व्यवस्था संविधान के हिसाब से चलता है वह अलग बात है लेकिन कैसे इसे इम्पलीमेण्ट करेंगे यह होना चाहिए। हमारे भाई ने कहा कि प्रदेश में कोई घटना नहीं हुई कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ कोई दंगा नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में एक लाख लोग कैंपों में पिकनिक मनाने गए थे। वह पिकनिक मनाए मुश्किल से चार–पांच सौ लोग मरे। मैं मानता हूं कि यह चार–पांच सौ लोग पर्याप्त नहीं है अभी तो प्लानिंग 2017 के लिए चार–पांच हजार लोगों को गदर करवाने की है। जो स्टेटमेण्ट है हमारे मा0 सदस्य का मैं उनके रास्ते से गुजरता हूं उनकी बातों से सहमत हूं। उनके क्षेत्र में भी मात्र डेढ़ सौ दुकाने जला दी गई क्या हुआ मान्यवर यह तो बहुत छोटी बात है प्लानिंग बहुत लम्बा है। इस प्रदेश की जनता को इस सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जो प्लानिंग है सरकार की उसको समझने की आवश्यकता है। 2017 में अगर प्रदेश की जनता सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बनाएगी तो यह नेता कटवा करके गदर करवा करके फिर से कुर्सी लेने का काम करेगें। मैं यह बताना चाहता हूं मान्यवर कि अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बनाया गया सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का मतलब जहां हिंदू–मुस्लिम एक साथ हों सिख–ईसाई एक साथ हों जब बहुजन समाज पार्टी की गर्वनमेण्ट थी जब हम सत्ता में थे और एम0पी0 का चुनाव हुआ था तो जिसको सबसे बड़ा सांप्रदायिक पार्टी मानते थे वह चौथे नम्बर पर थी और जब आप सत्ता में थे और एम0पी0 का चुनाव हुआ तो 73 सीट पाकर के आप यह सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हैं। आप वोटों का ध्रुवीकरण कराते हैं काम बनाने का काम करते हैं। दृष्टिकोण की राजनीति करने वालों को मैं सावधान करना चाहता हूं कि अपनी नीयत बदल दें अपनी आदत बदल लें तभी इस देश में इस प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बन पाएगा। मेरा यह दिल कहता है मान्यवर कि अगर भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में आई है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है। मान्यवर मैं अब पूर्वांचल की तरफ आना चाहता हूं राज्यपाल जी के अभिभाषण में सबसे बड़ा स्वाइन फलू का मुद्दा इस समय प्रदेश में गरमाया हुआ। अभी हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यह कहकर चले गए कि पूरी दवाईयों की व्यवस्था है मैं सदन में यह घोषणा कर रहा हूं कि अभी मेडिकल कॉलेज में चले जाए और टेली फलू नाम की एक दवा वैक्सीन और जो मात्र तीन सौ रुपये में मिलती है अभी भी इस समय जांच करवा लें तो अभी विधान सभा सीट से इस्तीफा दे दूंगा मैं गारण्टी के साथ कहना चाहता हूं मैं कह रहा हूं अभी चले चलिए।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर–शराबे की स्थिति का उत्पन्न होना)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठिए।

श्री देव नारायन उर्फ जी0एम0सिंह–

अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि मैं बरसात के मौसम में अम्बेडकर पार्क घूमने गया। क्या मौसम को तलाश किया गया था मान्यवर। कोई व्यक्ति बरसात के मौसम में अम्बेडकर पार्क तो क्या कोई पार्क घूमने नहीं जाता। ऐसे मौसम की तलाश हमारे भाई किस मिजाज में किए होंगे एक गाना याद आता है कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया (हंसी) क्या मौसम को तलाश किए और उस समय उनको टपकता हुआ पानी अम्बेडकर पार्क में नजर आया बड़ा ताज्जुब महसूस होता है लेकिन रास्ते में गए थे तो जो बल्ब फ्यूज पड़े थे वह भी दिखाई दे दिया होता। जो वाटर पार्क लगा हुआ था वह फ्व्वारे खराब पड़े हुए थे वह भी दिखाई दे देता तो बड़ा सही होता। तो बेहतर होता। और जितना लखनऊ को पत्थरों का पार्क कहा जाता है। अगर मुम्बई से, मध्य प्रदेश से दिल्ली से 10 लोगों को सर्वे करने के लिए बुला लिया जाये तो अगर वह मायावती जी को दस में दस नम्बर ने दें तो कहियेगा।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों की टोटा–टाकी के मध्य)

और सुनिये। मान्यवर, कहते हैं कि लोहिया आवास गांव–गांव दिया। इनको बहन मायावती जी का शहरों में फ्लैट नहीं दिखायी देता है। अगर बहन मायावती जी के कामों की नकल यह सरकार छोड़ दे तो इनके पास कुछ बचता नहीं है। अभी हमारे पूर्वांचल के हमारे विधायक जी कह रहे थे। मान्यवर, पूर्वांचल में 1000 लोग इंसेफेलाइटिस से मर गये। और मेडिकल कालेज में सेंट्रलाइज आक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुयी। मा0 मुख्य मंत्री जी उद्घाटन करके आये, दूसरे दिन मेडिकल कालेज के जितने इंसेफेलाइटिस के मरीज थे उनको हटा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो गई आदमीयत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। सुधर जाइये मेरे भइयों। इतना ही नहीं मान्यवर। माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हुये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पिछली बार जब मैं राजस्व विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोल रहा था। मैंने सीलिंग का जिक्र किया था। मा0 राजस्व मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। इन्होंने घोषणा किया था कि जी0एम0 सिंह मैं जांच करवाउंगा। जांच की तो बात छोड़िये मैं प्रमुख सचिव, राजस्व से मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं–नहीं ऐसी कोई जांच की व्यवस्था यहां पर नहीं है। देखा जाएगा। मा0 मंत्री जी घोषणा किये हैं तो जाकर मा0 मंत्री जी से मिलो।

लोक निर्माण, सिंचाई एवं राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

माननीय अधिष्ठाता जी, अगर यह मा0 सदस्य कह रहे हैं तो एक तो पत्थरों की और राजस्व विभाग की, अगर कहें तो मैं तुरन्त जांच करा दूं। फिर यह जिम्मेदार हैं।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

ठीक है। धन्यवाद मा0 मंत्री जी।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

अच्छे–अच्छे लोगों को जेल जाना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 जी0एम0 सिंह जी, आपने एक सवाल उठाया। मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जांच कराने के लिए तैयार हैं।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

मैंने मा0 मंत्री जी को धन्यवाद दे दिया।

श्री अधिष्ठाता–

तो ठीक है।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

मा0 मंत्री जी हमारे महाराजगंज में जो सिंचाई विभाग आपके पास है।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

हम जांच करने के लिए तैयार है। फिर मा0 सदस्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप न करें। प्रस्ताव दे दीजिए।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

मा0 मंत्री जी आप तो कह ही दिये।

श्री अधिष्ठाता–

जी0एम0 सिंह जी, अब आप बैठें। समय समाप्त हो गया।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

मा0 मंत्री जी, महाराजगंज में नारायणी नदी में एक हजार एकड़ जमीन गिर गया है। उस पर ध्यान आकृष्ट करते हुए मा0 मंत्री जी मुआवजे की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

पहले कहिये जांच। प्रस्ताव कर दें।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

ठीक है, जांच करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 मंत्री जी इसकी जांच करा लें।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

आज ही लिखकर दे देना।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

ठीक है। मैं अपने नेता प्रतिपक्ष की बातों पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर दे दीजिए। मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच करायेंगे।

श्री मो0 इरफान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आज आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। मैं आज इस सदन को अपनी भावनाओं से पूरी तौर पर राज्यपाल महोदय के समर्थन में अपने को सम्बद्ध करता हूं और अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की जो लाभकारी योजनायें हैं वह इतनी अच्छी है कि अब तक का विधान सभा का जो कार्यकाल रहा हैं उनमें सबसे अच्छी योजनाएं हमारी सरकार की हैं। हमारी सरकार ने हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो जन उपयोगी योजनायें शुरू की हैं यकीनी तौर पर वह सब सराहनीय है। लोहिया ग्राम पिछले 03 सालों में अच्छी तरह से विकसित हुए हैं, यकीनी तौर पर बजट जो हमारा आने वाला है और माननीय गवर्नर महोदय जी ने जो इसमें इनडीकेट किया है कि दोनों वर्षों में 2100–2100 गांव लोहिया में चयनित किये जायेंगे, यह बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। दोनों वर्षों के लिए जिसमें 18 विभागों में 36 कार्यक्रम संचालित हैं, जैसे लोहिया आवास एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीबों को सीधे–सीधे लाभ पहुंचाती है। 305 हजार यानी 3.05 लाख का एक मकान उसके लिए कितना उपयोगी है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है नगरीय विकास के तहत गंगा जल आगरा की सप्लाई 130 किमी पाइप लाइन योजना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो अपने में अद्वितीय है। जिससे आगरा को गंगा का पानी सप्लाई होगा, पेयजल आपूर्ति होगी। मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर सारी दुनिया के लिए एक नमूना बनेगा।

जनपद मुरादाबाद और सम्भल के कास्तकारों के लिए बिलारी उपमण्डी की घोषणा एक बहुत बड़ा अद्वितीय कदम है। तेजी से बनवाये जाने के लिए मैं आग्रह करता हूं कि इसमें काम तेज कराया जाये। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 29 विभागों में संचालित 68 योजनाओं में से 20 प्रतिशत लक्ष्य जो अल्पसंख्यकों को रखा गया है वह एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है लेकिन कहीं–कहीं इसमें अगर लापरवाही हुई है तो उसमें मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा का एक गांव पैगा रफातपुर है उसमें ग्राम पंचायत में तैनात एक अधिकारी, एक कर्मचारी द्वारा अनियमितता की गयी है जिसमे समाजवादी पेंशन के 86 लाभार्थी हैं जिसमें केवल 05 अल्पसंख्यक और 02 सामान्य 17 ओ0बी0सी0 तथा 62 एस0सी0 के रखे गये हैं। इस तरह से जो असल मकसद था उसमें कहीं न कहीं चूक हूई है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। बाउन्ड्री, कब्रिस्तानों की बाउन्ड्री तथा अन्त्येष्टि स्थल पर जहां कुछ जगहों पर काम नहीं हुआ है, मैं यह चाहूंगा कि उसकी जांच करायी जाये और जो सरकार की योजना है कि अगर अधिकारी स्तर पर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका पूरी तौर पर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। एजुकेशन लोन जो योजना है उसके तहत अगर बैंकों ने कहीं लापरवाही की है तो उसको भी देखा जाना चाहिए। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वो दो जगह पड़ती है, मुरादाबाद जिला और सम्भल जिला।

मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक दरगाह है तिसावा उस तिसावा दरगाह में जाने से पहले लोग जो अजमेर शरीफ जाते है वह वहां से गुजरते हैं तो वहां एक बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल वहां बनाने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी उसको इन्तखाब कराया जाये। एक बेरनी शिव मन्दिर है जो मेरी विधान सभा क्षेत्र का बहुत आस्था वाला केन्द्र है उसको माननीय नेता जी ने धन दिया था, इस सरकार में दिये जाने की मांग करता हूं। हरित पट्टी विकास योजना के तहत जब बदायूं तक हरित पट्टी लग गयी है तो मुरादाबाद और रामपुर को भी शामिल कराया जाये। बच्चों के किसी भी क्लास में पढ़ने वाले दशमोत्तर या पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति का आधार धर्म नहीं होना चाहिए उसका आधार सिर्फ गरीबी होना चाहिए। इस आधार पर कुछ बच्चों के साथ नाइन्साफी हुई है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। श्रम विभाग में तैनात मुरादाबाद में एक अधिकारी ने जिन्होनें बहुत बड़ी अनियमितता की है। इस तरह के कारनामें हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। सरकार से मैं मांग करता हूं कि हमारी तरफ से पूरी तौर पर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। जो कहीं न कहीं पुरानी सरकार के समय के अधिकारी हैं, बेईमानी में लिप्त रहे हैं आज भी उनकी मानसिकता नहीं बदली, जो बदली जानी चाहिए। अन्त में बिजली व्यवस्था ठीक कराये जाने के लिए बधाई देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा किये चुनावी वायदे पूरे हुए हैं, प्रदेश तरक्की की तरफ अग्रसर है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का पूरी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के साथ अपनी बात खत्म करता हूं।

'श्रीमती अराधना मिश्रा ''मोना''–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के मा0 सदस्यों के संशोधन के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है, मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से जो विकास की रूपरेखा रखी गई है, उसकी हम सब सराहना करते हैं। मुझे उनके इरादे पर कोई संदेह नहीं है, परन्तु कुछ चीजें जिनका सुझाव मैं रखना चाहती हूं, शायद वह छूट गई हैं, उस पर मैं आप सबका ध्यान केन्द्रित करना चाहती हूं। सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण पर विचार करना चाहिए, मैं जानती हूं कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, परन्तु महिलाओं के अनुपात में उसी वर्ग की महिलाओं को उसी आरक्षण में बराबर से बांटा जा सकता है, उसी वर्ग की महिलाओं को ज्यादा मौके दिये जा सकते हैं, इससे आरक्षण की सीमा भी नहीं बढ़ेगी और सरकारी नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी भी होगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश एक युवा प्रदेश है, जहां युवाओं की संख्या साठ प्रतिशत से भी अधिक है, जब–जब हमारे नौजवानों को मौका मिला है, चाहे वह खेल के मैदान में हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, सभी जगह युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है,

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किन्तु लगभग 21 करोड़ की इस प्रदेश की युवाओं के हाथ अभी भी खाली हैं, इन्हें काम चाहिए, रोजगार चाहिए, इसके लिए प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पूंजीनिवेश को आकर्षित करना होगा। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी भी युवा हैं और उनकी मैं सराहना करती हूं कि आगरा एवं नोएडा समिट में जो उनका प्रयास रहा है, वह काफी सराहनीय है। मैं बल देकर के कहना चाहती हूं, हमारे वरिष्ठ मंत्री जी बैठे हैं, मा0 शिवपाल जी बैठे हैं, मैं उनसे बल देकर इस बात को कहना चाहती हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी बिना किसी आलोचना की परवाह किये इस प्रदेश में पूंजीनिवेश का वातावरण बनायें और उनका जो भी प्रयास रहेगा, हम सब उनके प्रयास में उनका समर्थन करेंगे।

मा0 मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव भी मैं देना चाहती हूं कि अगर पूंजीनिवेश करना है, उद्योग बनाने हैं, बढ़ाने हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे सामने चैलेन्ज है वह विद्युत की आपूर्ति का है। किसी न किसी तरह से हमें बेहतर विद्युत व्यवस्था की सुविधा प्रदेश में देनी होगी, तभी हम आकर्षित कर सकते हैं उद्योगों को। हम यही कहना चाहेंगे कि बेहतर विद्युत व्यवस्था प्रदान की जाय, अधिक से अधिक प्लाण्ट लगवाये जांय और लोगों को निवेश करने के लिए प्रदेश में बुलाया जाय। हम यह भी मानते हैं कि पिछले दिनों में विद्युत की जो सुविधायें हैं वह बेहतर हुई हैं, समस्यायें कुछ कम हुई हैं पर जब तक उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन जाता तब तक उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता, इसके लिए प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए हमें सबसे पहले बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया था, असेवित ब्लाकों में डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था उन्होंने की थी, जिसके परिणाम आज ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इन डिग्री कालेजों में पढ़कर शिक्षित हो रही हैं। आज हमें अपने नौजवानों को शिक्षा के साथ–साथ प्रोद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा भी देनी है, बिना इसके हम उनको रोजगार या स्वावलम्बी नहीं बना सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि शिक्षा के साथ–साथ आज ऐसे कोर्सेज को भी माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में जोड़ना चाहिए जिनसे रोजगार के बेहतर साधन हम उनको दिला सकें या स्वरोजगार की बेहतर व्यवस्था हम उनके लिए करा सकें। मैं इतना ही कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी, केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र की जो दो समस्यायें हैं, वह मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रतापगढ़ जनपद का एक इतिहास स्वतंत्रता संग्राम के समय से चला आ रहा है, एक बहुत पिछड़ा जिला है और स्वास्थ्य से सम्बन्धित बहुत दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। एक मेडिकल कालेज की स्थापना हम प्रतापगढ़ जनपद में करने के लिए आग्रह करते हैं। मा0 मंत्री जी, अटेहा–संग्रामगढ़ मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है और ये तीन–चार जिलों को जोड़ता है। इस पर फतेहपुर, कौशाम्बी, अमेठी, सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ जनपद के लोगों का काफी आना जाना है। इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिये हम आपसे आग्रह करते हैं और आखिर में बस इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आज महंगाई बढ़ रही है,

अगर आज उसकी मार जनता पर है तो हम विधायकों पर भी है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरह से आज सीमेण्ट, बालू, ईंट के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और जितनी भी विधायक निधि हम लोगों को मिल रही है, वह अपर्याप्त है। सदन के हम सब सदस्य अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं लेकिन जब यह विधायक निधि बढ़ाई जायेगी तभी यह सम्भव हो पायेगा और हम सब चुनाव लड़कर फिर दोबारा इस सदन में तब ही आ पायेंगे जब आपका संरक्षण हमको प्राप्त होगा। हम मा0 अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से यह मांग करते हैं कि मा0 मंत्री जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और हमारी बात मा0 मुख्य मंत्री जी तक पहुंचाइये। विधायक निधि में बढ़ोतरी होनी चाहिये और कम से कम 05 करोड़ तो होनी ही चाहिये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

' श्री विक्रम सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आज सदन को पहली बार सम्बोधित करने का मौका दिया। इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपका और सारे सदन का आशीर्वाद लेकर अपनी बात शुरू करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं फतेहपुर जनपद से आता हूं और फतेहपुर में मा0 नेता विपक्ष ने जब अपनी बातों को रखा तो स्वंतत्रता सेनानियों और बलिदानियों से अपनी बात शुरू की थी। मैं उसी बात से अपने आप को जोड़कर चलता हूं। फतेहपुर ने अपने हिस्से का खून, अपने हिस्से का पसीना देश की आजादी में बहाया, संताप झेला और बहुत से लोग जेल गये। चाहे वह 1857 की लड़ाई हो, चाहे वह 1947 की लड़ाई हो और चाहे वह इमरजेन्सी के खिलाफ लड़ाई हो लेकिन उसके बावजूद 68 वर्षों के बाद जनपद की स्थिति यह है कि यहां इतने सारे मा0 सदस्यों की बात सुनने के पश्चात् कहीं पर फ्लाई ओवर एक समस्या है, कहीं सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट एक समस्या है लेकिन हमारे जनपद में सीवर लाइन ही नहीं है। 68 वर्षों से आजाद इस भारत में मैं समझता हूं कि यह सदन के लिये, हमारे जैसे चुने हुये लोगों के लिये बहुत हर्ष का विषय नहीं है। 5 लाख लोग, 7 लाख लोग इस जनपद में रहते हैं। आज मैं उनका प्रतिनिधि हूं, मुझसे पहले और प्रतिनिधि रहे होंगे, मेरे बाद और प्रतिनिधि आयेंगे लेकिन जब हम समग्र विकास की बात करते हैं। जब हम लोहिया जी के विचारों की बात करते हैं, चन्द्र शेखर जी, जय प्रकाश नारायण और आचार्य नरेन्द्र देव जी के विचारों की बात करते हैं तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं।

सारी जातियों को, सारे सम्प्रदायों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सारे क्षेत्रों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इतिहास प्रदत्त जो व्यवस्था है, उसमें नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे सभ्यतायें विकसित हुईं। वह सब कुछ फतेहपुर में है जो किसी भी सभ्यता के विकसित होने के लिये आवश्यक है। यहां नदियां भी हैं, सौ–सौ किलोमीटर की गंगा एक तरफ, 100 किलोमीटर यमुना एक तरफ है। दिल्ली–हावड़ा रूट बीचों बीच से निकलता है। शेरशाह सूरी मार्ग से होते हुये जी0टी0 रोड और उसके बाद एन0एच0–01 और कई नामों से नवाजा गया हाई–वे बीच में से निकलता है। महोदय,

---

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सबके बावजूद विकास या तो इलाहाबाद चला जाता है या कानपुर चला जाता है। पलायन एक बड़ी समस्या बन गई है, प्रतिभायें पालयन कर जाती हैं, अर्थ पलायन कर जाता है जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा हुआ, अपने बच्चों की शिक्षा के लिये अच्छे क्षेत्रों को पलायन कर जाता है। अस्पताल हैं तो वहां डॉक्टर नहीं हैं। अस्पताल हैं तो वहां ट्रामा सेन्टर नहीं है। यदि हैं भी तो अधूरे बने पड़े हैं। मशीनें नहीं हैं, एम0आर0आई0 नहीं है। बड़ी मशीनें जो बड़े अस्पतालों में होती हैं, जिसके लिए 100–100 किलोमीटर, 150–150 किलोमीटर अपने परिजनों को लेकर जाना पड़ता है, रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। अधिष्ठाता महोदय, मेरा आग्रह यह है कि मेरा इस विषय पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इन सुझावों को यदि सरकार गंभीरतापूर्वक लेगी तो हमारे जनपद का कुछ भला होगा। हमारे जनपद में 13 ब्लॉक हैं, 13 ब्लॉकों में 8 ब्लॉक डार्क जोन में हैं। 47 वे जिले जिनका पानी दूषित है, उनमें से एक फतेहपुर भी है। अभिशप्त हैं वे लोग, जनमनादलित हैं। जनमना अभिशप्त हैं इस बात के लिए क्योंकि वह फतेहपुर में पैदा हो गए, तो कोई भी व्यवस्था उनको मिलने वाली नहीं है। बावजूद इसके कि वहां से एक प्रधानमंत्री हुए, वहां से कई मंत्री हो चुके हैं, लेकिन वहां पर व्यवस्थाओं की स्थिति यह है कि वहां कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहता जिसके पास थोड़े ही दिनों में कुछ पैसा आ जाता है वह या तो कानपुर या इलाहाबाद पलायन कर जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यमुना का किनारा होने के कारण, मौरंग लगातार वहां से निकाली जाती है। मौरंग को निकालना भी पड़ेगा निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक खनिज है लेकिन उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, वह सड़क जिस पर ये मौरंग के ट्रक चलते हैं और जो ओवर लोड होकर चलते हैं, वे सड़कें लगातार टूटी रहती हैं और कई बार कहने के बावजूद, उन सड़कों को बनाने का काम सरकार ने नहीं किया है।

मैं समझता हूं कि आप कितनी ही अच्छी सड़कें बनावा लें, वह सड़कें टूटेंगी हीं, क्योंकि ट्रक ओवर लोड चलते हैं। इन सड़कों को आर0सी0सी0 में कन्वर्ट करना मैं समझता हूं कि सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उस सड़क पर कभी मैं भी चलता हूं और कभी आप लोग भी चलते हैं और यह सड़कें सब के प्रयोग में आती हैं। जब अटल जी ने देश में सड़कें बनवायी थीं तब यह सोचकर नहीं बनवायी थी कि इस पर कोई जाति विशेष के लोग, सम्प्रदाय विशेष के लोग या पार्टी विशेष के लोग चलेंगे और मैं यह समझता हूं कि यह सारे सदन की इसमें एक भूमिका होनी चाहिए। एक विषय आया है इस 152 पेज की पुस्तिका में ''कौशल विकास मिशन''। कौशल विकास मिशन के तहत मैं समझता हूं कि अपने जो आई0टी0आई0 हैं, जितने भी हमारे आई0टी0आई0 हैं, उनको कौशल विकास मिशन के साथ जोड़कर और इम्प्लाईमेंट एक्सचेंज को उनके साथ जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो, जो रोजगारपरक हो। क्योंकि इस मिशन में कहीं–न–कहीं कमी तब आती है, जब सब व्यवस्थायें अपने तौर पर अलग–अलग काम करती दिखाई देती हैं और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी–जल्दी अपनी बातों को कहने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपका इशारा हो रहा है। हमारे यहां एक स्टेडियम भी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां उस स्टेडियम में सब कुछ तैयार है। वहां पर दो लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है जिसके कारण यह करोड़ों की सम्पत्ति बेकार पड़ी हुई है और जनता के उपयोग में नहीं आ रही

है। मैं चाहता हूं कि इसको अगर सरकार जल्दी करने का प्रयास करेगी तो यह हमारे जनपद की अच्छी सेवा हो पाएगी। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी पर दो मिनट का वक्त मैं आपका लेना चाहता हूं। मुख्य मंत्री महोदय, ने बहुत अच्छा अपने कार्यालय को आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रेक्चर के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। पेपरलैस सोसाइटी की तरफ बढ़ने का जो प्रयास समाज का है उसमें उन्होंने अपने कार्यालय से शुरू किया है लेकिन यह जो इनफॉरमेशन टैक्नॉलाजी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है। ये दुतरफा संवाद है, एकतरफा संवाद इसमें नहीं हो सकता। जब तक इसका जो एण्ड है, जो आप्टिकल फाइबर का एण्ड है जो जनपद मुख्यालयों तक आज सब जगह पहुंच चुका है, उसको जब तक गांवों से जोड़ने का काम नहीं होगा तब तक इस समस्या को लेकर गंभीरता यदि है भी तो वह दिखायी नहीं देगी, सिर्फ नीतियों और फाइलों में उस गंभीरता को देखा जा सकता है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले पेपरलैस करना है तो हमें विधान सभा को करना चाहिए। इतना बड़ा पुलिन्दा लेकर हम लोगों को रोज यहां से जाना पड़ता है और अगर यह सब नेट पर हो जाए और कम्प्यूटर पर हो जाए तो सूचना का आदान–प्रदान भी जल्दी होगा, अथैन्टिक होगा, कब हुआ, किस डेट पर हुआ, कितने बजे हुआ, इसकी पूरी जानकारी होगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बोलने के लिए आप समय बहुत कम दे रहे हैं और मेरे पास बोलने के लिए चीजें बहुत सारी हैं। मैं आपसे दो मिनट का और संरक्षण चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री विक्रम सिंह–

दो पंचायतों के सम्बन्ध में विषय हैं, जो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के भी नजदीक हैं। एक तो 1972 के बाद से न्याय पंचायतों का गठन समाप्त हो गया।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, किसी भी पार्टी ने इस पर विचार नहीं किया है और न्याय पंचायतों को खड़ा करने का काम नहीं किया है। मान्यवर न्याय पंचायतें, पंचायत स्तरों पर होती हैं और उनसे गांवों के लोगों को त्वरित न्याय मिलता है। वह व्यवस्था खत्म सी हो गयी है। मान्यवर, इसके अभाव में बहुत से ऐसे मुकदमें स्थापित हो गये हैं जो इनके माध्यम से हल हो सकते थे। मान्यवर, आपके सदस्य कह रहे थे इस माननीय सदन में कि हमारी सरकार किसानों की हमदर्द सरकार है तो उस सरकार को इन न्याय पंचायतों की प्रणाली को पुनर्स्थापित करने का काम करना चाहिये। मान्यवर, ताकि इन न्याय पंचायतों के माध्यम से गरीब किसानों को त्वरित, सस्ता और उन्हें अपनी जगह पर न्याय मिल सके। इसलिए मेरा कहना है कि आप इन न्याय पंचायतों की प्रणाली को रिजिव्यूनेट करने का काम करें। मान्यवर, संविधान में 73वां संशोधन हुआ था यह 1992 में हुआ था इसमें 29 बिन्दु ग्राम प्रधानों को दिये गये थे। मान्यवर यह सारे के सारे बिन्दु उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हैं। मान्यवर, यदि यह सभी बिन्दुओं को लागू करने का अधिकार ग्राम प्रधानों को दे दिया जाये, ग्राम सभायें, ग्राम सचिवालय सही तरीके से संचालित हो जायें और जो ग्राम के अधिकारी हैं उनको ग्राम प्रधान के अधीन कर दिया जाय तो बहुत

उपयुक्त होगा। मान्यवर यदि यह व्यवस्था लागू होगी तो यह प्रदेश की कार्य प्रणाली में एक माइलस्टोन साबित होगा। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको प्रणाम करता हूं धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो माननीय नेता विरोधी दल जी ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देने के लिये खड़ा हूं मान्यवर, मैंने सोचा था कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर इस बार सभी बल देने के लिये खड़े होंगे सारा सदन बल देगा हम लोग भी खड़े होंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमें महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा होना पड़ रहा है। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी को इस बात पर जरुर ध्यान देना चाहिये था कि यह सरकार जब सत्ता में आयी और आपने जो अपना एजेण्डा जनता को बताया उस पर कितना खरा उतरने का काम किया है जिसका ढिंढोरा यह सरकार पीट रही है। मान्यवर, इस सरकार ने अपने एजेण्डा में 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये कहा था। आज यह सरकार उन 17 जातियों के बारे में भूल गयी है। यह जो 152 पृष्ठों का एजेण्डा है अभिभाषण है इसमें मान्यवर कहीं भी इन 17 जातियों का जिक्र नहीं है। आपने इन 17 जातियों को ठगने का काम किया है। आपने अपनी चुनावी सभाओं में कहा था कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का काम करेंगे। मान्यवर, इस पर पूर्ववर्ती केन्द्र की सरकार में भी प्रस्ताव गया था आपके धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय भी उस सदन में मेम्बर थे उन्होंने उस सदन में इस पर चर्चा करने का काम नहीं किया। वे आज भी वहां मेम्बर हैं लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई है। मान्यवर, आपके सैफई के गांव में जब कार्यक्रम होता है तो आप देश के प्रधानमंत्री जी को न्यौता भेजते हैं और वे आते हैं वहां पर, लेकिन आपके माननीय नेता उस सदन में इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है आपको इस बारे में केन्द्र में कहना चाहिए था और प्रस्ताव भेजना चाहिये था।

(सत्तापक्ष की ओर से आवाजें प्रस्ताव गया है)

मान्यवर, माननीय शिव पाल सिंह यादव जी बहुत ही सीनियर मिनिस्टर हैं हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं आप इसमें पहल कीजिये और इन 17 जातियों को एस0सी0 में शामिल कराने का काम कीजिये। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके सामने तमाम गन्ना किसानों की बाते कही गयी, किसानों की हितैषी यह सरकार अपने आपको कहलाना चाहती है लेकिन गन्ना किसानों के बारे में कभी भी इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। आज तमाम चीनी मिले हैं जैसे मेरे यहां सरैंया चीनी मिल है पूर्वान्चल का सबसे बड़ा सरैंयां शुगर मिल कहा जाता था लेकिन उसको चलाने के बारे में तो सोचना दूर वहॉ के गन्ना किसानों का जो बकाया है जो वहां के गरीब किसानों का है उसके बारे में यह सरकार आज तक कभी भी गम्भीर नहीं हुई और न ही दबाव

बनाकर उन गरीब किसानों को बकाया दिलाने का काम यह सरकार कर रही है। आज तमाम बाते हैं सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही तो बेरोजगारी भत्ता किसको मिलना चाहिए इसका सर्वे कराने का काम नहीं हुआ और जिनको मिलना चाहिए बेरोजगारी भत्ता उनको नहीं मिल रहा है। आज तमाम सरकारें आई, आप खनन की बात करते हैं आज यह सरकार कहती है कि हम मुछुआरों के बड़े हितैषी हैं, पूरे प्रदेश में मछुआ के बारे में निषाद, मल्लाह, केवट के बारे में सरकार कहती है लेकिन मैं कहता हूं कि यह सरकार केवल कहती है सरकार के मुखिया कहते हैं लेकिन कभी भी इस समाज के बारे में इसको कभी गम्भीरता से नहीं लिया गया। आज जो बड़े बड़े पट्टे हैं तालाब के वह माफियाओं के हाथ में जा रहे हैं मैं कहना चाहता हूं मत्स्य पालन विभाग है वह विभाग इस पर हस्तक्षेप नहीं करता आज राजस्व विभाग के हाथों में सारा मामला है।

मत्स्यजीवी सहकारी समिति में देने में इधर उधर टहला करके कभी कोई कहता है कि मत्स्य पालन विभाग की तरफ जाओं, मत्स्य पालन विभाग में जाकर के अपनी बात करों तो मत्स्य पालन विभाग कहता है मैं क्या करूं राजस्व विभाग इसका मालिक बन बैठा है इसलिए मैं कहना चाहता हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा और यह समाज आपको समझाने के लिए तैयार हो जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समाज के प्रति आप संवेदनशील होइये और इसको राजस्व विभाग से हटा करके इसको मत्स्य पालन विभाग में ले जाने का काम अवश्य करिये। एक विभाग के पास में अगर होगा तो निश्चित रूप से मत्स्यजीवी सहकारी समिति का विकास हो सकता है। आपकी संवेदना है आप चाहते हैं सहकारिता बढ़े, आप सहकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मत्स्यजीवी सहकारी समिति भी सहकारिता के अन्तर्गत आती है। यह सरकार संवेदनशील होते हुए भी कभी भी मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के बारे में सोचने का काम नहीं किया और एस0सी0 बी0सी0 को कभी रिकोगनाइज करने का काम नहीं किया जिससे सारी सुविधाए इन मछुआरों को मिले। मछुआरों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले लेकिन ऐसा कोई कदम सरकार ने उठाया नहीं इसलिए मैं नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि अगर सरकार मछुआरों के प्रति संवेदनशील है क्योंकि सरकार कहती है कि मैने मछुआरों के आवास का पैसा बढ़ा दिया इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें हम सरकार को बधाई देते हैं उन्होंने इसको बढ़ाकर लोहिया के बराबर किया इसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं लेकिन एक बात और है जिस पर सरकार संवेदनशील नही हुई। मछुआ समाज का व्यक्ति जब आपदा आती है तो जा करके अपने जान की बाजी लगाकर लहरों से खेलता है, लोगों को बचाने का काम करता है लेकिन इस सरकार ने मछुआरों का बीमा 5 लाख भी नहीं किया, किसानों के बराबर का भी नहीं किया वह 2 लाख रुपया तक सिमटकर रह गया जबकि इसका बीमा 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपया होना चाहिए लेकिन किसानों के बराबर भी नहीं हुआ, 5 लाख का भी बीमा नहीं हुआ इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि निश्चित तौर से मछुआरों के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह 152 पेज का पुलिन्दा जिनको आवश्यकता है उनके साथ एक खिलवाड़ करके रख दिया गया है।

मान्यवर, आज तमाम बाते हैं किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए, गरीब किसानों ने जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया था वह आज भी इस आशा में बैठे हैं कि सरकार कर्ज माफ करेगी अब माफ करेगी, अब माफ करेगी जिनके पास थोड़ी भोड़ी जमीन भी थी वह भी गिरवी रखने की कगार पर आ गये है लेकिन उनके ऋण आज तक नहीं माफ किये गये हैं उनको प्रलोभन देकर सरकार ने उनको ठगने का काम किया है। केवल उनको लालच देकर, प्रलोभन देकर, उनको ठगने का काम सरकार ने किया है। इसलिए मान्यवर, यह सरकार काम किसी और का और नाम अपना करना चाहती है। जैसे कि गांव में कहते हैं कि सरकार बड़े से टीले पर खड़े होकर ऊंचा बनने वाला सपना दिखाने का काम कर रही है। सरकार तमाम दावे करती है कि श्रम विभाग में यह मिलता है, वह मिलता है, लेकिन श्रम विभाग में पैसा कहां से आता है, किसका पैसा है, इस पर कोई चर्चा नहीं करती है। आज बहुत भारी पैमाने पर गांव में बी0पी0एल0 कार्ड बनने की परेशानी है, जिनका बी0पी0एल0 कार्ड बनना चाहिये था, उनका बन नहीं पाया और जिनका बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बनना चाहिये था, उनका बन गया। जिनके पास खेत नहीं हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनके नाम दो–दो एकड़ जमीन दर्शा करके बी0पी0एल0 कार्ड से वंचित कर दिया गया है और जिसके पास जमीनें हैं, उनको भूमिहीन दिखाकर कार्ड दे दिये गये हैं। इससे भारी पैमाने पर गरीब लोग परेशान हैं। गांव के अंदर यह चीज सुधारी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आपकी सारी बातें आ गई हैं। कृपया अब आप बैठ जायें।

श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें तो अभी दो मिनट हुये हैं। कृपया मुझे बोलने दें। आप हम लोगों के संरक्षक हैं। मान्यवर, कुछ जरूरी बाते रह गई हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। आप अपनी बात संक्षेप में कहिये।

श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बात कहने वाला कोई सदन के अंदर नहीं होता है। मान्यवर, तीन लाख सोलह हजार जनता ने हमें जिताकर भेजा है और उसकी आस है कि हमारी भी बात कहने वाला कोई सदन के अंदर जायेगा। आज मैं आया हूं, मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज से पहले केन्द्र सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में मछुआ समुदाय के लोगों को विमुक्त जाति का दर्जा दिया गया था जिसमें ज्यादा कोई लाभ तो नहीं मिलता था, किन्तु उनको पढ़ने–लिखने की सुविधा मिलती थी, उनके बच्चों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाता था। इस सरकार ने सबसे ज्यादा दुश्मनी इस समाज के साथ निभाई है और इसको खत्म करने का काम किया है। स्पष्ट शासनादेश होने के बावजूद यह सरकार विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट बनाने का काम नहीं कर रही है। मान्यवर, इन्होंने

अपने आपको संवेदनशील बताते हुए खुद कहा कि हम 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करवायेंगे, लेकिन जो उन्हें पहले से मिला हुआ है, उसको भी इन्होंने खत्म करने का काम किया है। मैं इनसे दरखास्त करता हूं कि वह इन जातियों को जरूर जोड़वाने का काम करें ताकि जो यह सताई गई और दबाई गई पिछड़ी क्रान्तिकारी जातियां हैं, वह भी आगे बढ़ सके। मान्यवर, हम चाहते हैं कि इनके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और इनके भविष्य को सवांरने के लिए इनको भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं तमाम बातों पर बल देते हुए माननीय नेता विरोधी दल श्री मौर्या जी से मैं अपनी बात को सम्बद्ध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के लिए, मैं जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हम लोग शुरू से यही शब्द इस्तेमाल करते आये हैं अंग्रेजी में एच0ई0 और हिन्दी में महामहिम। किन्तु श्री प्रणव मुखर्जी जी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने इस बारे में निर्देश जारी किये और उन्होंने अपने लिए और बाकी राज्यपालगण के लिए कहा कि उनको महामहिम नहीं कहा जाये और सम्बोधन के लिए सम्मानजनक शब्द के रूप में माननीय शब्द का प्रयोग हो। सम्प्रति हमारे राज्यपाल श्री नाईक साहब ने भी कई बार इस पर आपत्ति जताई और महामहिम शब्द उन्होंने समुचित नहीं माना। हम लोग एवं माननीय सदस्यगण अपने सम्बोधन में जब भी इस माननीय सदन में राज्यपाल शब्द का जिक्र करते हैं, तो उसके पूर्व महामहिम शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि यह संसदीय नहीं है, लेकिन जब माननीय राष्ट्रपति जी ने और माननीय राज्यपाल महोदय ने स्वयं इस बात के लिए कहा है कि महामहिम शब्द उनके लिए प्रयोग न किया जाये, तो इस विषय में आप कोई निर्णय लेना चाहेंगे कि कार्यवाही में महामहिम शब्द का प्रयोग न किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

जब आलरेडी इसकी स्वीकृति हो गई है, तो माननीय राज्यपाल या श्री राज्यपाल कहा जा सकता है महामहिम नहीं कहा जाना चाहिये।

'श्री पूर्णमासी देहाती–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव जो श्री संग्राम सिंह यादव जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने की अनुमति दी है, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि जो अभिभाषण श्री राज्यपाल जी द्वारा दिया गया है उसमें उत्तर प्रदेश के विकास के लिये सारी चीजें विद्यमान हैं और हमारे साथी अभी 17 जातियों की बात कर रहे थे तो इनके जमाने में तो यह प्रस्ताव ही वापस मॅगा लिया गया था। जब माननीय मुलायम

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था और जब इनकी सरकार आई तो वह प्रस्ताव ही वहां से वापस मंगा लिया गया तो यह 17 जातियां, जो पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में शामिल होनी थी तो उसके सबसे बड़े दुश्मन यही लोग है। साथियों, जहां तक इस बात का सवाल है तो हम लोगों की सरकार बनने के बाद और माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 17 जातियों का प्रस्ताव फिर से भारत सरकार को भेजा गया है जो भारत सरकार में विचाराधीन है तो एक ही प्रस्ताव को बार–बार वहां भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले ही जा चुका है। रही बात, सहकारिता की, तो आपके जमाने में सहकारिता बिल्कुल समूल रूप से नष्ट हो गयी थी। जब हम लोगों की सरकार आई तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने, जितनी सहकारी समितियां हैं, सबको 5–5 लाख रुपया दे करके खाद बीज की व्यवस्था करने के लिये कहा और जो आपके जमाने में खाद लेने के लिये लोग लाठियां खाते थे तो वह बात खत्म हो गयी और खाद भी सही ढंग से हर जगह मिली है। तो साथियों मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिये जो भी चीजें अभिभाषण में कही गयी है उससे उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में भी मदद मिलेगी।

साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन तीन सालों में जितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, उतना किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। जहां तक आप बेकारी भत्ता की बात कर रहे थे, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के जमाने में बेकारी भत्ता तो आपने ही बंद कर दिया था, कन्या विद्या धन योजना बंद कर दी गयी और जब हम लोगों की सरकार बनी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार गठित हुयी तो बेरोजगारी भत्ता लोगों को दिया गया, लैपटाप भी दिया गया और कन्या विद्या धन भी दिया गया और बीच में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात रखी है कि जो लोग अच्छे नम्बर ले आयेंगे उनको लैपटाप सहित सारी सुविधायें दी जायेंगी। तो मान्यवर, कोई बहुत अधिक बात नहीं कहना है, आप लोग जब विपक्ष में चले जाते हैं तो राग बहुत अलापते हैं और जब सत्ता में रहते हैं तो गरीबों अनुसूचित जातियों और मछुवा की बात कभी आपके जमाने में नहीं आई। कम से कम इस सरकार में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तो मछुवा समुदाय के लिये आवास की व्यवस्था भी की गयी है और आवास मिल भी रहा है। यह सरकार जो है वह आगे भी इसकी व्यवस्था करेगी।

साथियों जहां तक गन्ना मूल्य की बात है तो आपके जमाने में चीनी मिलें बंद की गयी थीं। जहां तक सरदारनगर चीनी मिल की बात आपने रखी है तो उस मिल को आपके ही जमाने में बंद किया गया और करोड़ों रुपया बकाया उसी जमाने से चला आ रहा है, जबकि हमारी सरकार धीरे–धीरे उसकी भरपाई कर रही है। आपके ही जमाने में मेरे क्षेत्र और कुशीनगर के रामकोला, खेतान, लक्ष्मीगंज सहित दर्जनों चीनी मिलों को बेच दिया गया और आप ही की पार्टी के बड़े नेता रामकोला खेतान में चीनी मिल बन्द करा

करके उसी ग्राउण्ड में भाषण देने गये थे तब वहां की जनता और मजदूरों ने जूते से स्वागत किया था इसका रिकार्ड आप देख लीजिएगा। तो मान्यवर, मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से अपने वरिष्ठ मंत्री मा0 शिवपाल जी से यह निवेदन करूंगा कि इनके जमाने में जो कुकर्म किये गये हैं उस पर पर्दा डालने के लिए पिपराइल चीनी मिल और लक्ष्मीगंज चीनी मिल और अन्य बन्द चीनी मिलों को चलाने की कोशिश की जानी चाहिए क्योंकि उस इलाके की यह मुख्य बात है। आपके जमाने में रामकोला जहां आन्दोलन हुआ था वहां हजारों कुन्तल गन्ना छोड़ करके फैक्ट्रियों ने बन्द कर दिया। जबकि हम लोगों की सरकार आने के बाद कहीं एक भी गन्ना बाकी नहीं रहा है। तहसील प्रदेश में कई बने हैं और आपकी सरकार में मानक का बहाना बना करके कप्तानगंज और खड्डा तहसील को निरस्त कर दिया गया था, मैं मा0 राजस्व मंत्री श्री शिवपाल सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जनआकांक्षाओं को देखते हुए कप्तानगंज और खड्डा दोनों को तहसील घोषित कर दिया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। हमारे साथियों ने सारी बातें विस्तार से रखी हैं इसलिए मैं मा0 संग्राम यादव जी द्वारा पेश धन्यवाद् प्रस्ताव पर बल देते हुए एवं समर्थन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

कुं0 कौशल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, लोकतन्त्र के इस पावन मन्दिर में हमने देखा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त कितना लोग सच बोलते हैं और कितना लोग असत्य बोलते हैं। यहां बातें हुईं किसान विरोधी सरकार की, बातें हुईं अपराधमुक्त समाज की, कानून–व्यवस्था की। हालात यह हैं कि पिछली सरकार में हमारे जिले महाराजगंज में निचलौल तहसील के अन्तर्गत डिगही गांव में 11 ब्राह्मणों को जिन्दा जला दिया गया। पुलिस अधीक्षक सामने खड़े रहे और पी0ए0सी0 सामने खड़ी रही, कोई जवाबी कार्यवाही नहीं की गई। मैं बधाई देता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी को कि अभी इसी सरकार में आज से तीन महीने पहले हमारे ही जिले के बैदौली गांव में ग्रामीणों को पीटा गया और पीट करके उनके खेतों पर एक पूंजीपति को कब्जा दिलाया गया। जब इस बात का संज्ञान सरकार ने लिया तो तत्काल प्रभाव से वहां के एस0पी0 को हटाया और तुरन्त प्रमुख सचिव को जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी कि इसमें जो भी अधिकारी हैं उनको बर्खास्त करने का काम किया जायेगा, यह आश्वासन रहा सरकार का। जहां तक बात किसान विरोधी की है तो यहां पर गन्ने की बात की जाती है, मान्यवर, हमारा आधा क्षेत्र तो गन्नें से सिंचित है लेकिन बगल का देवरिया जिला है, मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश में उस समय जनेश्वर मिश्र जी हुआ करते थे और देवरिया के रामकोला में गोलीकाण्ड हुआ था जहां के विधायक श्री राधेश्याम सिंह जी बैठे हैं और क्या स्थिति घटी थी किसानों के ऊपर, वहीं बस्ती जिले के मुंडेरवा में दो–दो किसानों को गोली मार दी गई थी और उस समय हमारे बड़े भाई कुंवर अखिलेश सिंह जी सांसद थे हिन्दुस्तान की लोकसभा के अन्दर। किसानों ने ट्रेन रोक करके उतारने का काम किया था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की 26 चीनी मिलों को कबाड़ के भाव बेचने का काम किया वह महामहिम

राज्यपाल के भाषण पर टोपी लगा करके किसानों के किस सपने को साकार करना चाहते हैं यह देख करके शर्म आती है कभी–कभी कि गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए लोग कितना ख्या ग ग, बोलते हैं और कितना सच बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ख्या ग ग, शब्द असंसदीय है इसलिए असत्य कहिये।

कुं0 कौशल सिंह–

मान्यवर, मैं उसे वापस लेता हूं। जहां तक बताया जाता है कि लखनऊ के अन्दर अम्बेडकर जी के नाम पर पार्क बनाया गया। पार्क बनाना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन दलित समाज के लोग, दलित समाज की आवाज बुलन्द करने वाले लोग, जिन्होंने दलितों की झोपड़ी को नहीं देखा, जिन्होंने दलित समाज के नाम पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करके ऐसी व्यवस्था को लागू करने का काम किया कि आज सदन के अन्दर बलात्कार के ऊपर चर्चायें होती हैं। पालने का काम किसी ने किया, खिलाने का काम कोई कर रहा है, भरने का काम कोई कर रहा है। देश और प्रदेश के अन्दर स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि यहां पर दंगे–फसाद हुए। दंगा कराने वाले लोगों ने भी इसी प्रदेश के अन्दर भयमुक्त समाज की बात की। अभी उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के अन्दर लोक सभा का चुनाव चल रहा था बिजली की मांग की जाती है सदन के अन्दर, लेकिन शर्म आती है कि इसी हमारे गोरखपुर में वर्तमान प्रधानमंत्री जी उतरे तो उतरने के बाद उन्होंने एक नारा दिया जिनके कार्य क्षेत्र के बाहर की चीज थी उन्होंनें नारा लगाया कि हमारी सरकार बनवाने का काम करो, चौबीस घण्टे बिजली देने का काम करूंगा, दिल्ली के अन्दर सरकार बनती है और उसी दिल्ली सरकार के अन्दर राष्ट्रपति शासन चलता है, दिल्ली के अन्दर उन्होंने कहा कि भयमुक्त वातावरण देने का काम करूंगा। सहकारिता आन्दोलन के जननायक माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो इस सदन के मेम्बर भी रहे हैं जिन्होंने सहकारिता आन्दोलन को चला करके गांवों के किसानों को लाभान्वित करने का काम किया था। निश्चित तौर पर कहूंगा कि हमारा किसान चरमराया हुआ है। आज स्थिति यह है कि जिन लोगों ने गांव के अन्दर कर्ज लेकर सहकारी बैंकों में जमा किया और जिला सहकारी समितियों के द्वारा जिनका व्यापार चलता रहा, खेती चलती रही। आज स्थिति यह हो गयी है कि आज उनके घर में बच्चियों की शादी पड़ती है तो पैसा मांगने के लिए दर–दर भटक रहे हैं। गलती अगर किसी ने की तो समाज को सुधारने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, अगर बुराई कहीं से पैदा हुई, अगर हमारी तबियत खराब होती है हम इलाज कराने के लिए डाक्टर के पास जाते हैं लेकिन अगर डाक्टर यह कह देगा कि साहब तबियत आपकी वहां पर खराब हुई थी आप यहां क्यों इलाज कराने आये हो, तो इससे देश का और प्रदेश का विकास नहीं होगा। अगर हमको आगे जाना है तो निश्चित तौर पर सरकार को आगे आ करके समाज के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने की अपनी प्रणाली को मजबूत

नोट :–ख्या ग ग, यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करना पड़ेगा। जहां तक सवाल इस बात का है कि अभी बी–गैप पर चर्चा हो रही थी, हमारे एक भाई बी–गैप पर चर्चा कर रहे थे। संयोग से आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को बताना चाहूंगा, शायद विधायक जी भूल गये कि बी–गैप पर पिछली सरकार के अन्दर माओवादियों ने पूरे नेपाल के अन्दर हमारे अधिकारियों को मारकर भगा देने का काम किया था। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था कि काम हुआ ही नहीं था और कई सौ करोड़ रुपये निकाल लिये गये थे जिसमें माओवादियों ने कहा कि इसमें से हमको हिस्सा दो, अगर हिस्सा नहीं दोगे तो हम तुमको यहां खड़ा नहीं होंने देंगे। बधाई के पात्र हैं सिंचाई मंत्री जी कि मैंने इसी सदन के अन्दर यह मामला उठाया था और अब वहां पर कोई माओवादी आन्दोलन करने के लिए तैयार नहीं है। यह सच है कि नारायणी नहर से हमारे किसानों के खेतों की कटाई हुई, किसानों का खेत नहर में गया, नदी में गया, पलायन हुआ लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो हमारी सरकार को आगे आ करके समाज के साथ चलने की तत्परता दिखानी चाहिए। दूसरा, जहां तक सवाल इस बात का है कि किसान कैसे सुसज्जित होगा। अभी सरकार ने एक योजना चलायी थी कामधेनु योजना, डेयरी उत्पादन की व्यवस्था की। हम मानते हैं कि सरकार योजना लाती है लेकिन स्थिति यह है कि योजना लाने के बाद जब हमारा किसान स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के दरवाजे पर जा करके दरवाजा खटखटाने का काम करता है कि हमको डेयरी लोन चाहिए। इसी देश के अंदर प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनाने का काम करो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज देने का काम करूंगा। हालात यह है कि स्टेट बैंक के अन्दर के0सी0सी0 पर बिना 10 प्रतिशत दिये आज किसानों का लोन नहीं हो रहा है। तो पहले तो स्टेट बैंक के भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहे हैं जो भारत सरकार को बिलांग करते हैं और भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो रही है।

हमारा किसान अगर डेयरी लोन लेने के लिए जाता है तो उसको वहां से यह कहकर विदा कर दिया जाता है कि इसमें हम पैसा नहीं दे सकते हैं, आप हमारा क्या बिगाडोगे, तो सरकार योजना चला रही है तो इस योजना से हमारे किसानों को सिंचित करने की भी व्यवस्था करे। अगर वह सिंचित करने की व्यवस्था कर ले जायेगी तो निश्चित तौर पर डेयरी योजना का जो सरकार का प्रोग्राम है, आज स्थिति यह है कि आदमी अधिक हैं, जानवर कम हैं हम तो समझ ही नहीं पाते हैं हमारे यहां एक भैंस है वह 12 लीटर दूध देती है और 12 लीटर दूध घर में कम पड़ जाता है और जिनके घर में गाय, भैंस नहीं हैं तो कहां से दूध आ रहा है जिनके घरों में गाय भैंसें नहीं हैं कहां से उनके यहां दूध आ रहा है कहां से खोया बन रहा है कहां से मिठाई बन रही है अगर दुग्ध उत्पादन के पहले एक माह जब पेट में बच्चा रहता है तभी हम उसको सुविधा मुहैया नहीं करा पाते हैं। जब तक हमारा बच्चा प्राइमरी पाठशाला में पढ़ रहा है हम उसको अच्छे दूध से सिंचित नहीं कर सकते हैं उसके व्यायाम में अच्छा दूध नहीं पहुंचा सकते हैं तो न उसका मानसिक विकास हो सकता है न उसका शारीरिक विकास हो सकता है इसलिए डेरी दुग्घ उद्योग में सरकार को पहल करके उन लोगों के ऊपर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए जो इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यह मेरा अपना सुझाव है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो कानून व्यवस्था की स्थिति यहां तक आकर

पड़ी हुई है कि हम अपनी औलाद को नहीं संभाल पा रहे हैं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं सामाजिक तौर पर हालात यह है कि हम लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं और दरवाजे पर आने वाला फरियादी यह कहता है कि बाबू मेरा बेटा मेरे हिस्से के लिए पानी देना बंद कर दिया है। जब आदमी अपनी औलाद से न्याय नहीं पा रहा है तो मैं नहीं समझता कि जहां का नौजवान इतना भटक गया हो कि उसका बाप उससे पूछ न पाता हो कि एक घंटे से आप अपने मोबाइल से किससे बात कर रहे थे और अगर बाप पूछता है तो बेटा बाप से लड़ने को तत्पर हो जाता हो उस समाज के अन्दर हम नहीं मानते हैं कि एक मुख्य मंत्री पूरे प्रदेश को कंट्रोल कर सकता है। हमारे यहां जंगल पार्टी के लोगों ने चार–चार लोगों का अपहरण कर लिया मैंने 9 दिन में नैपाल सरकार के सहयोग से उनको लाने का काम किया अगर कोई विधायक की कुर्सी पर बिराजमान होता है तो अपने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करता है कि आप हमको वोट दो हम आपको न्याय देने का काम करेंगे। नैतिकता के साथ हर विधायक का न्यायिक कर्तव्य बनता है कि अपनी सरकार और अपने समाज के साथ बराबर की भागीदारी रखे सरकार का कर्तव्य बनता है कि हर विधायक के साथ भाईचारा और सामाजिक सामंजस्य बनाकर चले इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

'श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय–

अध्यक्ष जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे मौका दिया। मैं आदरणीय संग्राम सिंह जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हम इलाहाबाद से आते हैं हमने जब देखा कि जिस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण शुरू हो रहा है उस दिन हमारे कुछ साथी लोग टोपा लगाए हुए थे कुछ साथी लोग विधान सभा छोड़कर चले गए थे। बुकलेट को उन्होंने पढ़ा नहीं सोचा नहीं समझा नहीं जो मन में आ रहा है विपक्ष के साथी वही बोल रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि इस बुकलेट में उत्तर प्रदेश के किसान गरीब मजदूरों के लिए कौन सी ऐसी बात नहीं लिखी गई है जो गरीब के हित में न हो अनुसूचित जाति के हित में न हो किसान के हित में न हो कौन सी ऐसी बात नहीं है जो समाज के हित में न हो महामहिम के अभिभाषण में यह भी लिखा हुआ है कि हमारी सरकार ने सिंचाई माफ किया सिंचाई के लिए अमीन जब किसान के दरवाजे पर जाता था तो किसान को भागना पड़ता था इधर–उधर झांकना पड़ता था परन्तु आज हमारे किसान के पास अमीन नहीं जा रहा है तहसीलों के लाकअप में हमारा किसान बन्द नहीं हो रहा है। यह हमारी सरकार की सोच है उसको आपने नहीं देखा आपने टोपा इसलिए लगाया क्योंकि आपने पांच साल कुछ किया नहीं हमारे इलाहाबाद में आपकी बाण सागर परियोजना थी हमारे आदरणीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं उनकी कृपा से इलाहाबाद जनपद को 20 साल बाद पानी मिला आपने पॉच साल में एक बूँद पानी हमारे सिंचाई विभाग को देने का काम नहीं किया वाण सागर हमारी सरकार ने चालू किया कनहर परियोजना 20 साल से मिर्जापुर में बन्द थी उसको किसने चालू किया आपकी सरकार ने उस पर काम

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक नहीं शुरू किया आदरणीय शिवपाल यादव ने उस पर काम शुरू करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी सरकार ने सिंचाई माफ किया हमारी सरकार ने बच्चों से लेकर किसान मजदूर तक के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश का मजदूर आज लैपटाप इसलिए चला रहा है क्योंकि यह आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार है। अगर कलेक्टर का बेटा लैपटाप चलाता है तो आज हमारे गांव में बैठकर गरीब का बेटा भी लैपटाप चलाता है। यह हमारी सरकार की देन है। हमारी सरकार की देन है कि जिस कालोनी के लिये हमारा गरीब तरस रहा था। आप की सरकार में उसे 70 हजार रुपया मिलता था, 80 हजार रुपया मिलता था हमारी सरकार में आदरणीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से 3 लाख रुपया मिल रहा है। उसको शौचालय मुफ्त, बिजली मुफ्त, उसके छत पर पंखा मुफ्त मिल रहा है यह हमारी सरकार की देन है इसीलिये मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। हमारी सरकार ने क्या–क्या किया, उस पर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं। हमने लैपटाप उन गरीबों को दिया जिनकी झोपड़ियों में बत्ती जला करती थी लेकिन उनको पता नहीं था कि गरीबी होती क्या है। हमने उन गरीबों को कम्बल बंटवाया इस बार तहसीलों में। आप लोग दो कम्बल, चार कम्बल गांव में दिया करते थे हमने 10–10 हजार एक एक तहसीलों में कम्बल गरीबों को ठंडी में बचाने के लिये दिया, यह हमारी सरकार है। आप लोग कहते हैं मोदी साहब की सरकार, मोदी सरकार ने 9 महीने में एक पैसे का काम नहीं किया। कौन किसान का काम किया ? कौन गरीब का काम किया ? कौन मजदूर का काम किया ? हमारी सरकार ने 16–16 को–आपरेटिव बैंक जो बंद थे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने उन 16–16 को–आपरेटिव बैंकों को फिर से चालू कराने का काम किया है। यह हमारे भाई साहब कह रहे थे कि आपने चीनी मिल बन्द कराया। हमारी सरकार ने 16–16 को–आपरेटिव बैंक पुनः चालू कराने का काम किया है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, कि जिस सरकार में कभी विधान सभा चलती नहीं थी। मुख्य मंत्री का दर्शन करने के लिये विधायक लोग लालायित रहते थे। आज हमारे मुख्य मंत्री जी के बगल में चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो सब बैठकर मुख्य मंत्री से काम कराता है और बात करता है। मैं आपके मुख्य मंत्री को नहीं जानता, मैं उस समय विधायक नहीं था लेकिन जब सुनता हूं यहां बाबुओं से सुनता हूं, सचिवालय के कर्मचारियों से सुनता हूं कि मायावती के आने पर सिपाही का मुंह दीवार की तरफ कर दिया जाता था। आज क्या बात है, इसीलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया मैं उसका समर्थन करता हूं। आप कहते हैं अराजकता। विधान सभा में अराजकता कौन पैदा कर रहा है। कोई बाहरी आदमी नहीं आता है। हम आप विधायक हैं। जब हम आप विधायक होकर विधान सभा चलने नहीं देना चाहते, किसान की बात कहना नहीं चाहते, मजदूर के पक्ष में लड़ना नहीं चाहते। सिर्फ अपनी–अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। परन्तु हमारी समाजवादी पार्टी देश के किसान, मजदूर की मदद करना चाहती है। हर खेत को पानी देना चाहती है, हर घर को बिजली देना चाहती है, हर गरीब को कपड़ा देना चाहती है। यह हमारी समाजवादी

पार्टी की सरकार है इसलिये मैं संग्राम सिंह भाई साहब के विचारों का, धन्यवाद प्रस्ताव का, पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण रखा गया है, उसमें संशोधन जो माननीय नेता विरोधी दल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा रखा गया है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, मैं आपका आभारी हूं। अभी यह चर्चा चल रही थी तो माननीय अम्बिका चौधरी जी ने जो बात रखी थी कि महामहिम शब्द को भारत के राष्ट्रपति जी ने हटाने के लिये कहा है तो मैं इसको देख रहा था यह बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि इस पुस्तक में जो राज्यपाल जी के नाम के साथ जो पद लिखा गया है मुझे लग रहा है कि इसमें भी मान्यवर लिखना चाहिए या माननीय लिखना चाहिए था। ऐसा छपने में त्रुटि है, मैं समझता हूं कि इसको आगे जरूर देखा जाय। मान्यवर, आज हमारे पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सरकार के द्वारा और माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने की बात इसमें रखी गयी है। अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने के साथ–साथ कैसे हमारा प्रदेश विकास करे इस पर आज जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है।

मान्यवर, आज हमारे पूरे प्रदेश में.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

आपको जो मिला है इसमें महामहिम लिखा है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

पहले जो हम लोगों को मिलता था तो महामहिम लिखकर आता था अब महामहिम भी नहीं लिखा है और माननीय भी नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष–

श्री लिखा है, एक ही बात है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

नाम के आगे लिखा है पद के आगे नहीं लिखा है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैंने इसलिए पूछा कि कहीं त्रुटि से तो ऐसा नहीं हो गया है, आपकी बात स्वीकार कर ली है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है कई प्रदेश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल हमसे बड़ा है लेकिन आबादी यहां पर कम है तो इसमें कहीं न कहीं सदन को, सरकार को, यह चिन्ता करनी चाहिए कि प्रदेश की आबादी को कैसे नियंत्रण करें, अगर हम आबादी को नियंत्रण नहीं करते हैं तो जो अवस्थापना सुविधायें आप देते

हैं वह कई गुना बढ़ जाती हैं। इस पर गम्भीरता से सदन को विचार करना चाहिए, मैं भी पूरे दिन से चर्चा सुन रहा था यह जो अभिभाषण मा0 राज्यपाल जी का आया है, इसमें जो हमारे सत्तापक्ष के माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी मान्यवर, और जो हमारे माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए संशोधन रखे हैं लेकिन हम जानते हैं कि यह संशोधन न इधर के माने जाएंगे और न उधर के माने जाएंगे। यानि की सरकार ने जो योजनायें बनाई हैं उसमें कहीं न कहीं कमी है, त्रुटि है, और इस कमी को अगर वाकई में जो चर्चा हो रही है इसको सार्थक करना है तो इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो हमारे मा0 सदस्यों के सुझाव आए हैं चाहे वह सत्तापक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, उनको शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

मान्यवर, आज जनसंख्या नियंत्रण के साथ–साथ स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है इतनी खराब व्यवस्था है कि सरकारी अस्पतालों में गांव का वह कमजोर व्यक्ति जाता है जो कहीं और इलाज नहीं करा सकता है। सरकारी अस्पतालों के अन्दर एक तरह से लूट मची हुई है और इतनी स्थिति खराब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान के प्रस्ताव से आशाओं का चयन होता है उस चयन में जो पी0एच0सी0 के बैठे हुए डाक्टर हैं वह सीधे–सीधे इनसे मोलभाव करते हैं। अन्यथा उन प्रस्तावों को किनारे रखे रहते हैं। यह इतनी खराब स्थिति है सरकार का इतना बड़ा धन जो ग्रामीण क्षेत्र में, लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें मिलें, इसके लिए जाता है वह पूरी तरह से कहीं पर भी जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है इस पर भी सरकार को और गम्भीर होने की जरूरत है। आज मा0 लोक निर्माण मंत्री जी सामने बैठे हैं। हमारे क्षेत्र में राज्यपथ–43 जो फर्रुखाबाद से बदायूं को जाता है शाहजहांपुर के दो ब्लाक हैं मिर्जापुर और कलान, इनको जोड़ते हुए जाता है। इतनी हालत खराब है कि उसके ऊपर चलना मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रक उस पर आ रहा था। ईंटा पत्थर उस सड़क पर पड़े हैं वह पत्थर ट्रक के पहिए में आया वहां बगल में एक बहुत छोटा सा दुकानदार बैठा हुआ था उसके सिर पर पत्थर लगा और उसकी एक घंटे में मौत हो गई। इस घटना के विरोध में बड़ा आक्रोश हुआ सड़क जाम हुई और उसके बाद पी0डबलू0डी0 के जो इंजीनियर हैं उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखाई गई।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो मृतक है उसके परिवार को कुछ मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ सरकार ने इसमें लिखा है कि हम जिलों को जिले से जोड़ने वाली सड़कों को फोर लेन बनायेंगे। फोर लेन वह कब बनेगी यह तो पता नहीं है लेकिन वह बदायूँ तक सही है उसको फर्रुखाबाद से जो शाहजहांपुर का हिस्सा है उसको अगर हार्ड डिस्क प्लान्ट से सही करा लिया जाए तो कम से कम लोगों को चलने के लिए सुविधा हो जाएगी। इसको लेकर हमारे क्षेत्र में कई बार आन्दोलन हो चुके हैं। मेरे क्षेत्र की जो समस्यायें हैं उनको लेकर मैंने कई बार सदन में भी रखा है। हमारा क्षेत्र शाहजहांपुर की जो हमारी विधान सभा है जलालाबाद, वहां पर गंगा, रामगंगा और बहगुल नदी इसके अलावा कई छोटी–छोटी नदियां हैं। उन नदियों से बरसात के समय विकराल बाढ़ जब आती है तो कई गांव के गांव कटान से

इतना प्रभावित होते हैं। कई गांव के गांव उस कटान से इतना प्रभावित होते हैं कि लोगों के घर कट गए, लोग सड़कों पर आकर पड़े हुए हैं। बाढ़ को कैसे रोका जाए, इसके लिये पिछली बार जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो मैंने एक प्रत्यावेदन दिया था जिस पर सिंचाई विभाग ने उसका पूरा सर्वे कराकर एक पूरी योजना बनाई और वह योजना शासन में लम्बित है। 2012 में वह योजना आई थी और तब से वह लम्बित है। मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि जो योजना यहां लम्बित है उसको अगर आप लागू करा दें तो कम से कम वहां पर जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको निजात मिल जाएगी और जो गांव उजड़ रहे हैं वह उजड़ने से बच जाएंगे, यह मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक सोत नदी है उस नदी से उस पर जाने के लिये लगभग 35 से 40 गांव पड़ते हैं और उस पर पुल बनाने के लिये अभी लगातार क्षेत्र में आंदोलन भी चल रहा था। एक दिन मैंने जाकर वहां धरना खत्म कराया। उसके लिये सत्ता पक्ष के लोगों ने आश्वासन भी दिया था कि इस–इस पुल को बनवा दिया जायेगा।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दें, क्योंकि वहां पर यदि यह पुल बनता है तो 35 से 40 गांव के लोगों का जुड़ाव सीधे नगर क्षेत्र से हो जायेगा, ब्लॉक स्तर से हो जायेगा। मान्यवर, हमारे यहां एक गांव है पश्चिमी कबरा सलेमपुर, उस गांव में जाने के लिये एक बहुत बड़ा नाला पड़ता है। 2012 में उस नाले के ऊपर एक रपटा बनाने के लिये मंजूरी मिल गई। उसके बाद अखबार में उसका टेण्डर भी निकल गया, लेकिन फिर सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद पता नहीं क्यों उस टेण्डर को निरस्त कर दिया गया। मैंने जब वहां अधिकारियों से इस पर चर्चा की तो अधिकारियों ने बताया कि ब्रिज कार्पोरेशन के लोगों ने इसको रोक दिया है कि हम रपटा नहीं यहां पुल बनाएंगे। मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि जो स्वीकृत हुआ था उसको पुनः संज्ञान में लेते हुए सरकार वहां पर एक पुल या रपटा बनाने का काम करे जिससे कि गांव के लोगों की समस्या समाप्त हो सके। मान्यवर, हमारे यहां एक थाना पड़ता है परौर जनपद शाहजहांपुर में और परौर थाने से तीन गांव ऐसे लगते हैं जिनकी दूरी वहां से होगी लगभग 30 से 35 किलोमीटर और उन थानों से उन गांवों के बीच में एक और थाना पड़ता है कलान और कलान से उन गांवों की दूरी होगी लगभग 10 किलोमीटर। पता नहीं कब जब इनका गठन हुआ होगा तो वह तीन गांव भूलवश थाना परौर से जुड़े हुए हैं जबकि यदि उनको थाना कलान से जोड़ दिया जाए तो वहां के लोगों को न्याय भी मिले और वहां पर पुलिस भी आसानी से पहुंच सके। इस बारे में मैंने लिखित में भी दिया है और आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि इस पर जरूर विचार किया जाए।

मान्यवर, आज से लगभग 10–12 साल पहले हमारे क्षेत्र में मण्डी परिषद् से सड़कें बनाई गईं। हालत यह है कि दो–तीन गांवों में करनापुर, मुडिया खुर्द में मण्डी परिषद् की सड़कों पर ऐसा जलभराव है कि जैसे लग रहा है कि कोई नाला बह रहा हो और तीन–चार साल से मण्डी परिषद् की किसी भी सड़क के पुनर्निमाण की कोई योजना दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मैं चाहूंगा कि जो इस तरह की मण्डी परिषद् की सड़के हैं

अगर मण्डी परिषद् उनको नहीं बना पा रहा है तो उसको लोक निर्माण विभाग को दे दिया जाए, क्योंकि लोक निर्माण विभाग भी जिला स्तर पर उसको लेने को तैयार नहीं है। यदि मण्डी परिषद् से मरम्मत नहीं हो पा रही है तो उसको लोक निर्माण विभाग को देने का काम किया जाए जिससे कि वहां पर निर्माण हो सके, मरम्मत हो सके। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक गांव है भरतपुर पैलानी, यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वहां पर पी0एम0जी0एस0वाई0 से सड़क बनी थी। 2011 में सड़क बाढ़ के कटान से कट गई और उसके बाद तब से आज तक कई बार हमनें विभाग को लिखा तो हमारे पास जनपद शाहजहांपुर के डी0एम0 की तरफ से लेटर आया कि चूंकि वह फर्रुखाबाद का बार्डर पड़ता है और वह गांव आता है जनपद शाहजहांपुर में तो उस सड़क का निर्माण फर्रुखाबाद के पी0एम0जी0एस0वाई0 से करा दिया गया और जिला लगता है, शाहजहांपुर। क्योंकि गंगा के किनारे है तो इस बार्डर के कारण शाहजहांपुर जनपद इसको बनाने को तैयार नहीं और फर्रुखाबाद के लोगों ने उसका कोई पुरसाहाल नहीं रखा। हालत यह है कि जब गांव के लोग वहां से निकलते हैं तो बगैर साधन के या नीचे उतर कर आते हैं, बड़ी हालत खराब है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इसका संज्ञान ले करके शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद के बीच में जो पी0एम0जी0एस0वाई0 की टीम है, उससे वार्ता करके कहीं न कहीं से उसका निर्माण करा दिया जाए। मान्यवर, हमारे क्षेत्र के 60 फीसदी से ज्यादा गांव आज भी विद्युतीकरण से वंचित हैं और अभी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत एक सूची बनायी गयी। इस सूची में भी कई गांव वंचित कर दिए गए। इसके बारे में जब मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन लोगों ने मुझे यह बताया कि इसमें प्रत्येक वह गांव लिया गया है, जिसकी आबादी तीन सौ से ऊपर या पांच सौ के आसपास है। मैंने उनको ऐसे ही गांव बताये जिनकी आबादी पांच सौ या उससे ज्यादा है, वहां मतदान केन्द्र बना हुआ है। मान्यवर, मतदान केन्द्र वहीं बनता है जहां तीन सौ मतदाता कम से कम हों। वहां की आबादी पांच सौ से ऊपर हो गई है लेकिन पता नहीं किस तरह से सर्वे हुआ है कि उनको छोड़ दिया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इसका संज्ञान ले। पूरे प्रदेश में ऐसे और गांव भी छूटे होंगे, उनका भी दोबारा सर्वे करा कर ऐसे गांवों को इससे जोड़ने का काम किया जाए जो मानक के अनुरूप हैं और सूची में रह गए हैं। मान्यवर, हमारे यहां एक गांव है, संगहा, जिसको डा0 लोहिया गांव भी घोषित किया गया है। संगहा गांव डा0 लोहिया ग्राम में लिया गया है। लेकिन संगहा गांव जाने के पहले बहगुन नदी पड़ती है। लोहिया गांव होने के बावजूद भी वहां नदी पर कोई पुल नहीं है, एक पैन्टून पुल बना हुआ है, उस पैन्टून पुल पर भी स्थिति ऐसी रहती है कि गाड़ी रेत में फंस गयी, अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब उस गांव का चयन डा0 लोहिया ग्राम के अन्तर्गत किया गया है तो डा0 लोहिया ग्राम ऐसा ग्राम होना चाहिए जहां गाड़ी सीधे पहुंच जाए, कोई अधिकारी भी जाना चाहे तो जा सके। तो उसका जो सम्पर्क मार्ग है, वह बिना पुल के सम्पर्क मार्ग बन नहीं सकता है। तो बहगुल नदी पर एक पुल बना करके उस लोहिया ग्राम को जो उस गांव के अन्दर सी0सी0 रोड या और जो कार्य किए जा रहे हैं, वह तभी सार्थक होंगे जब वहां के सम्पर्क मार्ग को दुरुस्त करके और

पुल बना करके उसको विकसित किया जाए। यह कुछ बातें मैंने अपने क्षेत्र की रखी हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं नेता प्रतिपक्ष से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बातों पर बल देता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता एवं विपक्ष के अन्य सदस्यों की बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, यह 152 पेज का श्री राज्यपाल का अभिभाषण है, मुझे लगता है कि इसमें सरकार की आत्म प्रशंसा बहुत ज्यादा है। पहले पन्ने से ही अगर शुरू करें तो इसमें लिखा है कि हमने अधिकांश वायदे पूरे कर दिए हैं। मान्यवर, अगर ऐसा है तो पूरे सदन को सरकार को बधाई देनी चाहिए। लेकिन क्या मान्यवर, लैपटाप सब बंट गए, बेरोजगारी भत्ता सबको मिल गया या मान्यवर, इन्होंने जो वायदा किया था कि किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक देंगे, अन्य राज्यों में जो बोनस दिया जा रहा है, क्या इन्होंने दिया ? इन्होंने चुनाव में हर जगह वायदा किया था कि प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बेहतर होगी, क्या वह बेहतर हुई और उस वक्त जब कि वहां पर इतनी भीड़ थी कि टू व्हीलर से निकलना मुश्किल है।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा टोका–टाकी के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण इन्हें बोलने दीजिए।

श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

गोमतीनगर से इंजीनियर शिखा श्रीवास्तव का अपहरण होकर हत्या हुई। विधि की छात्रा गौरी श्रीवास्तव की जघन्य हत्या हो करके राजधानी में विभिन्न स्थानों पर उसके शव के हिस्से फेंके गए। ये लॉ एण्ड आर्डर है। पी0जी0आई0 के पास बमबारी हुई और युवा अधिवक्ता की हत्या हुई।

(सत्तापक्ष में मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ बोले जाने पर शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सुनिए बोलने दीजिए पहली बार सदस्य आए हैं। आप लोग बोलने दीजिए।

श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

मान्यवर इसी राजधानी में मैं कहना नहीं चाहता हूं किन्होंने लेकिन एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस को दौड़ा–दौड़ा कर पीटा। यह कानून की व्यवस्था है। मान्यवर, कहां वायदे पूरे हो गए। यह जरूर है कि मा0 मुख्य मंत्री जी मा0 लोक निर्माण मंत्री जी प्रदेश

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को एक बेहतर शासन देना चाहते हैं मैं उनकी नीयत पर नहीं शक करता हूं लेकिन वस्तुस्थिति क्या है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रदेश में जीडीपी 2012–13 में आपका ही शासन था 5.92 थी और 2013–14 में 5.14 हो गई दोनों साल आपका ही शासन था और कृषि विकास दर 4.73 थी 2012–13 में जो 2013–14 में 2.59 हो गई। मान्यवर यह विकास कहां हो रहा है कहां औद्योगीकरण हो रहा है। मुख्य मंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में निवेश आए औद्योगीकरण हो लेकिन कैसे होगा। मान्यवर, प्रदेश में उद्योग आने के लिए लॉ एण्ड आर्डर अच्छा चाहिए बिजली की उपलब्धता चाहिए। अभी परसों सदन में दो दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया उन्होंने ग्यारह सौ करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है और उसमें कहा गया कि एक लाख अड़तीस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा ग्यारह सौ करोड़ के निवेश में और मान्यवर, औद्योगीकरण कैसे होगा जब तक लॉ एण्ड आर्डर ठीक नहीं होगा और विद्युत की उपलब्धता नहीं होगी। आज तमाम ज्वलंत विषय है स्वास्थ्य का है, स्वाइन फ्लू का है सब देख रहे हैं न समुचित टीकाकरण हो रहा है न टेली फ्लू उपलब्ध है अभी तमाम मा0 सदस्यों ने जिक्र किया जिला अस्पतालों का लेकिन मैं राजधानी की बात करता हूं यहां पर संजय गांधी पी0जी0आई0 है मेरे ख्याल में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान होगा। पूरे प्रदेश से वहां पर मरीज आते हैं और हर समय सारे बेड फुल रहते हैं हालत यह है कि मरीज भर्ती नहीं हो पाते हैं। क्या सरकार सोच रही है कि वहां बेड बढ़ाने के लिए। आज हालत यह है लखनऊ राजधानी में तमाम प्रकोप चलते हैं इस वक्त यह स्वाइन फलू चल रहा है कभी डेंगू चलता है। वेंटीलेटर की कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पी0जी0आई0 में मेडिकल कालेज में लोहिया अस्पताल में सब जगह वेंटीलेटर फुल होते हैं और मरीज के पास क्या चारा है कहां ले जाए। मान्यवर इन सब पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी की आज हालत यह है कि कितनी भारी–भरकम फीस दे कर उच्च शिक्षा के लिए फीस दे कर और जो बच्चे पढ़ कर निकलते हैं एमबीए करके बीटेक, एमटेक करके और उनको दस हजार रुपये की नौकरी नहीं मिल रही है। मान्यवर, इस सबका भी जिक्र इसमें होना चाहिए।

श्री इकबाल महमूद–

उनको केन्द्र में भेज दीजिए।

श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

आप क्या कर रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार सिर्फ आठ–नौ महीने से है। इसके पहले केंद्र में दो–ढाई साल जिनका आपको समर्थन था और उनको आपका समर्थन था। उनकी सरकार थी तो आपने क्या किया। मान्यवर, नगर विकास में सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में बहुत तेजी से पलायन हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या की तुलना में इन्फ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहे हैं। श्री राज्यपाल के अभिभाषण में है कि एफोरडेबिल आवास बनाये जायेंगे उनकी कीमत भी दी है आपने 15 से 30 लाख। मान्यवर, समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो 15 लाख भी एफोर्ड नहीं कर सकता। जो

कालोनियां बन रही हैं उनमें जो मल्टीस्टोरी आवास बन रहे हैं उसकी तुलना में निम्न आय वर्ग और दुर्बल आय वर्ग के आवास बीस गुना ज्यादा बनने चालिए। जो फ्लेट लेता है उसके घर में कितने कर्मचारी होते हैं। कहां रहेंगे। मान्यवर, हर आवासीय क्षेत्र के पास कुछ स्पेस ऐसा होना चाहिए जहां अपर्स लगा सकें। उनके लिए फ्री हो जाये वहां लगायें। वर्ना अतिक्रमण की समस्या इसीलिए है। इन सबका विकल्प इसमें कुछ नहीं है। मान्यवर, जे0एन0एन0आर0यू0एम0 में सीवर पड़ी। मैं लखनऊ के बारे में जानता हूं। आज दो–दो साल हो गये हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो सकी है। क्या फायदा है ऐसी स्कीम से। जनता को उसका क्या लाभ मिला। मान्यवर, सरकार की मंशा नेक है। मैं आपकी मंशा पर शक नहीं कर रहा हूं। लेकिन कहीं न कहीं उसके इम्प्लीमेंट होने में कमी है। मेरे क्षेत्र में खुर्रमनगर चौराहे के पास दो साल से ट्रंक सीवर खुली पड़ी है। मैं स्वयं जाकर नगर विकास सचिव से मिला। उसमें गिरकर एक व्यक्ति की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गयी और सर्विस लेन पूरी बंद है जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक जाम रहता है। लेकिन उसका कोई उपाय नहीं है। ग्रीन और क्लीन आपका नारा है। लेकिन लखनऊ में पेड़ कट रहे हैं।

इमामबाड़े के पास सौंदर्यीकरण हो रहा है। नवाबी टाइम के पेड़ काट दिये गये। जो घण्टाघर आपने पहले देखा होगा और अब वहां कोई पेड़ नहीं है। सिर्फ बीच में घण्टाघर है। कूड़ा नष्ट करने के प्रोजेक्ट, उसमें पिछले एक दशक में कितना धन गया और उसका कोई उपाय नहीं है। आपने इसमें श्री जनेश्वर मिश्र पार्क का जिक्र किया है उसके लिए 321 करोड़ रुपये दिये हैं। श्रद्धेय जनेश्वर मिश्र जी हमारे बहुत श्रद्धा का केंद्र हैं। प्रदेश का कोई भी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता उन पर गर्व कर सकता है और उनकी स्मृति में कुछ भी किया जाये वह कम है। लेकिन मान्यवर, 321 करोड़ का वह पार्क और उससे पहले यह बना गये पार्क। अभी मा0 श्री जी0 एम0 सिंह जी कह रहे थे कि प्रदेश की हालत पर पत्थर भी रोयेंगे। अरे साहब, वह पत्थर रो रहे हैं। वह पत्थर के जो यह सब बना गये हैं वह कोई इको पार्क है कोई जीको पार्क बना रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े यह पार्क हैं उसमें जनता का पैसा लगा है लेकिन उसमें एक आदमी नहीं जाता है। आप दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर किसी उसमें बना दीजिए। इनके बनाये हुए किसी को डिस्टर्ब मत करिये। जो इन्होंने बनाया है वह वैसे ही रहे लेकिन वह जनता के उपयोग में आये। इन्होंने कुछ हजार करोड़ लगाये आपने कुछ सौ करोड़ लगाये। आप इनसे कुछ बेहतर हैं। आपने उसमें कुछ हरियाली भी लगायी है। लेकिन क्या इन्होंने या आपने कभी सोचा कि लखनऊ के अंदर हजारों पार्क हैं। क्या पूरा लखनऊ सिर्फ उन्हीं पार्कों में घूमने जा सकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इंदिरा नगर कालोनी है जिसमें 300 के लगभग पार्क हैं। आपने कभी कोई स्कीम बनायी कि हम इतने पार्क लखनऊ के विकसित करेंगे। कितने बदहाल पड़े हुए हैं। मान्यवर, इन सब चीजों का इसमें जिक्र होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

मान्यवर, इस सदन के सबसे नये विधायकों में मैं एक हूं और मैंने ऐसा सुन रखा है कि जो पहली बार बोलता है उस पर आपकी कृपा रहती है। आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर पर्यटन के लिए इसमें लिखा हे कि वृक्ष क्षेत्र आगरा, बौद्ध सर्किट और वाराणसी में अपार सम्भावनायें हैं पर्यटन की। वहां वास्तव में अपार सम्भावनायें हैं लेकिन सुविधाओं की बहुत कमी है लेकिन और भी बहुत से स्थान हैं, नैमिषारण है, इलाहाबाद प्रयाग है, अयोध्या है, चित्रकूट है यह सब तो समझ में आता है, यह नाम हो सकता है सरकार की प्राथमिकता पर न हो किसी विशेष कारण से। लेकिन और तो और इसमें लखनऊ का जिक्र कहीं नहीं है। लखनऊ एक बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र हो सकता है। लखनऊ के अन्दर बहुत सम्भावनायें है, भूल–भूलइया, इमामबाड़ा जैसी ऐतिहासिक इमारतें हैं यहां। अनेक पौराणिक मन्दिर हैं यहां पर कितने बाग और हवेलिया हैं। यहां पर मूसा बाग और कुकरैल जैसे वन हैं लेकिन यहां पर विकसित करने की जरूरत है। मान्यवर, पर्यटन इस समय दुनिया में बहुत बड़ा उद्योग हो रहा है और हम अपने आप विकसित कर सकते हैं लखनऊ में जू भी है, प्लेनेटोरियम भी हैं लखनऊ में क्या नहीं है ? लेकिन ताज्जुब है इन 152 पन्नों में लखनऊ को पर्यटन स्थान नहीं मिला।

मान्यवर, यह सारी चीजें होनी चाहिए इसमें। शिक्षा के लिए सारे अखबार रंगे पड़े हैं अभी एक रीडिंग न्यूज पेपर ने निकाला था 10,000 करोड़ रुपये का व्यवसाय हो रहा है नकल माफिया का। हमारी जब सरकार थी तब उसने नकल रोकी थी, उसके बाद से कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। लखनऊ के ट्रैफिक की हालत देख लीजिये, पूरे प्रदेश में ट्रैफिक की हालत के लिए कोई ठोस योजना होनी चाहिए। लखनऊ में हालत यह है कि विधान सभा के सामने हजरतगंज चौराहे में हर वक्त जाम रहता है। लिखा है इसमें कि 02 फ्लाई ओवर सरकार ने कम्पलीट करवाये मगर दर्जनों और भी जरूरतें हैं। मैं सुझाव देता हूं कि हजरतगंज में एक अण्डर पास बनवा दीजिये क्योंकि फ्लाई ओवर नहीं बन सकता उससे विधान सभा की ब्यूटी जाती है उधर हजरतगंज की ब्यूटी जाती है। यह सड़क लखनऊ की जीवन रेखा है यहां से इन्दिरा नगर, गोमती नगर की तरफ सारा ट्राफिक इधर से जाता है। आधा लखनऊ इधर से गुजरता है। तमाम स्थानो पर ट्राफिक सिपाही नहीं हैं। लखनऊ राजधानी होने के बावजूद दो–चार चौराहे छोड़ दीजिये ट्राफिक सिगनल नहीं हैं लखनऊ में। दो फ्लाई ओवर बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। यह मेरे सारे सुझाव हैं मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की दो–चार समस्यायें इसमें जोड़ना चाहता हूं। शंकरपुरवा प्रथम, शंकरपुरवा द्वितीय, इस्माइल गंज प्रथम, इस्माइल गंज द्वितीय, इन्दिरा प्रदर्शनी वार्ड यह ऐसे हैं जहां पर कोई विकास नहीं है अधिकांश एरिये में सड़क नहीं है, नाली नहीं हैं पेय जल व्यवस्था नहीं है। विधान सभा से 10–12 किमी दूर बिजली की आप बात कर रहे हैं परन्तु बिजली के खम्भे तक नहीं हैं। लखनऊ राजधानी में यहां से 10 किमी दूर बल्लियों के ऊपर तार लगे हुए हैं और वह बल्लियां समय के साथ नीचे से गल गयीं कई जगह तो ऐसे झुकी हुई हैं कि

आदमी सर झुका कर वहां से निकलता है। मैं चाहता हूं इसको भी उसमें शामिल किया जाये। गोमती नगर, इन्दिरा नगर, विकास नगर, गोमती नगर में जब एल0डी0ए0 ने कालोनी शुरू की, आवास विकास ने विकास नगर और इन्दिरा नगर शुरू की तो बीच–बीच में कुछ गांव है, जिन पर दशकों पहले यह वादा किया गया था मूल–भूत सुविधायें सरकार उपलब्ध करायेगी। आज तक गांव, गांव है, जहां गोमती नगर में इतने बड़े–बड़े सब पार्क बने हैं और ताज होटल बना है वहीं अगर आप बीच में जाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि यह गोमती नगर के बीच में है यह भी इसमें शामिल किया जाये। मैं फिलहाल आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद।

बाल विकास पुष्टाहार एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने भाई संग्राम यादव ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, इसके समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह अभिभाषण है, पूरा का पूरा अभिभाषण हमारी सरकार ने जो किया, मा0 अखिलेश यादव जी ने और पूरी सरकार ने जो किया है उसका एक आइना है। बार–बार कहा जा रहा था, अभी हमारे सदस्य महोदय कह रहे थे कि मैं पहली बार आया हूं, लेकिन आपके पिता जी कई बार इस सदन के सदस्य रहे हैं और नगर विकास मंत्री रहे हैं। उनकी निगाहें, आपने आभार व्यक्त किया कि बहुत उपरिगामी पुल बने, लेकिन आपकी सरकार में आपके पिताजी नगर विकास मंत्री रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दस साल सरकारें चली हैं।

श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

आज की समस्या के लिए 10–11 साल पुरानी सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं।

श्री वसीम अहमद–

10 साल गठबन्धन की सरकार थी, दस साल थे आपकी सरकार थी, तब नहीं देखा गया कि एक भी उपरिगामी पुल बनवाने का काम किया गया हो। हमारे मा0 अखिलेश यादव जी ने जो युवा मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने एक नहीं कम से कम दस जगहों पर उपरिगामी पुल बनवाने का काम किया लखनऊ शहर में।

श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

इंजीनियरिंग कालेज, रैदास मंदिर, मवइया ये सारे पुल किसने बनवाया ?

श्री वसीम अहमद–

महोदय, उस वक्त भी आपकी सरकार थी, भारतीय जनता और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, उस वक्त आपको कुछ कर लेना चाहिए था, अब तक ये काम क्यों बाकी रह गये, दस साल तक सरकार चलाने का काम आप लोगों ने किया, दोनों लोगों ने मिल करके, भाई–बहन ने। हम आपसे कहना चाहते हैं, उस वक्त निगाहें नहीं गईं। किसान बहुत टूटा जा रहा है, हमारे नेता जिनको हम भी अपना नेता मानते हैं,

विपक्ष के नेता हैं, आपकी सरकार थी, हमारे नेता हमारी सरकार के मा0 मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, किसानों के लिए जो दर्द उनके दिलो–दिमाग में था, वह किसी के दिलो–दिमाग में नहीं है। अगर कोई उसकी छाप पाया तो वह हमारे मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी के दिलो–दिमाग में किसानों को बढ़ाने के लिए और मा0 सहकारिता मंत्री मा0 शिवपाल यादव जी ने जो–जो करने का काम किया है, आज तक किसी ने करने का काम नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ की द किसान सहकारी चीनी मिल, मा0 अध्यक्ष जी आप भी जानते हैं, जिसको बेचने जा रही थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जब हमारे नेता मुख्य मंत्री थे मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने पैसा देकर उस चीनी मिल को चलवाने का काम किया था। जब चीनी मिल चली भाई रामदर्शन यादव के कहने पर, बात करने पर नेता जी ने उसे चलाने का काम किया, पैसा दिया और वह चीनी मिल चली। उस वक्त धरना देने का काम बहुजन समाज पार्टी के सारे नेताओं, हमारे चार लोग जीते थे और छः बहुजन समाज पार्टी के नेता वहां से जीत करके आये थे और वहां पर एक आन्दोलन किया था बैठ करके कहा था कि हम सारी निधि देने का काम करेंगे और इस चीनी मिल को चलाने का काम करेंगे, उस चीनी मिल को चलाने का काम तो नहीं किया, उस चीनी मिल को बन्द करने की व्यवस्था कर ली गई थी, लेकिन किसी तरह से आन्दोलन कर के वहां के किसानों ने और सारे लोगों ने इसको रोकने का काम किया। मा0 अध्यक्ष जी, वहां हमारा विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं है मुबारकपुर में, लेकिन कभी भेदभाव करने का काम हमारी सरकार ने नहीं किया, यहां तक कि चार सौ हजार करोड़ देकर के चीनी मिल को चलवाने के लिए हमारे नेता मा0 शिवपाल यादव जी ने और मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने वहां जाकर उसकी बुनियाद रखने का काम किया है और उस चीनी मिल को चलवाने के लिए 28 साल के बाद बड़ी सरकारें आई, बहुत सरकारें गईं, 28 साल तक किसी ने सहकारी चीनी मिल जो बन्द हो गई थी, बनना बन्द हो गई थी, उसको बनवाने का काम हमारी सरकार करने जा रही है, उसका शिलान्यास भी हो गया है, उसका पैसा भी चला गया है। रोना रोने वाले लोग हमेशा रोते रहेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी ने कभी रोने का काम नहीं किया कि पैसे की कमी है। जब हमने पिछड़ों को दिया था कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता तीन साल हमारी सरकार थी, हमने इन तीनों सालों में देने का काम किया था लेकिन उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई और इन चीजों को बन्द करने का काम कर दिया और हमारे ऊपर लांछन लगाया जाता है।

हमने लैपटाप देने का काम किया और अभी हमने बन्द नहीं किया, हमारी सरकार ने बन्द नहीं किया बल्कि मा0 अध्यक्ष जी, जो हमारे मेधावी छात्र हैं, उनको भी हमारी सरकार इसे देने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में जो कुछ बचा है उसे करने जा रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी का और मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का कि हमारा क्षेत्र बाढ़ का इलाका है। पूरी सगड़ी तहसील बाढ़ की चपेट में रहती है। छोटी सरयू और बड़ी सरयू दोनों के

बीच में हमारा विधान सभा क्षेत्र और भाई अभय सिंह पटेल का विधान सभा क्षेत्र है। इसकी तरफ किसी ने देखने का काम नहीं किया। अभी चन्द रोज पहले, तीन चार तारीख को मा0 शिवपाल सिंह यादव जी वहां गये थे और तीन चार तारीख में जाकर के उन्होंने पूरे बन्धे को देखने का, यहां से लेकर के 40 किलो मीटर सगड़ी का जो पूरा इलाका होता है उस बन्धे को देखने का काम किया है कि कहां पर पुलिया चाहिये, कहां पर रपटा पुल चाहिये, उसको देख करके स्वीकृत करने का काम किया है। जितने रपटा पुल थे हमारे क्षेत्र में, उनको बनवाने के लिये उन्होंने कह दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, यही नहीं, हमारे गोरखपुर के भाई हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और आज वे यहां नहीं हैं। हमारे नेता ने, भाई शिवपाल यादव जी वहां दो, तीन, चार तारीख में थे और उन्होंने सगड़ी तहसील में एक बड़ा पुल, घाघरा नदी पर कई सौ हजार करोड़ रुपये का पुल दे दिया है। आजमगढ़ से गोरखपुर की दूरी और वहां से आने वाले बस्ती, गोरखपुर से होकर के बेलहा में मिलने जा रहा है। आपको हमारी सरकार को, हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी, मा0 शिवपाल यादव जी को धन्यवाद देना चाहिये। ये है काम, हिम्मत होनी चाहिये और अपने में कम से कम दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होना चाहिये तब इस तरीके से काम होते हैं। खाली बातों से काम नहीं चलता, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। यही नहीं, आजमगढ़ से बनारस तक की फोर लेन, आजमगढ़ से जौनपुर तक की फोर लेन, आजमगढ़ से सुल्तानपुर तक की फोर लेन, आजमगढ़ से फैजाबाद तक की फोर लेन, आजमगढ़ से गोरखपुर तक की फोर लेन बनवाने के लिये, उसको देने का काम आदरणीय शिवपाल यादव जी ने कर दिया है, हम आपसे यह कहना चाहते हैं। फिर बातें किस चीज की करते हैं आप, आपके पास तो हर दम पैसे की कमी थी। मैं किसी पार्क की बात नहीं करना चाहता, मैं उस तरफ उंगली उठाने का काम नहीं करना चाहता लेकिन जिसकी जो मंशा होती है, जिसके दिल–ओ–दिमाग में जो भरता रहता है, वह उसी चीज को करने का काम करता है। हमारे नेता मा0 मुख्य मंत्री, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार पर आप क्या बात करते हैं ? आप कहते हैं कि किसान विरोधी सरकार है। आपकी सरकार भी थी क्यों नहीं पानी मुफ्त कर दिया आपने। मा0 अध्यक्ष जी, नहरों का पानी क्यों नहीं मुफ्त कर दिया गया, आपकी सरकार थी ट्यूबवेल का पानी क्यों नहीं मुफ्त कर दिया लेकिन मुफ्त करने का काम जिसके अन्दर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वही माफ करने का काम करता है। नहरों का पानी, आपके सरकारी ट्यूबवेल का पानी मुफ्त करने का काम किसी ने किया तो मा0 अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। हम आपसे कहना चाहते हैं। यही नहीं, आप सहकारिता के बारे में बहुत बात बोल रहे हैं। सहकारिता में भी आपने देखा कि जितनी सहकारी समितियां थीं जो मर चुकी थीं, उन समितियों को 5–5 लाख रुपये देकर के जिन्दा करने का काम हमारे सहकारिता मंत्री मा0 शिवपाल सिंह यादव जी ने किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि दोहरीघाट कैनाल को बनाने के लिये, किसानों के हित के लिये उन्होंने काम किया है। पश्चिम में तो बहुत नहरें हैं लेकिन पूर्व में आप जानते हैं कि कोई नहर नहीं है।

शारदा नदी पर दोहरीघाट कैनाल नहर के लिये भी मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने, सहकारिता मंत्री जी ने उसको बनाने के लिये पैसा दे दिया है, उसको बनाने के लिये कह दिया गया है ताकि जो हमारी जमीन असिंचित बची रह जाती थी उसको सींचने का काम हो सके। इस तरह की व्यवस्था देने का काम किया है मा0 अखिलेश यादव जी ने। आज मेट्रो किसी को नजर नहीं आ रही है। मेट्रो के बारे में एक बार भी हमारे मा0 विधायक जी नहीं बोले। मेट्रो की जो लाइन पहली बिछेगी, वह लाइन जाकर समाप्त होगी आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र में वह क्षेत्र होगा मुंशी पुलिया, जहां पर समाप्त होने का काम होगा। मेट्रो पर आपने कुछ कहने का काम नहीं किया। मेडिकल कालेज में छात्रों की 500 सीटें बढ़ाने का काम किसी ने किया तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। आजमगढ़ के बारे में लोग कहते हैं कि नेता जी की तो हमेशा निगाह आजमगढ़ में रहती है। आजमगढ़ में पैरा मेडिकल कालेज (पी0जी0आई0), जो पी0जी0आई0 माननीय नेता जी ने दिया था, बन रहा था, उस पी0जी0आई0 का सामान पिछली सरकार ने उठाकर अम्बेडकर नगर को देने का काम किया। सारा सामान उठा ले गए। सामान खरीदने का काम नहीं दिया बल्कि जो सामान दिया था हमारी सरकार ने उसको उठाकर ले जाने का काम पिछली सरकार ने किया। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, पशुओं का मेडिकल कालेज दो थे। उसमें से एक चला गया उत्तरांचल में और दूसरा मथुरा में है और तीसरा अगर खोलने की बात हुई और केवल खोलने की बात ही नहीं, बल्कि उसको पैसा देने की बात भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने की है, आजमगढ़ में वह खुलने जा रहा है, यह हम आपसे कहना चाह रहे हैं। बड़ी किसानों की बात करते हैं, बड़े किसानों के हमदर्द हैं लेकिन कोई काम किसानों के लिए आप लोगों द्वारा क्यों नहीं किया गया ? राधेश्याम भाई मैं आप ही को ढूढ रहा था, एक पुल दिया है जिसके द्वारा आजमगढ़ को गोरखपुर से मिलाने, गोला से मिलाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। कब्रिस्तानों को जब हमने घेरने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बड़ा बवाल मचाया लेकिन इनकी दस साल सरकार थी, क्या मुसलमानों को दिया। बहुत किसानों के हमदर्द बैठे हैं, सामने ये लोग, कोई मुसलमानों की बात कही, एक बार भी एक काम भी करने का काम नहीं किया। कब्रिस्तानों को घेरने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया तो अन्त्येष्टि स्थलों को भी पैसा देने का काम किया। हम इस बात को कहना चाहते हैं, इन चीजों को कहने की बात इसलिए है क्योंकि हर चीज में कहते हैं कि कुछ किया ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सारे लोग परेशान हैं, लखनऊ परेशान है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री वसीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, बोलने के लिए अनेक बातें हैं, लेकिन समय कम है और आप मुझे रोक रहे हैं इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए और भाई संग्राम यादव

जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत–बहुत, धन्यवाद।

श्री प्रदीप चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संसोधन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत सारी समस्यायें हैं, बहुत सारे साथियों ने तमाम समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्य रूप से कानून व्यवस्था से सम्बन्धित कुछ बातें कहना चाहता हूं। सहारनपुर में कुछ दिनों पहले बहुत बड़ी घटना हुई राघव ज्वैलर्स के यहां से और तनिष्क शोरूम में तथा उसके बाद रेल में पंजाब मेल ट्रेन जो अमृतसर से चलकर हाबड़ा तक जाती है उसमें लूट हुई। लूट होने पर सरकार ने भी बड़ी गंभीरता दिखाई और एस0एस0पी0 को तुरन्त सस्पेण्ड भी किया, लेकिन मुख्य रूप से जो बात हम सभी लोगों के मन में खटकती है वह घटना के खुलासे को लेकर है। घटना का खुलासा किसी का भी अभी तक उस तरीके से नहीं हुआ, जिससे की लोग संन्तुष्ट हो जाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इन मामलों का खुलासा अतिशीघ्र करे और उसके बाद बहुत सारी समस्यायें हमारे क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, जिससे आमजन, छात्र, किसान सभी लोग परेशान हैं। किसान अपने भुगतान को लेकर परेशान है। पिछले दिनों कोर्ट ने भी आदेश दिया कि 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाए, ब्याज सहित भुगतान हो जाए लेकिन नहीं हुआ। सरकार अभी दबाव दे रही है कि भुगतान जल्दी हो जाए। मान्यवर, खासतौर से सरकार ने कुछ पेमेंट दिया भी है सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए, लेकिन प्राइवेट चीनी मिल मालिक किसानों का बकाया गन्ना मूल्य अदा करने में आनाकानी कर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि गन्ना किसानों का जो बकाया मूल्य है प्राइवेट चीनी मिलों पर उसका अतिशीघ्र भुगतान कराने की व्यवस्था सरकार कराये। मान्यवर, सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना यह सरकार कराये क्योंकि मेरठ विश्वविद्यालय से बहुत से महाविद्यालय सम्बद्ध हैं और उस पर इतना लोड है कि उससे भार नहीं संभल पा रहा है। छात्र अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं उनका समाधान नहीं हो पाता है। गंगोह के अंतर्गत ग्राम–खुडाना एवं दुधला में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करायी जाये। मान्यवर, हथिनीकुण्ड लिंक, चैनल 2 नहर परियोजना जो गंगोह वि0स0 क्षेत्र एवं नकुड़ वि0स0 क्षेत्र से होकर जाने वाली नहर का निर्माण कराया जाये। मान्यवर, हम लोग सहारनपुर को एक विशेष जनपद हम लोग मानते हैं। मान्यवर, सहारनपुर को विशेष औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिया जाय। सहारनपुर जिला उत्तराखण्ड, हरियाणा और हिमांचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, शामली और मुजफ्फरनगर को एन0सी0आर0 भी क्षेत्र से जोड़ दिया गया है और सहारनपुर को छोड़ दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि सहारनपुर को भी एन0सी0आर0 में शामिल कराया जाये। सहारनपुर–दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग को शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कराया जाये वह बहुत दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है। मान्यवर, यह कार्य उपसा को दिया गया था टेण्डर भी हुआ था लेकिन अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिये हैं किसी तरीके से काम

करने के लिये तैयार नहीं हैं। अतिशीघ्र वह कार्य पूर्ण हो सके। यह बात माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में भी है माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था परन्तु अभी कोई हल नहीं निकल पाया है। इसका हल निकाला जाये। मान्यवर, हमारे यहां पीने के पानी की बहुत समस्या है जो सरकारी हैंडपम्प लगते हैं उनमें दूषित पानी निकलता है उससे लोगों में पीलिया, हार्ट की समस्या और दूसरी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक वॉटर टैंक स्थापित कराये जायें और उसके माध्यम से लोगों को वाटर सप्लाई दी जाये। गंगोह के अन्तर्गत जो हैंडपम्प खराब हैं उनको ठीक कराया जाये।

मान्यवर, हमारे यहां यमुना ब्रिज बन रहा है यह दोनों स्टेट उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ता है। इस पर पिछली सरकार में भी काम शुरू हुआ था यह 2012 तक पूर्ण हो जाना चाहिये था इस पर सरकार ध्यान दे। धन की कमी है तो सरकार उसकी पूर्ति कराये। गंगोह कस्बे में तहसील की स्थापना करायी जाये। हमारे यहां नकुड़ तहसील है तहसील में आये दिन बहुत सारी समस्यायें बनी रहती हैं। यहां पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करायी जाये। इससे जनता को लाभ होगा। गंगोह से ननौता, बडगांव मार्ग की मरम्मत शीघ्र करायी जाये। गंगोह में अम्बेहटा से फंदपुरी मार्ग की मरम्मत शीघ्र करायी जाये। गंगोह में यमुना नदी की पटरी पर कुंडा कला से सोनौली तक यमुना नदी के बंधे पर सड़क बनवायी जाये। मान्यवर, बिजली की हमारे यहां समस्या है आगे गर्मी का मौसम आने वाला है। गर्मी के मौसम में समस्या और भी बढ़ जायेगी। आपकी सरकार ने कहा है कि 2016 तक पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली दी जायेगी। हमें आशा है कि आप इसमें सफल भी होंगे। मान्यवर, हमारे यहां गंगोह के अन्तर्गत कुछ गांव के मजरों में जहां विद्युतीकरण बिल्कुल नहीं हुआ है, वहां पर विद्युतीकरण कराने का काम करायें। मान्यवर, हमारे यहां 132 के0वी0 का गंगोह में बिजलीघर बना हुआ है और जो 220 ननौता में बना हुआ है ननौता कस्बे से उसकी लाइन बननी है और जो गंगोह तक आनी है उसमें कुछ काम हुआ है वह ज्यादातर कार्य अधूरा है। उसको पूरा कराया जाये। उसमें कुछ किसानों का विरोध हो सकता है कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है उनको मुआवजा दिलाया जाये और उस लाइन को जल्दी से जल्दी ठीक ढंग से खड़ा करवाया जाय और लाइन चालू करा दी जाये। मान्यवर, हमारे यहां बिजली के बहुत से सब–स्टेशन ऐसे हैं जिन पर लोड बहुत है, इनमें गंगोह के अन्तर्गत विद्युत केन्द्र सिकन्दरपुर, लखनौती, खडलाना, दुधला, इस्सापुर तथा जुखेड़ी केन्द्रों में आये दिन उनकी मशीन जल जाती है, कहीं लाइन ट्रिपिंग हो जाती है उसका समाधान कराया जाये उसकी क्षमता वृद्धि करायी जाय जहां 5 एम0वी0ए0 की मशीन है वहां 10 कर दी जाये जहां 10 है वहां पर 15 कर दी जाये जहां पर 15 है वहां 20 कर दी जाये। मान्यवर, इनकी क्षमता वृद्धि से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायेगा ताकि शेष को सरलता से विद्युत सप्लाई मिल सके। मान्यवर, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो हमारे क्षेत्र से संबंधित हैं कहना चाहता था आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का आपका मैं आभारी हूं मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक समस्या है उसके बारे में जरूर कहना चाहता हूं कि गंगोह ब्लाक व जनपद के अन्दर बहुत सारे लोग आंखों के पेसेन्ट

होते हैं और हमारे वहां के व्यापारी गंगोह के अन्दर हास्पिटल के लिए जमीन भी देना चाहते हैं आंखों का हास्पिटल वहां पर स्वीकृत करा दिया जाय। आप लोगों का संज्ञान वहां चला जायेगा तो उसको स्वीकृति मिल जायेगी और वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। आपने मुझे अवसर दिया आपका आभारी हूं बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री रोशन लाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी विधायकगण जब हाउस चलता है तो अपनी–अपनी बात रखते हैं, अपनी पीड़ा यहां पर रखते हैं यहां पर अधिकारी भी यहां पर राज्यपाल दीर्घा में रहते हैं यह इतनी बड़ी लापरवाही की बात कि ऐसे हाउस के चलते वक्त यहॉ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है जब यहां पर यह स्थिति है अधिकारियों की तो हमारे जिले पर और ब्लाक पर और थानों पर क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी हमारे सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने कानून व्यवस्था की बात कही कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है ऐसे लोगों के लिए कानून व्यवस्था अच्छी है माननीय अध्यक्ष जी उदाहरण के तौर पर हमारे होम थाने पर एक गांव यतिथुरा पृथ्वीपुर है वहां पर एक भोजराम सन आफ सोनी लाल जिसकी आयु 75 वर्ष है और आंखों से भी अंधे हैं और उनका एक बेटा है दोनों बाप बेटों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है उनके ऊपर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी है जिनके जमानती वारन्ट हमारे पास हैं ऐसी कानून व्यवस्था है।

ऐसे निर्धन गरीब लाचार लोगों पर वहां के कर्मचारीगण/अधिकारीगण जुल्म, ज्यादती, अत्याचार करते हैं और जो वास्तव में गुण्डा बवाली है उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है तो उनके राजीनामा गवाह बनाने के लिए उनके ऊपर जो मुद्दई होते हैं उनके ऊपर बदले की भावना से कि इनके ऊपर दबाव बने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिये जाते हैं हमारे यहां एक गांव सफौरा है थाना निगाही वहां पर नेमपाल के फायर लगा, गोली लगी आज 6 महीना हो गया है मुकदमा दर्ज हुए और उस पर यहां तक पुलिस वालों ने दबाव बनाया राजीनामा के लिए जब वह नहीं माना तो उल्टे उसके ऊपर 307 की एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी। मैंने दबाव बनाया कप्तान साहब के ऊपर, कप्तान साहब के यहां कागज मंगवाये गये लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैने 301 में मामला यहां लगाया गया था माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आया कि मुल्जिमों की गिरफ्तारी की जा रही है दबिस दी जा रही है लेकिन अब तक उनकी न गिरफ्तारी हुई है न कोई कार्यवाही हुई, मुल्जिम खुलेआम घूम रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी ? कानून यहां पर दो तरीके के हैं, गरीबों और विपक्षी दल के लोगों के लिए अलग कानून और सत्तापक्ष के लोगों के लिए अलग कानून। माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी जानकारी है और आपने मेरा सहयोग भी किया था। मेरे स्वयं के ऊपर पांच संगीन मुकदमें कायम कराये गये हैं, जिससे हम गरीब जनता और लाचारों की आवाज न उठा सके। मैंने आपसे विनती की थी और आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहकर मेरा मुकदमा सी0बी0सी0आई0डी0 में ट्रांसफर करवा दिया था। मुकदमों की

विवेचना चल रही है, किंतु उन अधिकारियों पर भी सत्तापक्ष के लोग जबर्दस्त दबाव बनाये हुये हैं। पूरे प्रदेश को जानकारी होगी कि इसी दौरान मेरे और मेरे परिवार पर 307, लूट, अपहरण के दो मुकदमें और दर्ज करा दिये गये हैं। विधायकगणों और गरीब लाचार लोगों पर झूठे मुकदमें दर्ज कराये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह अपने अधिकारियों को देखें, अपने कार्यकर्ताओं को देखें जो लोकल थानों में पुलिस से सांठ–गांठ करके बड़े पैमाने पर जुल्म–ज्यादती करते हैं। ऐसे लोगों, ऐसे कार्यकर्ताओं और थानेदारों के खिलाफ जब तक कार्यवाही नहीं होगी, काननू–व्यवस्था ठीक–ठाक नहीं हो सकती है। अभी विकास की बड़ी–बड़ी बातें की गईं और माननीय मुख्य मंत्री जी के पिताश्री हमारी ही विधान सभा से विधायक चुने गये थे। वह हमारे विधायक रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र पर बहुत अहसान किया था।

माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में क्षेत्र की 1 से लेकर 183 तक समस्यायें इसमें अंकित कराई गई हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2012 में आई भयंकर बाढ़ के कारण निगोही से तिलहर मार्ग की लगभग 200 मीटर सड़क कट गई है। यह 25 किलोमीटर लम्बी सड़क है और तहसील तिलहर जाने के लिए एक मात्र रोड है, जिसमें पचासों हजार लोग प्रभावित होते हैं। मैंने कई बार अनुरोध किया है लेकिन 2012 से अब तक वह सड़क नहीं बनाई गई है। इसी तरीके से उनकलां से चमुरूआ चौराहे तक, डेतखेड़ा से खुदागंज तक, परसरा–परसरी से बरीलालपुर तक अनेक सड़कें हैं, जो बनाई जानी आवश्यक हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे माननीय सदस्यगणों ने बड़ी कानून–व्यवस्था की बात की। किसानों के हित की बात की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो धान के क्रय केन्द्र लगाये गये थे, उनकी जांच करा ली जाये। किसी एक भी किसान के धान माननीय अध्यक्ष जी तौले नहीं गये हैं। धान के सेण्टर कहीं राइस मिल पर बना दिये गये तो कहीं आढ़ती के यहां बना दिये गये। एक भी धान किसी कृषक का नहीं तौला गया है। अभी हमारे सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण गन्ने की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि यह किसानों की हितैषी सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी जानकारी होगी, वर्ष 2007 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गन्ने का रेट मात्र 125 रुपये प्रति कुन्तल था। जब वर्ष 2007 में हमारी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार तो 2007 से 2012 के बीच में 280 और 290 प्रति कुन्तल का रेट किया गया। तीन साल के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने गन्ने का एक रुपया भी नहीं बढ़ाया। यह कह रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री रोशन लाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष, यह लोग जानकारी कर लें। रिकार्ड निकलवा सकते हैं कि एक रुपये का भी अगर इस सरकार में रेट बढ़ाया गया हो, तो कहें। गन्ने का प्रति कुन्तल 280–290 रुपये का रेट तो पिछली सरकार का रेट था। बिजली की बात करते हैं और कहते हैं कि नहरों का पानी फ्री किया, जब नहरों में पानी नहीं जायेगा, तो पानी तो फ्री है ही। जहां तक बिजली की बात है तो बिजली कब गई, कब आई, 5 मिनट में गई, 5

मिनट में आई, आज गांव देहात क्षेत्र में 4 घन्टे भी बिजली नहीं मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक ट्रांसफारमर की बात है तो हमारे क्षेत्र में तमाम ट्रांसफारमर फुंके, एक–एक हफ्ते तक मैनें स्वंय प्रयास किया, उसके बाद भी ट्रांसफारमर नहीं बदले जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहां जर्जर तारों की समस्या है जिसका मैनें पहले भी जिक्र किया है। हमारे यहां इन्हीं जर्जर तारों की वजह से चार लोगों की मौत हुयी, मैंने इस विषय को नियम–51 में भी लगाया था, उसमें कहा गया कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। मान्यवर, चार लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, मैं उनके नाम भी बताना चाहता हूं। गंगाराम पुत्र मैकूलाल 05–05–2014 को अपने गन्ने के खेत में पानी लगा रहे थे उनके खेत में 11 हजार करंट की लाइन के तार नीचे लटक रहे थे, उसकी चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, अनिल पुत्र ओम प्रकाश यानि अनिल और उनका पिता टैंक में कुछ काम कर रहे थे, उसमें जहरीली गैस बनने से बाप बेटे की ग्राम परसौना खलीलपुर थानों निगोही के अन्तर्गत मौत हो गयी। इसके लिये मैंने पंचम तल पर भी पत्र दिया। पत्र देने के बाद कृषि दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत मदद देने की बात कही गयी इसमें 1 लाख से 5 लाख माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, बड़ी अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन अधिकारी उसको जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक कृषि दुर्घटना बीमा का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से सरकार कृषकों की अनदेखी कर रही है और किसानों का हितैषी अपने को कहने वाली यह सरकार घोर कृषक विरोधी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार को निर्देश दें कि इन चारों किसानों को कृषि दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाया जाय और मेरे यहां जर्जर 11 हजार लाइन के तारों को बदलवाया जाय। इनसे कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं और समय रहते इनको न बदला गया तो कई दुर्घटनायें और हो सकती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, संख्या बल पर ही सब कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि–

हम अगर चांद नहीं तो हैं सितारे ही सही,
रात अंधेरी हो तो तारें भी सिया देते हैं,
और इससे पहले फलक से कोई बिजली टूटे
आग हम खुद ही नशेमन में लगा देते हैं
और नाखुदा होश में आ, देख हवा के झोंके
आने वाले 2017 के चुनाव में किसी तूफां का पता देते हैं।

इन्हीं बातों के साथ मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार अल्पमत में है, कोरम का अभाव है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहिये।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं और कोरम के संबंध में स्पष्ट नियम है कि जब तक कोई नई मद न शुरू हो और जब मद प्रारम्भ हो तो कोरम का प्रश्न होता है। अगर यह मद समाप्त हो जाय और नई मद आने को हो, तब कोरम का प्रश्न है। दूसरी एक और बात, कि कोरम के लिये सिर्फ सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या ही नहीं, बल्कि सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या देखी जाती है, वह दशांश होनी चाहिये इस समय 40 से ज्यादा संख्या आलरेडी है इसलिये कोरम है और कोरम का प्रश्न तब तक नहीं उठ सकता, जब तक यह मद जारी है।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन यह प्रयास होना चाहिए कि सत्तादल के लोग भी सदन में उपस्थित रहें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपके आदेश का पालन किया जायेगा।

' श्री पंकज गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात रखूं इससे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले बहुजन समाज पार्टी के हमारे एक साथी जी0एम0 सिंह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए क्योंकि सदन में उन्होंने बड़े दुस्साहस का काम किया, बड़े साहस का इन्होंने काम किया कि पत्थरों की जांच के सम्बन्ध में उन्होंने मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से अपनी बात रखने का काम किया। मैं बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर कोई अपराध हुआ है, कोई गलती हुई है तो गलती या अपराध करने वाले से ज्यादा जिम्मेदार वह होता है जिसके संज्ञान में अपराध होता हुआ दिखाई देता है या जो इस सम्बन्ध में कुछ करने या सजा देने में सक्षम होता है। मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सदन में स्वीकार किया है उन्होंने इस बात को कहा है कि आप इस प्रस्ताव को दीजिए अगर जांच हुई तो जांच में बहुत बड़े–बड़े लोग अन्दर चले जायेंगे, जेल चले जायेंगे, इससे बड़ी दिक्कतें आ जायेंगी। इससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार के संज्ञान में है कि पत्थरों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार के संज्ञान में है कि प्रदेश में बहुत गलतियां हुई हैं, प्रदेशवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत करप्शन हुआ है और इतना संज्ञान में आने के बाद भी सरकार द्वारा चुप्पी साधे रखना, आज तक कोई कार्यवाही न करना।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा टीका–टिप्पणी करने पर)

मान्यवर, जब आपकी बात आये तो आप निश्चित रूप से कहियेगा, आपके ही मा0 सदस्य ने बात रखी थी और सरकार के काबीना मंत्री ने उस पर अपने वक्तव्य दिये थे, मैं उन्हीं बातों को कहना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई बात है तो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निश्चित रूप से उसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए क्योंकि इस तरह की बातें सदन में आई हैं रिकार्ड में आई हैं इसलिए इसे बहुत आगे–पीछे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी सत्तादल के कुछ सदस्यों ने अपनी–अपनी बात रखी, मैं अभी श्री शारदा प्रताप शुक्ला जी के विचारों को सुन रहा था उन्होंने भी अपना दर्द रखा और एक हमारे और मा0 सदस्य हैं उन्होंने भी अपने विचारों को यहां रखा। उन्होंने बताया कि जो लोहिया आवास और इन्दिरा आवास बांटे जा रहे हैं उनमें बड़ा गड़बड़झाला है, बड़ा घोटाला है। यह आवास इस प्रकार से पैसे लेकर धन लेकर बांटे जा रहे हैं कि जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनको यह आवास नहीं मिल पा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, हम विपक्ष के लोग इस तरह की बातें कहते हैं तो निश्चित रूप से आपने तर्क कर लिया, वितर्क कर लिया, मेजें थपथपाईं या उपहास कर लिया या कुछ भी कर लिया लेकिन जब सरकार के लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो यह चिन्ता का विषय बनता है। हम सब लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कहीं न कहीं हम लोग जो नियम बनाते हैं, जो सरकारी योजनाएं बनाते हैं जनता के हित के लिए वह वास्तविक रूप से, मूल रूप से लोअर तबके तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है यह आज सरकार के लिए सोचने का विषय बन गया है। बहुत सारे विषय हैं क्षेत्र से सम्बन्धित विषय भी हैं लेकिन मैं एक बात इस सदन में बड़ी प्रमुखता के साथ कहना चाहता हूं। कोई भी सरकार हो सरकार की गरिमा उसके मुखिया के द्वारा कहे गये वचनों के आधार पर चिन्हित की जाती है, मानी जाती है। सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री युवा हैं, नौजवान हैं और हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है वह हमारे जनपद उन्नाव में पिछले ढाई वर्षों में तीन–चार बार आ चुके हैं। इन तीन–चार दौरों में उन्होंने तमाम घोषणाएं हमारे जनपद उन्नाव में की हैं। उन घोषणाओं के बारे में परश्यू करने के लिए जब हम अनुभाग जाते हैं तो इसमें कोई अलग से लेने वाली बात नहीं है लेकिन अनुभाग के अधिकारी हमें बड़े आराम से बताते हैं कि अभी तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी को ढाई साल मुख्य मंत्री बने हुआ है आप यकीन मानो अभी तो मा0 नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा की घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई हैं।

इस प्रकार जुमला कहा जाता है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की गरिमा के लिए यह आवश्यक है कि जो भी घोषणाएं मा0 मुख्यमंत्री जी करें उसको जिम्मेदारी के साथ करें और सरकार के मंत्री और अधिकारी नियमित रूप से उनका आब्जर्वेशन करें और उन्हें पूरा कराने का काम करें। मैं ऐसी ही कई घोषणाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे उन्नाव में दो साल पहले सिटी जेल ड्रेन को पक्का निर्माण कराने की घोषणा की थी। दो साल पहले घोषणा की थी उसका साढ़े 12 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भी बन करके आ गया लेकिन आज तक उसमें चार आना भी रिलीज नहीं हुआ, यह दुर्भाग्य की बात है। इसी प्रकार से इन्होंने लेहनी ड्रेन को पक्का कराने की बात कही थी यह भी साढ़े 10 करोड़ रुपये की परियोजना, दो साल से शासन में लटकी हुई है लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है। परतापुर की सड़क, अतरी की सड़क, एक बांध गंगाजी में बनाने का काम किया गया था घोषणा की गयी थी

क्योंकि गंगाजी का पानी बाढ़ में अक्सर नगरीय इलाकों और ग्रामीण इलाकों में भर जाता था, आज तक उसको भी पूरा कराने का काम नहीं किया गया। ऐसी तमाम घोषणायें हैं और मुझे लगता है कि प्रदेश में अगर अन्य जनपदों को भी गिन लिया जाए तो ऐसी सैकड़ों घोषणायें होंगी जो आज तक उनको पूरा करने का काम न उनके विभाग के मंत्रियों ने किया और न ही विभाग के अधिकारियों ने किया, यह दुर्भाग्य की बात है। इससे सरकार की साख गिरती है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस अभिभाषण के माध्यम से नहीं आया तो आगे बजट में इसको निश्चित रूप से सम्मिलित किया जाए और इनको पूरा कराने का काम किया जाए इससे इनकी भी गरिमा सुरक्षित रहेगी, इस सदन की भी गरिमा सुरक्षित रहेगी और जब सदन की गरिमा सुरक्षित रहेगी तो निश्चित रूप से हम सबकी गरिमा भी सुरक्षित रहेगी। नगरों के बारे में तमाम बातें इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने अपना पक्ष रखा। मैं आज से ढाई–तीन साल पहले उन्नाव नगर पालिका चेयरमैन था तो नगरों की समस्याओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अध्यक्ष जी हमको है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल नगरों में बड़ा प्रेशर हो गया है ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगरों की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं कि वहां रहने के लिए अच्छी सुविधायें मिलेंगी लेकिन दुर्भाग्य से मैं अपनी नगर पालिका की बात क्या करूं उत्तर प्रदेश की ज्यादातर नगर पालिकाओं की स्थिति खराब है। नगर निगमों की स्थिति हो सकती है ठीक हो गयी हो लेकिन नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की स्थिति कहीं भी ठीक नहीं है और इनमें सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए और इस पर भी आने वाले समय में हमें सुधार करने की आवश्यकता है। ड्रेनेज की स्थिति भी उसी प्रकार से है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जब नगरों के ड्रेनेज की बात आती है। हमने कई बार इस सदन में बहस करते हुए सुना, मैं भी नया सदस्य हूं और ईश्वर की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से यहां पर आने का मुझे मौका मिला है। कई बार नगरों के जल निकासी के संबंध में इस सदन में चर्चा करते हुए सुना है, हमने यह भी सुना है कि नालियां साफ करा दी जाती है, नाले साफ करा दिये जाते हैं लेकिन कभी इसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गयी कि नाली और हमारे नाले जो शहर के बाहर जिनसे जुड़ते हैं उस नाले को साफ कराने की व्यवस्था या बजटीय प्राविधान आज तक हमने किसी बजट में यहां पर नहीं देखा। हम शहर की नालियां साफ करा लें, नाले साफ करा लें लेकिन ये नाले बाहर जाकर फिर रुक जाएं वहीं पर, तो यह पानी बैक मारकर फिर शहर में भरने का काम करेगा, ऐसा कभी बजटीय प्राविधान नहीं देखा।

हमने जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जो शहर के बाहर नाले हैं जिनमें शहर का पानी जाता है इनको कैसे साफ किया जायेगा तो अधिकारी कहते हैं कि न राज्य वित्त में, न 13वें वित्त में, न अवस्थापना में, न विधायक निधि में, न सांसद निधि में कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में आप कच्चा काम नहीं करा सकते सिर्फ मनरेगा से आप कच्चा काम करा सकते हो। दुर्भाग्य से ऐसी कई ड्रेनें हैं जो सिंचाई विभाग में भी नहीं हैं शहरों और इण्डस्ट्रीज का पानी बाहर ले जाने का काम करती हैं वहां पर केमीकल युक्त पानी

होता है। अगर वहां पर हम लोग मशीन नहीं लगायेंगे तो उसको साफ नहीं किया जा सकता लेकिन किसी भी बजट में इस प्रकार का प्राविधान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी भी हैं कि इसको भी कहीं न कहीं प्राविधानित करने का काम किया जाए जिससे आने वाले समय में यह बड़ी समस्या है। शहर की नाली हम साफ कर लेंगे लेकिन शहर से बाहर ले नहीं जा पायेंगे तो शहरों में पानी घूमता रहेगा और जब बैक वाटर मारता है तो केमिकल युक्त पानी हमारे शहर के अन्दर दुबारा आ जाता है और पेयजल वाटर को भी दूषित करने का काम करता है। इसी प्रकार से हमारे यहां एस0टी0पी0 प्लाण्ट की समस्या है और भी तमाम प्रकार की समस्या है मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मुख्य रूप से शहर में शहरी क्षेत्र में समस्या चल रही है जो हमारे तालाब हैं उनमें बेतहाशा रूप से भराई का काम चल रहा है, उनमें कब्जेदारी का काम चल रहा है उनको सुरक्षित रखने का समय आ गया है। अगर हम लोग अब अपने तालाब और पोखरे सुरक्षित नहीं कर पाये, जी0एस0 लैण्ड नहीं बची तो आने वाले समय में हमको कोई ठिकाना नहीं मिलेगा कि हम अपना भूगर्भ–जल का स्तर सुरक्षित रख सकें। इसलिए मैं सरकार से विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने का काम करें जिससे उन्हें चिन्हित किया जाए, उनका निरीक्षण किया जाए और उनको किस प्रकार भविष्य में सुरक्षित रख सकें। पी0डब्लू0डी0 के बारे में यहां पर बताया गया कि हम लोग मुख्यालय से जोड़ने के लिए फोर लेन की सड़कें बनाने का काम कर रहें हैं। हम उन्नाव की बात कर सकते हैं अगल–बगल के जनपदों के बारे में बात करेंगे लेकिन हमने जितना देखा है उसको देख करके कह सकते हैं कि उन्नाव मुख्यालय जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं संबंधित हूं। वहां से सरोसी परियर होते हुए एक रोड आती है उसे सिंगल रोड क्या कहिए वह तीन मीटर वाली रोड है। एक बांगरमऊ से रोड आती है यह भी सिंगल रोड है। जितनी रोडें उन्नाव मुख्यालय को जोड़ने वाली हैं वह सब सिंगल रोडे हैं चार लेन की बातें हमारी समझ से परे हैं यह कहने और किताब की बातें हैं जमीनी हकीकत से यह काफी दूर हैं। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जनपद को भी किसी न किसी माध्यम से मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने का काम सरकार करने का कष्ट करे। हमारी 500 की जो आबादी है ऐसी बसावटों को सड़कों से जोड़ने की बात कही गई है वह भी तमाम बसावटें छूटी हुई हैं यहां तक कि जो ओ0डी0आर0 सड़कें हैं हमारे तमाम साथी पी0डब्लू0डी0 की स्थिति के बारे में बता रहे थे जो ओ0डी0आर0 सड़कें हैं जो ब्लाक स्टेट हाई वे के अगल–बगल हैं उनकी भी स्थिति बहुत खराब है सड़कों की स्थिति जर्जर हो गई है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा में एक सड़क है जो करवल से सरौसी होते हुए परियर जाती है वह पूरी तरह से साफ हो चुकी है वहां कुछ नहीं बचा है इसका कोई पुरसाहाल नहीं है बिजली के बारे में तमाम बातें कही गई हैं वास्तव में प्रदेश सरकार के पास पैसा है हमारे पास ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत पैसा है जिससे हम शहरों में काम करा सकते हैं जवाहर लाल नेहरू योजना के अन्तर्गत हमारे पास पैसा है जिससे हम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करा सकते हैं। दुर्भाग्य से पिछले तीन–चार सालों से इन योजनाओं के अन्तर्गत जिस गति से काम होना चाहिए था उस गति से काम नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं कोर्ट की दिक्कतें आईं कुछ न कुछ

समस्या लगातार रही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी न किसी स्तर पर इस समस्या का हल करने की प्रदेश सरकार को आवश्यकता है। अगर इसका समाधान हो जाए और इन योजनाओं में जिसका धन हमारे पास पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से तमाम समस्याएं बिजली की अपने आप हल हो जाएंगीं। बिजली से जुड़ी एक बात मैं अवश्य रखना चाहता हूं हम विधायकों की डेढ़ करोड़ की निधि है अध्यक्ष जी मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहता हूं हम विधायकों की डेढ़ करोड़ की निधि है इसमें जो भी विकास कराना है हम व्यक्तिगत ढंग से करा सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिजली का भी काम कराएं। बिजली का काम कराने में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं एक विभागीय काम कराने की व्यवस्था है एक ठेकेदारी प्रथा से हम लोग काम करा सकते हैं। हम अक्सर एम0डी0 साहब से मिलते हैं अपने अधिकारियों से भी मिलते हैं कि हम अपनी निधि बिजली विभाग को देना चाहते हैं निधि से काम कराना चाहते हैं एम0डी0 साहब कहते हैं कि हम इसको विभागीय करा देंगे लेकिन ठेकेदारी प्रथा से हम काम कराने की अनुमति नहीं देंगे। उसका कारण चाहे जो कुछ हो लेकिन वह इस प्रकार की बात करते हैं हमारा सबसे निवेदन यही है कि माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि ठेकेदारी बेसिस पर भी काम कराने की अनुमति प्रदान कर दी जाए होता क्या है हम विभाग को पैसा दे देते हैं विभाग मैटीरियल भी पहुंचा देता है लेकिन कई बार सत्ता और विपक्ष के संघर्ष में हमारे ट्रांसफार्मर पड़े हैं और सत्तापक्ष के किसी मंत्री का फोन आ गया या विधायक का फोन आ गया तो वह उनके क्षेत्र में चले जाते हैं हमारी निधि का पैसा होते हुए भी काम लटक जाता है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम विधायकों को उनकी निधि के काम उनके तरीके से कराने की अनुमति देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री पंकज गुप्ता–

अध्यक्ष जी एक दो विषय रह गया है हम भी नए सदस्य हैं आप सभी के सहयोग से सीख जाएंगे। सोलर लाइट की बात है इसी प्रकार की समस्या सोलर लाइट में भी है हम लोगों को निधि से खरीदने के लिए नेडा से खरीदने के लिए कहा गया है। नेडा में दुर्भाग्य से एक लाइट मिलती है वह भी 22 हजार वाली इसके अलावा नेडा में दूसरे प्रकार की कोई लाइट नहीं है। अगर उसमें प्रोवीजन दे दिया जाय कुछ और लाइटें मंगा दी जाएं तो ठीक रहेगा। पूर्व में विधायकों को और सांसदों को सब्सिडी में लाइटें मिला करती थीं दुर्भाग्य से पिछले एक साल से सब्सिडी की लाइटें कहीं भी मिली हों लेकिन उन्नाव में नहीं मिलीं। इसका मतलब यह है कि सोलर के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे बढ़ रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार को इस विषय में भी विचार करने की आवश्यकता है। हम खेलकूद के बारे में बात करते हैं इस अभिभाषण में भी कहा गया है कि हम तमाम स्टेडियम बनाएंगे तमाम चीजें बनाएंगे लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टेडियम हैं वह बनाए गए उन पर धन भी खर्च किया गया लेकिन अभी हमारे एक पूर्व के माननीय सदस्य बता रहे थे कि उनमें गधे घास चरा करते हैं। यहां

तक तो ठीक है लेकिन उनकी बाउण्ड्री गिर जाती है दीवार गिर जाती है पूरा स्टेडियम समाप्त हो जाता है। उसका मेंटीनेंस करने वाला कोई नहीं है। उसका कारण है हम चीजें बना देते हैं लेकिन जब किसी कार्यदायी संस्था को सौंपते हैं तो वह ग्राम सभा होती है या ब्लाक होता है उसके पास इतना मद नहीं होता है कि वह उसका मेंटीनेंस कर सके इसलिए मैं सरकार के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए भी एक प्राविधानित धनराशि रखी जाय कि जो चीज बन जाए उसे कैसे संरक्षित रखना है इसको कैसे मेनटेन करना है इस ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, बहुत हो गया है।

श्री पंकज गुप्ता–

मान्यवर, थोड़ी सी समस्याओं की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

पहले इतने का निदान हो जाय।

श्री पंकज गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जनपद और उन्नाव विधान सभा जब भी कभी आप लखनऊ से उन्नाव की तरफ जाइयेगा जहां बदबू आना शुरू हो आप मान लीजियेगा कि यह हमारी विधान सभा है और जहां बदबू समाप्त हो जाय आप मान लीजियेगा कि हमारी विधान सभा खत्म। मान्यवर, पर्यावरण और प्रदूषण विभाग की स्थिति यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रमुख सचिव से मिलता हूं, विशेष सचिव से मिलता हूं तो वह सब एक ही बात कहते हैं कि भई इसमें तो प्रदूषण बोर्ड ही कुछ कर सकता है मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री पंकज गुप्ता–

मान्यवर, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे पास पूरी लिस्ट है मुख्य मंत्री सचिवालय की। इस मुख्य मंत्री सचिवालय की लिस्ट में जो भी सचिव हों मुख्य मंत्री के, जिनके पास जो भी अलग–अलग विभाग हैं उसमें प्रदूषण विभाग का, पर्यावरण विभाग का, कोई भी सचिव आज तक नियुक्त नहीं हुआ यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इतने महत्वपूर्ण विभाग हैं और मुख्य मंत्री का कोई सचिव न होना, यह दुर्भाग्य की बात है। इस पर जरूर कोई न कोई नियुक्ति होनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी बात उन तक पहुँचा सकें। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा पावन स्थल है जहां हम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा के साथ साथ सत्ता पार्टी को, सत्ता दल के अपने सदस्यों को, माननीय मंत्रीगण को सुझाव देने का भी काम करते हैं। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि विपक्ष की तरफ से जब भी कोई सुझाव दिया जाता है तो हमारे सत्ता पक्ष के साथी उसको बड़ी कड़ुवाहट के साथ लेते हैं बड़ी झुंझलाहट के साथ लेते हैं जब कि वह सुझाव इस प्रदेश के लिये एक सही दिशा में प्रयास हो सकता है। अभी हमारे नव निर्वाचित माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बात कही तो माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि वह दोनों जब बहिन भाई थे। तो बहिन भाई के ऊपर टाल दिया। अरे मैं तो बड़ी नम्रतापूर्वक अनुरोधपूर्वक कहना चाहता हूं कि बहिन भाई पर आप जो आरोप लगा रहे हो यह काम तो जनता पर छोड़ दीजिये। बहिन को तो पहले विदा कर दिया और भाई को देखो दिल्ली में विदा कर दिया। अब किसकी बारी है भाई ? तो भाई बहिन तो विदा हो चुके अब तो मैं समझता हूं कि उन सुझावों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है न कि उनको कड़वाहट में लेने की। और केवल विरोध के लिये विरोध करना, यह परम्परा समाप्त होनी चाहिए, यह जरूरी नहीं है। बहुत सारे कार्य हैं, जो सरकार के द्वारा किये जाते हैं। हर सरकार के द्वारा किये जाते हैं और आपकी सरकार के द्वारा भी अच्छे कार्य किये गये और माननीय अध्यक्ष जी मैं विशेष रूप से आपको और सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को, पूरे सदन का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे मोदीनगर में जो बन्द मोदी कपड़ा मिल की समस्या थी वह आपके आर्शीवाद से, आपके सहयोग से, और इस सरकार के सहयोग से उन गरीब मजदूरों का भला हुआ जो कम से कम 25–30 साल पुरानी समस्या थी। आज उन मजदूरों को न्याय मिल सका, आज उन मजदूरों को मैं समझता हूं कि आने वाले चन्द दिनों में पैसा बंटना प्रारम्भ हो जायेगा। इसका सारा श्रेय माननीय अध्यक्ष जी आपको जाता है और इसके लिये निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, मोहिदिनपुर शुगर मिल को भी आपके द्वारा चलाने का प्रयास किया गया। इसके लिये भी मैंने सदन में खुद कई बार धन्यवाद दिया है और आज फिर मैं उस धन्यवाद को आपको देता हूं कि आपने उस मिल को चलवाने का काम किया कि जिसको बेच दिया गया था उस मिल को चलाने का काम करके किसानों को एक नई राह दिखाने का कार्य किया है उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी केवल मिल चला देने से केवल यहां भला नहीं होने वाला है किसानों का। आज मोदी शुगर मिल एक अकेले मोदीनगर शुगर मिल पर किसानों का 170 करोड़ रुपया मोदी मिल पर बकाया है जिसमें से एक नये पैसे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। बल्कि जो पिछले साल का भुगतान है वह भी केवल फरवरी तक का भुगतान अभी किया जा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की हैसियत से बड़े विद्वान मंत्री हैं हमारे आदरणीय अम्बिका चौधरी जी आप बैठे हैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की हैसियत से मा0 अम्बिका चौधरी

जी बैठे हैं बड़े विद्वान मंत्री जी हैं मैं बताना चाहता हूं मेरे विचार से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और न जाने कहां–कहां से आदेश आ गए हैं तो क्या इसमें सरकार की कमी नहीं है। अगर सरकार की इच्छाशक्ति हो और सरकार अपने आपको किसानों का समर्थक और किसानों की हितैषी होने का दावा करती है तो मैं समझता हूं कि उन्हें अपनी इच्छाशक्ति को जाग्रत करना होगा कि इस दिशा में पहल करने के लिए बहुत आवश्यक कदम उठाना होगा लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मा0 राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों के गन्ना भुगतान का कोई जिक्र नहीं है।

मान्यवर, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, तो कानून–व्यवस्था की बात पर माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक एन0एच0–24 है, हमारे बहुत से साथी वहां से गुजरते होंगे जो गाजियाबाद से हापुड़ को जाता है।उसका टोल टैक्स समाप्त हुए मेरे ख्याल से वर्षों हो गया है लेकिन आज भी पुलिस की मिली भगत से लाइन लगाकर के चाहे कोई वी0आई0पी0 हो, चाहे कोई साधारण इंसान हो, उससे लाइन लगवाकर टैक्स वसूला जा रहा है। मेरे अगर कोई गाजियाबाद के साथी होंगे तो वह बता सकते हैं, देखिए एक माननीय सदस्य हाथ भी उठा रहे हैं।मैं स्वंय वहां से कल निकला हूं और पास गाड़ी पर लगा हुआ था उसके बाद भी पैसे मांगने की इन्होंने हिम्मत की, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सॉरी बोला और यह भी बताया गया कि हां इसकी टोल टैक्स की मियाद खत्म हो चुकी है तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा भद्दा मजाक समाज के साथ और क्या हो सकता है।यह किसकी मिली भगत से चल रहा है क्या यह सरकार के संज्ञान में नहीं है क्या जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं है। मान्यवर, दूसरी बात बताना चाहता हूं मेरे आवास से लगभग पचास मीटर पर मोदीनगर में भव्य जैन मन्दिर है पूरे जैन मन्दिर को खाली कर दिया गया परसों, जैन मन्दिर की समस्त मूर्तियों को चुराकर, जितना भी उस जैन मन्दिर के अन्दर समान था, अब इसको आप चाहे चोरी कह लें, चाहे डकैती कह लें तमाम जो भगवान जी की मूर्तियां जो उसके अन्दर स्थापित थीं किसी मूर्ति को नहीं छोड़ा गया और पूरे मन्दिर को खाली करके ले गए।

आज ही वहां से फोन आया है एक दूसरी घटना हुई है एक बहुत बड़ा शोरूम है 'ब्यूटी सेन्टर' के नाम से, उस ब्यूटी सेन्टर में भी दिन दहाड़े चोरी की गई, यह डकैती है मान्यवर, लेकिन इनको वहां का प्रशासन चोरियों में तब्दील कर लेता है तो जहां तक कानून व्यवस्था की बात है मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मेरा यह कहना है आप बहुत से विकास के कार्य कर रहे होंगे कुछ छूट रहे होंगे, लेकिन यदि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो माननीय मंत्री जी, वह आपके काम निरर्थक हो जाएंगे और यह जनता आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, जब चुनाव चल रहा था तो मोदी नगर के अन्दर उन्होंने एक सभा की थी और स्वयं उन्होंने घोषणा की थी, जब मैंने सबसे पहली बार यह मुद्दा उठाया था तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया था मोदीनगर के अन्दर एक जाम का मुद्दा बहुत ज्यादा है। यह

उत्तरांचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तीनों को जोड़ता है और उसी रोड से गुजरना पड़ता है चाहे किसी को दिल्ली जाना हो चाहे हरिद्वार जाना हो, चाहे दिल्ली से उत्तरांचल जाना हो,चाहे उत्तरांचल से दिल्ली जाना हो, मा0 अध्यक्ष जी, बड़े सौभाग्य की बात थी कि उस दिन तो दोपहरी थी, आप दिन में आए थे मोदीनगर, आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ा, वरना गाड़ी तीन–तीन घंटे में मोदीनगर के जाम से नहीं निकल पाती है। यह मोदीनगर न होकर के जामनगर बना हुआ है। अनेकों बार मैं इस मुद्दे को उठा चुका हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मा0 श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि इसको भी जोड़ा जाए कि मोदी नगर को जाम मुक्त करने के लिए या तो वाईपास, जिसमें कार्यवाही बहुत धीमी गति से चल रही है या तो वाईपास या एक एलीवेटेड पुल बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाए। क्योंकि इसकी वजह से मा0 अध्यक्ष जी, करोड़ों रुपये का तेल मैं समझता हूं दिन प्रतिदिन फुंकता है जो सीधे–सीधे राजस्व की हानि है लोग बीमारों को लेकर के अपने बच्चों को ले करके घंटों जाम में फंसे रहते हैं। मान्यवर, जहां एक घंटे का शैड्यूल होता है वहां चार–चार घंटे लगते हैं और पुलिस भी असहाय हो जाती है, क्योंकि पूरा शहर वहां पर ऑन रोड बसा हुआ हैं। हमारे साथी आदरणीय राणा जी बैठे हैं ये रोज निकलते होंगे वहां से। जाम की समस्या मोदी नगर की बहुत भयंकर समस्या है। यदि आप अपनी पीठ से सरकार को इस दिशा में कदम उठाने का आदेश दे दें, निर्देशित कर दें तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा और निश्चित रूप से आपकी सरकार के लिये भी एक अच्छा प्रयास होगा।

श्री अध्यक्ष–

आपका 10 मिनट का समय खत्म हो गया, अब आप समाप्त करें।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, मैं केवल अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं बताना चाहूंगा। आपने मोदी नगर कपड़ा मिल की समस्या का समाधान कराया था तो मैं बता दूं कि वहां के वर्करों नें पम्पलेट छपवा करके आपकी सरकार को और आपको महिमामंडित करने का काम किया है। मैंने मोदी कपड़ा मिल के साथ–साथ मोदी स्टील को भी उसमें जोड़ा था। मोदी स्टील को बन्द हुए काफी समय हो गया है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है कि कोई उसके अन्दर से माल नहीं निकालेगा और मेरे विचार से वहां पर अरबों रुपये का माल था, लेकिन धीरे–धीरे प्रशासन के द्वारा मिलकर के और मोदियों के द्वारा जिनकी वह फैक्ट्री है उनके द्वारा महीने में कम से कम हर महीने दो–तीन करोड़ का माल चोरी से ट्रकों से निकाल लिया जाता है और मजदूरों ने मौके पर पकड़ा है, थाने में उनके अधिकारी बन्द हुए हैं, मुकदमें कायम हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती और मजदूरों का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां वह संसदीय कमेटी बरकरार है और मोदी स्टील के मजदूरों का भी यदि भुगतान हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा में सुधार का दावा सरकार पिछले दो–ढाई साल से कर रही है। मैं भी मानता हूं कि शिक्षा में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन इसमें सुधार की और आवश्यकता है। इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, ऐसे कानूनों को बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसी चीजें है जो रीढ़ की हड्डी हैं और यदि इनमें सुधार हो जाएगा तो हमारा समाज सही दिशा में अग्रसर होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

मान्यवर, आपने मुझे संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने महामहिम राज्यपाल जी की अभिभाषण पत्रिका को देखा और इसका अध्ययन किया। इसमें बुन्देलखण्ड को और खासकर झांसी को कोई तवज्जो नहीं दी गई है। मान्यवर, हमारे बहुत से साथी इस बात की चर्चा करते हैं कि बुन्देलखण्ड पिछड़ा क्षेत्र है और इस सरकार की प्राथमिकता भी है कि बुन्देलखण्ड को आगे लाया जाए। प्रदेश के सभी क्षेत्रों की तरह बुन्देलखण्ड को विकास के हर पहलू पर आगे बढ़ाया जाए, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी की इस अभिभाषण पुस्तिका में बुन्देलखण्ड के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। मान्यवर, खासकर मैं अपने जनपद झांसी की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने पूरे प्रदेश की समस्याओं को और अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। मेरे झांसी जनपद की कुछ समस्याएं हैं और खासकर मेरे बबीना विधान सभा क्षेत्र जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मैंने कई बार नियमों के माध्यम से और प्रश्नों के माध्यम से इन समस्याओं को तमाम एंगिल से सदन के सामने लाने का प्रयास किया है। लेकिन अभी हमारी समस्याएं, हमारे क्षेत्र की समस्याएं जस की तस हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अभी जो गांव चयनित किए गए हैं, उस सूची में शामिल किए गए हैं, उसमें मेरी बबीना विधान सभा क्षेत्र के जो भी गांव हैं, उस सूची में नहीं हैं। वह सूची उस समय की उठा ली जाती है, जो राजस्व गांव हैं, राजस्व में उन मजरों की जिनकी आबादी पांच सौ, सात सौ है, उन गांवों को अभी तक राजस्व गांवों की सूची में शामिल नहीं कराया गया है और उसी कारण से वह गांव जिनमें विद्युतीकरण नहीं है, वह गांव किसी भी योजना में चाहे सड़क सम्पर्क मार्ग की योजना हो, उसमें नहीं आ पाते हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण की जो योजना है, उसमें नहीं आ पाते हैं, इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र

के ग्राम पंचायत खैरा के अन्तर्गत परिहार मोहल्ला, पड़ती मोहल्ला, पाल मोहल्ला और ढिमरपुरा मोहल्ला, ये चार ऐसे मजरे हैं, जिनकी आबादी सात सौ, आठ सौ से ऊपर है, लेकिन आज तक इन गांवों में न तो सम्पर्क मार्ग हैं, न विद्युतीकरण हुआ है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसी तरह से हमारे ग्राम पंचायत खजराह बुजुर्ग के दया नगर, पथरवारा, चन्द्र नगर, पनहारी, टौरिया, सड़, यह ऐसे मजरे हैं, जिनमें आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत सिमरावारी के चौका, कोडरा, भखडयाऊ और वादली, यह मोहल्ले हैं। ग्राम पंचायत बेदौरा की डुबकी छोटी, बड़ी डुबकी, भडरा और छर्रा, इनमें आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आजादी के 66 साल बाद भी सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े हैं जैसे मडौरा से हाजीपुरा का सम्पर्क मार्ग नहीं है। इन गॉव के बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है, बरसात के महीने में वहां के बच्चे स्कूल जाना बन्द कर देते हैं, इसके कारण उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है और उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो रहा है। इसी तरह से पालर से बावल टाडा है, मवई से खिरिया है, फोरलेन से कारीटोरन मटयाई रसीना मार्ग है, फोरलेन से वधौरा होते हुए पंचमपुर तक, छिसौली से सुजानपुरा तक, गुडा से ढिमरपुरा तक, मठ से बाजना तक, सुकुयां रोड से चन्दौली तक और फोरलेन से सन्तरी के डेरा होते हुए राम नगर रोड तक, यह जो सम्पर्क मार्ग हैं, 66 साल की आजादी में आज तक नहीं बने हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार बहुत लम्बे–चौड़े वायदे करती है और कहती है कि सरकार इन मजरों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ेगी। यहां तक कि मंत्री जी ने कई बार कहा है कि पूरे प्रदेश की जो सड़के हैं, जिनमें गड्ढे थे, गड्ढे मुक्त करा दिए गए हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा बबीना में रसीना रोड से रतनपुर तक का मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, अगर माननीय मंत्री जी इस सड़क पर जायें तो उन्हें लगेगा कि वह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि किसी बहुत पिछड़े प्रदेश में हैं, जहां आज भी ऐसी सड़कों की हालत है।

इसी तरह से बबीना से खाड़ी बुडपुरा होते हुए हीरापुर तक का मार्ग, बबीना से ठकुरपुरा तक का मार्ग, लहर से सुकुवॉ मार्ग, चिरगांव से हवानी मार्ग, फोरलेन से मुराटा तक का मार्ग, जौरी रोड से जौरी खुर्द मार्ग, गौरारी से लेवा अतपेई होते हुए बिठरी मार्ग, यह ऐसे मार्ग हैं, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले बजट में इन मार्गों को शामिल कराया जाए और जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उनके लिए बजट में व्यवस्था कराई जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, सरकार कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं लेकिन हमारे यहां ऐसी समस्या है कि कागजों में तो नहर सिमथरी तक है, लेकिन नहर केवल पचार तक बची है, किसानों ने उस नहर को खेतों में मिला लिया है। जब टेल तक नहरें ही नहीं बची तो पानी कैसे पहुंचेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पहले तो उस टेल तक जहां तक कागज में वह नहर है वहां तक उस नहर को खुदवाया जाए। इसके

बाद उस टेल तक पानी पहुंचाया जाए। इसी तरह से हमारी नहर की जो पटरियां हैं वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। इसके माध्यम से गणेशपुरा से नहर ठकुरपुरा तक वल्लमपुर से नगरा तक दुर्गापुर से नयागांव तक नकुबां से छपार होते हुए पुलिया तक माण्डेर रोड से नरी तक और पारीक्षा से पचार तक जो नहर की पटरियां है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कि आने वाले बजट में इनकी व्यवस्था की जाए और कानून व्यवस्था पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में थाना रकसा के अंतर्गत कप्तान का पुत्र भईया लाल जिसकी उम्र आठ वर्ष है माननीय अध्यक्ष जी जो चार महीनें से गायब है आज तक पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। कई बार धरना प्रदर्शन हुआ और उन्होंने कल तक का समय डी0एम0 साहब को दिया था कि अगर हमारा बच्चा नहीं मिला तो हम फिर धरना प्रदर्शन देंगे। उसी तरह से चिरगांव थाना अनूप राजपूत का है जो रेलवे में नौकरी करता है उसको भी पांच माह हो गए अभी तक उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। उसके परिवार के लोग भी कल से धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करें और शासन को निर्देश करें कि इन दोनों बच्चों को उपलब्ध कराएं। इसी आशा के साथ मा0 अध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ। सरकार की नीतिगत बातों पर प्रकाश पड़ा। सरकार एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहती है लेकिन ऐसा लगता है नीतियों में कमजोरी है ठीक से इसकी प्लानिंग नहीं कर पाई है। सरकार कहती है कि हमने लोहिया गांव के लिए इतना चयन किया। सवाल यह है कि लोहिया गांव के लिए उपयुक्त कितने गांव हैं क्या सबका होगा ? एक ही साथ सब नहीं हो सकता लेकिन समयबद्ध कार्यक्रम लेना चाहिए कि कुल इतने गांव हैं एक साल में इतने गांव लिए जाएंगे। तब तो लगेगा कि सबकी पारी आएगी। लेकिन आपने कितने गांव लिए है अब कितने बचे हैं और कितने रह जाएंगे इसका कहीं अंदाजा नहीं लगता। इसी प्रकार से राज्यपाल के अभिभाषण में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा ध्यान दिया गया है उनको हेल्पलाइन दिया गया है जब वो बुलाएंगे तो एम्बुलेंस आ जाएगी लेकिन आए दिन अखबार में आता है कि कोई महिला गई अस्पताल में बेड नहीं है अस्पताल ने लौटा दिया। एक अस्पताल से दूसरा दूसरे से तीसरा और अन्त में रास्ते में ही प्रसव हो गया और वह महिला मर गई। तो इससे ऐसा लगता है कि यहां भी कुछ ऐसी कमियां हैं दूर–दराज की महिलाओं को भी निकटवर्ती अस्पतालों की सुविधा होनी चाहिए। हम सभी जाएं कुछ चुने हुए अस्पतालों में जाएं और वहां जगह न मिले तो भटकते रहे और जीवन की आस ही बुझ जाए यह गलत है। कुछ समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा लखनऊ

में संजय गांधी अस्पताल है तो बगल में रायबरेली में क्यों खोला जा रहा है। ये तो पूर्वांचल में होना चाहिए था। यह सारी योजनायें उत्तर प्रदेश की जनता की सुख–सुविधाओं को ध्यान में रखकर सबकी हित को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। इसी तरह से महिलाओं की सुरक्षा में सबसे बड़ी कमजोरी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने हेल्पलाइन दिया है सरकार ने व्यवस्था की है और अगर उसके साथ दुर्व्यवहार हुई तो उसको आपने आर्थिक सहायता दिया जाय। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सुरक्षा चाहिए। हम पर इस प्रकार की विपत्ति न पड़े हमें यह चाहिए। क्या कारण है कि खुले आम तेजाब बिकती है। कुछ दवाइयों के लिए अगर जरूरी है तो उसकी व्यवस्था किया जाय। तो कोई भी नौजवान जा करके तेजाब खरीदता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है। बाजारों में खुले आम तेजाब की बिक्री होती क्यों है ? यह प्रश्न रह रह कर उठता है। इसी प्रकार से महिलाएं शाम को शौचालय में जाती है। शौचालय न होने से खुले मैदान में जाती है। जितनी महिलाओं से रेप की घटनाएं मिलती है यही मिलता है कि वह शाम को मैदान में गई और उनको खींच के खेत में ले गए। शौचालय हर जगह चाहिए। जब आप शौचालय के निर्माण की योजना बनाते हैं तो कहते हैं गांव में बनेगी शहर में नहीं बनेगी और हम सोचते हैं कि शहरों की दुर्दशा गांवों से ज्यादा है। बस्ती की महिलायें आकर कहती हैं कि हम लोटा लेकर निकले, ससुर महाराज को देखकर लौट आये और हम जा नहीं पाये। वहां खुले मैदान भी नहीं हैं। बड़ी–बड़ी दीवार, मकान खड़े हो गये हैं। यहां औरतों को ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए बस्तियों जहां शौचालय ही नहीं हैं वहां इस नीति में शहरों को भी शामिल करना चाहिए। इसी प्रकार से यह कहा गया है कि हम किसानों को ऋण दे रहे हैं। किसानों को ऋण लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। आप कितने दिन तक किसानों को ऋण दीजिएगा। ऋण की मात्रा बहुत अच्छी है। आपने 30 हजार से लेकर दो लाख तक का ऋण किसानों को देने की व्यवस्था की है। लेकिन क्या हर किसान को मिल जाता है। व्याप्त भ्रष्टाचार यह कहां तक करने देता होगा यह संदेहास्पद है ही। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसान आत्मनिर्भर हो, किसान की खेती लाभदायक हो। फसल को वह अच्छे दामों में बेच सके। उसकी लागत, खर्चा निकले। कर्जा बहुत बुरी चीज है चाहे सरकारी कर्जा हो या साहूकार का कर्जा हो। आज हम देखते हैं कि या तो किसान कर्ज से डूबा हुआ है वह फसल की लागत निकाल नहीं पा रहा है। इसलिए वह या तो आत्महत्या कर रहा है या अपने खेत को कोलोनाइजर के हाथ में बेचकर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहा है।

यह देश के भविष्य के लिए घातक है हमारी खेतीहर जमीन बहुत तेजी से घटती जा रही है। गांव खत्म हो रहे हैं सिर्फ कालोनी बन रही है। हर देश की जमीन सीमित है। चाहे वह घर बनाये, फैक्ट्री बनाये या खेती कराये। हमें देश का विकास चाहिए देश का विकास संतुलित होना चाहिए, उसमें खेती का भी विकास होना चाहिए। अर्थव्यवस्था हर अंग जब तक संतुलित ढंग से विकसित नहीं होगा तब तक कोई भी देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता। हम आर्थिक विकास की बड़ी–बड़ी बातें करें, ट्रामा सेंटर बनायेंगे। इतना रेलवे लाइन का विस्तार करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि पूजा

की थाल लेकर हमारी औरतें मंदिर जा रही हैं तो रास्ते में सीवर के पानी के ऊपर से जा रही हैं तो उनके सामने विकास की कोई अच्छी तस्वीर उपस्थित नहीं होती है। हमें विकास चाहिए, बुनियादी आवश्यकतायें चाहिए। खाना चाहिए। हर वह आदमी जो सड़क पर जिंदगी बिता रहा हो उसको एक अदद छत चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यह सब परस्पर संबंधित हैं। खेत विकसित होंगे तो कच्चा माल मिलेगा। कच्चा माल मिलेगा तभी आपकी फैक्ट्रियां चलेंगी। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को गेहूं, चावल खाने के लिए चाहिए। इसलिए जितना विकास हो उसकी संतुलित योजना बननी चाहिए। जब हम सबका परस्पर संतुलित करके विकास करेंगे तभी विकास की अवधारणा पूरी होगी। मान्यवर, समाजवादी पेंशन योजना की बात कही गयी है। बहुत अच्छी योजना है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें महिला वर्ग की प्रधान महिला को अधिकार दिया गया है। लेकिन समझ में नहीं आता कि समाजवादी पेंशन योजना की प्रशंसा करने के साथ–साथ कहना पड़ता है कि वृद्धावस्था पेंशन या विकलांग पेंशन का पैसा दो–दो, ढाई–ढाई साल से क्यों नहीं दिया गया है ? हम बार–बार जिला समाज कल्याण अधिकारी को फोन करते हैं तो वह कहते हैं कि इस महीने आ जाएगा। यह चीज ठीक नहीं है। आप या तो जो वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं या विकलांग पेंशनधारी हैं उनको समाजवादी पेंशन में कनवर्ट करिये या फिर उसको कन्टीन्यू करिये। इसका पैसा जो दो–ढाई साल से रूका है। वह गलत है। उसको चालू करिये।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। पांच बज गये।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

इसी प्रकार से आपने कहा है कि हम किसानों को समर्थन मूल्य दे रहे हैं। समर्थन मूल्य भी संतुलित होना चाहिए। आप कभी गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा देते हैं कभी चावल का समर्थन मूल्य बढ़ा देते हैं। किसान बोला करता है कि इसको बोने से हमें ज्यादा फायदा होगा। परिणाम क्या है, आज दाल की खेती बंद हो रही है। अब दाल का हाहाकार हो रहा है। सरकार योजना बना रही है कि दलहन की खेती करने वाले किसानों को हम आर्थिक सहायता देंगे। यह सब दिखाता है कि हमारी नीतियां कमजोर हैं। हमारे जो खेती की प्रमुख उपज हैं। उन सबका संतुलित कृषि समर्थन मूल्य होना चाहिए। किसी एक को बढ़ावा दें एक को घटायें यह नहीं होना चाहिए। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मोटी–मोटी बातें बता रही हूं।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कल बोल लीजियेगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा कल कन्टीन्यू कर लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

ख05.00 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23–02–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 43 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना ठाकुर दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के किरनदेवी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामौती, अलीगढ़ के पूर्व प्रबन्धक एवं वर्तमान प्रधानाचार्य को प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कदाचार की जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद मण्डलीय सचल दल का प्रभारी बनाकर नकल रोकने की जिम्मेदारी सौपे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री गेंदा लाल चौधरी की उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर में वेव चीनी मिल को माह दिसम्बर 2014 में चालू कर के माह जनवरी 2015 में बन्द किये जाने से उत्पनन स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर की पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा पर्यटन विभाग को मेजा डेस्टीनेशन स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि द्वारा जमुना नदी पर अवस्थित घाटों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवी सूचना श्री प्रभु दयाल वाल्मिकी की जनपद मेरठ के विधानसभा क्षेत्र हस्तिनापुर में किसानों के गन्ना बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में दिनांक 05–05–2014 को गंगा राम पुत्र मैकूलाल की विद्युत तार की चपेट में आने से हुई मृत्यु के उपरान्त कृषक दुर्घटना बीमा की सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सांतवी सूचना श्रीमती लाल मुन्नी सिंह राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ में तैनात अधीक्षक द्वारा बड़े पैमाने पर की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की जनपद वाराणसी नगर के पेय जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के कार्य में जलनिगम द्वारा अत्यधिक विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर में नजूल की भूमि को फ्री–होल्ड कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सकों, टैक्नीशियन्स की तैनाती तथा आवश्यक उपकरण लगाये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, ग्यारवहीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ग्राम सभा की भूमि, पोखरों, चारागाहों की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :–

1–श्री पंकज कुमार मलिक,

2–श्री रविदास मल्होत्रा,
3–श्री राजीव गुम्बर,
4–श्री रामचन्द्र यादव,
5–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,
6–श्री रविन्द्र जायसवाल,
7–श्रीमती सीमा,
8–श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट,
9–श्री गुलाब चन्द्र सरोज,
10– श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,
11–श्री दलजीत सिंह,
12–श्रीमती अराधना मिश्रा,
13–श्री विजय कुमार दुबे,
14–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या,
15–श्री बब्बन सिंह चौहान,
16–श्री पूर्णमासी देहाती,
17–श्री अनिल कुमार,
18–श्री संत राम कुशवाहा,
19–श्री भगवान सिंह कुशवाहा,
20–श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत,
21–श्री बालाप्रसाद अवस्थी,
22–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,
23–श्री सन्त प्रसाद,
24–श्री जगन प्रसाद गर्ग,
25–श्री अगयश रामसरन वर्मा,
26–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल,
27–श्री मनीष असीजा,
28–श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
29–श्री अरूण कुमार,
30–श्री ममतेश शाक्य,
31–पं0 सुदेश शर्मा तथा
32–श्री संजय कपूर।

श्री अध्यक्ष–

कल अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। अब हम उठते हैं कल दिनांक 24–02–2015 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 04 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 23 फरवरी, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 35 विधान सभा (60)–10–05–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।